



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939

No. 172]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

अंतिम जांच परिणाम

**विषय:** यूरोपीय संघ, कोरिया जनवादी गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500 सीरीज एवं 1700 सीरीज के स्टाइरिन बुटाडीन रबर (एसबीआर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

**सं. 14/10/2015-डीजीएडी.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और उसके बाद समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और वसूली तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमों (जिन्हें बाद में यहां पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

**क. प्रक्रिया**

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां बाद में "प्राधिकारी" कहा गया है) को संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग के रूप में द इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड (आईएसआरपीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) (जिन्हें यहां बाद में "याचिकाकर्ता" कहा गया है) से एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ (ईयू), कोरिया जनवादी गणराज्य और थाइलैंड (जिन्हें यहां बाद में संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टाइरिन बुटाडीन रबर (जिसे यहां बाद में "संबद्ध सामान" अथवा "एसबीआर" कहा गया है) का पाटन हो रहा है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए सिफारिशें की जाएं।

ख. यह आवेदन पत्र की प्राथमिक जांच में कुछ कमियां सामने आईं जिन्हें याचिकाकर्ता ने बाद में ठीक कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने अद्यतन विधिवत दस्तावेजयुक्त याचिका दायर की जिस पर प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के लिए विचार कर लिया।

- ग. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने का औचित्य दर्शाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध जांच शुरू करने का निर्णय लिया।
- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व आवेदन पत्र के फॉर्म के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को सूचित किया।
- ङ. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 14 जनवरी, 2016 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांचें शुरू कीं।
- च. प्राधिकारी सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके व्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को उस सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में ज्ञात अपने विचार देने का अवसर प्रदान किया।
- छ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात आयातकों को उस सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी कि वे उस पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर लिखित में अपने विचार रखें।
- ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भेजी। आवेदन पत्र की एक प्रति, जहां भी अनुरोध किया गया था, अन्य हितवद्ध पक्षकारों को भी दी।
- झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना देने के लिए प्रश्नावली भेजी:

कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि., ईस्ट विंग, 10-14वां तल, सिग्रेचर टावर्स सिओल, 100, चियोंग्येचियोन-रो, जुंग-गु, सिओल, कोरिया	एलजी केम. लि. 128, यीयुई-डायरो, यियोंगदियूंगपो-गु, सिओल, कोरिया
स्ट्रोन एलएलसी: 1000 केस्टरब्रूक बिल्डिंग, बेरविन, पेन्सिलवैनिया 19312, संयुक्त राज्य अमेरिका	सिंथस एसए: अल. चेमिको 1, 32-600 ओस्विसिम, पौलेंड
वेरसालिस एसपीए: पियाजा बोलद्रिनी, 1 – 20097 सन दोनातो, मिलानेस (एमआई), इटली	सिबुर (जेपीएससी सिबुर होल्लिंग) 16/1 कृष्णिझानोवस्कोगो स्टे., मॉस्को, जीएसपी-7, 117997, रूस
लैंक्सेस एजी: केन्नेडाइप्लाट्ज 1, 50569 कोलोप्पे, जर्मनी	बैंकॉक सिंथेटिक्स कं. लि., 175 सथोर्न सिटी टावर, 11वां तल, साउथ सथोर्न रोड, टंगमहामेक सथोर्न, बैंकॉक - 10120

- अ. जांच शुरू करने की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से पत्र प्राप्त हुए हैं:

- i. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य
- ii. मैसर्स देवू इंटरनेशनल, कोरिया जनवादी गणराज्य
- iii. मैसर्स देवू इंटरनेशनल, सिंगापुर
- iv. मैसर्स एलजी केम. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य

- v. मैसर्स एलजी केम. अमेरिका इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका
- vi. मैसर्स वोनकेम लि., कोरिया जनवादी गणराज्य
- vii. मैसर्स हर्टकिम कारपो., कोरिया जनवादी गणराज्य
- viii. मैसर्स एवरलाइट कोरिया कं. सि., कोरिया जनवादी गणराज्य
- ix. मैसर्स हनसुक केमिकल्स कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य
- x. मैसर्स सिंथस करालुपी ए. एस., चेज गणराज्य
- xi. मैसर्स सिंथस डाउरी 7 एसपी. जेड. ओओ, पौलैंड
- xii. मैसर्स ट्रिसियो प्रा. लि.

ट. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत ने संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी गई थी:

मैसर्स जेके टायर्स, लिंक हाउस 3, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002	मैसर्स बिरला टायर, शिवम चैंबर्स, 53, सैयद आमिर अली एवेन्यू, कोलकाता – 700 019, पश्चिम बंगाल
मैसर्स अपोलो टायर्स, अपोलो हाउस 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर – 32, गुडगांव – 122001 (हरियाणा)	मैसर्स सियेट लि., सियेट महल, 463, डॉ. ऐनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई – 400 030
मैसर्स एमआरएफ लि., 124, ग्रीम्स रोड, चेन्नई – 06	मैसर्स रालसन, प्लॉट नं. 3, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, मणिद्वीप, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश – 462 046
मैसर्स पोद्दार टायर, जीटी रोड जुगियाना, लधियाना (पंजाब) – 141 420	मैसर्स ओरियंटल रबर इंडस्ट्रीज, 525 कोरगांव बीमा पुणे नगर रोड, पुणे
मैसर्स हिंदुस्तान रबर, 1 जानकी सेंटर, स्वर्गीय वीरा देसाई रोड, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई – 53	मैसर्स अग्रवाल रबर, 15-1-503/49/ए, अशोक मार्केट, सिद्धिचंवर बाजार, हैदराबाद – 500 01, आंध्र प्रदेश
मैसर्स एक्सल रबर, फ्लैट नं. 507, साई सदन अपार्टमेंट्स, एसबीआई बालकम्पेट के सामने, एस. आर. नगर, हैदराबाद – 500 038	मैसर्स टेगा इंडस्ट्रीज, प्रथम तल, सं. 210, 5वां मेन रोड, विजय नगर, दूसरा स्टेज, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई – 400 053
फोनिक्स कनवेयर बेल्ट इंडिया प्राइवेट लि., आइडियल प्लाजा, नॉर्थ ब्लॉक, चौथा तल, 11/1, सरत बोस रोड, श्रीपल्ली, भोवानीपोर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700020	हिंदुस्तान रबर्स, 1, जानकी सेंटर, वीरा देसाई रोड के सामने, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई – 400 053
फॉरेक इंडिया लि., हिल्टन हाउस, एस-23, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110 016	गढ़वाड़े बेस्ट्रेच, अमर अविनाश कारपोरेट प्लाजा, चौथा तल, बंद गार्डन रोड, पुणे – 411 001 (महाराष्ट्र), भारत

पैरागॉन पॉलीमर प्रोडक्ट प्राइवेट लि., पी. बी. नं. 61, पैरागॉन बिल्डिंग, बिशोप जैकब मैमोरियल हॉल के सामने, श्रीनिवासा अयैर रोड, चलुकुन्नू, केरल – 686 001	ओरियंटल रबर इंडस्ट्रीज लि., शरवानी गार्डन्स, 20, विमान नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411 014
मिदास रबर (पी) लि., मिदास मार्केटिंग बिल्डिंग, वरीस्सेरी जंक्., मरियाथुरुथू, पी. ओ. कोट्टायम, केरल, भारत – 686 027	रालसन (इंडिया) लि., रालसन नगर, जी. टी. रोड, लुधियाना – 141 003, पंजाब, भारत
सेम्परट्रेस निरलोन (पी) लि., निरलोन कॉम्प्लेक्स, पहाड़ी गांव, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई – 400 063	मैट्रो टायर्स लि., मैट्रो टावर, सी – 49, सेक्टर – 62, नोएडा – 201 301, भारत
बालाकृष्ण टायर्स लि.	अलियांस टायर्स ग्रुप
मैसर्स बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीकेटी हाउस, सी/15, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013	मैसर्स एटीसी टायर्स प्रा. लि., यूनिट नं. टी 6 और 7, 5वां तल, हाई स्ट्रीट, फोनिक्स ए विंग, फोनिक्स मिल्स, कंपाउंड, 462, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013
गुड्रियर इंडिया लि., पहला तल, एबीडब्ल्यू एलीगेंस टावर. जसोला, नई दिल्ली – 110 025	ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. ओ 43, फेज – II, एमआईडीसी चकन, गांव सावरदारी, तालुकाखेद, जिला पुणे, महाराष्ट्र – 410 501

<b>ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन</b> पीएचडी हाउस, चौथा तल, श्री फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, एशियन गांव के सामने, नई दिल्ली – 110 016	<b>ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन</b> 601, प्रमुख प्लाजा, बी विंग, 485, कार्डीनल ग्रेसियस रोड, प्रोक्टर और गैबल के सामने, चकाला, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई – 400 099
---	---

ड. निम्नलिखित आयातकों/उपभोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- मैसर्स अपोलो टायर्स लि.
- मैसर्स ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा. लि.
- मैसर्स सियेट लि.
- मैसर्स जेके टायर्स लि.
- मैसर्स एमआरएफ लि.
- मैसर्स टीवीएस श्रीचक्र लि.

इसके अतिरिक्त, कई अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणियां की हैं और वर्तमान जांच के संबंध में अपनी बात रखी है जिसको उपयुक्त रूप से ध्यान में रखा गया है। उपर्युक्त हितबद्ध पक्षकार निम्नलिखित हैं:

- यूरोपियन कमीशन (व्यवसाय के लिए डायरेक्टर जनरल)
- कोरिया जनवादी गणराज्य सरकार

- iii. ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए)
  - iv. ऑटोमोटिव टायर्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए)
  - v. मैसर्स ऋषिरूप पॉलीमर्स प्रा. लि.
  - vi. मैसर्स ऋषिरूप लि.
- ड. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए लेन-देन वार आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं और डीजीसीआईएस/निर्यातकों के उत्तर में आयातकों द्वारा दायर किए गए आंकड़ों से उनका व्यापक रूप से संबंध इस सीमा तक देखा है जहां तक वे व्यापक वैधकरण के लिए व्यावहारिक हों।
- ण. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गैर गोपनीय रूपांतरण सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए। सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कई हितबद्ध पक्षकारों ने कई बार किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने निरीक्षण तथा सार्वजनिक फाइल से दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध किया, उन्हें वे दे दी गई।
- त. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के अनुसार की गई। प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक समझा, गोपनीयता के दावे स्वीकार किए और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीयता के आधार पर दायर सूचना के पर्याप्त गैर गोपनीय रूपांतरण दें जो सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।
- थ. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से सूचना उतनी ही मांगी गई, जितनी आवश्यक समझी गई। घरेलू उद्योग का सत्यापन उसी सीमा तक किया गया, जहां तक वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझा गया।
- द. निम्नलिखित निर्यातकों के परिसरों में स्थल सत्यापन भी किया गया।
- (i) कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य
  - (ii) मैसर्स देवू इंटरनेशनल, कोरिया जनवादी गणराज्य
  - (iii) मैसर्स एलजी केम. कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य
- ध. उपर्युक्त निर्यातकों को किए गए सत्यापन की रिपोर्ट जारी की गई है। निर्यातकों द्वारा की गई टिप्पणियों को इस निष्कर्ष में ध्यान में रखा गया है।
- न. जांच 01 अक्तूबर, 2014 से 30 सितंबर, 2015 (12 माह) (जिसे इसके बाद यहां जांच की अवधि अथवा पीओआई कहा जाएगा) की अवधि के लिए की गई। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में फरवरी, 2014 से तथा जांच की अवधि तक की अवधि शामिल की गई जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष को 4 तिमाहियों में बांटा गया।
- प. सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना पर आधारित भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्माण और बिक्री की लागत को ध्यान में रखते हुए गैर क्षतिकारक कीमत (जिसे आगे यहां एनआईपी कहा गया है) निकाल ली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त होगा। चूंकि मैसर्स आईएसआरपीएल ने जांच की अवधि के बाद में वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया, अतः केवल मैसर्स आईएसआरपीएल की सूचना इस एनआईपी की गणना के लिए स्वीकार की गई है।
- फ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 14 सितंबर, 2016 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से देने का अवसर प्रदान किया। उसके बाद दूसरी मौखिक सुनवाई 04 नवंबर, 2016 को आयोजित की गई थी। जिन पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक सुनवाई में दिए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए विचारों को लिखित रूप में दर्ज कराएं और उसके बाद अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- ब. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे दें जिसमें जांच की अवधि शामिल हो, यह सूचना प्राधिकारी को प्राप्त हो गई थी। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा तथा मूल्य और क्षति विश्लेषण की गणना के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों का संदर्भ दिया है।
- भ. प्राधिकारी ने 15.06.2017 को नियम 16 के तहत प्रकटन विवरण जारी किया और 23 जून, 2017 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणी देने के लिए अवसर प्रदान किया जिसे आगे 27 जून, 2017 तक बढ़ा दिया गया है। चूंकि प्रकटन

विवरण सभी भारतीय रबड़ उद्योग एसोसिएशन को भेजने में गलती से चूक हो गई थी अतः वह 9 जुलाई, 2017 को ई-मेल कर दी गई थी ताकि उन्हें दबावपूर्ण सांविधिक समयबद्धता, जिसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था, की दृष्टि से शीघ्र उत्तर देने के लिए अवसर मिल सके।

- म. अमेरिकी डॉलर को रूपए में बदलने के लिए विनिमय दर सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए 63.62 रूपए के रूप में मानी गई है।
- य. इस अंतिम जांच परिणाम में \*\*\* का अभिप्राय गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना से है और इसीलिए नियमों के तहत प्राधिकारी ने यह मान लिया।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

1. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद यूरोपीय संघ, कोरिया (आरपी) तथा थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टाइरिन बूटाडीन रबर है।

#### निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

2. एसबीआर 1500, 1700 और 1900 पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन थे तथा 1999 से 2001 तक संरक्षण में थे। शेष घरेलू उत्पादक 1900 सीरीज का उत्पादन करते हुए अतः केवल इस कारण कि मौजूदा उत्पादकों ने एसबीआर 1500 तथा 1700 का उत्पादन करने के लिए मौजूदा उत्पादन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विचाराधीन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
3. विशिष्ट ग्रेडों यथा 1502 एनएफ, 1507, 1507 एच, 1745, 1763, 1769, 1789, 1793, 1799 को विचाराधीन उत्पाद से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि उनका उत्पादन घरेलू तौर पर नहीं होता है।
4. दिनांक 24.04.2017 के पत्र द्वारा एटीएमए का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स लूथरा एंड लूथरा विधि कार्यालयों ने यह बात रखी है कि ईएसबीआर 1739 तथा 1789 ग्रेडों को अलग कर दिया जाए क्योंकि मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्वीकार किया है कि वह इस समय ईएसबीआर से 1789 का विनिर्माण नहीं कर सकता और मैसर्स आईएसआरपीएल ने अपनी वेबसाइट अपने उत्पादों की सूची में इस ग्रेड को नहीं रखा है।
5. जैसा कि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि एसबीआर 1500, 1700 तथा 1900 सीरीज परस्पर परिवर्तनीय रूप से निर्मित की जा सकती हैं और यह अन्य देशों में विद्यमान परिपाटी हैं। यह घरेलू उद्योग की अंतर्निहित कमी जानी जाती है कि वह इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रेडों का विनिर्माण नहीं कर सकता कि भारत में 1900 सीरीज के ज्ञात उत्पादक हैं।
6. 1739 और 1789 जैसे कई उत्पाद ग्रेड तथा सॉल्यूशन एसबीआर, जो कि संघटन और प्रयोगों की दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों से भिन्न हैं, को अलग किया ही जाना चाहिए।
7. एटीएमए का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स लूथरा एंड लूथरा ने अपने दिनांक 24.05.2017 के पत्र के माध्यम से 30.03.2017 के अपने पूर्व पत्र के उत्तर में लिखित 15.05.2017 के डीजीएडी के पत्र का उत्तर यह कहते हुए दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि जैसा विगत में किया जाता रहा है तथा नियम 6(7) के अनुसार और इस अनुरोध के समर्थन में उल्लिखित कानूनी निर्णयों के अनुसार, डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेन-देन वार आयात आंकड़ों को बताएं।
8. विदेशी विनिर्माता परस्पर परिवर्तनीय रूप से एसबीआर सीरीज 1500, 1700 और 1900 का विनिर्माण कर सकते हैं तथा इसीलिए, घरेलू उद्योग भी उनका विनिर्माण कर सकता है।

#### घरेलू उद्योग के विचार

9. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित बातें रखी हैं:

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद स्टाइरिन बूटाडीन रबर है। स्टाइरिन बूटाडीन रबर (एसबीआर) स्टाइरिन और बूटाडीन से व्युत्पन्न सिंथेटिक रबरों के परिवार का वर्णन करता है। इस सामग्री में अच्छी अपघर्षण प्रतिरोधकता है तथा संवर्द्धकों द्वारा संरक्षित होने पर अच्छी स्थिरता भी है। एसबीआर दो कारकों स्टाइरिन और बूटाडीन से तैयार किया जाता है। इन दो कारकों के मिश्रण को दो प्रक्रियाओं से पॉल्यूमराइज किया जाता है – सॉल्यूशन (एस-एसबीआर) से अथवा इमल्शन (ई-एसबीआर) के रूप में। वर्तमान मामला इमल्शन एसबीआर के संबंध में ही है।
- ख. स्टाइरिन बूटाडीन रबर अथवा एसबीआर वैश्विक रूप से उत्पादित एवं उपयोग में लाए जाने वाले सिंथेटिक रबर की सबसे बड़ी मात्रा है। प्राकृतिक रबर की तुलना में एसबीआर में बेहतर प्रक्रिया क्षमता, समरूपता, दहनदक्षता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता है, परंतु दीर्घीकरण ऊष्णता सहन शक्ति वातान्मुक्तता, लचीलापन और तननशक्ति की दृष्टि से यह घटिया है। अधिकतर एसबीआर का उपयोग टायरों के विनिर्माण में किया जाता है।
- ग. एसबीआर की कई ग्रेडों का उत्पादन होता है जिनको कोपोलाइमर (सीरीन का प्रतिशत) इमल्सफायर टाइप, सामान्य मूनीविस्कोसिटी, कोगुलेशन, विशिष्ट घनत्व और उत्पाद के स्तर द्वारा लक्षण दिए जाते हैं। उन्हें सीरीज 1000, 1500, 1600, 1700, 1800 और 1900 में अलग-अलग किया जाता है। वर्तमान याचिका केवल एसबीआर 1500

सीरीज और एसबीआर 1700 सीरीज से संबंधित है। एसबीआर 1900 सीरीज को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से अलग किया गया है, यद्यपि, उनका उत्पादन भी विदेशी उत्पादकों द्वारा किया जाता है। एसबीआर 1000, 1600, 1700, 1800 सीरीज भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

- घ. ग्रेडों में अंतर बुटाडीन और स्टाइरिन के संघटन में अंतर के कारण है, फिर यह तथ्य कि याचिकाकर्ता भी विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है, इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। कोई भी अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाएं शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं है और मौजूदा सुविधाओं के भीतर याचिकाकर्ता अन्य ग्रेडों का भी उत्पादन कर सकते हैं। याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे उत्पादों का कोई भी ग्रेड अलग न करें।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद दो मोनोमर्स स्टीरीन और बुटाडीन में उत्पन्न सिंथेटिक रबड़ के (एसबीआर) के 1500 और 1700 सीरीज के स्टीरीन बुटाडीन रबड़ हैं। इन वस्तुओं की अच्छी अपघर्षण प्रतिरोधक और काल प्रभाव न स्थिरता है जब इन्हें योजकों द्वारा संरक्षित किया जाता है। सोल्यूशन एसबीआर ग्रेड जांच के क्षेत्र से बाहर हैं।
- ख. प्राकृतिक रबड़ की तुलना में, एस बी आर की प्रक्रिया क्षमता, होमोजिनीटी, हीट एजिंग और अपघर्षण प्रतिरोधक बेहतर है। किंतु इलॉगेशन, हॉट टियर स्ट्रेंथ, हिस्टरेमिस, रेजिलिएंस और टनसाइल क्षमता की शर्तों में निकृष्ट है। एसबीआर की मुख्य मांग टायरों के विनिर्माण में ऑटोमोटिव सैक्टर में हैं।
- ग. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क शीर्ष संख्या 400219 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- घ. "समान वस्तु" की परिभाषा संबंधित नियम 2(घ) विनिर्दिष्ट करता है कि समान वस्तु का अभिप्राय उस वस्तु से है जो जांच के तहत वस्तु के सभी मामलों में समान अथवा उसी तरह हो अथवा उस वस्तु के अभाव में निकट रूप से विशेषताओं वाली अन्य वस्तु हो जो जांच के अधीन उन वस्तुओं के समान हो।
- ङ. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जो संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से भारत में निर्यात की जाती हैं, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित स्टाइरिन बुटाडीन रबर तथा संबद्ध देशों से निर्यातित रबर भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसीलिए इन्हें पाटनरोधी नियमों के तहत समान वस्तु माना जाना चाहिए। घरेलू एवं आयातित संबद्ध वस्तुओं की प्रतिस्थापनीयता को प्रभावित करने वाली तकनीकी विशेषताओं में कोई भी विशिष्ट अंतरों के उदाहरण स्थापित नहीं हो पाए और जिनसे विस्तृत जांच की जानी आवश्यक समझी जाए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन से भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं की तरह समान वस्तु माना जाता है।
- च. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य कि मैसर्स आरआईएल, 1739 और 1789 ग्रेडों का विनिर्माण करने की स्थिति में इस समय नहीं है, को इस प्रकटन में मैसर्स आरआईएल के लिए बाद में जांच किए गए बाजार कमी की दृष्टि से क्षति के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। ग्रेड/ग्रेडों के वर्तमान विनिर्माण स्तर से भविष्य में उस समय उन ग्रेडों का उत्पादन करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को कम नहीं करता, जब उसके लिए ऑर्डर हो तथा स्वच्छ बाजार भी स्थापित हो। इसके अतिरिक्त, मैसर्स आरआईएल ने इन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता दर्शाते हुए इन ग्रेडों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस भी रिकार्ड में रखा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने वास्तविक मंदी के निमित्त आरआईएल को हुई क्षति का मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इन दो ग्रेडों को अलग नहीं किया जा सकता।
- छ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उन आंकड़ों के अधिकृत वास्तविक उपयोग के संबंध में घोषणा करने के बाद डीजीएडी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर पाटनरोधी जांच में भाग लेने वाले सभी अधिकृत हितबद्ध पक्षकारों को वे आंकड़े दिए जाएं तथा वे यह भी सुनिश्चित करें कि पाटनरोधी शुल्क के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोग के लिए इसका प्रयोग न किया जाए तथा इसका प्रकटन न किया जाए। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध पर प्राधिकार जारी किए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त आंकड़े मांगने वाले लूथरा एंड लूथरा का अनुरोध किसी औचित्यपूर्ण कारण पर आधारित नहीं है क्योंकि वही आंकड़े प्राधिकारी द्वारा ऊपर बताए गए अनुसार प्राधिकार पत्र के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए वही दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।
- ज. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के अनुसार, स्टाइरिन बुटाडीन रबर

की सीरीज से संबंधित विभिन्न ग्रेडों के बीच एक मात्र अंतर रबर तथा संबद्ध तेल की मात्रा में स्टाइरिन और बुटाडीन की मात्रा के संघटन अनुपात का है। यह विश्वास करने का कोई कारण और साक्ष्य नहीं है कि यदि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों का उत्पादन करना चाहे तो अपनी मौजूदा सुविधाओं से वे रबर के ऐसी ग्रेडों का उत्पादन कर सकते हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित उत्पाद में संबद्ध देशों से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं में समान वस्तु शामिल है। विचाराधीन उत्पाद 1500 और 1700 सीरीज का स्टाइरिन बुटाडीन रबर है जिसमें सॉल्यूशन एसबीआर ग्रेड शामिल नहीं है। चूंकि, सॉल्यूशन एसबीआर ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटा दिए गए हैं और यह उस विचाराधीन उत्पाद का पाठ विवरण है जिसमें सीमा प्रशुल्क शीर्ष पर प्रमुखता है, प्राधिकारी मानते हैं कि एसबीआर के इन सॉल्यूशन ग्रेडों को इस प्रकार हटाए जाने से पाटनरोधी उपायों को लगाए जाने में कोई भ्रामकता नहीं बनेगी।

#### ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

*"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समय घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

#### निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- क. आवेदक वास्तविक मंदी के आधार पर आवेदन दायर करने के पात्र नहीं हैं और सामग्री की मंदी का दावा केवल नए उत्पादक/नए उद्योग के लिए किया जा सकता है। यह उत्पाद नया नहीं है और आवेदक द्वारा वास्तविक रूप से मंदन का दावा मानने योग्य नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद भारत में पहले से ही मौजूद है और 2010 तक पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन था।
- ख. एपकोटैक्स एक दूसरा भारतीय विनिर्माता है जो अब भी एपकोटैक्स एसआर 502 नाम के ब्रांड से एसबीआर 1502 का विनिर्माण कर रहा है। भारत में बेचे जाने वाले इस उत्पाद की मालसूची 2014 में आवेदकों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुल्क दिए जाने से पूर्व भी 2007-08 से ली गई है।

#### घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित तथ्य रखे हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक के रूप में मैसर्स इंडियन सिंथेटिक रबर प्रा. लि. (आईएसआरपीएल) और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा यह याचिका दायर की गई है।
- ख. आईएसआरपीएल इंडियन ऑयल कारपोरेशन; टीएसआरसी, ताइवान और मरूबेनी कारपोरेशन, जापान द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें इंडियन ऑयल का 50 प्रतिशत का इक्विटी शेयर है, ईएसआरसी की 30 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी है; यद्यपि यह पूर्णतः निजी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, त्रिमूर्ति होल्डिंग कारपोरेशन (टीएचसी) मरूबेनी कारपोरेशन की कंपनी में 20 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी है। यद्यपि यह पूर्ण रूप से निजी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मरूबेनी पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट बी.वी. (एम.पी.आई.), नीदरलैंड है।
- ग. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. तेल का पता लगाने, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एवं विपणन तथा पेट्रोकेमिकल्स में देश में एक सुरक्षा उत्पादक है। आरआईएल ने जांच की अवधि के अंत तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया।
- घ. याचिकाकर्ता ही स्टाइरिन बुटाडीन रबर के एक मात्र घरेलू उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता का संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक अथवा निर्यातक से कोई संबंध नहीं है। किसी भी दशा में ऐसा कोई संबंध नहीं है जो कि नियम 2(ख) के तहत उसे हटाने की संभावनाएं सिद्ध करे।

#### अन्य पक्षकारों के तर्कों को घरेलू उद्योग का प्रत्युत्तर

11. घरेलू उद्योग में अन्य पक्षकारों के तर्कों के उत्तर में निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

- क. प्राधिकारी ने पूर्व के एसबीआर जांच में मध्यावधि समीक्षा की थी और एसबीआर 1500 तथा 1700 पर शुल्क हटा दिया था तथा इस आधार पर एसबीआर 1900 पर शुल्क जारी रखा कि समीक्षा अवधि के दौरान एसबीआर 1500

व 1700 का कोई उत्पादक नहीं था। अतः प्राधिकारी ने स्वयं ही निष्कर्ष निकाला है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई घरेलू उद्योग नहीं था।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स सिंथेटिक रबर प्रा. लि. (आईएसआरपीएल) और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू उद्योग के रूप में आवेदन पत्र दायर किया था। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध सामनों के पूर्ण उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक अथवा आयातक से कोई संबंध (प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से) नहीं है। उत्पादन व्यौरे नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं:

**तालिका 1: याचिकाकर्ताओं का उत्पादन**

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादन मात्रा					
आईएसआरपीएल	मी. टन	-	***	***	***
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	मी. टन	-	-	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	-	6,912	46,657	92,540
उत्पादन में हिस्सा					
आईएसआरपीएल	%	-	***	***	***
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	%	-	***	***	***
याचिकाकर्ता का हिस्सा - कुल	%	-	100%	100%	100%

- ख. जहां तक इस बात का संबंध है कि घरेलू उद्योग याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचालन शुरू करने से पूर्व पहले से ही अस्तित्व में था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसबीआर 1900 सीरीज से संबंधित पूर्व की जांच के दौरान देश में एसबीआर 1500 और एसबीआर 1700 सीरीज के लिए कोई उत्पादक नहीं था जिससे विचाराधीन उत्पाद वर्तमान याचिका में आता है।
- ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स आरआईएल ने वाणिज्यिक उत्पादन को केवल जांच की अवधि के बाद अर्थात् अक्तूबर, 2016 में घोषित किया है और इसीलिए उनके आंकड़ों सहित एनआईपी की गणना करना व्यवहार्य एवं उपयुक्त नहीं है, परंतु यह घरेलू उद्योग का एक हिस्सा है और उसका क्षति मूल्यांकन वास्तविक मंदी के रूप में किया जाता है। प्राधिकारी ने आईएसआरपीएल को वास्तविक क्षति का मूल्यांकन करने के लिए इसे मैसर्स आईएसआरपीएल के आंकड़ों के आधार पर ही एनआईपी का मूल्यांकन करना उपयुक्त माना है। घरेलू उद्योग के दोनों उत्पादकों के संबंध में क्षति मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन किया गया है।
- घ. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) की आवश्यकताओं अर्थात् नियमावली के तहत स्थायी आवश्यकता को पूरा करते हैं। अतः याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के भीतर घरेलू उद्योग में आते हैं।

धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य-

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।

### घरेलू उद्योग के विचार

12. सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क निम्नलिखित हैं:

- क. निर्यातक देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत तथा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की कीमत सूचियों अथवा दरों की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। तथापि, इन प्रयासों से कुछ हासिल नहीं हुआ। संबद्ध देशों में संबद्ध सामनों के बहुत ही सीमित उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं। अतः व्यापार सीधे ही उत्पादकों एवं निर्यातकों के बीच होता है।
  - i. याचिकाकर्ता यह बात रखते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के अधिकतर उत्पादक, उत्पादकों का स्टाइरिन और बुटाडीन का उत्पादन नहीं है।
  - ii. इसी के मद्देनजर और यह मानते हुए कि उत्पादक विचाराधीन उत्पाद को उत्पादन की लागत से कम कीमत पर बेच रहे हैं, याचिकाकर्ताओं ने कच्ची सामग्री की कीमतों तथा उपभोग मानदंडों परिवर्तन लागतों के अनुमानों, बिक्री, सामान्य प्रशासन खर्चों तथा उपयुक्त लाभ मार्जिन के आधार पर संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य बनाया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रणाली निम्नलिखित है:

### निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

- क. संविदा में निहित सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन कीमत कटौती तथा क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्क विश्व व्यापार संगठन के करार तथा डीजीएडी की परिपाटियों के अनुरूप नहीं है। यह परिपाटी केवल उच्च कीमत के विचलन के मामलों में अपनाई गई है।
- ख. ऑर्डर की बुकिंग के समय इनपुट लागत माने जाने पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए समयमान दृष्टिकोण का प्रयोग करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्क यह ज्वलन्त प्रश्न उत्पन्न करता है कि यह सूचना आवेदक द्वारा उस समय प्राप्त की गई थी जबकि वह सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं थी।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा निर्माण सही नहीं है क्योंकि उपभोग के कारक के रूप में परिकलित मानदंड स्वाभाविक रूप से पूर्वानुमानक हैं।
- घ. निर्मित सामान्य मूल्य तभी अपनाया जा सकता है जब कि निर्यातक देशों के घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री न हो अथवा बाजार स्थिति विशेष हो अथवा घरेलू बाजार में बिक्री की मात्रा कम हो।
- ङ. केवल आईएसआरएल की उत्पादन लागत पर विचार किया गया है जब कोई अन्य आवेदक नहीं है।
- च. विकसित उद्योगों का सामान्य मूल्य एक उदीयमान उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर हो सकता है।
- छ. उत्तर पूर्व एशिया से बुटाडीन की कच्ची सामग्री कीमतें यूरोपीय संघ के लिए गलत मानी गई हैं।
- ज. जांच में शामिल देशों के लिए कच्ची सामग्री के वास्ते अपनाई गई कीमतों के आधार में कोई सुसंगति नहीं है।
- झ. निर्मित सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए कच्ची सामग्री (एम-3) में समायोजन से सामान्य मूल्य में वृद्धि हुई है।
- ञ. निर्मित सामान्य मूल्य में इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन हाल ही में आरंभ किया है।
- ट. याचिकाकर्ता की लागत के आधार पर निर्माण सही नहीं है क्योंकि दक्षताओं का स्तर और उत्पादन दरें अलग-अलग हैं।
- ठ. यूरोपीय संघ का लागत ढांचा उनके आकार और अर्थव्यवस्था के मानदंड के कारण भिन्न हो सकता है।

**अन्य पक्षकारों के निवेदनों के उत्तर में घरेलू उद्योग के अनुरोध**

- क. जांच की अवधि में एसबीआर की उत्पादन लागत दोनों आवेदकों के लिए तुलनीय है। अतः किसी भी आवेदक की लागत के आधार पर परिकल्पित विचाराधीन उत्पाद का निर्मित सामान्य मूल्य तुलनीय होगा।
- ख. सामान्य मूल्य का निर्माण करते समय उत्पादन की वास्तविक लागत नए उत्पादकों की शुरुआत में शामिल उच्च निर्धारित लागत के मद्देनजर नहीं रखी गई है, उत्पादन की निर्धारित लागत 90 प्रतिशत पूंजी उपयोग पर मानी गई है।
- ग. उत्तर पूर्व एशिया की कीमतों के लिए बुटाडीन यूरोपीय संघ के लिए माना गया है क्योंकि वह याचिकाकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना थी।
- घ. घरेलू उद्योग ने कभी यह दावा नहीं किया है कि लागतें घरेलू उद्योग और उत्तरदायी निर्यातकों के लिए समान हैं। आवेदकों ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार किया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

14. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- (क) (i) मैसर्स कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(ii) मैसर्स देवू इंटरनेशनल, कोरिया जनवादी गणराज्य  
(iii) मैसर्स देवू इंटरनेशनल, सिंगापुर
- (ख) (i) मैसर्स एलजी केम. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(ii) मैसर्स एलजी केम. अमेरिका इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका  
(iii) मैसर्स वोकेम लि., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(iv) मैसर्स हर्टिकेम कारपो., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(v) मैसर्स एवरलाइट कोरिया कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(vi) मैसर्स हनसुक केमिकल्स कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य
- (ग) (i) मैसर्स सिंथस करालुपी ए. एस., चेज गणराज्य  
(ii) मैसर्स सिंथस डाउरी 7 एसपी. जेड. ओओ, पौलैंड
- (घ) मैसर्स ट्रिसियो जीएमबीएच, जर्मनी
- (ङ) मैसर्स बीएसटी एलास्टमर्स, थाइलैंड

यद्यपि, उत्पादकों/निर्यातकों ने उपर्युक्त (क) से (ग) में निर्मित एवं पूर्ण व्यौरे दायर किए हैं, जबकि (घ) और (ङ) में उल्लिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने आंशिक/सीमित आंकड़े दायर किए हैं।

पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के लिए प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान भारत औसत कारखानागत निर्यात कीमत के साथ भारत औसत सामान्य मूल्य की 1500 और 1700 सीरीज के लिए अलग-अलग तुलना भी की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात में कमी का सकारात्मक साक्ष्य कोई नहीं है जो ऑर्डर/संविदा की तारीख का संदर्भ देकर तुलना करे तथा सामान्य रूप से किए जाने वाले मालसूची की तारीख पर न हो।

**I. यूरोपीय संघ****क. सहकारी उत्पादक/निर्यातक**

- क. मैसर्स सिंथस डाउरी 7 स्पोकला जेड ऑर्गेनिकजोना ऑडोपोवीडजियालनोसिया स्पोकला जावना, पौलैंड ("सिंथस डाउरी") और सिंथस करालुपी ए. एस., चेज गणराज्य ("सिंथस करालुपी")

15. मैसर्स सिंथस डाउरी, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक ने उत्पादक के रूप में प्रश्नावली का उत्तर दिया है। इसके संबंधित कंपनी अर्थात् उत्पादक एवं निर्यातक अर्थात् मैसर्स सिंथस करालुपी ने भी प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं। उनके तर्क निम्नलिखित हैं:
- क. उत्पादित स्टाइरिन बुटाडीन कोपोलाइमर शीत पोलीमराइनेशन प्रक्रिया में होता है जिसमें मिश्रण प्रणाली के रूप में रोजिन और वसा युक्त एसिड साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य हिस्से रोजिन तथा वसा युक्त एसिडों एंटीऑक्सीडेंट तथा/अथवा एस्टेंडर ऑयल होते हैं।
- ख. इस उत्पाद के उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री मोनोमर है: \*\*\* तथा \*\*\*
- ग. यह उत्पाद गांठों के रूप में बेचा जाता है, वजन \*\*\* किग्रा., लगभग \*\*\* एमएम.
- घ. इस उत्पाद का इस्तेमाल कार टायरों और बिजली ट्यूबों, कंवेयर बेल्ट, फुटवियर, केबिल, हौज पाइप और विभिन्न तकनीकी रबर की वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है।
- ङ. सामान्य मूल्य का दावा गृह बाजार में बिक्री के आधार पर किया जाता है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

#### (i) सामान्य मूल्य

जांच की अवधि के दौरान, मैसर्स सिंथस डाउरी ने 1500 सीरीज के \*\*\* मी. टन और 1700 सीरीज के \*\*\* मी. टन तथा मैसर्स सिंथस करालुपी ने 1500 सीरीज के \*\*\* मी. टन तथा 1700 सीरीज के \*\*\* मी. टन घरेलू बाजार में बेचे। दोनों कंपनियों द्वारा घरेलू बाजार में सभी बिक्रियां जांच की अवधि के दौरान गैर संबद्ध पक्षकारों को की गईं। भारत में निर्यात से तुलना करने पर घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने प्रत्येक सीरीज के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया अपनाई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंथस डाउरी और सिंथस करालुपी के लाभप्रद लेन-देन 1500 और 1700 दोनों सीरीज के लिए कुल घरेलू बिक्री के \*\*\* प्रतिशत से अधिक थे। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी घरेलू बिक्रियों पर विचार किया है।

सिंथस डाउरी ने 1500 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तथा 1700 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन एवं \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक 1700 सीरीज के लिए देश में और समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पैकिंग, अन्य बिक्री वस्तुएं तथा ऋण लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है, प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दे दी है। तदनुसार, फैक्ट्री से बाहर सिंथस डाउरी के लिए 1500 सीरीज के लिए सामान्य मूल्य \*\*\* अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन है और 1700 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनता है।

सिंथस करालुपी ने भारत को केवल 1700 सीरीज का \*\*\* मी. टन निर्यात किया, अतः प्राधिकारी ने सिंथस करालुपी के लिए केवल 1700 सीरीज के वास्ते सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सिंथस करालुपी ने अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, कमीशन, पैकिंग, अन्य बिक्री वस्तुएं तथा ऋण लागत के निमित्त \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दे दी है। तदनुसार, फैक्ट्री से बाहर सिंथस करालुपी के लिए 1700 सीरीज के लिए सामान्य मूल्य \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनता है।

#### (ii) निर्यात कीमत

सिंथस डाउरी और सिंथस करालुपी द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंथस डाउरी ने भारत को 1500 सीरीज के \*\*\* मी. टन तथा 1700 सीरीज के \*\*\* मी. टन निर्यात किए और सिंथस करालुपी ने भारत को 1700 सीरीज के \*\*\* मी. टन निर्यात किए। सभी निर्यात असंगत पक्षकारों को किए गए।

सिंथस डाउरी ने अंतर्देशीय और समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पैकिंग, बैंक प्रभार, अन्य बिक्री वस्तुएं तथा ऋण लागत के निमित्त 1500 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन एवं \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तथा 1700 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन एवं \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दे दी है। तदनुसार, सिंथस डाउरी के लिए फैक्ट्री से बाहर निवल निर्यात कीमत 1500 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनती है।

सिंथस करालुपी ने अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार, बीमा, कमीशन, पैकिंग, अन्य बिक्री वस्तुएं तथा ऋण लागत के निमित्त 1700 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन एवं \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दे दी है। तदनुसार, सिंथस करालुपी के लिए फैक्ट्री से बाहर निवल निर्यात कीमत 1700 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनती है।

सिंथस डाउरी के लिए 1500 और 1700 सीरीज के वास्ते भारित औसत पाटन मार्जिन \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन हैं। सिंथस करालुपी के लिए पाटन मार्जिन \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनता है। सिंथस डाउरी और सिंथस करालुपी के लिए समग्र पाटन मार्जिन \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन है।

**ख. गैर सहयोगी उत्पादक/निर्यातक**

**क. मैसर्स ट्रिसियो यूरोप जीएमबीएच**

मैसर्स ट्रिसियो यूरोप जीएमबीएच का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स कंठ एंड एसोसिएट्स ने दिनांक 28.03.2016 के पत्र के माध्यम से उत्तर दायर किया है जिसमें उन्होंने भारत को निर्यातित 1723/1739 ईएसबीआर ग्रेडों के ब्यौरे दिए हैं। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि मैसर्स ट्रिसियो यूरोप जीएमबीएच का मैसर्स ट्रिसियो डचलैंड जीएमबीएच के साथ एक समान विनिर्माण का करार है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

मैसर्स ट्रिसियो यूरोप जीएमबीएच (टीईजी), जिसका मैसर्स ट्रिसियो डचलैंड जीएमबीएच के साथ समान विनिर्माण करार है, ने यह प्रश्नावली दायर की थी।

मैसर्स टीईजी द्वारा दायर उत्तर में कमियां थीं और इसलिए उत्पादक/निर्यातक से अनुरोध किया गया था कि वे आंकड़े पूरे करें तथा 14.10.2016 के ई-मेल द्वारा आंकड़ों के ऑनसाइट सत्यापन के लिए अपनी सहमति देने के लिए अनुरोध किया गया था। आंकड़ों की पर्याप्तता तथा ऑनसाइट सत्यापन के लिए सहमति के अभाव में उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने अलग से मूल्यांकन के लिए उत्पादक/निर्यातक के संबंध में विचार नहीं किया है बल्कि उन्हें नियमानुसार शेष श्रेणी के तहत मान लिया।

गैर सहयोगी/शेष उत्पादक/निर्यातक के लिए सहयोगी निर्यातकों के विश्लेषण में विचाराधीन उत्पाद की दो सीरीज में से किसी भी सीरीज के लिए मूल्यांकित उच्चतम पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन का हवाला दिया गया है।

यूरोपीय संघ							
उत्पादक/निर्यातक	एनवी डॉलर/मी. टन		एक्स-ईपी डॉलर/मी. टन		डीएम डॉलर/मी. टन (भारित औसत)	डीएम % डॉलर/मी. टन (भारित औसत)	डीएम रेंज (%)
	1500 सीरीज	1700 सीरीज	1500 सीरीज	1700 सीरीज			
(i) सिंथस डाउरी 7 स्पे. जेड. ओओ, पौलैंड	***	***	***	***	***	***	10 – 20
(ii) सिंथस करालुपी ए. एस., चेज गणराज्य (केवल 1700 सीरीज)	***	***	***	***	***	***	0 – 10
उपरोक्त (i) व (ii) का भारित औसत	***	***	***	***	***	***	10 – 20
मैसर्स ट्रिसियो सहित शेष उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	***	20 – 30

**II. कोरिया जनवादी गणराज्य**

**क. सहकारी उत्पादक/निर्यातक**

क. मैसर्स कुन्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य ("केकेपीसी")

- प्राधिकारी द्वारा जांच

[illegible]

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा दिए गए उत्तर में भारत को कुल घरेलू बिक्री तथा निर्यात पूर्णतः शामिल हैं। अतः प्राधिकारी ने उसके निर्यात चैनलों अर्थात् प्रत्यक्ष और देवू इंटरनेशनल तथा देवू इंटरनेशनल, सिंगापुर के माध्यम से दोनों निर्यात के लिए उत्पादक के वास्ते एकल भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

25. 1500 सीरीज, 1700 सीरीज और 1500 एवं 1700 सीरीज के भारित औसत के लिए पाटन मार्जिन क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनता है।

**ख. मैसर्स एलजी केम. लि. ("एलजी केम.")**

26. मैसर्स एलजी केम. ने अपने सामान्य मूल्य के परिकलन आंकड़ों के लिए प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है जबकि 5 व्यापारियों ने निर्यात कीमतों पर अलग-अलग उत्तर दायर किए हैं।

उनके उत्तर इस प्रकार हैं:

- उसने वितरण चैनलों के माध्यम से निर्यात किया है – भारत में अंतिम प्रयोक्ता को सीधा निर्यात करके, संबंधित निर्यातक एलजी केम. अमेरिका इंक. के माध्यम से तथा असंबद्ध निर्यातकों हनसुक केमिकल्स लि., एवरलाइट कोरिया कं. लि., हर्टिकेम कारपोरेशन तथा वोनकेम लि. के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं को निर्यात किया।
- एलजी केम. अमेरिका इंक., एलजी केम. लि. की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह केवल एलजी केम. लि. द्वारा विनिर्मित सामानों के बिक्री क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। यह कंपनी घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं करती है।
- हनसुक केमिकल्स कं. लि., कोरिया पैट्रोलियम इंड. कं. लि. द्वारा 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली है। यह कंपनी संबद्ध वस्तुओं अथवा विशेष रूप से अन्य किसी सामान का विनिर्माण नहीं करती है। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में उत्पाद की विशिष्टियां नहीं रखी जाती हैं अथवा किससे खरीदी गई, यह अंतर नहीं बताया जाता है।
- एवर लाइट कोरिया कं. लि. संबद्ध वस्तु अथवा अन्य किसी विशिष्ट सामान का विनिर्माण नहीं करती है।
- हार्टी केमिकल्स कारपो. संबद्ध वस्तु अथवा अन्य किसी सामान का विनिर्माण नहीं करती है।
- वोनकेम लि. कं. संबद्ध वस्तु अथवा अन्य किसी सामान का विनिर्माण नहीं करती है। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में उत्पाद की विशिष्टियां नहीं रखी जाती हैं अथवा किससे खरीदी गई, यह अंतर नहीं बताया जाता है। संबद्ध वस्तुओं के संबंध में कोई विशेष सूची अथवा ब्रोशर कंपनी द्वारा नहीं रखा जाता है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

**(i) सामान्य मूल्य**

27. मैसर्स एलजी केम. लि. कं., कोरिया (एलजी केम) ने जांच की अवधि के दौरान \*\*\* मी. टन तथा \*\*\* मी. टन तक घरेलू बाजार में क्रमशः 1500 सीरीज और 1700 सीरीज की बिक्री की। घरेलू बाजार में बिक्री पर्याप्त मात्रा में है और प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान एलजी केम. द्वारा घरेलू बिक्री के आधार पर अलग-अलग दो सीरीज का सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने उत्पादन की फैक्ट्री से बाहर की लागत के साथ फैक्ट्री से बाहर घरेलू बिक्री कीमत की तुलना कर व्यापारिक परीक्षणों की सामान्य प्रक्रिया लागू की है और यह मानते हैं कि घरेलू बाजार में 1500 सीरीज \*\*\* प्रतिशत और 1700 सीरीज \*\*\* प्रतिशत के मामले में लेन-देन लाभ में है। अतः सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यह लाभप्रद लेन-देन ही विचार में लाए गए हैं।

28. उत्पादक/निर्यातक ने भाड़ा व्यय, ऋण व्यय तथा पैकिंग व्यय के निमित्त 1500 सीरीज के लिए घरेलू बिक्री कीमत का समायोजन का दावा किया है जिसे क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन व \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन पर माना गया है तथा 1700 सीरीज के लिए भी उपर्युक्त समायोजनों का दावा किया है जिसे सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन व \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन माना गया है।

1500 सीरीज और 1700 सीरीज के लिए सामान्य मूल्य क्रमशः \*\*\* डॉलर/मी. टन और \*\*\* डॉलर/मी. टन बनता है।

**(ii) निर्यात कीमत**

29. मैसर्स एलजी केम. ने प्रत्यक्ष रूप से तथा व्यापारियों के माध्यम से भारत को जांच की अवधि के दौरान क्रमशः 1500 सीरीज के लिए \*\*\* मी. टन और 1700 सीरीज के लिए \*\*\* मी. टन का निर्यात किया है जिसके लिए उन्होंने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, अन्य व्यय, ऋण व्यय, बैंक प्रभार, समुद्री बीमा, सीमा एजेंट शुल्क और पैकिंग खर्च के निमित्त 1500 सीरीज के लिए क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन,

\*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन व \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तथा 1700 सीरीज के लिए क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन व \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन का दावा किया है। मैसर्स एलजी केम ने सीधे ही \*\*\* प्रतिशत का निर्यात किया और शेष \*\*\* प्रतिशत का निर्यात 5 व्यापारियों अर्थात् मैसर्स हनसुक केमिकल्स, मैसर्स एवरलाइट कोरिया कं. लि., मैसर्स हर्टिकिम कारपोरेशन और मैसर्स वोनकेम लि. (असंबद्ध), मैसर्स एलजी केम. अमेरिका इंक.(संबद्ध) के माध्यम से किया। चूंकि, जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और निर्यात का पूरा उत्तर सूचित किया गया है तथा सत्यापित किया गया है, अतः प्राधिकारी ने दोनों चैनलों अर्थात् प्रत्यक्ष निर्यात और व्यापारियों के माध्यम से निर्यात के लिए उत्पादक के लिए एकल भारित औसत पाटन मार्जिन पर विचार किया है। प्राधिकारी ने इन समायोजनों पर विचार कर लिया है तथा 1500 और 1700 सीरीज के लिए कारखानागत निर्यात कीमत क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन निर्धारित की है। 5 व्यापारियों के माध्यम से सभी अप्रत्यक्ष निर्यात के लिए, जोकि यहां तक बहुत कम है, प्राधिकारी ने सुनिश्चित किया है कि ये निर्यातक सामान्य प्रक्रिया में हैं और कारखानागत निर्यात कीमत के लिए कोई आवश्यक समायोजन छोड़ा नहीं गया है।

1500 सीरीज तथा 1700 सीरीज के भारित औसत के लिए पाटन मार्जिन क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन और \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनता है।

#### ख. कोरिया जनवादी गणराज्य से असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

30. असहयोगी/शेष उत्पादक/निर्यातक के लिए सहयोगी निर्यातकों के विश्लेषण में विचाराधीन उत्पाद की दो सीरीज में से किसी भी सीरीज पर लक्षित उच्चतम पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन का संदर्भ लिया गया है।

कोरिया							
उत्पादक/निर्यातक	एनवी डॉलर/मी. टन		एक्स-ईपी डॉलर/मी. टन		डीएम डॉलर/मी. टन (भारित औसत)	डीएम % डॉलर/मी. टन (भारित औसत)	डीएम रेंज (%)
	1500 सीरीज	1700 सीरीज	1500 सीरीज	1700 सीरीज			
केकेपीसी (भारित औसत) सहित - देवू इंटरनेशनल/देवू इंटरनेशनल, सिंगापुर के माध्यम से निर्यात	***	***	***	***	***	***	0 – 10
एलजी (भारित औसत) - 5 व्यापारियों सहित	***	***	***	***	***	***	0 – 10
शेष उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	***	0 – 10

### III. थाइलैंड

#### क. मैसर्स बीएसटी एलस्टोमर्स ("बीएसटीई")

31. मैसर्स बीएसटीई ने अपने दिनांक 01.04.2016 के उत्तर/आंशिक उत्तर में कहा है कि निर्यात में उनका हिस्सा मांग के 5 प्रतिशत से कम था जिससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती। साथ ही उनके लिए पाटन मार्जिन 0-2 प्रतिशत के घेरे में होगा।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स बीएसटीई, थाइलैंड ने 01.04.2016 को आंशिक आंकड़े निर्मित प्रश्नावली के अनुसार भी दर्ज नहीं किए हैं। दिनांक 14.09.2016 और 04.11.2016 को हुई मौखिक सुनवाई के बाद उन्होंने अपने 01.04.2016 को दायर किए हुए उत्तर पर जोर देते हुए पुनः कहा कि बीएसटीई का हिस्सा मांग के 5 प्रतिशत से कम था, अतः इससे क्षति नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि बीएसटीई की उत्पादन लागत के आधार पर पाटन मार्जिन केवल 0-2 प्रतिशत होगा, परंतु केवल इसके लिए कुछ हल्के-फुल्के आंकड़े दिए गए हैं।

अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख कच्ची सामग्री और उपयोगिताओं, बीएसटीई द्वारा दावा की गई खरीद कीमत तथा खरीदी गई कच्ची सामग्री की संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, लुभावनी उत्पादित कच्ची सामग्री की कीमतों, उपयुक्त परिवर्तन लागत, व्याज, एसजीए और उपयुक्त लाभ आदि के लिए इष्टतम उपभोग मानदंडों पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। बीएसटीई द्वारा उल्लिखित परिवर्तन कारक संबंधी आंकड़ों पर व्यवहार्य सीमा तक भी विचार किया गया है।

सामान्य मूल्य बीएसटीई और थाइलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए 1500 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन और 1700 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन आता है। फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार 1500 और 1700 सीरीज की भारत औसत सीआईएफ आयात कीमत पर अलग से विचार किया है और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार सीआईएफ, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा (सीआईएफ का 0.5 प्रतिशत), कमीशन (एफओबी का 3 प्रतिशत), व्यय प्रभार (एफओबी का 0.5 प्रतिशत), पत्तन व्यय (एफओबी का 0.5 प्रतिशत) और अंतर्देशीय भाड़े (एफओबी का 0.5 प्रतिशत) के लिए क्रमशः 1500 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन व \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तथा 1700 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन व \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक के समायोजन की अनुमति दे दी है। फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत 1500 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन और 1700 सीरीज के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनती है।

पाटन मार्जिन 1500 सीरीज, 1700 सीरीज और 1500 व 1700 सीरीज के भारत औसत के लिए क्रमशः \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन, \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन एवं \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन बनता है।

उपर्युक्त आंकलित पाटन मार्जिन बीएसटीई सहित थाइलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागू है।

थाइलैंड							
उत्पादक/निर्यातक	एनवी		एक्स-ईपी		डीएम	डीएम %	डीएम रेंज
	डॉलर/मी. टन		डॉलर/मी. टन		डॉलर/मी. टन	डॉलर/मी. टन	(%)
	1500 सीरीज	1700 सीरीज	1500 सीरीज	1700 सीरीज	(भारित औसत)	(भारित औसत)	
बीएसटी एलोस्टमर्स कं. लि. सहित सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	***	10 – 20

#### ड. क्षति

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि:

- क. चूंकि, जनवरी, 2014 तक भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई उत्पादन नहीं हुआ, अतः संबद्ध वस्तुओं की पूरी मांग केवल आयात द्वारा पूरी की जा रही थी। तथापि, उत्पादन शुरू होने के बाद घरेलू उद्योग को इस तथ्य के बावजूद मांग में अपना प्रस्तावित हिस्सा प्राप्त नहीं हो पाया कि घरेलू उद्योग में महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं।
- ख. देश में उत्पाद के लिए मांग पिछली अवधियों में धीरे-धीरे बढ़ी है और इसके भविष्य में भी बढ़ने की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग आईएसआरपीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा संस्थापित क्षमता का पूर्ण औचित्य दर्शाती है। विचाराधीन उत्पाद के लिए ऊपर उल्लिखित विगत, वर्तमान और संभावित मांग के विरुद्ध घरेलू उद्योग में संयुक्त क्षमताएं अब 2,70,000 मीट्रिक टन हैं। तथापि, मांग के इस स्तर के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग अब तक काफी कम है। घरेलू उद्योग की स्थापना भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से मंद होती जा रही है।
- ग. संबद्ध देशों से आयात 2014-15 तक भारी मात्रा में बढ़ा है और याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के कारण जांच की अवधि में उसके बाद घटा है।
- घ. संबद्ध देशों से आयात याचिकाकर्ताओं के पास पड़ी पर्याप्त क्षमताओं के बावजूद भारत में कुल आयात, उपभोग और उत्पादन की तुलना में महत्वपूर्ण रहा है।

- ड. संबद्ध देशों से आयात इतना अधिक रहा है कि उससे घरेलू उद्योग अपना उत्पादन बढ़ाने में रुक गया। वस्तुतः आयात इतने अधिक थे कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की सीमा तक सामानों की बिक्री करने से रह गया है।
- च. घरेलू उद्योग बाजार में अपने उत्पाद बेचने में अपनी असमर्थता के कारण क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहा है। देश में बिक्री की मात्रा बहुत कम होने के परिणामस्वरूप उत्पाद का भारी पाटन हो रहा है।
- छ. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पाद नहीं बेच पा रहा है, परिणामस्वरूप मालसूची इकट्ठी होती जा रही है जिससे आगे घरेलू उद्योग को वाहक लागत वहन करनी पड़ रही है।
- ज. घरेलू उद्योग को कार्यशील पूंजी ऋण पर भारी ब्याज लागत देनी पड़ रही है। इसके परिणामस्वरूप भी घरेलू उद्योग को और क्षति हुई है। यद्यपि, घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा बढ़ रही है, तथापि, यह बिक्री की उस मात्रा से काफी कम है जिसे उद्योग पाटन के अभाव में प्राप्त कर लेता।
- झ. उत्पादन में कटौती करने के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण उत्पाद को बेचने के लिए उद्योग की असमर्थता की दृष्टि से मालसूची बढ़ रही है।
- ञ. संबद्ध वस्तुओं की मांग में बाजार का हिस्सा सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शा रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को अब तक देश में आकर्षक बाजार हिस्सा प्राप्त कर लेना चाहिए था। तथापि, उत्पाद का भारी मात्रा में पाटन घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि को बहुत ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।
- ट. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्ताव किया था कि उत्पाद की बिक्री कीमत और कच्ची सामग्री की लागत के बीच का अंतर कम से कम अमेरिकी डॉलर 800 पीएमटी के क्षेत्र में हो। कोई भी कीमत, जो इस डेल्टा से कम है (उद्योग में डेल्टा उत्पाद की बिक्री कीमत और प्रमुख/मुख्य कच्ची सामग्री के निमित्त लागत के बीच अंतर के रूप में जाना जाता है। यह शब्द पेट्रोकेमिकल उद्योग में व्यापक रूप से जाना/समझा जाता है), उसका अभिप्राय है घरेलू उद्योग को क्षति। वस्तुतः यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने आयात प्रतिस्थापन उत्पाद शुरू किया है, घरेलू उद्योग को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए बहुत अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। इस अवधि के दौरान की गई बिक्री पर घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त डेल्टा उम्मीद किए गए डेल्टा से काफी कम है। जैसा कि पूर्व में दायर की गई याचिका के साथ संलग्न सूचना में देखा जाएगा। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि यह तथ्य आयातों से क्षति हो रही है, इस एक मात्र कारक से पूर्णतः सिद्ध हो जाता है।
- ठ. लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर आय पर उत्पादन शुरू किए जाने से ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रतिकूल लाभप्रदता के लिए प्रमुख कारण संबद्ध देशों द्वारा भारी पाटन है।
- ड. घरेलू उद्योग का अब तक बहुत छोटा अस्तित्व है और उस नई कंपनी के लिए यह कारक किसी भी दशा में असंगत हैं जिसने फरवरी, 2014 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।
- ढ. लाभप्रदता उसी दिशा में गई है जिस दिशा में उत्पादन की गति रही है।
- ण. घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रा एवं कीमत के मानदंडों, दोनों के संबंध में प्रतिकूल है। बिक्री, उत्पादन, लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में वृद्धि उन अनुमानों की तुलना में प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान बहुत प्रतिकूल थी, जो संयंत्र की स्थापना के समय याचिकाकर्ता द्वारा तैयार की गई थी।
- त. क्षति अवधि के दौरान किए गए निवेशों के व्यौरे कुल एवं निवल अचल संपत्तियों से संबंधित सूचना में देखे जा सकते हैं। नए निवेशों के बावजूद घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल है। काफी निवेश के परिणामस्वरूप काफी राजस्व और लाभ होना चाहिए था। तथापि, घरेलू उद्योग उस मात्रा तक उत्पादन और बिक्री नहीं कर पा रहा है, जितना वह कर सकता था क्योंकि देश में विचाराधीन उत्पाद का पाटन हो रहा है। घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय हानियां हुई हैं।
- थ. वर्तमान मामले में आईएसआरपीएल ने फरवरी, 2014 (आईएसआरपीएल) से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने जांच की अवधि के अंत तक अभी भी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है। अतः याचिकाकर्ता का यह कहना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी (क) पाटन का प्रभाव स्थापित करने के लिए अब तक का वास्तविक निष्पादन, (ख) क्षति का खतरा स्थापित करने के लिए संभावित स्थिति और (ग) क्या विचाराधीन उत्पाद के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना वास्तविक रूप से मंद हो रही है, पर विचार करें।
- द. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि किसी भी मामले में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े इस कारण के लिए संगत नहीं हैं कि याचिकाकर्ताओं का वाणिज्यिक उत्पादन का कोई इतिहास नहीं है तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं था।
- ध. कानून के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी का दावा करने के लिए वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करना चाहिए था।

- न. अनुमोदन प्रक्रिया के संबंध में यह एक प्रक्रिया है जो उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है और उत्पादकों को उसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को उन उपभोक्ताओं द्वारा मंजूर किया गया था जिनकी जांच की अवधि में सामूहिक मांग 70 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति केवल 19 प्रतिशत थी जो कि पाटित आयातों के कारण है।
- प. कच्चे तेल की उच्च कीमतों और विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता को जोड़ना तर्कसंगत नहीं है।
- फ. लगाई गई पूंजी पर आय की दर मानक है और मामला दर मामला आधार पर उसे बदला नहीं जाना चाहिए।
- ब. याचिकाकर्ताओं की हानियां मांग में कमी के कारण नहीं हैं, जैसा कि मूलसहास और उस अवधि में ब्याज हटाए जाने पर देखा जा सकता है।
- भ. समय निकलने के दृष्टिकोण का उपयोग करने की अनुमति पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन के लिए दी जाती है तथा उसे यदि शुद्धता की आवश्यकता हो, तो सही तुलना के सिद्धांतों के तहत पृष्ठांकित किया जाता है।
- म. आयातित सामानों के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति करने वाले अन्य कोई कारक नहीं हैं।
- य. क्षति के मामले में, तीन रूपों में क्षति होती है क्योंकि नियम यह नहीं कहते कि तीनों तरह की क्षति का साथ-साथ दावा नहीं किया जा सकता, परंतु उसका अभिप्राय यही है कि यदि एक तरह की क्षति नहीं पाई जाती, तो दूसरी तरह की क्षति की जांच की जाए।
- कक. क्षमता उपयोग में कमी के कारण क्षमता अभिवृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता नहीं बढ़ाई गई है।
- खख. बाजार में नए प्रवेशकों के लिए आरंभिक अवधि में निहित उच्च निर्धारित लागत के कारण उत्पादन की वास्तविक लागत नहीं मानी गई है।
- गग. आवेदकों का निष्पादन बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनी की सामान्य आरंभिक स्थितियों के कारण प्रभावित नहीं हुआ है। उनका निष्पादन पाटन से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का निष्पादन उससे बदतर है जिसकी उम्मीद की गई थी। वास्तविक निष्पादन के साथ अनुमानित निष्पादन की तुलना करने से यह तथ्य अपने आप स्थापित हो जाएगा।

### **निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों के द्वारा किए गए अनुरोध**

34. आयातकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

- क. निर्यात कीमत के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समायोजन असाधारण रूप से अधिक हैं।
- ख. भारतीय कानून के तहत वास्तविक मंदी के निर्धारण के लिए कोई दिशा निर्देश तैयार नहीं किए हैं और इस प्रकार विषयगत जांच शुरू करना कानूनी तौर पर बुरा है।
- ग. ये आंकड़े केवल सामान्य आरंभिक स्थितियां दर्शाते हैं तथा याचिकाकर्ता बिक्री और बाजार हिस्से की तत्काल उपलब्धि की उम्मीद नहीं कर सकता।
- घ. वास्तविक रूप से मंद याचिकाकर्ता क्षमताएं बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा।
- ङ. तथाकथित क्षति उन अंतिम प्रयोक्ताओं/क्रेताओं से उत्पाद मंजूरी के अभाव के कारण है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री एवं कीमतें कम हुई हैं, आरआईएल द्वारा कम कीमतों पर "ऑफ ग्रेड" बिक्री योजना के स्तर पर तथा संयंत्र आरंभ करने के स्तर के बीच बाजार स्थितियों में परिवर्तन, नई क्षमता अभिवृद्धि और एसबीआर के लिए कमजोर मांग, विलंबित वाणिज्यिक उत्पादन के बदले आरंभ करने की लागत, कोरिया और थाइलैंड के साथ इंडो कोरिया सीईपीए तथा इंडिया एशियन एफटीए के कारण बढ़ा हुआ व्यापार; आरआईएसएल की वार्षिक रिपोर्ट में सूचीबद्ध अन्य कारक जैसी भारी लागत होना, वाणिज्यिक उत्पादन का विलंबित आरंभ, एसबीआर की कीमत और बिक्री को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक रबर कीमतों में भारी गिरावट, आईएसआरपीएल का स्थान उपयुक्त न होने से भी कीमतें कम हुई हैं।
- च. घरेलू उद्योग की लागतें और हानियां एक घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाते हैं जो स्थिरीकरण, तथाकथित वास्तविक मंदी और तथाकथित क्षति की कमी दर्शाते हैं।
- छ. याचिकाकर्ता ने बढ़ी हुई लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है और निर्मित सामान्य मूल्य पर गोपनीयता का दावा गलत किया है। इस संबंध में बिरला एरिक्सन ऑप्टिकलव्स डेजिग्रेटेड अथॉरिटी 2004 (167) ई.एल.टी. 163 (ट्राइ. - डेल.) उल्लिखित किया गया था।

- ज. याचिकाकर्ताओं की मालसूची कम होती जा रही है जो यह दर्शाती है कि उसके निष्पादन में सुधार हो रहा है।
- झ. उत्तरदाता की क्षमताओं में वृद्धि हुई है और इसीलिए कोरिया जनवादी गणराज्य से आयात आ रहे हैं।
- ञ. प्राधिकारी को चाहिए कि वे याचिकाकर्ताओं की योजनागत लागतों पर विचार करें न कि उनकी वास्तविक लागतों पर।
- ट. याचिकाकर्ता की अच्छी कीमतों को दर्शाने के लिए संबद्ध पक्षकारों के लेन-देनों को पुनः समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि यह जांच करना महत्वपूर्ण है कि क्या मरुबेनी और आईओसीएल के साथ लेन-देन किसी दूरी पर किया गया है।
- ठ. निर्यात कीमत के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किया गया समायोजन असाधारण रूप से अधिक है।
- ड. एसबीआर 1700 सीरीज के आयात 12-13 से अगले वर्ष तक 1495 मी. टन से 70787 मी. टन तक बढ़ गए जिससे आयात आंकड़ों की प्राधिकारिता पर संदेह उठता है।
- ढ. लगाई गई पूंजी पर आय से घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ मिलता है और इक्विटी पर 41 प्रतिशत लाभ मार्जिन उपयुक्त नहीं है, वास्तविक लाभ अपनाया जाना चाहिए।
- ण. याचिकाकर्ता ने फरवरी, 2014 की अपेक्षा सूचीकरण की आधार अवधि के रूप में 2014-15 की पहली तिमाही को लिया है। बाजार हिस्सा जैसे कारकों का सूचीकरण तार्किक नहीं है। लिया गया आधार जांच की अवधि ही होना चाहिए न कि पिछला वित्तीय वर्ष। दिए गए गैर गोपनीय आंकड़े स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं।
- त. याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित 1500 और 1700 सीरीज के तहत आने वाले उप उत्पाद ग्रेडों के लिए अलग से क्षति दर्शाने के लिए आंकड़े नहीं दिए हैं।
- थ. घरेलू उद्योग के क्षति आंकड़े घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं करते, जबकि संस्थापित क्षमता अप्रैल-जून, 2014 में 100 मी. टन से जांच की अवधि में 225 मी. टन तक बढ़ गई, उत्पादन अप्रैल-जून, 2014 से जुलाई-सितंबर, 2015 में 365 प्रतिशत तक बढ़ गया। घरेलू बिक्री की मात्रा अप्रैल-जून, 2014 से जुलाई-सितंबर, 2015 तक 408 प्रतिशत तक बढ़ गई। आयात की मात्रा जांच की अवधि में 15 प्रतिशत से 148, 104 मी. टन तक बढ़ गई जो कि 2014-15 में 173, 323 मी. टन थी। बाजार हिस्सा बढ़ गया क्योंकि आयात 15 प्रतिशत तक गिर गया। कीमतें दबने की कोई स्थिति नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा आरंभ करने की लागत जैसे अन्य कारकों के कारण लाभ में कमी रही।
- द. याचिकाकर्ता वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति के कारण हुई क्षति दोनों का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता।
- ध. तथाकथित क्षति अंतिम प्रयोक्ताओं/क्रेताओं से उत्पाद की मंजूरी के कारण है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री और कीमतें कम हुई हैं। ऑफ ग्रेड बिक्री, संयंत्र को आरंभ करने का चरण, नई क्षमता अभिवृद्धि और एसबीआर के लिए कमजोर मांग, विलंबित वाणिज्यिक उत्पादन के बदले आरंभ करने की लागतें इसके कारण हैं।
- न. आईएसआरएल की वार्षिक रिपोर्ट में वे कारक निहित हैं जिनसे उनके प्रचालन प्रभावित हुए हैं, जैसे – महत्वपूर्ण रूप से लागत बढ़ जाना, वाणिज्यिक उत्पादन का विलंब से शुरू होना, एसबीआर की कीमत और बिक्री को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक खबर की कीमतों में भारी गिरावट आना तथा संयंत्र का सही स्थान पर न होना।
- प. विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तावित संशोधन वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- फ. क्षमता उपयोग में कमी, क्षमता अभिवृद्धि के कारण है न कि आयात के कारण।
- ब. हानियां होने का दावा कम मांग के कारण होना चाहिए, जैसा कि एक याचिकाकर्ता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है।
- भ. लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत आय से घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ मिलता है और इक्विटी पर 41 प्रतिशत लाभ मार्जिन उपयुक्त नहीं है, वास्तविक लाभ अपनाए जाने चाहिए। आरओसी काल्पनिक नहीं होना चाहिए और इसे पुनः देखा जाना चाहिए। (ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी)। यह यूरोपीय संघ की परिपाटी को सही-सही दर्शाता है। ईएफएमएवी काउंसिल (1999) ईसीआर-II-3291
- म. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित 1500 और 1700 सीरीज के अंतर्गत आने वाले उप उत्पाद ग्रेडों के लिए अलग से क्षति दर्शाने वाले आंकड़े नहीं दिए हैं।
- य. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यह कोरियन आयात के कारण वास्तविक रूप से मंद हो रहा है और इसीलिए यूरोपीय संघ और थाइलैंड से आयातों को शामिल करने के लिए कोई आधार नहीं है।

- कक. जांच के अवधि के बाद की स्थिति स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग अच्छा निष्पादन कर रहा है और उसे कोई क्षति नहीं हो रही है।
- खख. उपलब्ध सूचना तथा याचिका के अनुसार कोई कीमत आधारित क्षति अथवा भारी क्षति नहीं हो रही है।
- गग. याचिकाकर्ता की योजनागत लागत पर विचार किया जाना चाहिए न कि उनकी वास्तविक लागत पर।
- घघ. याचिकाकर्ताओं से संबंधित संबद्ध पक्षकार के लेन-देनों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की जानी चाहिए कि क्या वे सही कीमतें और नजदीकी से की गई हैं।
- ङङ. आयात आंकड़े गलत हैं क्योंकि गैर विचाराधीन उत्पाद सामान घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आयात आंकड़ों में शामिल किए गए हैं।
- चच. वास्तविक मंदी के मामले में अंतिम शुल्क नहीं लगाए जा सकते।
- छछ. भारतीय कानून के तहत वास्तविक मंदी का निर्धारण करने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं है।
- जज. घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े केवल आरंभ करने की सामान्य स्थितियों को दर्शाते हैं।
- झझ. क्षमता उपयोग अप्रैल, 2014 में 100 मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि में 225 मी. टन तक हो गया है। इसके कारण क्षमता उपयोग में कमी आने की उम्मीद है।
- ञञ. घरेलू उद्योग का यह दावा कि उसकी प्रचालन दर 90 प्रतिशत है जो उसकी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के विपरीत है जो कि वैश्विक रूप से यह बताती है कि यह 70 प्रतिशत है और कोरिया में यह 40 प्रतिशत – 50 प्रतिशत थी।
- टट. उपर्युक्त के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा मौखिक तर्क कि डेल्टा 53 प्रतिशत तक सुधरा है, आधारहीन है और वैश्विक उपभोग, प्रचालन दरों में कमी, ब्याज के भुगतान में वृद्धि तथा मूल्य ह्रास के कारण ही हुआ है।
- ठठ. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि कीमत कटौती नकारात्मक है।
- डड. इस आधार पर स्वैच्छिक समायोजन कि निर्यातक 90 दिन के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज मुक्त ऋण लें, की कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- ढढ. एसबीआर 1502 और 1712 की घरेलू कीमत भारतीय रुपए में 93,400 और 86,000 है, जबकि पहुँच कीमत बहुत अधिक है।
- णण. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है क्योंकि आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के एनआईपी से अधिक है। क्षति मार्जिन का निर्धारण औसत भारित कीमत पर विचार करके किया जाना चाहिए न कि भारत में बताई गई न्यूनतम कीमत पर। सकारात्मक क्षति मार्जिन बढ़ा चढ़ाकर और गलत आंकड़े देकर कानून के अनुसार नहीं है। अतः यह रद्द किए जाने योग्य है।
- तत. आयात कीमत तथा घरेलू उद्योग कीमतों में भारी कमी, जो बुटाडीन और स्टाइरिन, जिनका कच्चे तेल से सह संबंध है, की वैश्विक रूप से घटती कीमतों के कारण है।
- थथ. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर निर्मित सामान्य मूल्य पर आधारित स्थिति विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2 के अनुरूप नहीं है।
- दद. आरआईएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कम मांग का उल्लेख किया है, जो कि उनकी कमियाँ हैं और इसीलिए यह आयात के कारण नहीं हैं।
- धध. आरआईएल ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है तथा घरेलू उद्योग वास्तविक मंदी का दावा कर रहा है, जबकि वह विचाराधीन उत्पाद की वाणिज्यिक रूप से आपूर्ति के लिए पात्र नहीं है।
- नन. घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट में दिए गए अनुमान सही नहीं हो सकते क्योंकि 2012-13 में उच्च कच्चे तेल के कारण बाजार आशावादी था जो तब से आधा हो गया है।
- पप. घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति के खतरे और साथ-साथ वास्तविक मंदी का दावा नहीं कर सकता।
- फफ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति परिलक्षित नहीं होती। अन्य कई कारण हैं जिनसे वास्तविक क्षति और संबद्ध देशों से आयातों के दावे के बीच कारणात्मक संबंध में रुकावट आती है।
- बब. वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति के खतरे और वास्तविक मंदी का साथ-साथ दावा नहीं किया जा सकता।
- भभ. यदि भारतीय उद्योग को अवसंरचना की कमी है अथवा बाजार की मांग को पूरा नहीं कर सकता तो निर्यातक देशों को दोष नहीं दिया जा सकता।

- मम. मैसर्स केकेपीसी, मैसर्स ऋषिरूप पॉलीमर्स प्रा. लि. और मैसर्स ऋषिरूप प्रा. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स एलकेएस ने 24.05.2017 के पत्र के माध्यम से तर्क दिया है कि जांच की अवधि के बाद अर्थात् अक्तूबर, 2015 से सितंबर, 2016 में कोरिया से आयात का हिस्सा 27 प्रतिशत तक घट गया है और याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा भी काफी बढ़ गया है क्योंकि प्रयोक्ताओं ने प्रयोक्ताओं द्वारा मंजूरी प्रक्रिया के कारण घरेलू उद्योग से खरीद बढ़ा दी है। अतः वास्तविक मंदी की जांच के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़े अत्यधिक संगत हैं।
- यय. मैसर्स ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एआईआरआईए) ने यह तर्क दिया है कि अपना तर्क रखने के लिए 6(6) और 6(5) के अनुसार अपेक्षित कानूनी आधार है। उनका कहना है कि जांच प्रक्रिया दोषपूर्ण और अपरिपक्व है, आय की ऐतिहासिक दर एनआईपी के लिए मानी जाए और प्रयोक्ता उद्योग के हित पर भी विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त, आईएसआरपीएल द्वारा कच्ची सामग्री की खरीद सही कीमत नहीं है।
- ककक. एटीएमए का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स लूथरा एंड लूथरा ने यह तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य और समायोजन में घरेलू उद्योग का दावा सारहीन है। कोई वास्तविक मंदी नहीं है और शुरुआत वृद्धिपूर्ण है। घरेलू उद्योग के लिए खरीद की मात्रा बढ़ी है। वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति पर साथ-साथ विचार नहीं किया जा सकता और उनमें कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। केवल कोरिया के मामले में ही जांच की जाए।
- खखख. कोरिया सरकार ने कहा है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में पाटन को छोड़कर अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए, यथा – घरेलू उद्योग की आरंभिक लागत, विलंबित शुरुआत, स्थानिक हानि, प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट और इस तथ्य की कि प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में सामान्यतः लंबा समय लगता है। इसके अतिरिक्त, कोरिया से आयात घटा है। यह याचिका समय पूर्व है और अन्य कारक इस क्षति के लिए कारण हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री तिमाही दर तिमाही बढ़ी है। कीमतों में कटौती की नकारात्मक सूचना मिली है और यह कि प्राधिकारी को वास्तविक मंदी संबंधित सिद्धांत बताने चाहिए।
- गगग. यूरोपीय आयोग, व्यापार महानिदेशक ने उल्लेख किया है कि प्राधिकारी को ऑर्डर/संविदा तारीख से हटे बिना स्थापित परिपाटी के आधार पर पाटन मार्जिन की जांच करनी चाहिए, विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार क्षति की जांच करनी चाहिए और वह संदर्भ विश्व व्यापार संगठन की तरह किसी संशोधन प्रस्ताव में नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी का कोई मामला नहीं है। घरेलू उद्योग आरंभिक लागत से प्रभावित है। अन्य कारक संबद्ध देशों से आयात के शुल्क में कमी जैसे अन्य कारक हैं। परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित निष्पादन पर विचार किया जाए और इस मामले को समाप्त किया जाए।
- घघघ. मैसर्स एलजी केम और उसके 5 व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स डब्ल्यूटीसी का कहना है कि दिनांक 02.06.1998 के अंतिम जांच परिणाम के आधार पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों पर आयोजित एमटीआर 1500 और 1700 सीरीज पर बाहर किए गए थे और वे शर्त अभी भी जारी हैं। घरेलू उद्योग की गैर गोपनीय याचिकाएं नियम 7 की शर्त का उल्लंघन करती हैं, जैसा कि पूर्णतः उनकी कमी है। क्षति और कारणात्मक संबंध का कोई साक्ष्य नहीं है तथा आयात आंकड़ों में छेड़छाड़ की गई है। वास्तविक मंदी का दावा गलत रखा गया है क्योंकि दोनों कंपनियों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है और 40 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त कर लिया है। घरेलू उद्योग को क्षति उच्च आरंभिक लागत, उनके द्वारा उत्पादित ऑफ ग्रेड सामग्री के कारण है जिसके कारण भारी छूट देनी पड़ती है। आयात कीमत में गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण हैं और परिणामस्वरूप स्टाइरिन और बुटाडीन की कीमतों में गिरावट आई है तथा यह पाटन का मामला नहीं है।
- डडड. एनआईपी का सिद्धांत ब्रिज स्टोन टायर के विनिर्माण के मामले में सेसटेक के नियम तथा यूरोपियन फर्टिलाइजर मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन के आदेश में घोषित यूरोपीय संघ की परिपाटी को भी ध्यान में रखते हुए 22 प्रतिशत आय के संबंध में विशेष रूप से संशोधित किया जाना चाहिए जिसमें न्यायालय ने माना है कि कोई पाटन न होने पर सामान्य स्थितियों में प्राप्त सामान्य लाभ को इस मामले में अपनाए जाने के लिए विचार किया जाए।
- चचच. सिंथस डाउरी और सिंथस करालुपी का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स एलकेएस ने यह तर्क दिया है कि शुरुआत दोषपूर्ण है और तीन तरह की सामग्री की साथ-साथ क्षति का दावा, क्षति का खतरा और वास्तविक मंदी तर्क संगत नहीं है। ईएसबीआर 1739 और ईएसबीआर 1789 ग्रेडों को अलग कर दिया जाए। पाटन मार्जिन और वास्तविक मंदी के लिए छूटी हुई अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा दोषपूर्ण नहीं है तथा तर्क संगत नहीं है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की वास्तविक मंदी के दावे का मूल्यांकन करने के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग को क्षति गैर- टायर क्षेत्र के बाजार के कारण है जहां दो घरेलू उद्योग उत्पादक एक-दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हानियां घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित ऑफ ग्रेड सामग्री के कारण हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग में प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दिए गए ऑर्डरों को पूरा नहीं किया है। लागत बढ़ जाना, इंडिया एशियन एफटीए, विलंबित वाणिज्यिक उत्पादन, स्थानिक हानि, मंजूरी का अभाव, एसबीआर की कमजोर मांग और प्राकृतिक रबर कीमतों में गिरावट जैसे कारक पाटन के अलावा हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

35. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग को वास्तविक और वास्तविक मंदी दोनों क्षति की जांच की है तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर भी विचार किया है। वास्तविक क्षति के लिए आईएसआरपीएल के आंकड़ों का संदर्भ दिया गया है। जिन्होंने जांच की अवधि से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया था, जबकि वास्तविक मंदी के लिए मैसर्स आरआईएल के आंकड़ों की जांच की गई है जिन्होंने जांच की अवधि के बाद वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया।
36. पाटनरोधी नियमावली की प्राधिकारी से अपेक्षा होती है कि वे मात्रा और कीमत प्रभाव दोनों की जांच करके क्षति की जांच करें। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वास्तविक जांच शामिल है।
37. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से इस बात पर विचार करने की अपेक्षा होती है कि क्या पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि, पूरे संदर्भ में अथवा भारत में उत्पादन या उपभोग के संबंध में वृद्धि हुई है। कीमतों के संबंध में पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में ज्यादा कटौती हुई है अथवा ऐसे आयात पर प्रभाव काफी मात्रा में कीमतों को प्रभावित करने के लिए अन्यथा है अथवा कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हो गई होती।

**संचयी मूल्यांकन**

38. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-
- क. प्रत्येक देश/क्षेत्र से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा
- ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।
39. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है; प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयात की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है; और संबद्ध देशों से निर्यात की भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए समान सामानों के साथ परस्पर प्रतिस्पर्द्धा है। आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है। अतः प्राधिकारी ने पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन किया है।

**घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड**

40. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लिखित है:
- "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"*
41. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं, कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं जबकि कुछ मानदंड सुधार दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी ने क्षति संबंधी सभी मानदंडों पर विचार किया है और उसके बाद पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाला कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं।
42. अतः प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए तर्कों तथा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से क्षति मानदंडों की जांच की है।

**मांग का मूल्यांकन**

43. इस विषय की मांग कुल मिलाकर घरेलू बिक्री और सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा दायर उत्तरों के उपयुक्त सह-संबंध में

डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग क्षति अवधि में काफी बढ़ी है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

**तालिका 2: संबद्ध वस्तुओं की मांग**

अवधि	यूनिट	संबद्ध देश	अन्य देश	कुल आयात	भारतीय उत्पादन	भारतीय मांग
2012-13	मी. टन	1,18,468	37,357	1,55,825	-	1,55,825
2013-14	मी. टन	1,58,567	18,838	1,77,405	-	1,78,031
2014-15	मी. टन	1,57,514	9,196	1,66,710	46,657	1,93,234
तिमाही-1 14-15	मी. टन	27,807	1,886	29,693	5,168	32,616
तिमाही-2 14-15	मी. टन	49,452	3,683	53,135	5,977	57,053
तिमाही-3 14-15	मी. टन	40,948	2,981	43,930	19,601	49,465
तिमाही-4 14-15	मी. टन	39,307	645	39,952	15,911	54,100
तिमाही-1 15-16	मी. टन	35,436	1,077	36,513	32,985	60,583
तिमाही-2 15-16	मी. टन	33,040	2,626	35,666	24,043	54,397
पीओआई	मी. टन	1,48,732	7,329	1,56,061	92,540	2,18,546
पीओआई (तिमाही)	मी. टन	37,183	1,832	39,015	23,135	54,636
पीओआई के पश्चात - 6 माह	मी. टन	53,465	2,284	55,749	56,784	1,14,517
पीओआई के पश्चात - 3 माह	मी. टन	26,732	1,142	27,875	18,928	57,258

44. उपर्युक्त तालिका में यह देखा गया है कि देश में उत्पाद के लिए मांग वार्षिक आधार पर इस अवधि में पर्याप्त रूप से बढ़ी है।

**घरेलू उद्योग की आयात मात्रा पर और संबद्ध देश के हिस्से से संबंधित पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव**

45. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों में, पूरी मात्रा की दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा निम्नलिखित है:

**तालिका 3: संबद्ध देशों से पूर्ण आयात**

आयातों की मात्रा	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
यूरोपीय संघ	मी. टन	41,276	39,626	27,695	32,523
कोरिया जनवादी गणराज्य	मी. टन	74,735	1,04,994	1,11,133	1,02,034
थाइलैंड	मी. टन	2,456	13,947	18,686	14,175
संबद्ध देश	मी. टन	1,18,468	1,58,567	1,57,514	1,48,732

अन्य देश	मी. टन	37,357	18,838	9,196	7,329
कुल आयात	मी. टन	1,55,825	1,77,405	1,66,710	1,56,061
भारतीय उत्पादन	मी. टन	0	6,912	46,657	92,540
भारतीय मांग	मी. टन	1,55,825	1,78,031	1,93,234	2,18,546
<b>निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात:</b>					
भारतीय उत्पादन	%	-	2294.01%	337.60%	160.72%
भारतीय खपत	%	76.03%	89.07%	81.51%	68.06%
भारत में आयात	%	76.03%	89.38%	94.48%	95.30%

46. उपर्युक्त का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- क. संबद्ध देशों से आयात 2014-15 तक पूरी तरह से बढ़ा है और जांच की अवधि में घटा है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन शुरू कर दिया था।
- ख. संबद्ध देशों से आयात याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध पर्याप्त क्षमता के बावजूद भारत में उपभोग और उत्पादन के संबंध में तथा कुल आयात की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है।
- ग. संबद्ध देशों से आयात महत्वपूर्ण रहा है तथा उसने अपना उत्पादन और बिक्री को बढ़ाकर घरेलू उद्योग को रोका है। वस्तुतः आयात इतने थे कि घरेलू उद्योग अपने इष्टतम मात्रा तक अपने सामानों की बिक्री नहीं कर पाया।

#### उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

47. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

**तालिका 4 (क)**

अवधि	संबद्ध देशों से आयात	अन्य देशों से आयात	भारतीय उद्योग में क्षमताएं	भारतीय मांग	आईएसआर पीएल का उत्पादन	आईएसआरपीएल की बिक्री	आरआईएल का उत्पादन	आरआईएल की बिक्री
	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन
2012-13	1,18,468	37,357	-	-	-	-	-	-
2013-14	1,58,567	18,838	-	-	-	-	-	-
2014-15	1,57,514	9,196	50,000	-	100	100	-	-
तिमाही-1 14-15	27,807	1,886	30,000	32,616	75	467	-	-
तिमाही-2 14-15	49,452	3,683	30,000	57,053	86	625	-	-
तिमाही-3 14-15	40,948	2,981	65,250	49,465	88	756	100	100
तिमाही-4 14-15	39,307	645	65,250	54,100	106	1,322	63	736
तिमाही-1 15-16	35,436	1,077	65,250	60,583	299	2,694	91	902
तिमाही-2 15-16	33,040	2,626	65,250	54,397	168	1,736	92	985
पीओआई	1,48,732	7,329	2,61,000	2,18,546	165	1,627	87	681
पीओआई (तिमाही)	37,183	1,832	65,250	54,636	165	1,627	87	681

पीओआई के पश्चात - 6 माह	53,465	2,284	1,30,500	1,14,517	192	2,064	112	2,063
पीओआई के पश्चात - 3 माह	26,732	1,142	65,250	57,258	192	2,064	42	2,063

तालिका 4 (ख): आईएसआरपीएल का उत्पादन और क्षमता

अवधि	संस्थापित क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग	घरेलू बिक्री	औसत मालसूची	निर्यात
	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन
तिमाही-1 14-15	100	100	17%	100	100	100
तिमाही-2 14-15	100	116	20%	134	112	189
तिमाही-3 14-15	100	117	20%	162	108	220
तिमाही-4 14-15	100	142	24%	283	83	157
तिमाही-1 15-16	100	399	69%	577	74	270
तिमाही-2 15-16	100	224	39%	372	75	174
पीओआई के पश्चात - 3 माह	100	221	38%	349	91	205

48. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने देश में मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए क्षमताएं संस्थापित की।
- ख. देश में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग क्षति अवधि में बढ़ी है।
- ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन यद्यपि बढ़ा, परंतु इष्टतम स्तर तक नहीं बढ़ा।
- घ. क्षमता उपयोग 2014-15 में और जांच की अवधि में पर्याप्त रूप से बढ़ा है। तथापि, घरेलू उद्योग में काफी उपयोग न की गई क्षमता है।
- ङ. घरेलू उद्योग की बिक्री 2014-15 में और जांच की अवधि में उनका उत्पादन और बिक्री शुरू करने वाली नई यूनिटों के कारण बढ़ी।

49. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री तथा क्षमता उपयोग इस तथ्य के कारण बढ़ा कि दो नई यूनिटों ने उनका उत्पादन शुरू कर दिया जिसके कारण घरेलू उत्पादन और बिक्री में बढ़ती हुई प्रवृत्ति की आशा की जाती है। तथापि, बढ़ती प्रवृत्ति काफी नहीं है जो घरेलू उद्योग की बिक्री के रूप में मानी जा सके।

#### बाजार हिस्सा

50. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच नीचे की गई है:

तालिका 5 (क)

अवधि	घरेलू उद्योग की बिक्री	संबद्ध देश	अन्य देश	कुल मांग
	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन

तिमाही-1 14-15	2,923	27,807	1,886	32,616
तिमाही-2 14-5	3,918	49,452	3,683	57,053
तिमाही-3 14-15	5,535	40,948	2,981	49,465
तिमाही-4 14-15	14,148	39,307	645	54,100
तिमाही-1 15-16	24,070	35,436	1,077	60,583
तिमाही-2 15-16	18,731	33,040	2,626	54,397
पीओआई	62,485	1,48,732	7,329	2,18,546
पीओआई (तिमाही)	15,621	37,183	1,832	54,636
पीओआई के पश्चात - 6 माह	58,767	53,465	2,284	1,14,517
पीओआई के पश्चात - 3 माह	29,384	26,732	1,142	57,258

तालिका 5 (ख)

अवधि	मांग % में हिस्सा			
	घरेलू उद्योग	संबद्ध देश	अन्य देश	कुल
तिमाही-1 14-15	9%	85%	6%	100%
तिमाही-2 14-5	7%	87%	6%	100%
तिमाही-3 14-15	11%	83%	6%	100%
तिमाही-4 14-15	26%	73%	1%	100%
तिमाही-1 15-16	40%	58%	2%	100%
तिमाही-2 15-16	34%	61%	5%	100%
पीओआई	29%	68%	3%	100%
पीओआई (तिमाही)	29%	68%	3%	100%
पीओआई के पश्चात - 6 माह	51%	47%	2%	100%
पीओआई के पश्चात - 3 माह	51%	47%	2%	100%

तालिका 5 (ग) सूचीबद्ध आधार पर मांग में आईएसआरपीएल का हिस्सा

अवधि	हिस्सा
तिमाही-1 14-15	100
तिमाही-2 14-5	78

तिमाही-3 14-15	111
तिमाही-4 14-15	167
तिमाही-1 15-16	311
तिमाही-2 15-16	222
पीओआई	211
पीओआई (तिमाही)	211
पीओआई के पश्चात - 6 माह	256
पीओआई के पश्चात - 3 माह	256

तालिका 5 (घ)

अवधि	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात		
	भारतीय उत्पादन	भारतीय खपत	भारत में आयात
तिमाही-1 14-15	538%	85%	94%
तिमाही-2 14-5	827%	87%	93%
तिमाही-3 14-15	209%	83%	93%
तिमाही-4 14-15	247%	73%	98%
तिमाही-1 15-16	107%	58%	97%
तिमाही-2 15-16	137%	61%	93%
पीओआई	161%	68%	95%
पीओआई (तिमाही)	161%	68%	95%
पीओआई के पश्चात - 6 माह	94%	47%	96%
पीओआई के पश्चात - 3 माह	94%	47%	96%

51. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2014-15 में उसकी स्थापना से ही बढ़ा है। तथापि, मांग में बाजार हिस्से में प्राप्ति, देश में संबद्ध वस्तुओं के एक मात्र उत्पादक होने के बावजूद, काफी नहीं है। संबद्ध देश से आयात का हिस्सा, जिसका मूल्यांकन पाटित के रूप में किया गया था, इस अवधि में काफी रहा है।

#### घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

52. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

“जहां तक नियम 18 के उप-नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक

कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक हास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

53. इस बात की जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद के पाटित आयातों की कीमत से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों प्रभावित करने के लिए अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए अन्यथा है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हो गया होता। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत दबाव तथा कीमत न्युनीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित है।

## कीमत कटौती

54. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री मिलाकर आयातों की पहुँच कीमत से तुलना की है। प्राधिकारी ने एसबीआर 1500 और एसबीआर 1700 सीरीज के लिए अलग-अलग कटौती निकाली है। इस संबंध में प्रत्येक संबद्ध देश से उत्पाद के पहुँच मूल्य तथा व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूटों और करों का निवल घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

निम्नलिखित तालिका कीमत कटौती के स्तर को दर्शाती है।

### तालिका 6: कीमत प्रभाव

कीमत कटौती	यूनिट	तिमाही-1 14-15	तिमाही-2 14-15	तिमाही-3 14-15	तिमाही-4 14-15	तिमाही-1 15-16	तिमाही-2 15-16	पीओआई	पीओआई के पश्चात
एसबीआर-1500 सीरीज									
निवल विक्री वसूली	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
समग्र रूप से संबद्ध देश									
पहुँच मूल्य	रु./मी. ट.	1,08,428	1,21,842	1,23,795	96,541	82,305	96,101	1,01,164	83,431
कीमत कटौती	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	(0-10)	(15-25)	(20-30)	(30-40)	(0-10)	(20-30)	(20-30)	(0-10)
यूरोपीय संघ									
पहुँच मूल्य	रु./मी. ट.	1,25,906	1,28,748	1,29,711	1,07,549	82,436	96,031	1,08,783	82,035
कीमत कटौती	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	(20-30)	(30-40)	(25-35)	(40-50)	(0-10)	(20-30)	(30-40)	(0-10)
कोरिया									
पहुँच मूल्य	रु./मी. ट.	1,07,953	1,20,423	1,22,067	95,532	82,349	96,202	99,901	83,762
कीमत कटौती	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	(0-10)	(15-25)	(20-30)	(30-40)	(0-10)	(20-30)	(20-30)	(0-10)
थाइलैंड									
पहुँच मूल्य	रु./मी. ट.	1,10,493	1,17,700	1,19,755	82,165	81,256	94,084	91,228	82,183
कीमत कटौती	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***

कीमत कटौती %	%	(10-20)	(10-20)	(20-30)	(10-20)	(0-10)	(10-20)	(15-25)	(0-10)
एसबीआर-1700 सीरीज									
समग्र रूप से संबद्ध देश									
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
समग्र रूप से संबद्ध देश									
पहुँच मूल्य	रु./मी. ट.	1,02,806	1,12,377	1,15,378	91,890	81,464	95,757	96,086	81,620
कीमत कटौती	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	(0-10)	(15-25)	(25-35)	(30-40)	(0-10)	(30-40)	(20-30)	(25-35)
यूरोपीय संघ									
पहुँच मूल्य	रु./मी. ट.	1,26,072	1,20,287	1,21,526	98,545	81,705	97,172	98,225	82,659
कीमत कटौती	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	(30-40)	(25-35)	(30-40)	(40-50)	(0-10)	(30-40)	(20-30)	(25-35)
कोरिया									
पहुँच मूल्य	रु./मी. ट.	1,02,801	1,10,259	1,15,631	95,704	84,414	95,339	98,753	85,059
कीमत कटौती	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	(5-15)	(15-25)	(25-35)	(35-45)	(5-15)	(25-35)	(25-35)	(30-40)
थाइलैंड									
पहुँच मूल्य	रु./मी. ट.	98,778	1,09,361	1,07,149	77,154	75,513	89,698	84,646	70,128
कीमत कटौती	रु./मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	(0-10)	(15-25)	(15-25)	(10-20)	0-10	(20-30)	(5-15)	(5-15)

55. वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में जबकि कोरिया के मामले में कीमत कटौती सकारात्मक थी, यह अन्यथा नकारात्मक रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव, जो कि बाजार में अभी-अभी आया है, एक नकारात्मक कीमत कटौती यह दर्शाती है कि उद्योग ने बाजार में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आयात कीमतों को आक्रामक रूप से मिलाया है।

#### **कीमत दबाव/मंदी**

56. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक दबाने के लिए है और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हो गया होता। प्राधिकारी क्षति अवधि में लागत एवं कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं। यह स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

**तालिका 7: बिक्री की लागत और बिक्री कीमत पर कीमत प्रभाव**

अवधि	बिक्री की लागत	प्रवृत्ति	बिक्री कीमत	प्रवृत्ति	पहुँच मूल्य	प्रवृत्ति
	रु./मी. टन		रु./मी. टन		रु./मी. टन	
तिमाही-1 14-15	***	100	***	100	92,730	100
तिमाही-2 14-15	***	94	***	102	1,04,576	113
तिमाही-3 14-15	***	95	***	101	1,11,899	121
तिमाही-4 14-15	***	68	***	73	85,034	92
तिमाही-1 15-16	***	47	***	83	72,162	78
तिमाही-2 15-16	***	60	***	82	93,063	100
पीओआई	***	60	***	83	99,003	107
पीओआई के पश्चात	***	54	***	79	82,612	89

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री कीमतें बिक्री की लागत से कम होने के कारण कीमत पर दबाव एवं ह्रास है। निम्नलिखित पैरा में कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन पाटन की मात्रा किस हद तक हुई, यह बताता है।

कम कीमत पर बिक्री

58. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री के कारण हुई क्षति की जांच भी की है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना केवल आइएसआरपीएल के आंकड़ों पर विचार करके आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने एसबीआर 1500 और 1700 सीरीज के पहुँच मूल्य का अलग से मूल्यांकन किया है। पहुँच मूल्य का परिकलन आयातों के मूल्यांकन योग्य मूल्य पर लागू आधारभूत सीमा शुल्क और उप कर को जोड़कर किया गया है। डीडब्ल्यूआई/डीडब्ल्यूआईएसजी के माध्यम से किए गए निर्यातों के संबंध में केकेपीसी के मामले में डीडब्ल्यूआई/डीडब्ल्यूआईएसजी की सीआईएफ कीमत का संदर्भ लिया गया है, जबकि केकेपीसी द्वारा सीधे निर्यात के लिए मैसर्स केकेपीसी की सीआईएफ कीमतें अपनाई गई हैं। इसी प्रकार, एलजी केम. के मामले में एलजी केम. द्वारा सीधे निर्याती की सीआईएफ कीमत अपनाई गई है। जबकि व्यापारियों के माध्यम से निर्यात के लिए व्यापारियों के आंकड़ों से सीआईएफ कीमत अपनाई गई है। मैसर्स सिंथस डाउरी तथा मैसर्स सिंथस करालुपी द्वारा किए गए निर्यात सीधे हैं, जिनकी सीआईएफ कीमतें पहुँच मूल्य के लिए अपनाई गई हैं। मैसर्स ट्रिसियो के मामले में उत्तर आंशिक रहा है तथा उत्पादक सत्यापन के लिए सहमत नहीं हुए। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन किसी के भी अलग-अलग निर्धारण के लिए उनके उत्तर पर विचार नहीं किया है। यूरोपीय संघ के सहकारी उत्पादकों में अधिकतम क्षति मार्जिन सभी अन्य शेष तथा सहकारी सहकारी उत्पादकों के लिए अपनाया गया है। मैसर्स बीएसटीई, थाइलैंड के लिए जांच की अवधि के दौरान भारत औसत सीआईएफ कीमत डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर संदर्भित की गई है। विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर क्षति मार्जिन निम्नलिखित हैं।

### तालिका 8

[illegible]

इंटरनेशनल, सिंगापुर के माध्यम से निर्यातों सहित									
<b>एलजी</b> (भारत औसत) - 5 व्यापारियों सहित	***	***	***	***	***	***	***	***	10 – 20
शेष उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	***	***	***	20 - 30
<b>यूरोपीय संघ</b>									
(i) सिंथस डाउरी 7 स्पे. जेड. ओओ, पौलेंड	***	***	***	***	***	***	***	***	10 – 20
(ii) सिंथस करालुपी ए. एस., चेज गणराज्य (केवल 1700 सीरीज)	***		***		***		***	***	10 – 20
उपर्युक्त (i) व (ii) का भारत औसत	***	***	***	***	***	***	***	***	10 – 20
मैसर्स ट्रिंसियो सहित शेष उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	***	***	***	20 – 30
<b>थाइलैंड</b>									
वीएसटी एलास्टोमर्स कं. लि. सहित सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	***	***	***	20 – 30

**लाभ, लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ**

59. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकद लाभ तथा निवेश पर आय का निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है:

**तालिका 9**

विवरण	यूओएम	तिमाही-1 14-15	तिमाही-2 14-15	तिमाही-3 14-15	तिमाही-4 14-15	तिमाही-1 15-16	तिमाही-2 15-16	पीओ आई	पीओआई के पश्चात
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	95	68	47	60	60	54
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	101	73	83	82	83	79
लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(86)	(90)	(62)	(12)	(38)	(38)	(29)
कुल लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(115)	(145)	(176)	(70)	(141)	(133)	(126)
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(119)	(136)	(226)	(48)	(145)	(139)	(118)

पीबीआईटी - घरेलू	रु. लाख	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(119)	(150)	(171)	(46)	(124)	(123)	(95)
आरओआई	%	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	रेंज	(0-20)	(0-20)	(20-30)	(20-30)	(0-10)	(15-25)	(15-25)	(15-25)

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत, दोनों इस अवधि में कम हुए हैं। जांच की अवधि में उत्पादन लागत काफी घट जाने के बावजूद बिक्री कीमत से काफी अधिक थी जिसके कारण हानि हुई। लागत में कमी कच्ची सामग्री कीमतों और ऊपरी लागत में कमी के कारण है। उत्पादन में कुछ वृद्धि होने के कारण प्रति यूनिट ऊपरी लागत में कमी आई है।
- ख. घरेलू उद्योग को पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मांग, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद बड़ी हुई हानि हुई थी।
- ग. क्षति की अवधि में निवेश पर आय हानि की तरह उसी प्रवृत्ति में रही है, जबकि यह जांच की अवधि में थोड़ी सी सुधरी है।
- घ. ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) इस अवधि में नकारात्मक था।
- ङ. नकद हानियां जांच की अवधि में काफी बढ़ी हैं, जबकि जांच की अवधि में हुई हानि लगभग दोगुनी थी और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी।

61. चूंकि, घरेलू उद्योग ने अभी उत्पादन शुरू किया है, अतः यह कारक तब तक कम होने की संभावना है जब तक घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपना स्थान प्राप्त करने की व्यवस्था न कर ले। तथापि, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को उनकी स्थापना से ही हानियां हुई हैं।

#### रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी

62. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है:

**तालिका 10**

अवधि	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	रोजगार	मजदूरी
	मी. टन/सं.	संख्या	रुपए लाख
तिमाही-1 14-15	***	***	***
तिमाही-2 14-15	***	***	***
तिमाही-3 14-15	***	***	***
तिमाही-4 14-15	***	***	***
तिमाही-1 15-16	***	***	***
तिमाही-2 15-16	***	***	***
पीओआई	***	***	***
पीओआई के पश्चात	***	***	***

63. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में रोजगार जांच की अवधि में बढ़ा है। तथापि, प्रति यूनिट मजदूरी कम हुई है।

**मालसूची**

64. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

**तालिका 11**

अवधि	प्रारंभिक स्टॉक	अंतिम स्टॉक	औसत स्टॉक
	मी. टन	मी. टन	मी. टन
तिमाही-1 14-15	***	***	***
तिमाही-2 14-15	***	***	***
तिमाही-3 14-15	***	***	***
तिमाही-4 14-15	***	***	***
तिमाही-1 15-16	***	***	***
तिमाही-2 15-16	***	***	***
पीओआई	***	***	***
पीओआई के पश्चात	***	***	***

65. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची जांच की अवधि में कम हुई है, परंतु महत्वपूर्ण रही है।

**पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए योग्यता**

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की मांग बढ़ने से घरेलू उद्योग ने नई क्षमता स्थापित करने में निवेश किए हैं। तथापि, इन निवेशों के बावजूद घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल रूप से कम हुआ है जिससे निधियां जुटाने में इसकी क्षमता प्रभावित हुई है।

**पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर**

67. यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर देश में आ रहे हैं और यह कि पाटन का मार्जिन न्यूनतम सीमा से ऊपर है।

**घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक**

68. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच लागत, ढांचे में परिवर्तन, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारक कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में कम कीमत पर बिक्री हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों के अनुरूप होनी चाहिए और घरेलू उद्योग इन इनपुट कीमतों तथा आयात के पहुँच मूल्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कीमतें निर्धारित करता रहा है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुँच मूल्य घरेलू कीमतों के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

**भारत में उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी**

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स आईएसआरपीएल ने वाणिज्यिक उत्पादन फरवरी, 2014 से शुरू किया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने 30 सितंबर, 2016 को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया था। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद छः माह के आंकड़ों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग को प्रदान किए गए अनुमोदन के कारण जांच की अवधि के बाद में बिक्री के सुधार के संबंध में यह बात घरेलू उद्योग के लिए बाजार स्थिति के केवल एक पहलू का संकेत है। स्वच्छ व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए भी क्षति की सीमा को जांच की अवधि के दौरान आंकलित पाटन के कारण कम करने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण में व्यापक रूप से दोनों पहलुओं को नोट करते हैं। प्राधिकारी पाटन, क्षति का खतरा सिद्ध करने के लिए संभावित स्थिति तथा भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना वास्तविक रूप से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण कम हो रही है, के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए अब तक के वास्तविक निष्पादन को नोट करते हैं।

70. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ख में निम्नलिखित प्रावधान है:

**9ख -** केंद्र सरकार कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी:

(ii) इन धाराओं की प्रत्येक उप धारा (1) के तहत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश अथवा उस देश, जिसके साथ भारत सरकार ने सर्वाधिक पक्षकारी राष्ट्रीय करार (जिसे इसके बाद विनिर्दिष्ट देश कहा जाएगा) से भारत में आयात पर, जब तक कि इस धारा की उप धारा (2) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार न हो, यह निर्धारण किया गया है कि ऐसी वस्तु के भारत में आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा होता है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद करता है; और

पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान है:

**क्षति का निर्धारण:** (1) निर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अगला निष्कर्ष रिकार्ड करेंगे कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है अथवा क्षति का खतरा हो रहा अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद कर रहा है।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना पर वास्तविक मंदी तथा पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर करेंगे। इन कारकों में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल होंगे तथा इन नियमों के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार करेंगे।

71. यद्यपि, वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति के खतरे का परीक्षण मौजूदा घरेलू उद्योग पर लागू किया जा सकता है अथवा उन प्रचालनों तक लागू किया जा सकता है जो घरेलू उद्योग के पास विगत में थे। तथापि, घरेलू उद्योग के मामले में वे अभी पूर्णतः स्थापित किए जाने हैं, जो परीक्षण लागू किया जाना है, वह वास्तविक मंदी का है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित दो स्थितियां वहां संगत हैं, जहां वास्तविक मंदी का परीक्षण लागू हो।

(i) उन "विकासशील उद्योगों" के मामले में, जिन्होंने अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है, परन्तु उत्पादन शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता कर दी है;

(ii) उन "उदासीन उद्योगों" के मामले में, जिनका वाणिज्यिक उत्पादन यद्यपि शुरू हो गया है, परन्तु उद्योग को बाजार में अभी अपना स्थान ढूंढना है।

72. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों को नोट करते हैं कि एक उदासीन उद्योग में घरेलू उद्योग के रूप में इस मामले में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े संगत नहीं हैं और उनका वाणिज्यिक उत्पादन का कोई पिछला इतिहास नहीं है।

73. प्राधिकारी पाटनरोधी परिपाटियों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की समिति के दिशा-निर्देश नोट करते हैं जिनमें यह उल्लेख है कि क्षति की जांच के लिए आंकड़े एकत्र करने की अवधि सामान्यतः कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए, जब तक कि जिस पक्षकार से आंकड़े लिए जा रहे हैं, वह कम अवधि के लिए विद्यमान रहा हो और उसमें पाटन जांच के लिए आंकड़ों के एकत्र करने की पूरी अवधि शामिल होनी चाहिए।

74. प्राधिकारी इस मुद्दे पर पाटनरोधी करार में विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावित संशोधन को नोट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में क्षति के समाधान के लिए करार में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

**3.9क घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी का निर्धारण** तथ्य के आधार पर होगा और न कि केवल आरोप अटकलबाजी अथवा सुदूर संभावना पर होगा। किसी उद्योग को स्थापना में तभी माना जाएगा जब किसी समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन करने के लिए संसाधनों की पर्याप्त एवं उपयुक्त प्रतिबद्धता की गई हो, इसमें आयातक सदस्य के क्षेत्र में पहले से उत्पादित उत्पाद शामिल नहीं होगा, परंतु वह उत्पाद शामिल होगा जिसका उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है और वाणिज्यिक मात्रा में अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। यह निर्धारण करने में कि क्या एक उद्योग स्थापना में है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच करने में प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ संस्थापित क्षमता, किए गए निवेशों और प्राप्त किए गए वित्त तथा व्यावहार्यता अध्ययनों, निवेश योजनाओं और बाजार अध्ययनों से संबंधित साक्ष्य को ध्यान में रख सकते हैं।

75. उपर्युक्त यह दर्शाता है कि सदस्य देश मानते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी कानून के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यद्यपि यह कानूनी तौर पर बाध्यकारी न हो, तथापि, यह घरेलू उद्योग की वास्तविक मंदी निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह प्रावधान यह दर्शाता है कि भले ही किसी कंपनी ने वाणिज्यिक

उत्पादन आरंभ न किया हो, फिर भी वह कंपनी नियमों के तहत संरक्षण प्राप्त करने की हकदार है। यह प्रस्ताव प्राधिकारी को यह भी दिशा-निर्देश देता है कि वह ऐसी स्थिति में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करें।

क. भारत में पूर्व में उत्पादित न किए गए समान उत्पाद का घरेलू उत्पादन करने के लिए संसाधनों की एक उपयुक्त एवं स्थायी प्रतिबद्धता कर दी गई है;

ख. उत्पादन वाणिज्यिक मात्रा में अभी तक शुरू नहीं किया गया है अथवा अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है।

76. उपर्युक्त का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने मैसर्स आरआईएल की निम्नलिखित मात्रा और कीमत मानदंडों का विश्लेषण किया है।

तालिका 12

विवरण	यूनिट	तिमाही-3 (2014 – 15)	तिमाही-4 (2014-15)	तिमाही-1 (2015 – 16)	तिमाही-2 (2015 -16)	पीओआई	पीओआई के पश्चात (1/10/2015 से 31/03/2016)
संस्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***	***
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***	***

तालिका 13

विवरण	यूनिट	तिमाही-3 (2014 – 15)	तिमाही-4 (2014-15)	तिमाही-1 (2015 – 16)	तिमाही-2 (2015 -16)	पीओआई	पीओआई के पश्चात (1/10/2015 से 31/03/2016)
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	30	20	20	26	18
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	78	76	77	68

तालिका 14

विवरण	यूओएम	तिमाही-3 (2014 – 15)	तिमाही-4 (2014-15)	तिमाही-1 (2015 – 16)	तिमाही-2 (2015 -16)	पीओआई	पीओआई के पश्चात (1/10/2015 से 31/03/2016)
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	30	20	20	26	18
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	74	78	76	77	68

लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100)	(18)	(5)	(4)	(12)	(5)
कुल लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100)	(135)	(41)	(39)	(79)	(96)
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100)	(135)	(41)	(39)	(79)	(95)
पीबीआईटी - घरेलू	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100)	(135)	(41)	(39)	(79)	(93)
आरओआई	%	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100)	(134)	(41)	(39)	(78)	(92)

तालिका 15

विवरण	यूनिट	तिमाही-3 (2014 - 15)	तिमाही-4 (2014-15)	तिमाही-1 (2015 - 16)	तिमाही-2 (2015 - 16)	पीओआई	पीओआई के पश्चात (1/10/2015 से 31/03/2016)
औसत स्टॉक	मी. टन	100	213	214	185	84	113

77. मैसर्स आरआईएल ने वाणिज्यिक उत्पादन 30.09.2016 को ही घोषित किया। जांच की अवधि के बाद में यद्यपि मैसर्स आरआईएल का क्षमता उपयोग बढ़ा, तथापि, उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में बिक्री नहीं बढ़ी जिससे मालसूची बड़ गई। बिक्री की लागत जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद घटी है, परंतु बिक्री कीमत उत्पादन लागत से कम बनी रही। यद्यपि, मैसर्स आरआईएल ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 30.09.2016 को ही घोषित किया है। तथापि, जांच की अवधि के पश्चात बिक्री कीमत मैसर्स आईएसआरपीएल के लिए निर्धारित एनआईपी के शुद्ध शुरूआती स्तर से काफी नीचे है जो कि मैसर्स आरआईएल के लिए एक संकेत भी है। अतः उत्पादन पर मंदी तथा अधिकतम क्षमता उपयोग स्तर प्राप्त करने सहित कीमत दबाव एवं हास के साक्ष्य हैं। प्रतिकूल कीमत प्रभाव के कारण नकद प्रवाह, पीबीआईटी और आरओआई जैसे लाभप्रदता मानदंडों में गिरावट आई है।

#### कारणात्मक संबंध

78. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 और भारतीय नियमावली का अनुबंध-II घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित है और उसमें निम्नलिखित उल्लेख है:

"3.5 यह दर्शाया जाना चाहिए कि पैरा 2 और 4 में निर्धारित किए गए अनुसार पाटन के प्रभाव के माध्यम से पाटित आयात इस करार के अभिप्राय के भीतर क्षति पहुँचा रहे हैं। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन प्राधिकारियों के समक्ष सभी संगत साक्ष्यों की जांच के आधार पर होगा। प्राधिकारी उन पाटित आयातों के अलावा, ज्ञात कारकों की भी जांच करेंगे जिनकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और इन अन्य कारकों के कारण भी हुई क्षतियाँ पाटित आयातों के कारण नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में जो कारक संगत हों, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटन कीमतों पर बिक्री न किए गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल होनी चाहिए।"

"(v) यह दर्शाया जाना चाहिए कि उपर्युक्त पैरा (ii) और (iv) में निर्धारित किए गए अनुसार पाटन के प्रभाव के माध्यम से पाटित आयात से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच रही है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सभी संगत साक्ष्यों की जांच के आधार पर होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी उन पाटित आयातों के अलावा, ज्ञात कारकों की भी जांच करेंगे जिनकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और इन अन्य कारकों के कारण भी हुई क्षतियाँ पाटित आयातों के कारण नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में जो कारक संगत हों, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटन कीमतों पर बिक्री न किए गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल होनी चाहिए।

79. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संभावित कारणों के संबंध में दिए गए तर्कों को नोट किया है और संगत पाटनरोधी नियमावली तथा उसकी जारी परिपाटी के अनुसार ही इसके निमित्त पाटन और परिणामी क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों का मूल्यांकन किया। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की भी निम्नलिखित रूप में जांच की है।

**क) पाटित कीमतों पर बेचे न गए आयातों की मात्रा और मूल्य:** घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से इस देश में आ रहे पाटित आयातों से क्षति हो रही है। अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात मात्रा में काफी नहीं है। अन्य देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है।

**ख) मांग में कमी:** विचाराधीन उत्पाद की मांग ने पूरी क्षति अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है, अतः मांग में कमी एक संभावित कारण नहीं है जो घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण हो सके।

**ग) उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन:** विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उपभोग के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आया है। घरेलू उद्योग को क्षति के कारण उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है।

**घ) प्रौद्योगिकी में विकास:** उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में न तो कोई परिवर्तन हुआ है और न ही आगामी भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है। वस्तुतः याचिकाकर्ता ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है जो विचाराधीन उत्पाद के लिए उपलब्ध सर्वाधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारक नहीं है।

**ङ) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा:** कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो।

**च) निर्यात निष्पादन:** घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने घरेलू प्रचालनों के लिए बिक्री एवं कीमत मानदंडों के संबंध में सूचना को अलग किया है।

**छ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए अन्य उत्पादों का निष्पादन:** इस संबंध में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पहले चर्चा कर दी गई है।

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (ii) के तहत पाटित आयातों से मात्रा एवं कीमत पर प्रभाव पड़ा है और पाटित आयातों के कारण हुए क्षति के प्रभाव नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निर्धारित मानदंडों के संबंध में प्रदर्शित किए गए हैं तो अगला कदम यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है, विश्लेषण के कारण हुई है, अर्थात् उन अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है। जैसा कि पिछले पैराग्राफों में प्रदर्शित किया गया है, सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह सिद्ध नहीं करते कि इन अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण भी हुई है। निम्नलिखित मानदंड कारणात्मक संबंध दर्शाते हैं:

क. संबद्ध देशों से पाटित आयात भारत में कीमतों से कम कीमतों पर भारी मात्रा में उपलब्ध हैं।

ख. चूंकि, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद बाजार में फरवरी, 2014 से पेश करना शुरू कर दिया था, अतः घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतें आयात कीमतों के निर्धारण के अनुरूप हैं।

ग. पाटित आयातों की मौजूदगी उनकी क्षमता का पूर्णतः उपयोग करने और उनका उत्पादन एवं बिक्री अधिकतम करने के लिए घरेलू उद्योग को रोक रही है।

घ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता भी क्षति अवधि में नुकसान उठा रही है।

ङ. विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग अपने आप को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पा रहा है।

81. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन और क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

**कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक**

82. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के मैसर्स आईएसआरपीएल और मैसर्स आरआईएल, दोनों का निष्पादन वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी के कारण संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से भी कम हुआ है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधार पर सिद्ध है:
- क. घरेलू उद्योग विभिन्न संबद्ध देशों से आयात कीमत के आधार पर अपनी बिक्री कीमतें निर्धारित कर रहा है। विचाराधीन उत्पाद के आयात से कीमत पर दबाव पड़ रहा है और घरेलू उद्योग को वह कीमतें बढ़ाने से रोक रहा है। बिक्री कीमतें उत्पादन लागत से कम बनी हुई हैं। परिणामस्वरूप लाभ, नकद प्रवाह और आरओआई घटा है।
- ख. संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप भी बाजार में कम कीमतों पर बिक्री हो रही है, जब इसकी तुलना गैर क्षतिकारक कीमत से की जाए।
- ग. घरेलू उद्योग की वृद्धि विभिन्न कीमत और मात्रा से संबंधित आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में नकारात्मक हुई। यद्यपि, मात्रा मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि किसी तरह से उत्पादन के आरंभिक वर्षों के कारण हो, तथापि, कीमत मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि अनिवार्य रूप से उत्पाद के पाटन के कारण है।
- घ. मैसर्स आरआईएल की वास्तविक मंदी की जांच करते समय जांच की अवधि के बाद के मानदंड यह सिद्ध करते हैं कि उत्पादन पर दबाव रहा है, क्षमता उपयोग इष्टतम नहीं रहा है, कम कीमत पर बिक्री हुई है और समग्र रूप से कीमत पर दबाव/ह्रास हुआ है जिससे लाभप्रदता का घटक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।
83. प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री और उपयोग के सर्वोत्तम उपभोग प्रतिमानों पर विचार कर मैसर्स आईएसआरपीएल के आंकड़ों के आधार पर गैर क्षतिकारक कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने उस सर्वोत्तम क्षमता उपयोग के साथ \*\*\* मी. टन की इष्टतम उत्पादन मात्रा पर विचार कर निर्धारित व्यय पर विचार किया है, जिसका उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट में अनुमान लगाया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III के प्रावधानों पर विचार करते हुए विभिन्न व्ययों को भी अलग किया है तथा हटाया है। घरेलू उद्योग की लगाई गई पूंजी का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-III के प्रावधानों के आधार पर किया है तथा लगाई गई पूंजी पर आय का परिकलन राष्ट्रीय उत्पादन के इष्टतम स्तर पर किया गया है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की निर्धारित गैर क्षतिकारक कीमत की तुलना संबद्ध देशों से प्रत्येक उत्तरदायी निर्यातक से संबद्ध आयात के पहुँच मूल्य से तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए शेष उत्पादकों/निर्यातकों के लिए किया है। इस मामले में "एनआईपी" का सिद्धांत काफी हद तक गैर जिम्मेदार विश्लेषण का समाधान करता है जैसा कि विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है।

#### प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

#### 84. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध:

याचिकाकर्ताओं ने 16 जून, 2017 और 17 जून, 2017 के अपने ई-मेल द्वारा संबंधित तथ्यों को प्रकट किए जाने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं को 19 जून, 2017 के ई-मेल द्वारा उत्तर प्राप्त हो गया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्राधिकारी ने अगला प्रकटन एनआईपी के संबंध में दिया है। इसके अतिरिक्त, कोई सूचना याचिकाकर्ताओं को प्रकट नहीं की गई है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने 20 जून, 2017 के ई-मेल द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे प्रकटन की आवश्यकता का उल्लेख करने के लिए विस्तृत अनुरोध दायर किए थे। तथापि, आगे कोई प्रकटन याचिकाकर्ताओं को नहीं किया गया।

उपर्युक्त के मद्देनजर याचिकाकर्ता प्रभावकारी रूप से अपनी टिप्पणियाँ नहीं दे पाए। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए एक सप्ताह के अतिरिक्त समय के लिए अनुरोध किया। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने द्वारा समय बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध के संबंध में याचिकाकर्ताओं को कोई उत्तर नहीं मिला।

इसके मद्देनजर याचिकाकर्ताओं की ओर से एक अंतरिम अनुरोध के रूप में वर्तमान अनुरोधों को माना जाए।

प्रकटन विवरण से पृष्ठ है कि ये तथ्य कि विभिन्न ग्रेडों के स्टाइरिन बुटाडीन रबर एक वस्तु है और किसी भी ग्रेड को अलग करना उपयुक्त नहीं होगा। चूंकि, याचिकाकर्ता बाजार में नए व्यापारी हैं (याचिकाकर्ताओं की एक कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू भी नहीं किया है), अतः यह स्वाभाविक है कि याचिकाकर्ताओं ने उन सभी ग्रेडों का पूरे पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं किया है जिनका ये कंपनियाँ उत्पादन कर सकती हैं और याचिकाकर्ताओं का पहला जोर भारी मात्रा में उपभोग में लाए जाने वाले ग्रेडों पर है। याचिकाकर्ता यथा समय शेष ग्रेडों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेंगे। याचिकाकर्ताओं के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन करने की ग्रेड-वार क्षमता निम्नलिखित है:

ग्रेड	आईएसआरपीएल	आरआईएल
1502	उत्पादित एवं आपूर्ति की गई	उत्पादित एवं आपूर्ति की गई

1507	कोई क्षमता नहीं	उत्पादन करने की क्षमता है
<b>उप जोड़</b>		
1705	कोई क्षमता नहीं	उत्पादन करने की क्षमता है
1712	उत्पादित एवं आपूर्ति की गई	उत्पादित एवं आपूर्ति की गई
1721	कोई क्षमता नहीं	उत्पादन करने की क्षमता है
1723	उत्पादित एवं आपूर्ति की गई	उत्पादित एवं आपूर्ति की गई
1732	कोई क्षमता नहीं	उत्पादन करने की क्षमता है
1737	कोई क्षमता नहीं	उत्पादन करने की क्षमता है
1739	कोई क्षमता नहीं	उत्पादन करने की क्षमता है
1778	उत्पादन करने की क्षमता है	उत्पादन करने की क्षमता है
1783	कोई क्षमता नहीं	उत्पादित एवं आपूर्ति की गई
1789	कोई क्षमता नहीं	उत्पादन करने की क्षमता है

आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद पाटनरोधी शुल्कों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

याचिकाकर्ता इस बात से असहमत हैं कि एनआईपी केवल उस कंपनी के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है जिसने वर्तमान मामले के तथ्यों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया हो, जहां क्षति स्पष्ट रूप से वास्तविक उत्पादन और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग पर पहले से ही प्रभाव डालने वाली क्षति के अलावा घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी के रूप में हो। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि एनआईपी का निर्धारण याचिका करने वाली कंपनियों के सभी घटकों के संबंध में किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी द्वारा की गई व्याख्या का अभिप्राय होगा कि जिस कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है, वह कानून के तहत संरक्षण की हकदार नहीं है। तथापि, यह इस कारण किसी कानूनी आधार के बिना है कि केवल ये तथ्य कि जो कंपनी बाजार में अपनी स्थापना कर रही है, वही संरक्षण की हकदार है, का मतलब है कि कंपनी को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता इस कानूनी आवश्यकता पर जोर देते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति "घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी" के रूप में हो। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने ऐसी स्थितियों में परियोजना रिपोर्ट पर विश्वास किया है तथा इसीलिए वास्तविक उत्पादन का तथ्य नगण्य परिणामों का है। जैसे भी हो, आरआईएल ने उत्पादों की काफी मात्रा का उत्पादन किया है और उनकी आपूर्ति की है।

चूंकि, उत्पादन परीक्षण उत्पादों के रूप में घोषित किया गया था, केवल इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि एनआईपी के निर्धारण के लिए सूचना अपर्याप्त है।

कुल मिलाकर नियमों में परीक्षण उत्पादन और वाणिज्यिक उत्पादन के बीच अंतर/भेद नहीं किया गया है। नियम केवल "उत्पादन" का संदर्भ लेते हैं। कंपनी ने बाजार में एसबीआर की मात्रा का केवल उत्पादन ही नहीं किया है बल्कि काफी मात्रा में बेची भी है।

घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति (उसके उत्पादन तथा बाजार में बिक्री की सीमा तक) तथा उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में क्षति हुई है।

घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति तथा वास्तविक मंदी संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण है।

पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन काफी महत्वपूर्ण हैं।

प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को सही-सही परिभाषित किया है। याचिकाकर्ता 1739 तथा 1789 जैसे उत्पाद ग्रेडों को अलग न करने के निर्णय पर प्राधिकारी ने सहमत है क्योंकि घरेलू उद्योग में ऐसे ऑर्डर आने पर इन ग्रेडों का उत्पादन करने की क्षमता है तथा बाजार एक स्वच्छ व्यापारिक क्षेत्र है। घरेलू उद्योग के पास विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन करने की तकनीकी क्षमता है

क्योंकि विभिन्न ग्रेड उनके संघटन में स्टाइरिन और बूटाडीन की मात्रा में अंतर के कारण निर्धारित किए जाते हैं। ग्रेडों की वर्तमान विनिर्माण स्थिति से याचिकाकर्ता की क्षमता कम नहीं होती।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि जब ऐसी स्थिति में उत्पादन की क्षमता इतनी संगत नहीं है, जहां घरेलू उत्पादक अब कुछ समय से प्रचालन में हैं तथा पूरी क्षति अवधि में उत्पादन किया हो तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग ने हाल ही में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है तथा 4 वर्षों की क्षति अवधि के विरुद्ध उसका 20 माह का इतिहास है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि उत्पादन करने की क्षमता अधिक संगत तथा उचित मानदंड बन जाती है।

याचिकाकर्ता पुनः पुष्ट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई घरेलू उद्योग नहीं था। एसबीआर 1900 ग्रेड के उत्पादक मौजूद हैं, परंतु वे एसबीआर 1500 तथा 1700 ग्रेड का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं, जो कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद है।

दो याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा दी गई परियोजना रिपोर्ट यह पुष्ट करती है कि याचिकाकर्ताओं ने संयंत्र की स्थापना करते समय देश में उत्पादन की गैर-मौजूदगी पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक एपकोटेक्स द्वारा एसबीआर के उत्पादन का संबंध है, कंपनी ने केवल 1900 सीरीज के एसबीआर का उत्पादन किया है। कंपनी एसबीआर 1700 और 1500 सीरीज का उत्पादन नहीं करती है। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि एसबीआर 1500 सीरीज के लिए उत्पादन सुविधाओं का प्रयोग एसबीआर 1700 और 1500 के उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता।

चूंकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क तालिका में यह उल्लेख करने की कृपा करें कि विचाराधीन उत्पाद पर उन शुल्क वर्गीकरणों पर ध्यान न देकर शुल्क लगाया जाए, जिनके तहत सामान आयातकों द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी शुल्क तालिका में कृपया यह उल्लेख करें कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं। याचिकाकर्ता का यह कहना है इस संबंध में केवल शुल्क तालिका का विवरण संगत है। जो भी "विचाराधीन उत्पाद" से संबंधित पैरा में उल्लिखित है, परंतु शुल्क तालिका में नहीं दिया गया है, उसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते समय छोड़े जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क प्राधिकारी पोर्ट पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर विचार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। सीमा शुल्क प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के रूप में डीजीएडी द्वारा जारी अधिसूचना को संज्ञान में नहीं लेते हैं। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शुल्क तालिका में इन सभी स्पष्टीकरणों को शामिल किया जाए।

याचिकाकर्ता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अन्य उत्पादकों से काफी अधिक कीमत पर उत्पाद किस्म कैसे बेचें।

याचिकाकर्ताओं ने प्रकटन विवरण में निर्धारित पाटन मार्जिन की कम मात्रा के संबंध में पहले अपनी चिंताएं उठाई थीं और संबंधित दस्तावेजों/सूचना/व्यौरों को प्रकट किए जाने का अनुरोध किया। निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे गए पत्र की प्रति पर विश्वास किया गया और संक्षिप्ता के लिए उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त व्यौरे प्रकट नहीं किए जाते हैं तब तक याचिकाकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने में असमर्थ हैं।

किसी पूर्वाग्रह के बिना, याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न स्थितियों के संबंध में अपना स्वतंत्र अनुसंधान किया है और उनके निम्नलिखित अनुरोध हैं:

एलजी केम. द्वारा तथ्यों को दबाना – याचिकाकर्ता यह पाते हैं कि एलजी केम. ने प्राधिकारी से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का सहारा लिया है। याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक विस्तृत पत्र लिखा है जिसकी एक प्रति अनुबंध-II के रूप में इन अनुरोधों के साथ भी संलग्न है। चूंकि, एलजी केम. ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का सहारा लिया है, प्राधिकारी के समक्ष सच्चाई से नहीं आए हैं तथा जानबूझकर सूचना छिपाई है, प्राधिकारी को चाहिए कि वे प्रश्नावली के उत्तर को पूर्ण रूप से रद्द करें। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह वह मामला नहीं है जहां प्राधिकारी पूर्व में निर्धारित पाटन मार्जिन से संबंधित संशोधन करें। यह तथ्यों को छिपाने तथा प्राधिकारी से संगत सूचना को दबाने का मामला है। पाटन मार्जिन में संशोधन का अभिप्राय वास्तविक रूप से ऐसे निर्यातक द्वारा किए गए ऐसे अपराधों का क्षमा करना है जिसने देश में उत्पाद के पाटन का सहारा लिया है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि यदि निर्यातक उन तथ्यों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना को छिपाते हैं जो भारत में याचिकाकर्ताओं को मालूम हो जाए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उत्पादन लागत अथवा घरेलू बिक्री के संबंध में उत्पादक द्वारा दी गई सूचना काफी विश्वसनीय हो। निर्यातक की विश्वसनीयता बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होना चाहिए तथा प्रश्नावली का उत्तर इस कारण रद्द किया जाना चाहिए।

प्रकटन विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए भारत में सीआईएफ निर्यात कीमत के रूप में अपनाई गई आरंभिक कीमत पर विचार किया गया है अथवा वह उत्पादक की निर्यात कीमत है। यदि प्राधिकारी ने भारत में सीआईएफ कीमत पर विचार किया है तो इसका मतलब यह है कि निर्यात कीमत उत्पादक तथा कई व्यापारियों द्वारा दी गई मालसूची के संयोजन के आधार पर है। जैसा कि, प्राधिकारी ने पाया है कि कुछ निर्यात सीधे किए गए हैं और कुछ बिक्री कुछ संबंधित अथवा असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से किए गए हैं। इस प्रकार, यदि आरंभिक निर्यात कीमत भारत में सीआईएफ

निर्यात कीमत है तो इसका मतलब यह है कि प्राधिकारी ने ऐसी निर्यात कीमत भारतीय उपभोक्ताओं को दी गई मालसूची के आधार पर निर्धारित की है और यह मालसूची निम्नलिखित पक्षकारों को दी गई थी:

- (क) (i) मैसर्स कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(ii) मैसर्स देवू इंटरनेशनल, कोरिया जनवादी गणराज्य  
(iii) मैसर्स देवू इंटरनेशनल, सिंगापुर
- (ख) (i) मैसर्स मैसर्स एलजी केम. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(ii) मैसर्स एलजी केम. अमेरिका इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका  
(iii) मैसर्स वॉकेम लि., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(iv) मैसर्स हटीकिम कारपो., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(v) मैसर्स एवरलाइट कोरिया कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य  
(vi) मैसर्स हनसुक केमिकल्स कं. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य

वैकल्पिक रूप में प्राधिकारी ने संबंधित उत्पादक (अर्थात् एलजी केम. और कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स) की बहियों में निर्यात मूल्य तथा निर्यात मात्रा पर विचार किया है। यदि ऐसा है तो निर्यात कीमत संबंधित उत्पादक द्वारा सूचित किए गए निर्यात मूल्य के आधार पर निर्धारित की गई है। उस स्थिति में इसका मतलब यह है कि व्यापारियों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर पूर्ण रूप से बेकार है। ऐसी स्थिति में यह जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या स्वतंत्र व्यापारियों ने ऐसा कोई मार्जिन रखा है जो उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और वे पर्याप्त लाभ अर्जित कर सकें। व्यापारियों ने भारी मार्जिन अथवा अपर्याप्त मार्जिन रखे हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि किसी भी स्थिति में व्यापारियों द्वारा रखे गए मार्जिन यह जांच करने के लिए संगत हो जाते हैं कि क्या वे पर्याप्त थे तथा उन व्यापारियों द्वारा किए गए खर्चों से न तो कम थे और न ही अधिक थे तथा लाभ के लिए पर्याप्त राशि थी। इसके अतिरिक्त, संबंधित पक्षकार के माध्यम से बीजक बनाने के मामले में प्राधिकारी को ऐसे व्यापारियों की पुनः बिक्री कीमत पर विचार करना होता है तथा उत्पादक की वार्षिक कीमत बनानी होती है (विगत में प्राधिकारी ने संबंधित व्यापारी की पुनः बिक्री कीमत पर विचार किया है तथा ऐसे संबंधित व्यापारी के सभी खर्चों तथा उपयुक्त लाभ को कम किया है)। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में वह किया गया है।

कैप्टिव कच्ची सामग्री और उपयोगिताओं का मूल्य निर्धारण – याचिकाकर्ताओं ने पहले यह अनुरोध किया था कि इन उत्पादकों द्वारा कई कैप्टिव कच्ची सामग्री और इनपुट लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में, जबकि किसी उत्पादक के पास कैप्टिव कच्ची सामग्री अथवा यूटिलिटी हो, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या प्राधिकारी को सूचित की गई ऐसी कच्ची सामग्री अथवा यूटिलिटी का मूल्य निर्धारण उत्पादन लागत के निर्धारण के प्रयोजन से उपयुक्त तथा पर्याप्त है। प्राधिकारी ने पहले ही यह पाया है कि दोनों उत्पादकों द्वारा घरेलू बाजार में की गई महत्वपूर्ण बिक्री उत्पादन लागत से कम थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सकारात्मक पाटन मार्जिन की स्थिति में यह बात सामने आती है कि दो उत्पादकों द्वारा काफी निर्यात उत्पादन लागत से कम पर थे। याचिकाकर्ता यह मानते हैं कि निर्यातकों ने रिकार्ड के आधार पर अपने कैप्टिव उपभोग का दावा किया है तथा यह दावा किया है कि वर्तमान प्रयोजनों के लिए वह पर्याप्त है। तथापि, केवल यह तथ्य कि उत्पादक ने रिकार्ड के आधार पर अपनी कैप्टिव इनपुट लागत का दावा किया है, वर्तमान प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त है। याचिकाकर्ताओं को प्रकट किए गए किसी भी दस्तावेज अथवा प्रकटन विवरण अथवा प्रश्नावली के उत्तर में यह नहीं दिखाई देता कि निर्यातक ने ऐसी कैप्टिव कच्ची सामग्री के पूरे ब्यौरे दिए हैं तथा प्राधिकारी उत्पादक द्वारा ऐसे कैप्टिव इनपुट के मूल्य निर्धारण की उपयुक्तता के संबंध में अपने को संतुष्ट कर सकें।

यूटिलिटियां – कुम्हो तथा एलजी केम., दोनों के पास यूटिलिटियों का काफी भाग है, जो अन्य उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया से कैप्टिव रूप में उत्पादन कर रही हैं अथवा प्रश्नावली के उत्तर में ऐसा कुछ नहीं है जो कैप्टिव यूटिलिटियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में हो।

कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स तथा एलजी केम., दोनों के पास काफी कैप्टिव यूटिलिटियां हैं। इसके अतिरिक्त, वे कुछ उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं जिनमें से कुछ की सूची नीचे दी गई है। इन उत्पादों के उत्पादन से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो यूटिलिटियों के रूप में परिवर्तित की जाती है तथा फिर अन्य उत्पादों के उत्पादन में उपयोग में लाई जाती है। यह साफ नहीं है कि क्या यह तथ्य प्राधिकारी को प्रकट किया गया है; तथा, यदि हां तो ऐसे इनपुट का मूल्य विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में कैसे लगाया गया है।

एसजीए व्यय – प्राधिकारी ने एसजीए व्यय के निमित्त कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स द्वारा लागत के भाग को पहले रद्द किया है तथा अलग सिद्धांत को अपनाया है जिसका कंपनी ने दावा किया है। वस्तुतः कंपनी ने सेसटेक के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया था। संगत निर्णय अनुबंध-III के रूप में संलग्न है। यह साफ नहीं है कि क्या कंपनी अपने इस गलत भाग के सिद्धांत को जारी रखती रही तथा क्या प्राधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि यूएस प्राधिकारी ने भी एलजी केम. द्वारा अपनाए गए विभाजन सिद्धांत को रद्द किया है तथा उनके एसजीए खर्चों को पुनर्विनियोजित किया है। यूएस प्राधिकारियों के निर्णय ज्ञापन के संगत उद्धरण इन अनुरोधों के साथ अनुबंध-IV के रूप में संलग्न हैं।

ब्याज लागत – कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज आय के लिए उसे समायोजित करने के बाद ब्याज आय सूचित कर रहा है (विभिन्न प्रचालनों के लिए)। विभिन्न सामानों के उत्पादन के लिए ली गई निधियों पर किए गए ब्याज खर्चों तथा निवेश क्रियाकलाप से अर्जित ब्याज आय की तुलना नहीं की जा सकती। वित्तीय क्रियाकलापों से अर्जित ऐसी ब्याज आय किए गए ब्याज खर्चों के विरुद्ध समायोजित नहीं की जा सकती। प्राधिकारी ने विगत में वस्तुतः ब्याज खर्चों से ब्याज आय घटाकर इसे रद्द कर दिया था तथा विचाराधीन उत्पाद की लागत के भाग के रूप में रखा था। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी ने इस समय उत्पादन लागत कैसे निर्धारित की है।

कारोबार अनुपात – कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स ने बिक्री कारोबार (कारोबार अनुपात के आधार पर भाग के व्यय में) पर विचार करते हुए विगत में विशिष्ट रूप से कारोबार अनुपात निर्धारित किया था। तथापि, यह मानते हुए कि बिक्री कारोबार विभिन्न उत्पादों के संबंधित लाभों से प्रभावित हैं और किए गए खर्चों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, अधिक उपयुक्त अनुपात सीओजीएस अनुपात है न कि कारोबार अनुपात। सीओजीएस अनुपात सीधे ही विभिन्न आधारों पर की गई लागत के प्रभाव दर्शाते हैं। तथापि, यह साफ नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने कारोबार अनुपात अथवा सीओजीएस अनुपात को अपनाया है।

टीएसआरसी द्वारा सूचित उत्पादन लागत की पूरी तरह उपेक्षा की गई – टीएसआरसी ने केवल अपनी उत्पादन लागत के संबंध में ही विस्तृत सूचना नहीं दी है बल्कि कोरियन उत्पादकों की उत्पादन लागत का अपना अनुमान भी दिया है। टीएसआरसी विश्व का एक प्रमुख एसबीआर उत्पादक है और विचाराधीन उत्पाद का विश्व का सबसे अधिक लागत प्रतिस्पर्द्धी उत्पादक है। तथापि, यह पाया गया है कि टीएसआरसी द्वारा दी गई समस्त सूचना को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। यह भी नहीं दिखाई देता कि इन प्रयोजनों के लिए किसी संदर्भ मूल्य के रूप में उस पर विचार किया गया है।

बिक्री की तारीख – याचिकाकर्ताओं ने पहले ही जोरदार ढंग से यह कहा था कि वर्तमान मामले में प्राथमिक मुद्दा पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन से बिक्री की संगत लागत स्थापित करना है। प्रकटन विवरण से याचिकाकर्ता निर्यातक द्वारा बताई गई बिक्री के लिए निर्धारण तथा औचित्य हेतु अपनाई गई बिक्री की संगत तारीख निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए आधार को नहीं समझ पा रहे हैं। बिक्री की तारीख संविदा की तारीख, बीजक की तारीख, पेशकश की तारीख, भारत में सामान पहुँचने की तारीख हो सकती है, इनमें से जो भी बिक्री की वास्तविक शर्त हो, याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि वे यह निर्धारित करें कि निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा वास्तविक रूप में बिक्री कब बंद की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उत्पाद उसी समय के लगभग वास्तव में विभिन्न कीमतों पर आयात किए गए थे। लिखित अनुरोधों से संगत उद्धरण संलग्न हैं। प्रकटन विवरण में बिक्री की तारीख पुष्ट करने के लिए प्रयुक्त मानदंड के संबंध में कुछ नहीं है और सत्यापन रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को नहीं बताई गई है जिससे ऐसी स्थिति बनती है जिसमें याचिकाकर्ता अपनी टिप्पणियां देने में समर्थ नहीं हैं।

तुलना सिद्धांत – याचिकाकर्ता ने माह दर माह विश्लेषण करके सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन निर्धारित किया था। तथापि, प्रकटन विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वर्तमान पाटन मार्जिन जांच की अवधि के लिए वार्षिक तुलना अथवा तिमाही अथवा माह दर माह तुलना के आधार पर है अथवा उनकी उपयुक्तता के आधार पर है।

आईएचएस ट्रेड जर्नल में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि कोरियाई उत्पादकों के संगत अवधि में नकारात्मक मार्जिन थे। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक जर्नल ने \*\*\* अमेरिकी डॉलर कोरियाई उत्पादकों की परिवर्तन लागत के रूप में बताई है। यह साफ नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा पुष्ट नियत लागत आईएचएस के अनुमानों के साथ कैसे तुलनीय है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आईएचएस में सूचित मार्जिन सभी निर्धारित खर्चों जैसे एसजीए और ब्याज के आधार पर हैं। इस प्रकार, निर्यातक की वास्तविक लागत इस लागत से काफी अधिक होनी चाहिए।

एनआईपी दो वैकल्पिक स्थितियों – \*\*\* प्रतिशत क्षमता उपयोग और \*\*\* प्रतिशत क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। उसके बाद, प्राधिकारी ने एनआईपी के निर्धारण के प्रयोजन से \*\*\* प्रतिशत क्षमता उपयोग को अपनाया है।

चूंकि, याचिकाकर्ता ने नई उत्पादन सुविधाएं तय की हैं, अतः यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता पूरी अवधि में पहले पूर्ण लागत लगा रहा हो। अधिकतम उपयोग की संकल्पना कम क्षमता उपयोग के लिए लागत का समायोजन करने के वास्ते केवल कानून के तहत लाई गई है, जबकि कंपनी पहले ही सभी निर्धारित खर्च कर रही हो। तथापि, ऐसी स्थिति में, जबकि याचिकाकर्ता पूर्ण निर्धारित लागत न लगा रहा हो (जैसा कि वर्तमान मामला है), याचिकाकर्ता इतने अधिक क्षमता उपयोग पर

खर्च कर रहा होता तो अधिक क्षमता उपयोग पर विचार करना उपयुक्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित तालिका में जांच की अवधि, 2015-16 और 2016-17 में उत्पादन और निर्धारित खर्च दर्शाए गए हैं:

विवरण	यूनिट	पीओआई	2015-16	2016-17
90 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर उत्पादन	मी. टन	***	***	***
वेतन एवं मजदूरी	रु./मी. टन	***	***	***
अन्य व्यय	रु./मी. टन	***	***	***
मूल्यहास	रु./मी. टन	***	***	***
वित्तीय खर्च	रु./मी. टन	***	***	***
कुल	रु./मी. टन	***	***	***

हमने पहले अनुरोध किया था कि यदि निर्यातक ने प्राधिकारी को सभी प्रकटन सच्चाई से नहीं किए हैं तो उन्हें चाहिए कि वे पूरे प्रश्नावली के उत्तर रद्द कर दें। इस पर विचार करते हुए कि जांच की गई हैं, यह अत्यधिक सराहनीय है कि प्राधिकारी निष्ठा और विश्वास के आधार पर कार्रवाई करें तथा सभी पक्षकारों से उम्मीद है कि वे प्राधिकारी को सभी तथ्य सच्चाई के साथ दें। तथापि, हमारे पास इसके साक्ष्य हैं कि एलजी केम., वर्तमान मामले में निर्यातक, ने प्राधिकारी को सभी तथ्य सच्चाई के साथ नहीं दिए हैं तथा प्राधिकारी से महत्वपूर्ण सूचना छिपाई है।

एलजी केम. ने प्राधिकारी को यह सूचित नहीं किया है कि इसका भारत में कोई कार्यालय है (यथा एलजी केमिकल्स इंडिया प्रा. लि.), जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल है। यह कार्यालय ऑर्डर लेने और विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापों जैसे बिक्री, पूर्वानुमान, रणनीतिक/आर्थिक योजना, कार्य प्रशिक्षण/विनिमय, इंजीनियरी सेवाएं, विज्ञापन, बिक्री, संवर्द्धन, वितरक/डीलर प्रशिक्षण, खरीद/स्रोत सेवाएं, पैकिंग, मालसूची का रख-रखाव, ऑर्डर इनपुट/प्रसंस्करण, प्रत्यक्ष बिक्री कार्मिक, बिक्री/विपणन सहायता, बाजार अनुसंधान, तकनीकी सहायता, छूट प्रदान करना, नकद रियायत प्रदान करना, कमीशन देना, वारंटी सेवा देना, गारंटी देना, बिक्री के बाद सेवाएं देना, पुनः पैकिंग कराना, भाड़ा एवं सुपुर्दगी की सुविधा देना तथा बिक्री के बाद भंडारण प्रदान करने की सेवाएं देने में लगा है।

एलजी केमिकल्स इंडिया प्रा. लि., एलजी केम., कोरिया की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ऐसी स्थिति में, जहां ऐसे महत्वपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप भारत में एक सहायक कंपनी द्वारा किए जा रहे हों, स्थापित कानूनी स्थिति यह बनती है कि ऊपरी खर्च कम किए जाएं तथा कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजन से कीमत समायोजन के रूप में उपयुक्त लाभ घटा दिया जाए।

चूंकि, एलजी केम. ने यह सूचित नहीं किया है कि इसका भारतीय कार्यालय बिक्री कार्य में लगा हुआ है, न ही इस पर कीमत समायोजनों की सूचना दी है, अतः यह माना जाना चाहिए कि एलजी केम. ने प्राधिकारी से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का सहारा लिया है।

ऐसी स्थिति में, जहां हितवद्ध पक्षकार भ्रामक सूचना दे अथवा अन्यथा संगत तथ्य छिपाए, वहां प्रश्नावली के उत्तर रद्द किए जाने की आवश्यकता है तथा नियम 6(8) के आधार पर अर्थात् उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के समर्थन में, उत्पादक द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर से संगत उद्धरण संलग्न हैं जिनमें उत्पादक ने केवल अपनी यूएस सहायक कंपनी ही घोषित की है तथा भारतीय सहायक कंपनी घोषित नहीं की है, वेबसाइट सूचना एलजी केमिकल्स इंडिया प्रा. लि. के संबंध में ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण; एलजी केमिकल्स प्रा. लि. के व्यापारिक क्रियाकलापों के संबंध में ब्यौरे देने वाली याचिकाकर्ता कंपनी से ई-मेल; एलजी केम. द्वारा दावे किए गए कीमत समायोजनों को दर्शाने वाले प्रश्नावली के उत्तर से संगत उद्धरण, प्रकटन विवरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए कीमत समायोजनों को दर्शाने वाले प्रकटन विवरण से संगत उद्धरण; सर्कुलर वीविंग मशीन के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों से संगत उद्धरण, जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारतीय अंग के एसजीए तथा लाभ को समायोजित किया; एलजी केमिकल्स इंडिया लि. का आयात विवरण, जिसमें एलजी केमिकल्स इंडिया लि. की आय एवं व्यय के ब्यौरे दर्शाए गए हैं तथा एलजी – अमेरिका आईएनसी के प्रश्नावली के उत्तर, जिनमें उनके द्वारा किया गया विपणन दर्शाया गया है, घोषित नहीं किया है।

इन समूह कंपनियों में कुछ कंपनियां विभिन्न एलजी ग्रुप कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने में लगी हैं, जो स्पष्ट रूप से एसबीआर के उत्पादक को दी जा रही सेवाएं बताता है। कई समूह कंपनियां किसी विनिर्माण प्रचालन में नहीं लगी हैं और इसके बजाए कुछ सेवाएं – तकनीकी अथवा वाणिज्यिक प्रदान करने में लगी हैं। एलजी केमिकल्स द्वारा यह तथ्य भी छिपाया गया है और प्रभावली का उत्तर इस कारण अतिरिक्त रूप से रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

सहायक कंपनियां ये हैं, एलजी केम. एचके लि., हांगकांग; एलजी केम. अमेरिका इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका; एलजी केम. यूरोप जीएमबीएच, जर्मनी; एलजीसी पैट्रोकेमिकल इंडिया प्रा. लि., इंडिया; हेंगवोकनुरी, कोरिया; एलजी केम. टीके केन्या; सनायी वे टीआईसी लि., एसटीआई, तुर्की; एलजी केम. जापान कंपनी लि., जापान; सहायक हैं, एलजी होल्लिंग्स (एचके) लि., हांगकांग, टेक्निक कंपनी लि., कोरिया; एलजी केम. ब्रासिलइंटरमीडियाको डी नेगोसियोस डो सेक्टर किमीकोल लि., ब्राजील; एलजी केम. मलेशिया एसडीएन, बीएचडी, 12 मलेशिया; एलजी फ्यूल सेल सिस्टम्स इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका; संयुक्त उद्यम हैं, सीटेक कं. लि. कोरिया; एलजी कारपो. कोरिया; एलजी कारपो. की सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम हैं, सर्वन कं. लि., एलजी सीएनएस कं. लि., एलजी सिलट्रोन इंक., एलजी प्रबंधन विकास संस्थान, एलजी स्पोर्ट्स लि., एलजी एमएमए कारपोरेशन।

सत्यातापूर्ण प्रकटन का दायित्व उत्तरदायी निर्यातक पर है। घरेलू उद्योग जासूसी कार्य नहीं कर सकता तथा प्राधिकारी को संगत सूचना नहीं दे सकता। प्राधिकारी द्वारा बार-बार यह कहा गया है कि जांचें विश्वास और निष्ठा के आधार पर की जाती हैं। तथापि, ऐसी स्थिति में, जहां निर्यातक द्वारा इस प्रकार के छिपाव का सहारा लिया गया हो, प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि निर्यातक द्वारा विश्वास और निष्ठा खोई गई है और निर्यातक का उत्तर रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

#### **निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

85. मैसर्स ऑटोमोटिव टायर्स मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स लूथरा एंड लूथरा विधि कार्यालयों ने विभिन्न अनुरोध दायर किए हैं:

- एस-एसबीआर ग्रेड जांचों के क्षेत्र में नहीं आते हैं तथा घरेलू उद्योग ने इसे अपने अनुरोध में स्वीकार किया है। अतः यह स्पष्ट है कि एस-एसबीआर ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से साफ तौर पर बाहर किया जाए। इसी के मद्देनजर उत्तरदायी यह अनुरोध करते हैं कि आरंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पाद एचएसएन कोड 4002.19 (6 अंक के स्तर पर) दिया है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि एचएसएन 6 अंकीय स्तर पर इमल्सन एसबीआर (ई-एसबीआर) तथा सॉल्यूशन एसबीआर (एस-एसबीआर) जैसे सभी एसबीआर ग्रेडों को शामिल किया गया है।
  - अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद का विवरण उपयुक्त रूप से यह दर्शाता है कि एस-एसबीआर को उसके क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है, उत्तरदायी सादर अनुरोध करते हैं कि अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद का विवरण एचएसएन 8 अंकीय स्तर पर दिया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर विचार करने में कोई भ्रामकता का मामला नहीं होगा। अंतिम रूप से यह भी नोट किया जाना चाहिए कि उत्तरदायी की ओर से यह अनुरोध अपने इस तर्क के पूर्वाग्रह के बिना है कि वर्तमान जांच में वास्तविक एवं कानूनी स्थिति पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं समझता जो लिखित अनुरोध में दिया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाए कि यह लिखित अनुरोध किसी पूर्वाग्रह के बिना है और हमारे दिनांक 21 मार्च, 2016, 23 सितंबर, 2016, 11 नवंबर, 2016, 16 नवंबर, 2016 और 03 अप्रैल, 2017 के अनुरोधों तथा 01 सितंबर, 2016, 30 मार्च, 2017 तथा 24 मई, 2017 के पत्रों के अलावा है। निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 15 जून, 2017 के ई-मेल द्वारा जारी प्रकटन विवरण के निमित्त उत्तरदायी अपना लिखित उत्तर देते हैं।
- (1) उत्तरदायी का निरंतर यह अनुरोध रहा है कि वास्तविक क्षति/वास्तविक क्षति के खतरे तथा वास्तविक मंदी के दावे की साथ-साथ जांच नहीं की जा सकती और पाटनरोधी जांच नहीं की जा सकती। यह इस तथ्य के निमित्त है कि दोनों संकल्पनाएं अर्थात् घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी पूर्णतः एक-दूसरे के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए वास्तविक क्षति के दावे के अनुरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति अथवा क्षति के खतरे की जांच सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण तथा वसूली) नियमावली, 1995 ("भारतीय पाटनरोधी नियमावली") के अनुसार करते हैं।
  - (2) दूसरी ओर, घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी के लिए दावे के अनुरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी यह जांच करते हैं कि क्या पाटित वस्तुओं के आयात के परिणामस्वरूप भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में मंदी आई है। यह नोट किया जाता है कि वास्तविक मंदी के तहत दावे के लिए मूलभूत आवश्यकता जांचाधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की गैर-मौजूदगी है। यह इस कारण है कि यदि घरेलू उद्योग पहले से ही स्थापित है, तो वास्तविक मंदी का दावा बन नहीं

सकता। वस्तुतः वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थिति यह भी रही है और घरेलू उद्योग की निम्नलिखित बात नोट करने योग्य है:

*“यदि याचिकाकर्ता लंबी अवधि तक उत्पादन कर रहे थे तो यह कहा जा सकता है कि वास्तविक मंदी का प्रावधान नहीं लगाना चाहिए और इस मामले की जांच या तो वास्तविक क्षति के तहत अथवा वास्तविक क्षति के खतरे के प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए।”*

- (3) इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन पाटनरोधी के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के करार (एडीए) द्वारा भी किया गया है। एडीए के फुटनोट 9 में निम्नलिखित प्रावधान है:

*इस करार के तहत क्षति “क्षति” शब्द को अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए जाने तक उसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के अर्थ में, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के अर्थ में अथवा ऐसे किसी उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी के अर्थ में लिया जाएगा तथा इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार उसकी व्याख्या की जाएगी।*

- (4) यह फुटनोट स्पष्ट रूप से बताता है कि “क्षति” का अर्थ या तो वास्तविक क्षति/वास्तविक क्षति का खतरा अथवा वास्तविक मंदी होगा न कि दोनों। एडीए का फुटनोट 9 सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (अधिनियम) की धारा 9ख(1)(ख)(ii) में शामिल कर लिया गया है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

*कुछ मामलों में धारा 9 अथवा धारा 9क के तहत कोई शुल्क नहीं लगेगा – (1) किसी बात के होते हुए धारा 9 अथवा धारा 9क में निहित कोई बात*

*(ख) केंद्र सरकार कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अथवा पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी:*

*(ii) इन धाराओं की प्रत्येक उप धारा (1) के तहत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश अथवा उस देश, जिसके साथ भारत सरकार ने सर्वाधिक पक्षकारी राष्ट्रीय करार (जिसे इसके बाद विनिर्दिष्ट देश कहा जाएगा) से भारत में आयात पर, जब तक कि इस धारा की उप धारा (2) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार न हो, यह निर्धारण किया गया है कि ऐसी वस्तु के भारत में आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा होता है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद करता है।*

- (5) उपर्युक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर क्षति का दावा वास्तविक क्षति/वास्तविक क्षति के खतरे अथवा वास्तविक मंदी के लिए हो सकता है। यह स्थिति भी यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई जांच प्राधिकारी यह पाता है कि वास्तविक क्षति/वास्तविक क्षति के खतरे का मामला है तो वास्तविक मंदी से संबंधित दावा संधारणीय नहीं बनता है। जैसा कि कुछ उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग पहले से ही मौजूद है।
- (6) यह कानूनी स्थिति होने के बावजूद कि क्षति का अभिप्राय वास्तविक क्षति/वास्तविक क्षति के खतरे अथवा वास्तविक मंदी से होगा न कि दोनों से, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह निष्कर्ष निकाला है कि वास्तविक क्षति है तथा वास्तविक मंदी का मामला बनता है। इस संबंध में प्रकटन विवरण के पैरा 35 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणी दी है:

*“प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी, दोनों की जांच की है। वास्तविक क्षति के लिए आईएसआरपीएल के आंकड़ों का संदर्भ दिया गया है जिन्होंने जांच की अवधि से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया था जबकि वास्तविक मंदी के लिए मैसर्स आरआईएल के आंकड़ों की जांच की गई है जिन्होंने जांच की अवधि के बाद के समय में वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया था।”*

- (7) निर्दिष्ट प्राधिकारी इस वास्तविक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग के एक घटक के लिए अर्थात् आईएसआरपीएल के लिए वास्तविक क्षति बनती है और घरेलू उद्योग के दूसरे घटक के लिए अर्थात् आरआईएल के लिए वास्तविक मंदी है। उत्तरदायी सशक्त रूप से निर्दिष्ट प्राधिकारी की इस टिप्पणी से असहमत हैं क्योंकि इससे एक विसंगति बनती है जो कि कानून में निर्धारित नहीं है। यदि आईएसआरपीएल को वास्तविक क्षति हुई है तो इसका अर्थ यह है कि एसबीआर सीरीज 1500 और 1700 के लिए एक स्थापित उद्योग है तथा इसीलिए ऐसी स्थितियों में वास्तविक मंदी का मामला नहीं बन सकता।

- (8) उपर्युक्त के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो वास्तविक क्षति का अथवा वास्तविक मंदी का निष्कर्ष निकल सकता है पर दोनों का नहीं। इसी दृष्टि से उत्तरदायी सादर अनुरोध करते हैं कि आईएसआरपीएल के

लिए वास्तविक क्षति तथा आरआईएल के लिए वास्तविक मंदी की मौजूदगी के संबंध में पैराग्राफ 35 में निर्दिष्ट प्राधिकारी का निष्कर्ष कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है। उत्तरदायी निर्दिष्ट प्राधिकारी से सादर अनुरोध करते हैं कि वे उपर्युक्त तर्कों पर ध्यान दें और तदनुसार, अंतिम निष्कर्ष जारी करते समय वास्तविक मंदी संबंधित निष्कर्षों को रद्द करें।

- (9) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह निष्कर्ष निकाला है कि आईएसआरपीएल और आरआईएल भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं। अतः वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक मंदी का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग के क्षति आंकड़ों पर समग्र रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, घरेलू उद्योग को "क्षति" स्थापित करने के लिए, चाहे वास्तविक क्षति हो अथवा वास्तविक मंदी हो, दोनों आवेदकों के "क्षति" आंकड़ों को उसे सिद्ध करने के लिए साथ-साथ लिए जाने की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव अधिनियम की धारा 9ख(1)(ख)(ii) तथा एडीए के फुटनोट 9 के समर्थन में है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी नोट करने योग्य है:

*हमारे मत में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कानूनी तौर पर साफ-साफ गलती की है क्योंकि प्राधिकारी को क्षति का निर्धारण करना था तथा समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का परिकलन करना था न कि किसी कंपनी विशेष उद्यम विशेष के संबंध में। ..... पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में क्षति विश्लेषण से संबंधित प्रावधान भी स्पष्ट हैं कि क्षति निर्धारण हमेशा समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए न कि अलग-अलग कंपनियों के लिए।*

- (10) यह स्पष्ट है कि "क्षति" का निर्धारण समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए किया जाएगा न कि एक अलग कंपनी के लिए। इसके बजाए वास्तविक क्षति के निर्धारण के प्रयोजन से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आईएसआरपीएल के आंकड़ों पर विचार किया है जबकि वास्तविक मंदी के निर्धारण के लिए आरआईएल के आंकड़ों पर विचार किया है। इस प्रकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस जांच में घरेलू उद्योग की दो अलग-अलग श्रेणी बनाई हैं। तथापि, यदि आईएसआरपीएल पहले से ही एक स्थापित उद्योग है तो आरआईएल को वास्तविक मंदी का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (11) इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त विश्लेषण के फलस्वरूप एक विसंगति पैदा हुई है जिसकी अनुमति एडीए तथा भारतीय कानूनी प्रावधानों में नहीं की गई है। एडीए के अनुच्छेद 4.1 तथा फुटनोट 9, जो भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा अधिनियम की धारा 9ख(1)(ख)(ii) में दर्शाया गया है, में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि आवेदक के क्षति आंकड़ों पर वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक मंदी सिद्ध करने के लिए अलग-अलग विचार किया जाए क्योंकि एक पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग की दो अलग-अलग श्रेणियां नहीं हो सकतीं। यह कानूनी सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
- (12) प्रकटन विवरण में आईएसआरपीएल और आरआईएल के लिए अलग से क्षति विश्लेषण करने का निर्दिष्ट प्राधिकारी का निष्कर्ष कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है तथा घरेलू उद्योग के स्तर के संबंध में निष्कर्ष का विरोधाभासी भी है। निष्कर्ष में उत्तरदायी निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि अंतिम जांच परिणामों में वास्तविक मंदी से संबंधित क्षति निर्धारण को रद्द करें।
- (13) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह पाया है कि डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी ने लूथरा एंड लूथरा सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकार पत्र जारी किए थे और इसीलिए इस संबंध में उत्तरदायी का अनुरोध गलत रखा गया है तथा तर्कसंगत नहीं है।
- (14) आरंभ में उत्तरदायी यह उल्लेख करेंगे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिया गया उपर्युक्त स्पष्टीकरण सही वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाता है। यह नोट किया जाए कि उत्तरदायी ने अपने दिनांक 30 मार्च, 2017 और 24 मई, 2017 के पत्रों द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आयात आंकड़ों के गैर गोपनीय रूपांतरण की मांग की थी तथा डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के गैर गोपनीय रूपांतरण की सॉफ्ट प्रति भी मांगी थी जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विश्वास किया था। उत्तरदायी को सामान्य रूप से यह सूचित किया गया था कि वे डीजीसीआईएंडएस से सीधे संपर्क करके लेन-देन वार आयात आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।
- (15) उत्तरदायी को घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़े तथा डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़े, जिन पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विश्वास किया था, नहीं दिए गए थे। यह नोट किया जाना चाहिए कि डीजीसीआईएंडएस में उपलब्ध लेन-देन वार आयात आंकड़ों और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा दिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों, जिन पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विश्वास किया है, में अंतर है क्योंकि दोनों में कतिपय अंतर हो सकते हैं।
- (16) कानूनी स्थिति स्वीकार की जाती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्य प्रकृति में अर्धन्यायिक हैं तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है और उसे स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों को भी अपनाना होता है। इस तथ्य

के मद्देनजर कि ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार उत्तरदायी को संगत आयात आंकड़े नहीं दिए गए हैं, उत्तरदायी सादर अनुरोध करता है कि उत्तरदायी का प्रक्रिया के अनुसार अपने पर्याप्त रूप से रक्षा करने के अधिकार को नकारा गया है जिसके परिणामस्वरूप इस जांच के दौरान स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है।

- (17) उत्तरदायी को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़े तथा डीजीसीआईएसएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन पर विश्वास किया गया।
- (18) उत्तरदायी अनुरोध करते हैं कि स्वाभाविक न्याय का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि एक न्यायिक प्राधिकारी को उन दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए जिन पर उसने अपने निष्कर्ष पर विश्वास किया है ताकि विरोधी पक्षकार को उसके विरुद्ध किए गए मामले का सार्थक उत्तर देने के लिए एक अवसर प्राप्त हो सके। वर्तमान वास्तविक मामले में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आयातों की लेन-देन वार सूची आकार में बहुत लंबी फाइल होने की दृष्टि से सीडी रॉम में घरेलू उद्योग की याचिका के साथ संलग्न की गई थी। इस प्रकार, यदि घरेलू उद्योग ने लेने-देन वार आयात आंकड़े दे दिए थे, तो यह निर्दिष्ट प्राधिकारी पर था कि वे सुनिश्चित करते कि ऐसे आयात आंकड़ों के गैर गोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराया जाए।
- (19) उपर्युक्त प्रस्ताव का भारतीय पाटनरोधी नियमावली का नियम 6(7) समर्थन करता है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

*“निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच में भाग लेने वाले एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य दूसरे हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा।”*

- (20) उपर्युक्त प्रावधान में “कराएगा” शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का दायित्व है कि इस जांच में भाग लेने वाले एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को दूसरे हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराए। तदनुसार, बढ़े हुए आयात के लिए साक्ष्य के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आयात आंकड़ों के गैर गोपनीय रूपांतर को एक्सल फॉर्मेट में अन्य विरोधी पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- (21) उत्तरदायी द्वारा दिए गए उपर्युक्त तर्क का निर्दिष्ट प्राधिकारी की मौजूदा परिपाटी से समर्थन मिलता है। उदाहरण के लिए चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से आयातित सीमलेस ट्यूब, पाइप और लोहे की खोखली प्रोफाइल, अलॉय अथवा गैर अलॉय स्टील के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 09 दिसंबर, 2016 के अंतिम जांच परिणामों में निम्नलिखित पाया गया था:

*कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि डीजीसीआईएसएंडएस के लेन-देन वार आंकड़ों को गोपनीय नहीं माना जाना चाहिए था। तथापि, यह नोट किया जाता है कि डीजीसीआईएसएंडएस के लेन-देन वार आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करा दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग आंकड़े तथा विचाराधीन न रखे गए उत्पाद के लिए दोनों के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने एक्सल फाइल में सॉफ्ट कॉपी में भी दिए और उसे सार्वजनिक फाइल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया था। तथापि, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएसएंडएस के लेन-देन वार आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रख दिए हैं और उन्हें सार्वजनिक फाइल के माध्यम से हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराया दिया गया था (चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से आयातित सीमलेस ट्यूब, पाइप और लोहे की खोखली प्रोफाइल, अलॉय अथवा गैर अलॉय स्टील के आयात से संबंधित अंतिम जांच परिणाम दिनांक 09 दिसंबर, 2016 पैरा 120(घ))।*

- (22) एक्सल फॉर्मेट में डीजीसीआईएसएंडएस के आंकड़ों का गैर गोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया था और अन्य विरोधी पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया गया था। इसी दृष्टि से उत्तरदायी सादर अनुरोध करते हैं कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आयात आंकड़ों का गैर गोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया जाए ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके और उसके विरुद्ध टिप्पणियां दी जा सकें।
- (23) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

*“निःसंदेह यह सत्य है कि निर्णायक प्राधिकारी के पास जो भी रिपोर्टें और साक्ष्य हैं, उन्हें स्वाभाविक न्याय की दृष्टि से प्रायः प्रकट किए जाने की आवश्यकता होती है तथा क्षति के संबद्ध मामले में संगत ऐसी रिपोर्टें और साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बशर्ते कि अधिनियम की योजना विशिष्ट रूप से ऐसे प्रकटन को न रोकती हो।” (कंवर नटवर सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशक तथा अन्य (2010) 13 एससीसी 255 पैरा 26)।*

- (24) इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने नॉर्थ बिहार एजेंसी तथा अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में आवेदक के लाइसेंस को रद्द किए जाने के आदेश को इस आधार पर रद्द किया कि आवेदक को समुचित अवसर नहीं दिया गया क्योंकि जिस अतिरिक्त सामग्री पर लाइसेंस को रद्द करते समय विश्वास किया गया था, वह आवेदक को नहीं दी गई थी जो कि

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टैरलाईट इंडस्ट्रीज के मामले में भी अन्य विरोधी पक्षकारों को संगत सामग्री की पहुँच प्रदान करने के लिए तर्कसंगतता व्यक्त की थी क्योंकि उससे प्रभावित पक्षकार को प्रभावी अपील दायर करने की अनुमति मिल जाती है, जबकि संगत सामग्री प्रकट न किए जाने से प्रभावी अपील दायर करने में विरोधी पक्षकार पंगु हो जाता है।

- (25) उपर्युक्त के अतिरिक्त, उत्तरदायी इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखितानुसार बार-बार अनुरोधों के बावजूद डीजीसीआईएसएंडएस के आंकड़ों से प्राप्त लेन-देन वार आयात आंकड़ों का गैर गोपनीय रूपांतर उपलब्ध नहीं कराया। इस संबंध में उत्तरदायी यह अनुरोध करते हैं कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों/सूचना पर गोपनीयता का दावा नहीं कर सकते। इस प्रस्ताव को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

*हमारे मत में "नियम 7 गोपनीयता का दावा करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई अधिकार नहीं देता है। नियम 7 में विशिष्ट रूप से यह प्रावधान है कि गोपनीयता का अधिकार उस पक्षकार तक सीमित है जिसने सूचना दी है तथा यह कि पक्षकार को भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को संतुष्ट करना होता है कि मामला वास्तव में गोपनीय है" (रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य (2006) 2010 एससीसी 368 पैरा 22)।*

- (26) रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उपर्युक्त टिप्पणी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि. के मामले में मानी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों/सूचना पर गोपनीयता का दावा नहीं कर सकते। तदनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निर्णय कि डीजीसीआईएसएंडएस के आयात आंकड़ों का लेन-देन वार विवरण, जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विश्वास किया है, नहीं बांटे जा सकते, कानूनी तौर पर तर्कसंगत नहीं हैं।
- (27) अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आंकड़े प्रकट न करने की उपर्युक्त परिपाटी विश्व व्यापार संगठन के करार द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के उल्लंघन में भी है। एडीए के अनुच्छेद 6.4 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी को चाहिए कि वे वह समस्त सूचना देखने का मौका सभी हितबद्ध पक्षकारों को दें जो गोपनीय नहीं है और यह कि वह सूचना भी दें जिसका पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा इस्तेमाल किया गया है। एडीए के अनुच्छेद 6.4 की व्याख्या करते समय डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

*हम यूरोपीय संघ के विचारों को नोट करते हैं कि अनुच्छेद 6.4 में "सूचना" शब्द जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक निश्चरण और निष्कर्ष के बजाए तथ्यों और कच्चे आंकड़ों से संबंधित है। हमारी दृष्टि में "मामलों की प्रस्तुती (पक्षकार) से संगत" सूचना को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 6.4 में कोई पाठगत आधार नहीं है तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रिया में न लाए गए अथवा कच्चे आंकड़ों में "प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त" सूचना आदि के लिए कोई पाठगत आधार नहीं है। वस्तुतः अनुच्छेद 6.4 के तहत दायित्वों के अध्यक्षीन सूचना की व्यापक श्रृंखला में कई रूप हो सकते हैं जिनमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े और सूचना शामिल है जिस पर प्रक्रिया की गई है, आयोजित किया गया है अथवा प्राधिकारी द्वारा सारांश रूप में लिया गया है। हम नहीं देखते कि तथ्य और कच्चे आंकड़े कैसे पक्षकारों के लिए उनके मामलों में प्रस्तुती के लिए संगत होंगे (अपील निकाय की रिपोर्ट, ईसी – फासनर्स, डब्ल्यूटी/डीएस397/एबी/आर पैराग्राफ 480)*

*अनुच्छेद 6.4 के तहत हितबद्ध पक्षकारों का अधिकार है कि वे उनके मामलों की प्रस्तुती के लिए संगत सभी गैर गोपनीय सूचना तथा जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त सूचना को देखें। इस प्रकार अनुच्छेद 6.4 उस समस्त सूचना की व्यापक श्रृंखला पर लागू होता है जो पाटनरोधी जांच में अपेक्षित कदम उठाने के प्रयोजन से जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयोग में लाई गई हो।*

28. उत्तरदायी यह अनुरोध करते हैं कि प्रकटन विवरण के पृष्ठ 12 पर पैरा छ में निर्दिष्ट प्राधिकारी का निष्कर्ष कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और ऊपर उल्लिखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप भी नहीं है। तदनुसार, उत्तरदायी अपने हित की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में समर्थ नहीं रहे हैं क्योंकि उत्तरदायी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जिन संगत आयात आंकड़ों पर विश्वास किया गया है, उनका विश्लेषण नहीं कर पाए तथा उस पर अपनी टिप्पणियां नहीं दे पाए। उपर्युक्त के मद्देनजर उत्तरदायी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएसएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़े तथा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आयात आंकड़े विरोध हितबद्ध पक्षकारों को दिए जाने चाहिए और उत्तरदायियों को उस पर टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- (29) प्रकटन विवरण के पैरा 47 द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण किया है। तथापि, आईएसआरपीएल से संबंधित सम्पूर्ण क्षति आंकड़े गोपनीय रखे गए हैं और यहां तक कि क्षति आंकड़ों का सूची वाला रूपांतर भी नहीं दिया गया है। इस संबंध में उत्तरदायी अनुरोध

करते हैं कि उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री से संबंधित क्षति आंकड़े गोपनीय नहीं माने जा सकते और वास्तविक क्षति आंकड़े विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

- (30) डीजीएडी द्वारा जारी कई प्राथमिक और अंतिम जांच परिणामों के विश्लेषण से यह साफ-साफ सिद्ध होता है कि डीजीएडी एक परिपाटी के रूप में क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री तथा क्षमता उपयोग के संबंध में गोपनीयता की अनुमति नहीं देता, तब भी जब कि ये आंकड़े सार्वजनिक पटल पर न हों। इस प्रकार, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व जांचों में ऐसी सूचना को गोपनीयता प्रदान नहीं की तो वर्तमान जांच में कतिपय गोपनीय सूचना को इस दृष्टि में नहीं रखा जा सकता। दूसरे शब्दों में, यदि सूचना उसी मानदंड से संबंधित है तो सूचना की प्रकृति गैर गोपनीय से गोपनीय में नहीं बदल सकती। वस्तुतः जिस आधार पर उपर्युक्त तथ्यों से संबंधित आंकड़े गोपनीय रखे गए हैं, उन्हें आरंभिक अधिसूचना अथवा याचिका में भी प्रकट नहीं किया गया है।
- (31) यह नोट किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त मामलों से संबंधित आंकड़ों का सूची वाला रूपांतर भी प्रकटन विवरण में नहीं दिया गया है ताकि विरोधी हितबद्ध पक्षकार उस प्रवृत्ति का विश्लेषण कर सकें और उस पर अपनी टिप्पणी दे सकें। इस संबंध में 09 दिसंबर, 2013 के ट्रेड नोटिस संख्या 01/2013 के पैरा (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि आंकड़ों का गैर गोपनीय रूपांतर, गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सारांश के पर्याप्त समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, उपर्युक्त मामलों से संबंधित क्षति संबंधी आंकड़े गोपनीय रखे गए हैं और यहां तक कि क्षति सामग्री आंकड़ों का सूची वाला रूपांतर नहीं दिया गया है।
- (32) उपर्युक्त मामले संबंधित क्षति संबंधी आंकड़ों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता प्रदान करना ट्रेड नोटिस 01/2013 के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्षति संबंधी आंकड़ों को प्रकट न करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन भी हुआ है, क्योंकि उत्तरदायी क्षति संबंधी आंकड़ों के संबंध में कोई टिप्पणियां नहीं दे पाए तथा इस प्रकार अपने हित की पर्याप्त रूप से सुरक्षा नहीं कर पाए।
- (33) पैरा 75 में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वास्तविक मंदी के मामले का मूल्यांकन करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। यद्यपि, वास्तविक मंदी से संबंधित दावे का मूल्यांकन करने से संबंधित कानूनी भ्रामकता को यह स्पष्ट करता है, जैसा कि पूर्व अनुरोधों में उत्तरदायी द्वारा उल्लेख किया गया है, तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि प्रकटन विवरण में पहली बार विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को ये मानदंड तब निर्धारित किए गए हैं जब हितबद्ध पक्षकारों के संबंधित सभी आंकड़ों तथा सूचना का जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर दिया गया। इस देरी से इस प्रकटन के परिणामस्वरूप एटीएमए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर वास्तविक मंदी के दावे का सार्थक विरोध करने के अधिकार से वंचित रह गया।
- (34) कानून के नियम का एक मौलिक अभिलक्षण कानून के अनुप्रयोग में पूर्वानुमान भी है। इस स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस. जी. जयसिंहानी बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में टिप्पणी से समर्थन है जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

*"कानूनी नियम द्वारा शासित प्रणाली में जब किसी कार्यकारी प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्रदत्त किया जाता है तो वह स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं तक होना चाहिए। इस दृष्टि से कानूनी नियम का अर्थ है कि निर्णय ज्ञात सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग कर लिया जाए तथा सामान्यतः ऐसे निर्णय पूर्वानुमाननीय होने चाहिए और नागरिक को यह मालूम होना चाहिए कि वह कहां है।"*

- (35) उपर्युक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः निर्णय पूर्वानुमाननीय होना चाहिए जिसका अर्थ है कि कानून को लागू करने में और जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाटी में स्पष्टता होनी चाहिए, विशेषकर जब वह अर्धन्यायिक निकाय हो। इसी दृष्टि से एटीएमए का अनुरोध है कि चूंकि, मानदंड पहले निर्धारित नहीं किए गए थे और जिन सिद्धांतों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचार किया वे हितबद्ध पक्षकारों को मालूम नहीं थे। अतः वास्तविक मंदी से संबंधित दावे का मूल्यांकन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसी दृष्टि से वास्तविक मंदी से संबंधित दावे को रद्द किया जाना चाहिए।
- (36) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रकटन विवरण में कहा है कि एटीएमए का प्रतिनिधित्व करने वाले "मैसर्स लूथरा एंड लूथरा विधि कार्यालयों ने अपने दिनांक 24.04.2017 के पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि ई-एसबीआर 1739 और 1789 ग्रेडों को अलग कर दिया जाए क्योंकि मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने स्वीकार किया है कि वह ई-एसबीआर 1789 का इस समय निर्माण नहीं कर सकता और मैसर्स आईएसआरपीएल अपनी वेबसाइट पर अपनी उत्पाद सूची में इस ग्रेड को नहीं दर्शाता।" इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पृष्ठ 12 पैरा च द्वारा निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि आरआईएल के पास ई-एसबीआर 1739 और ई-एसबीआर 1789 के उत्पाद ग्रेडों का विनिर्माण करने की क्षमता है, अतः उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाता है।

- (37) उत्तरदायी यह अनुरोध करेंगे कि प्रकटन रिपोर्ट में उपर्युक्त विवरण उत्तरदायी द्वारा सामने रखे गए वास्तविक तर्क को नहीं दर्शाते। उत्तरदायी ने अपने पत्र में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि न केवल आरआईएल ने ई-एसबीआर ग्रेडों के 1739 और 1789 का विनिर्माण नहीं किया है, ये उत्पाद ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित अन्य उत्पाद ग्रेडों की समान वस्तु भी नहीं हैं जिसके कई कारण हैं यथा – रासायनिक संघटन, प्रयोग, कीमत, ग्राहक अवधारणा आदि। तदनुसार, उत्तरदायी का तर्क था कि ई-एसबीआर ग्रेड के 1739 और 1789 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग कर दिया जाना चाहिए।
- (38) तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से ई-एसबीआर ग्रेड के 1739 और 1789 को इस आधार पर अलग नहीं किया है कि आरआईएल के पास इन उत्पादों का विनिर्माण करने की क्षमता आरआईएल द्वारा अपनी स्वीकृति के बावजूद है। समान वस्तु के मुद्दे के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य रूप से पाया है कि स्टाइरिन बुटाडीन रबर की सीरीज से संबंधित विभिन्न ग्रेडों के बीच अंतर केवल रबर में स्टाइरिन और बुटाडीन तत्व के संघटन अनुपात का है। ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, उत्तरदायी ने अपने तर्क के समर्थन में कई कारणों का उल्लेख किया था कि ई-एसबीआर ग्रेड 1739 और 1789 घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों में समान वस्तु नहीं हैं जो कि प्रकटन रिपोर्ट में भी नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार, जिस वास्तविक आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि ये ई-एसबीआर ग्रेड समान वस्तु हैं, त्रुटिपूर्ण हैं और उसे गलत रखा गया है तथा इस प्रकार उसे अलग किया जाना चाहिए।
- (39) निर्दिष्ट प्राधिकारी का उपर्युक्त निष्कर्ष भी कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है और उनकी मौजूदा परिपाटी के भी विपरीत है जो कि बहुपक्षीय अंतिम जांच परिणामों में दर्शाया गया है, प्रथमतः समान वस्तु के मुद्दे के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह परिपाटी रही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू उद्योग में जांच की अवधि के दौरान विवादास्पद उत्पाद ग्रेडों का वास्तव में विनिर्माण किया है और उनकी आपूर्ति की है। चीन जन गण, जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, ताइवान (चीनी ताइपेई), थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:
- प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कुछ ग्रेडों/विशिष्टियों के उत्पादों को अलग करने के प्रयोजन से कतिपय व्यापक सिद्धांत अपनाए हैं। ऐसा एक सिद्धांत यह है कि क्या हितवद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई विशिष्टि/ग्रेड/उत्पादन प्रक्रिया/उत्पादन प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप भौतिक विशिष्टियों और रासायनिक संघटन, जिससे उत्पाद की विशिष्टता स्पष्टता और परिशुद्धता से स्थापित की जा सके, के संदर्भ में भिन्न उत्पाद बनते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि क्या घरेलू उद्योग ने इन ग्रेडों के विनिर्माता के रूप में अपने उत्पाद ब्रोशर के माध्यम से दावा किया है तथा जांच की अवधि के दौरान अथवा जांच की अवधि से पूर्व ऐसी विशिष्ट मदों का विनिर्माण/आपूर्ति कर रहा है। तीसरे क्या जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादों की आपूर्ति की गई और हटाए जाने के लिए प्रस्तावित/माने गए ग्रेडों के समान होने का दावा किया गया है तथा ऐसी स्थिति में क्या कोई प्रमाण स्वरूप वैज्ञानिक साहित्य अथवा कोई अन्य तकनीकी साक्ष्य घरेलू उद्योग द्वारा पुष्ट किया गया है।*
- (40) उपर्युक्त मानदंड के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम निकाला है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र "वर्तमान जांच में 1250 मिमी. तक प्रतिबंधित रखा जाए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई की वास्तविक आपूर्ति का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।" इसी प्रकार, वर्तमान जांच में यह एक विवादरहित तथ्य है कि आरआईएल ने जांच की अवधि में तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान ई-एसबीआर ग्रेड के 1739 और 1789 का विनिर्माण तथा आपूर्ति नहीं की है। अतः इस विगत परिपाटी के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन ई-एसबीआर ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग कर देना चाहिए था।
- (41) दूसरे, यह भी तर्क नहीं दिया जा सकता कि ई-एसबीआर ग्रेड 1739 और 1789 घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित अन्य ई-एसबीआर ग्रेडों में समान वस्तु हैं। उत्तरदायी ने अपने पूर्व अनुरोध में विस्तृत तर्क दिए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि ये ई-एसबीआर उत्पाद ग्रेड बहुत उच्च गति वाले टायरों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें अन्य ई-एसबीआर उत्पाद ग्रेड इस्तेमाल नहीं किए जा सकते और इसीलिए रासायनिक संघटन, प्रयोग, कीमत, ग्राहक अवधारणा आदि जैसे कारकों के कारण महत्वपूर्ण अंतर है। संक्षिप्तता की दृष्टि से उत्तरदायी अपना पूर्व अनुरोध पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहा है और इसके बजाए उसी पर विश्वास करता है।
- (42) सेसटेट द्वारा अन्य मामलों, यथा – इंडियन रिफ़ैक्ट्री मेकर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा मैग्नेट यूजर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी उपर्युक्त सिद्धांत को माना और लागू किया गया है। इन दोनों मामलों में यह माना गया था कि भिन्न उत्पाद विशेषताओं वाले विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों को समान वस्तु नहीं माना जा सकता और इसीलिए ये घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते। इस टिप्पणी की दृष्टि से इन ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटा दिया गया था।

- (43) यह नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग से प्रकटन विवरण में कोई विवरण नहीं है जिसमें यह तर्क दिया गया हो कि ई-एसबीआर उत्पाद ग्रेड 1739 और 1789 घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद ग्रेडों में समान वस्तु हैं। इस प्रकार, यह एक विवादरहित तथ्य है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ई-एसबीआर उत्पाद ग्रेड 1739 और 1789 उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद ग्रेडों में समान वस्तु नहीं है। इसी के मद्देनजर, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में इन ई-एसबीआर ग्रेडों को शामिल करने के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी का निष्कर्ष वास्तविक है और कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है।
- (44) उत्तरदायी यह अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त पैराग्राफों के मद्देनजर ई-एसबीआर ग्रेड 1739 और 1789 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटा ही दिया जाना चाहिए।
- (45) इस क्षेत्र में प्रयुक्त उत्पादों की सुरक्षा प्राथमिक महत्व की है। इस कारण से उनके प्रयोगों में इस्तेमाल प्रमुख इनपुट के अनुमोदन प्रक्रिया/परीक्षण के बाद ही प्रयोक्ता उद्योग इस्तेमाल के लिए इन इनपुट को ले सकता है। परीक्षण /अनुमोदन प्रक्रिया में प्रयोगशाला मूल्यांकन, कारखाना परीक्षण, भारी परीक्षण, फील्ड परीक्षण, फैक्ट्री जांच आदि जैसे विभिन्न स्तर शामिल होते हैं जिनमें सामग्री के आधार पर लगभग 1-2 वर्ष लग जाते हैं।
- (46) आईएसआरपीएल ने फरवरी, 2014 में और आरआईएल ने सितंबर, 2016 में उत्पादन शुरू किया था। इसके मतलब है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित ग्रेडों का प्रयोक्ता उद्योग ने उत्पाद परीक्षण और अनुमोदन उत्पादन शुरू होने के अनुसार कम से कम दो वर्ष तक चला। इसके मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की घरेलू शुरूआत उतनी अधिक नहीं हो सकती थी जितनी जांच की अवधि के दौरान आंकड़ों में दर्शाई गई है। तथापि, आईएसआरपीएल द्वारा प्रयोक्ता उद्योग ने अपने परीक्षण प्रक्रिया पूरी करने के अनुसार घरेलू शुरूआत काफी बड़ी है और वह भी जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों से सिद्ध है, जैसा कि उत्तरदायी के पत्र में उल्लेख किया गया है तथा नीचे भी दिया गया है। वस्तुतः मात्रा में घरेलू खरीद में तथा घरेलू खरीद कीमतों में वृद्धि हुई है। मात्रा और कीमतों में घरेलू खरीद में यह महत्वपूर्ण वृद्धि जांच की अवधि के दौरान व्यापक परीक्षणों के बाद प्रयोक्ता उद्योग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के अनुरूप है।
- (47) वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी से संबंधित विश्लेषण में यह उल्लेख किया गया है कि क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आंकड़ों को गोपनीयता दी गई है और उसके लिए वास्तविक आंकड़े नहीं दिए गए हैं। वस्तुतः उपर्युक्त महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों के सूचीबद्ध आंकड़े भी नहीं दिए गए हैं और इससे समुचित रूप से आंकड़ों का विश्लेषण करने तथा अपना पक्ष पर्याप्त रूप से रखने के अवसर से उत्तरदायी को वंचित रखा गया है।
- (48) वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति पुनः होने तथा कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के संबंध में घरेलू उद्योग के सभी दावों को नकारते हुए उत्तरदायी ने पहले ही विस्तृत अनुरोध कर दिए हैं और संक्षिप्तता के लिए उसी पर विश्वास करेगा। तथापि, उत्तरदायी पूर्व अनुरोधों के अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी के कतिपय निष्कर्षों का उल्लेख करेगा जो प्रकटन विवरण में दर्शाए गए अनुसार तथ्यों और आंकड़ों के अनुरूप नहीं हैं और जिन पर जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है:-
- (क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की मांग के मूल्यांकन से संबंधित प्रकटन विवरण के पैरा 43.44 में यह पाया है कि "देश में उत्पाद के लिए मांग वार्षिक आधार पर इस अवधि में काफी बढ़ी है।" उत्तरदायी इस टिप्पणी का विरोध करते हैं क्योंकि प्रकटन विवरण के पैरा 43 में तालिका से यह स्पष्ट है कि संबद्ध सामानों की मांग क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान बढ़ी है। तथापि, मांग में वृद्धि वार्षिक आधार पर इस अवधि में कल्पना के किसी स्तर पर काफी नहीं है। इसके अतिरिक्त, साथ ही संबद्ध वस्तुओं का आयात वार्षिक आधार पर इस अवधि में संबद्ध देशों से घटा है और घरेलू उद्योग का उत्पादन इस अवधि में काफी बढ़ा है। इस प्रकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अंतिम जांच परिणामों को जारी करते समय इस निष्कर्ष पर भी विचार करें।
- (ख) पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पैरा 46 में निम्नलिखित उल्लेख किया है:
- संबद्ध देशों से आयात याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के कारण 2014-15 तक पूर्ण रूप से बढ़ा है और जांच की अवधि में घटा है।*
- संबद्ध देशों से आयात कुल आयात के संदर्भ में तथा याचिकाकर्ताओं के पास पर्याप्त क्षमता के बावजूद भारत में उपभोग और उत्पादन के संबंध में काफी रहा है।*
- संबद्ध देशों से आयात काफी रहा है और उसने उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने से घरेलू उद्योग को रोका है। वस्तुतः आयात इतने अधिक थे कि घरेलू उद्योग अपने उप इष्टतम उत्पादन की सीमा तक सामान नहीं बेच पाया है।*

उत्तरदायी अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त टिप्पणी में एक पक्षीय दृष्टिकोण है जो वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स को सही-सही नहीं दर्शाता है। भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयात 2014-15 में 337.60 से घटकर 160.72 प्रतिशत हुआ है जबकि भारतीय उपभोग की तुलना में संबद्ध देशों से आयात 2014-15 में 81.51 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में 68.06 प्रतिशत हो गया। घरेलू उद्योग का उत्पादन 2013-14 में 6,912 मी. टन से बढ़कर 2014-15 में 46,657 मी. टन तथा जांच की अवधि में 92,540 मी. टन हो गया (अर्थात् वर्ष 2014-15 में 675 प्रतिशत, वर्ष 2013-14 में जांच की अवधि में 1238 प्रतिशत की वृद्धि)।

उत्तरदायी यह अनुरोध करते हैं कि आरआईएल ने सितंबर, 2016 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था तथा घरेलू उद्योग के अन्य आवेदक अर्थात् आईएसआरएल ने फरवरी, 2014 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर, 2014-सितंबर, 2015 (जांच की अवधि) में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात में पर्याप्त कमी यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार को कब्जे में करने के लिए तत्काल सक्षम रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने इतने अल्पकाल में घरेलू मांग का काफी हिस्सा हासिल किया है।

घरेलू उद्योग के लिए प्रयोक्ता उद्योग की उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया जांच की अवधि के बाद में अन्य ग्रेडों के लिए पूरी हो गई थी, उसका उत्पादन काफी बढ़ा है। अतः उत्तरदायी विनम्र अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग के सामने सामान्य रूप से आरंभ करने की कठिनाईयां थीं और जैसे ही उसने प्रयोक्ता उद्योग के साथ अपनी उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण की, उसका उत्पादन तथा बिक्री जांच की अवधि के बाद में काफी बढ़ा है। यहां तक कि कुल उत्पादन में जांच की अवधि में भी घरेलू उद्योग का हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि जब घरेलू उद्योग के पास अपेक्षित अनुमोदन नहीं थे, तो आयात अपरिहार्य थे, परंतु प्रयोक्ता उद्योग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के अनुसरण में घरेलू उद्योग सभी महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों पर अपना निष्पादन सुधारने में सक्षम रहा है। इस प्रकार, उत्तरदायी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग पर आयात का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।

- (ग) प्रकटन विवरण के पैरा 48 की धारा (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकारी का निष्कर्ष कि "घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है परंतु इष्टतम स्तर तक नहीं" अस्पष्ट और गलत है। इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि पूरे उद्योगों में यह एक मानक परिपाटी है कि नए विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित उत्पादों का पहले परीक्षण किया जाता है और यदि एक बार वे तकनीकी तथा गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो प्रयोक्ता उद्योग उन उत्पादों को खरीदता है। परीक्षण एवं अनुमोदन का चरण प्रायः 1-2 वर्ष ले लेता है और वर्तमान जांच में भी घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों का 2014-16 से प्रयोक्ता उद्योग द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्पादन अधिक इष्टतम स्तर तक पहुँचने में समय ले लेगा। इसी दृष्टि से उत्पाद अनुमोदन प्राप्त करने के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि एक अनुकूल संकेतक है। अतः उत्तरदायी अनुरोध करते हैं कि अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व ऐसे विश्लेषण की सिफारिश की आवश्यकता है।
- (घ) बाजार हिस्से से संबंधित प्रकटन विवरण के पैरा 50-51 में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि "देश में संबद्ध सामानों के एक मात्र उत्पादक होने के बावजूद मांग के बाजार हिस्से में प्राप्ति काफी नहीं है। इस अवधि में आयातों का हिस्सा काफी रहा है।" उत्तरदायी इस निष्कर्ष का विरोध करते हैं क्योंकि यह वास्तविक रूप से गलत है तथा प्रकटन विवरण में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग का हिस्सा जांच की अवधि में मांग का 29 प्रतिशत था जबकि उसी अवधि के दौरान आयात का हिस्सा मांग का 68 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का हिस्सा जांच की अवधि के बाद (6 माह) में 51 प्रतिशत तक बढ़ा है जबकि जांच की अवधि के बाद (6 माह) में आयात का हिस्सा जांच की अवधि की तुलना में 47 प्रतिशत तक घटा है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जांच की अवधि से लेकर जांच की अवधि के बाद के समय तक घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण उछाल आया है और यह प्रयोक्ता उद्योग से घरेलू उद्योग के उत्पाद अनुमोदनों को पूर्ण करने के कारण हो सकता है। इसी अवधि में आयात भी काफी कमी दर्शाते हैं। इस प्रकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त टिप्पणी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के अनुरूप नहीं है तथा पुनः सिफारिश किए जाने की आवश्यकता है।
- (ङ) प्रकटन विवरण के पैरा 54-55 में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कीमत कटौती के दावे के संबंध में यह उल्लेख किया है कि "यह तुलना यह दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान ऐसी स्थितियां हुई हैं जिनमें संबद्ध देशों के मूल के संबद्ध सामान भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमतों पर आयात किए गए थे।" उत्तरदायी उपर्युक्त कथन का विरोध करते हैं क्योंकि उसी पैरा में कीमत कटौती विश्लेषण में दी गई

तालिका यह दर्शाती है कि कीमत कटौती संबद्ध देशों से सभी ग्रेडों के लिए नकारात्मक है। अतः अपने आप में यह विरोधाभासी निष्कर्ष, जो प्रकटन विवरण में दिए गए आंकड़ों का समाधान नहीं करता, कीमत कटौती विश्लेषण के गलत होने को दर्शाता है।

उत्तरदायी प्रकटन विवरण के पैरा 55 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष का विरोध करते हैं कि "घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव, जो अभी बाजार में आया है, एक नकारात्मक कीमत कटौती यह दर्शाती है कि उद्योग ने बाजार में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक रूप से आयात कीमतों समान रखी हैं।" यह इस कारण है कि प्रकटन विवरण में दी गई नकारात्मक कीमत कटौती की इस समझ को आंकड़े आवश्यक नहीं मानते। नकारात्मक कीमत कटौती का अभिप्राय सामान्य रूप से यह है कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयात की कीमतों से अधिक हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः उत्तरदायी विनम्रतापूर्वक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि अंतिम निष्कर्ष जारी करने से पूर्व इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें।

- (च) प्रकटन विवरण में पैरा 59 में दिए गए लाभ के आंकड़े केवल आईएसआरपीएल से संबंधित हैं। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि "घरेलू उद्योग को उनकी स्थापना से ही भारी हानियां हुई हैं" तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि आरआईएल के लाभ के आंकड़े इस प्रकटन विवरण में हिसाब में नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तरदायी का तर्क उसके पत्रों में यह बताता है कि आईएसआरपीएल की वित्तीय स्थिति इंडियन ऑयल कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकट की गई है जिसका आईएसआरपीएल में 50 प्रतिशत हिस्सा है। आईएसआरपीएल ने वर्ष 2014-15 में भारतीय रुपए 242.64 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया है (वर्ष 2014-15 में लगभग 95 प्रतिशत की वृद्धि) और उसका वर्ष 2015-16 में 43.63 करोड़ रुपए का निवल नकद प्रवाह है (वर्ष 2014-15 में लगभग 194 प्रतिशत की वृद्धि)। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि आईएसआरपीएल जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक नकद प्रवाह में रहा है। चूंकि, रिलायंस वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं था और केवल आईएसआरपीएल एसबीआर का उत्पादन करता है, अतः इसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग का जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक नकद प्रवाह था। यह सीधे ही घरेलू उद्योग के दावे का खंडन करता है कि उसको जांच की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं और उसके बाद घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के किसी दावे का भी खंडन करता है।

हानियों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणी के संदर्भ में यह भी नोट किया जाना चाहिए कि यदि बार-बार घरेलू उद्योग की कंपनियों के संयंत्रों को बंद करने से हानियां हुई हैं, जो कि स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हैं कि घरेलू उद्योग के भीतर अंतरजात कमियां मौजूद हैं और इसीलिए घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक क्षति का दावा नहीं बनाए रखा जा सकता जैसा कि यह स्वप्रभावित है। उत्तरदायी के पत्रों में इस मुद्दे पर भी झंझट लगी हुई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आरआईएल का हजीरा संयंत्र, जो एसबीआर और ईबीआर का उत्पादन करता है, 24 मार्च, 2017 से 20 अप्रैल, 2017 तक की अवधि के लिए बंद था। इसी कारण प्रयोक्ता उद्योग के सामने विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति से संबंधित कठोर मुद्दे थे। इसी के मद्देनजर, उत्तरदायी विनम्रतापूर्वक निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे घरेलू उद्योग की अंतर्निहित कमियों को विचार में लें जिनके कारण क्षति हो सकती है। अतः घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का दावा संधारणीय नहीं है।

- (छ) गैर क्षतिकारक कीमत ("एनआईपी") के निर्धारण के लिए सिद्धांत से संबंधित प्रकटन विवरण के अनुबंध-4(झ) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि "आरआईएल के वित्तीय आंकड़ों को उन्हें भी वास्तविक मंदी की क्षति का विश्लेषण करने के लिए लिया गया है" उत्तरदायी प्रबल रूप से इसका विरोध करते हैं और अनुरोध करते हैं कि कोई भी नई फैक्ट्री/उद्यम शुरूआत की कठिनाईयों का सामना करने तथा बाजार हिस्सा और मात्रा लेने के लिए समय लेता है। जैसा कि प्रकटन विवरण में नोट किया गया है, आरआईएल ने आईएसआरपीएल की तुलना में काफी देर से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, (आईएसआरपीएल ने फरवरी, 2014 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और आरआईएल ने 30 सितंबर, 2016 को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया था और इसीलिए आरआईएल के लिए यह संभव नहीं है कि वह आईएसआरपीएल के बराबर रहे। आशा है कि आरआईएल प्रचालन स्थिर करने के लिए समय ले क्योंकि उसने वाणिज्यिक उत्पादन 2016 से शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, इस अनुरोध में जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति के दावों की साथ-साथ उसी जांच की अवधि में अलग-अलग जांच नहीं की जा सकती।

- (49) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इन मुद्दों पर पुनः विचार करें और अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व उपर्युक्त आधारों के आलोक में दावों का विश्लेषण करें।

- (50) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पैरा 81 में यह निष्कर्ष निकाला है कि "पाटन और क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध है।" उत्तरदायी ने पूर्व के अनुरोधों में इस दावे का विस्तृत खंडन किया है। उत्तरदायी का पुनः यह कहना है कि अधिक व्याज भुगतान के कारण क्षति, घरेलू बिक्री में वृद्धि, कीमत दबाव/हास न होना और घरेलू उद्योग की अंतर्निहित कमियां जैसे अन्य कारक भी हैं जिनके कारण संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात और क्षति के दावे के बीच कारणात्मक संबंध में अवरोध आया है।
- (51) घरेलू उद्योग लगभग सभी आर्थिक मानदंडों पर काफी अच्छे ढंग से निष्पादन करने में सक्षम रहा है और इसीलिए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को किसी क्षति/वास्तविक मंदी, यदि कोई है, उपर्युक्त सूचीबद्ध कारकों के कारण है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण नहीं हो सकती।

86. मैसर्स एलजी केम. लि. कोरिया का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स डब्ल्यूटीसी तथा उसके व्यापारियों ने निम्नलिखित अनुरोध दायर किए:

उपर्युक्त प्रकटन विवरण के अनुसार, डीजीएडी ने एलजी केम. द्वारा निर्यातों के संबंध में 2.07 प्रतिशत पाटन मार्जिन निकाला है। हम ऐसे परिकलन के विरुद्ध अपनी चिंता प्रबल रूप से उठाते हैं। हमें दिए गए प्रकटन विवरण के गोपनीय रूपांतरण के अनुसार हम समझते हैं कि इतने अधिक पाटन मार्जिन एवं मूल्यांकन का मुख्य कारण डीजीएडी द्वारा एलजी केम. पर एसबीआर के उत्पादन की बहुत ही अधिक लागत अपनाया जाना है। हम निम्नलिखित रूप में उसका तालिका दे रहे हैं:

उत्पादन की लागत (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	1500 सीरीज	1700 सीरीज
एलजी केम. द्वारा किए गए दावे के रूप में	***	***
प्रकटन विवरण में डीजीएडी द्वारा कंसीडर किए गए के रूप में	***	***

हम समझते हैं कि डीजीएडी ने कुछ स्वैच्छिक/काल्पनिक परिसर के आधार पर बीडी और एसएम की कीमत इस्तेमाल की है न कि एलजी केम. द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक लागत आंकड़ों के आधार पर तथा कोरिया में एलजी केम. के परिसरों में अधिकारियों के दल द्वारा विधिवत सत्यापित आंकड़ों के आधार पर।

एसबीआर के विनिर्माण के लिए दो मुख्य कच्ची सामग्री यथा बूटाडीन और एसएम हैं। अनुरोध है कि एलजी केम. एसबीआर के विनिर्माण के लिए एलजी केम. के संयंत्र के अगले दरवाजे पर स्थित अपने संयंत्र में लोटे केमिकल से दोनों कच्ची सामग्रियां ले रहा है। दोनों एलजी केम. और लोटे केमिकल असंबद्ध कंपनियां हैं। एलजी केम. और लोटे केमिकल की वेबसाइट से लिए गए स्क्रीन शॉट उनका पिछला इतिहास दर्शाते हुए संलग्न है। यह इस बात के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण है कि दोनों कच्ची सामग्रियों, बीडी और एसएम की कीमत कम करने के लिए लोटे केमिकल और एलजी केम. के बीच कोई प्रतिपूरक व्यवस्था नहीं है।

एलजी केम. (पूर्व में जिसका नाम एलजी डेसन युहवा था) और लोटे केमिकल (पूर्व में जिसका नाम होनम डेसन युहवा था) दोनों असंबद्ध कंपनियां हैं तथा उन्होंने लोटे केमिकल (पूर्व में जिसका नाम होनम डेसन युहवा था) द्वारा विनिर्मित कई मदों/उत्पादों की खरीद के लिए 2005 में काफी पहले एक दीर्घावधि करार किया था। इस करार की प्रति यहां संलग्न है (उसकी प्रति स्थल सत्यापन के दौरान जांच दल को दी गई थी)। लोटे केमिकल द्वारा एलजी केम. को बीडी की बिक्री एक फॉर्मूला के आधार पर की जाती है।

यह अनुरोध है कि डीजीएडी यह कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कच्ची सामग्री की खरीद कीमत इस कारण अविश्वसनीय है कि स्थान के लाभ के कारण वह अन्य से कम है। लोटे केमिकल और केकेपीसी के बीच बीडी और एसएम की कीमत में अंतर ज्यादा यातायात के कारण है। कृपया यह देखा जाए कि बीडी की परिवहन लागत बहुत अधिक है। बीडी एक उच्च ज्वलनशील उत्पाद है और इसीलिए उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष टैंकरों तथा सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

प्रतिभागी निर्यातक की लागत में परिवर्तन, जो कि विधिवत रूप से सत्यापित किया गया था, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 और अनुच्छेद 2.2.1.1 का उल्लंघन है:

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 में उल्लेख है कि: "इस सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागत तत्व सामान्य रूप से जांच के तहत आने वाले निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि वे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं और वे रिकार्ड विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागत को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं।"

पैरा 2 के प्रयोजन के लिए लागत सामान्य रूप से जांच के तहत आने वाले निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर परिकलित की जाएगी, बशर्ते कि वे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित लागत को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं।

इस मुद्दे का अपीलीय निकाय द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या डब्ल्यूटी/डीएस 473/एबी/आर, दिनांक 06 अक्तूबर, 2016 में विधिवत रूप से समाधान किया गया है (अर्जेंटीना से बायो डीजल के संबंध में यूरोपीय संघ – पाटनरोधी उपाय)।

अपीलीय प्राधिकारी की रिपोर्ट के पैरा 6.41 में यह उल्लेख है कि "हम पैनल रिपोर्ट के यूरोपीय संघ की रीडिंग को नहीं लेते हैं। हम नोट करते हैं कि पैनल में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के पहले वाक्य में दूसरी शर्त की यह अपेक्षा है कि उत्पादक के अथवा निर्यातक के रिकार्डों में लागत और उस उत्पादक अथवा निर्यातक द्वारा लगाई गई लागत के बीच तुलना की जाए। पैनल ने इस बात पर जोर दिया है कि "तुलना का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि क्या रिकार्ड पर्याप्त रूप से वास्तव में लगाई गई लागत को दर्शाते हैं और यह नहीं कि क्या वे किसी काल्पनिक लागत को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं जो कि विभिन्न शर्तों अथवा परिस्थितियों के तहत की गई हो और जिसे जांचकर्ता प्राधिकारी वास्तव में लगाई गई लागत से पर्याप्त रूप से अधिक मानता हो।" इस संबंध में पैनल ने यह स्पष्ट किया है कि इस शब्द को समझने का मतलब यह नहीं है कि "जो भी उत्पादक अथवा निर्यातक के रिकार्ड में रिकार्ड किया गया है, वह स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए।" पैनल ने एक जांचकर्ता प्राधिकारी "उत्पादकों/निर्यातकों के रिकार्डों में रिकार्ड की गई लागत की विश्वसनीयता तथा परिशुद्धता की जांच करने के लिए निश्चित रूप से विशेष रूप से यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या लगाई गई सभी लागतें ली गई हैं; क्या लगाई गई लागतें अधिक थीं अथवा कम बताई गई थीं; और क्या दूर के लेन-देनों अथवा अन्य परिपाटियों से सूचित की गई लागतों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।" पैनल ने यह भी उल्लेख किया है कि "अनुच्छेद 2.2.1.1 सूचित की गई लागतों की 'उपयुक्तता' की जांच में शामिल नहीं है, जब उत्पादक अथवा निर्यातक के रिकार्डों में रिकार्ड की गई वास्तविक लागतें सही और निष्ठापूर्वक होने के लिए स्वीकार्य सीमाओं के भीतर अन्यथा पाई जाएं।" इन विवरणों के आलोक में हम अनुच्छेद 2.2.1.1 के पैनल की व्याख्या को यूरोपीय संघ के तर्क के सुझाव की अपेक्षा अधिक मानते हैं।"

अपीलीय निकाय के उपर्युक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि यदि दावा की गई कीमत संबंधित कंपनी के लागत रिकार्ड में पर्याप्त रूप से दर्शाई गई है तो जांचकर्ता प्राधिकारी लागत को रद्द नहीं कर सकते और कोई अन्य लागत स्वैच्छिक रूप से नहीं अपना सकते। यह अनुरोध है कि एलजी केम. के सभी लागत आंकड़े सियोल, कोरिया जनवादी गणराज्य में एलजी केम. के परिसरों में सत्यापन के दौरान अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किए गए थे।

एलजी केम. द्वारा दावा की गई लागत कंपनी के रिकार्ड के अनुसार रखे गए रिकार्ड द्वारा विगत रूप से समर्थित थी। सत्यापन दल ने कंपनी की एसएपी प्रणाली की भी पूरी तरह से जांच की और सत्यापन प्रदर्शों के रूप में सभी आवश्यक रिकार्डों की प्रक्रियाएं एकत्रिक कीं।

एलजी केम. ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में एसबीआर के उत्पादन की लागत वास्तविक और सही सूचित की है तथा सत्यापन दल ने भी उसे विधिवत रूप से सत्यापित किया है।

- एलजी केम. द्वारा दावा की गई लागत, उत्पादन लागत को उपयुक्त रूप से दर्शाती है तथा संबंध के कारण अथवा अन्यथा आपूर्तिकर्ता से कच्ची सामग्री लेने के कारण तोड़ी मरोड़ी नहीं गई है।
- सभी बहीखाते एलजी केम. द्वारा कोरियाई जीएएपी के अनुसार रखे जाते हैं।
- एलजी केम. द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत में कोई संशोधन तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापित संशोधन विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के उल्लंघन में है।
- व्यापार परीक्षण के सामान्य कार्यक्रम के लिए आवेदन करने हेतु डीजीएडी जांचकर्ता दल द्वारा सत्यापित किए गए, रखे गए और सूचित किए गए रिकार्ड के आधार पर एसबीआर की उत्पादन लागत लेगा।
- लोटे केमिकल से लिए गए बीडी और एसएम की लागत स्थान संबंधी लाभ के कारण बहुत कम है।
- लोटे केमिकल, एलजी केम. के संयंत्र के आगे है जहां एसबीआर का विनिर्माण किया जाता है। लोटे केमिकल्स से लिए गए बीडी और एसएम के परिवहन के लिए कोई परिवहन लागत नहीं है।
- यदि परिवहन लागत के निमित्त समायोजन किया जाता है तो लोटे केमिकल से बीडी और एसएम की कीमतें कोरिया जनवादी गणराज्य में अन्य कंपनियों के लगभग समान होंगी।
- बीडी और एसएम की कीमतें अपनाते समय, जैसा कि दर्शाया गया है और कोरिया जनवादी गणराज्य में एसबीआर के अन्य उत्पादकों द्वारा दावा किया गया है, परिवहन लागत के लिए विधिवत रूप से उसे समायोजित किया जाएगा, जो कि लोटे केमिकल से ली गई सामग्री के लिए लागू नहीं है।

87. मैसर्स केकेपीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन, सिंथस ग्रुप, मैसर्स ऋषिरूप पॉलीमर्स प्रा. लि. और मैसर्स ऋषिरूप लि. ने विभिन्न अनुरोध निम्नलिखित रूप में दायर किए थे:

वास्तविक मंदी से संबंधित जांच की अवैधता:

- केकेपीसी ने अनुरोध किया है कि संबद्ध कार्रवाई अवैध है क्योंकि सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ख में घरेलू उद्योग की वास्तविक मंदी से संबंधित निर्धारण अथवा जांच करने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं है। वर्तमान कार्रवाई में केकेपीसी की प्रतिभागिता उसकी अवैधता के संबंध में उनकी स्थिति के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।
- केकेपीसी ने अनुरोध किया कि चूंकि, "क्षति" और "घरेलू उद्योग" को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, अतः उनके अभिप्राय की कठोरता से व्याख्या की जानी चाहिए, जैसा कि टैक्स संबंधी नियमों के नियम मानदंड हैं।
- केकेपीसी ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच करने के लिए डीजीएडी का प्राधिकार उप प्रत्यावेदन की अवैध कार्रवाई का परिणाम है और उसे वैध कार्रवाई नहीं माना जा सकता।

केकेपीसी के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का परिकलन:

- केकेपीसी ने दिनांक 15 जून, 2017 के प्रकटन विवरण के साथ केकेपीसी के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के परिकलन से संबंधित गोपनीय अनुबंध प्राप्त किया।
- केकेपीसी ने दावा किया है कि प्राधिकारी को परिशिष्ट-8ख में केकेपीसी द्वारा सूचित की गई वास्तविक लागत को नकारना नहीं चाहिए था और अनुरोध किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उसे स्वीकार करेगा। केकेपीसी ने अनुरोध किया कि ईक्यूआर में उसके आंकड़े वास्तविक लागत पर आधारित थे और डीजीएडी के जांच दल ने उनका विधिवत सत्यापन किया था।

प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है।

- केकेपीसी ने दावा किया कि किसी उद्योग की स्थापना को (i) वास्तविक क्षति, (ii) वास्तविक क्षति के खतरे और (iii) वास्तविक मंदी का दावा साथ-साथ करना याचिकाकर्ताओं के लिए यह संभव, वैधानिक नहीं है। जैसा कि मानक पारस्परिक रूप से विशिष्ट है।
- अनुरोध है कि इन मानकों पर विचार समान अथवा परस्पर परिवर्तनीय के रूप में गैर मौजूद कानूनी प्रावधान बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ख1(ख) का उल्लेख करते हुए केकेपीसी ने दावा किया है कि तीन क्षति आधारों के बीच "अथवा" क्षति का प्रयोग भेदभावपूर्ण, पृथक् वैधानिक आधारों का संकेत देते हैं। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी "अथवा" को "और" नहीं बढ़ा सकते।
- केकेपीसी का तर्क है कि आईएसआरपीएल के लिए वास्तविक क्षति और आरआईएल की स्थापना को वास्तविक मंदी के आधारों पर क्षति विश्लेषण को अलग-अलग करना संभव नहीं है। यह इस कारण से है क्योंकि वास्तविक क्षति की मौजूदगी वास्तविक मंदी की मौजूदगी से अलग है, जैसा कि वह एक "स्थापित" उद्योग की मौजूदगी को मानता है। केकेपीसी ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को चाहिए कि वे एकल घरेलू उद्योग (डीआई) निर्धारित करें तथा क्या घरेलू उद्योग समग्र रूप से स्थापित है अथवा नहीं। केकेपीसी इस संबंध में प्राधिकारी के विश्लेषण की मांग करता है कि क्या यह संभव है कि एक स्थापित बाजार में नया प्रवेशक वास्तविक मंदी का दावा कर सकता है।
- केकेपीसी ने दावा किया कि वर्तमान जांच करना गैर कानूनी है क्योंकि उसके लिए कोई वैधानिक दिशा निर्देश नहीं है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (i) और (vii) में क्रमशः क्षति तथा वास्तविक क्षति के खतरे के निर्धारण के लिए सिद्धांतों का प्रावधान है। तथापि, वास्तविक मंदी के निर्धारण के लिए ऐसे कोई सिद्धांत नहीं हैं।
- केकेपीसी ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी के अलग-अलग किए गए विश्लेषण से वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी, दोनों के लिए जांच करके एक ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति बन गई है कि एक अवधारणा है कि उद्योग एक ही समय में स्थापित तथा गैर स्थापित दोनों हैं।

आईएसआरपीएल के संबंध में प्राधिकारी का वास्तविक क्षति विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है।

- प्राधिकारी आईएसआरपीएल के लिए अपने वास्तविक क्षति विश्लेषण में आरआईएल से संबंधित उत्पादन तथा आपूर्ति के आंकड़ों की उपेक्षा नहीं कर पाए हैं। उसने आरआईएल के आंकड़ों को शामिल किए जाने के कई उदाहरणों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए, प्राधिकारी की विचाराधीन क्षमता बहुत अधिक 2,61,000 एमटीपीए है जो कि याचिकाकर्ताओं की संयंत्र क्षमता है।
- कोई मात्रात्मक क्षति नहीं है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात मात्रा 2014-15 तथा जांच की अवधि के बीच कुल मिलाकर घटी है और भारतीय उत्पादन तथा उपभोग की तुलना में भी घटी है। केकेपीसी ने यह भी अनुरोध किया है कि "कुल

आयातों के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयात काफी रहे हैं" जो पाटनरोधी नियमावली के तहत विश्लेषण के लिए मानदंड नहीं हैं।

- आईएसआरपीएल ने काफी बाजार हिस्सा लिया है तथा अकेले ही एक उत्पादन वर्ष के अंत में अर्थात् जांच की अवधि में बाजार हिस्से का 29 प्रतिशत लिया है। इस प्रकार, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि "घरेलू उद्योग का निष्पादन काफी नहीं है" आधारहीन है। केकेपीसी ने यह भी नोट किया है कि जांच की अवधि के बाद 6 माह के भीतर घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 51 प्रतिशत तक बढ़ गया।
- "कीमत कटौती" के बारे में दिग्भ्रमित किया गया है और प्राधिकारी से अनुरोध है कि उन कारणों को रिकार्ड करें जिनसे जांच की अवधि की एक तिमाही में संबद्ध देशों से कीमत कटौती का एक उदाहरण निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार है कि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां संबद्ध देशों के मूल के संबद्ध सामान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम कीमतों पर भारतीय बाजार में आयात किए गए हैं।
- केकेपीसी ने यह भी दावा किया है कि प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि "नकारात्मक कीमत कटौती यह दर्शाती है कि उद्योग ने बाजार में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए आयात कीमतों के समान आक्रामक रूप से अपनी कीमतें रखी हैं" स्वैच्छिक है क्योंकि कटौती करने का नकारात्मक मार्जिन महत्वपूर्ण है, यह सिद्ध करने के लिए कि घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध देशों की आयात कीमतों से 20-30 प्रतिशत कम थीं। केकेपीसी ने इंडियन स्पिनर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2004 (170) ईएलटी 144 (ट्राई. – डेल.)] का उल्लेख भी किया है जिसमें सेसटेट ने नोट किया है कि कथित रूप से पाटित आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतें लगभग 11 प्रतिशत अधिक होने के नाते वह दोनों की स्वतंत्रता सिद्ध करता है। केकेपीसी ने यह भी अनुरोध किया कि नकारात्मक कटौती केवल यह सिद्ध करती है कि आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक हैं और अकेले कीमत कटौती के विश्लेषण से कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
- प्राधिकारी के कीमत कटौती विश्लेषण के संबंध में केकेपीसी ने अनुरोध किया कि क्षति मार्जिन के परिकलन के बाद क्षति संबंधी निष्कर्ष निकालने चाहिए। यह क्षति का मूल्यांकन करने के लिए एक "कारक" नहीं है। इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के निरमा लि. बनाम भारत संघ में निर्णय [विशेष सिविल आवेदन संख्या 16426/2016 और 16427/2016] का उल्लेख किया है। केकेपीसी ने "घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक" की जांच के संबंध में भी इस मुद्दे को उठाया है।
- केकेपीसी ने याचिकाकर्ताओं को क्षति के कारक के रूप में याचिकाकर्ताओं के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया है, जैसा कि यह सिद्ध है कि आरआईएल की बिक्री लागत आईएसआरपीएल की बिक्री लागत से काफी कम है। आईएसआरपीएल को क्षति आरआईएल की कम बिक्री कीमत के कारण होती है। केकेपीसी ने उन "अन्य कारकों" से संबंधित अपने अनुरोध भी किए हैं जिनके कारण क्षति हुई है। हम केकेपीसी के अनुरोध को नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को क्षति निम्नलिखित कारणों से हुई है:
  - अंतिम प्रयोक्ता/क्रिता से उत्पाद अनुमोदन का अभाव तथा घरेलू उद्योग में आपूर्ति करने की प्रणाली असमर्थता।
  - आरआईएल द्वारा कम कीमतों पर की गई ऑफ ग्रेड बिक्री।
  - योजना चरण (जब बाजार अपूर्वानुमानित उभार का अनुभव कर रहा था तथा बहुत आशावादी था) और आरंभ करने के चरण (जब बाजार खराब हो गया और कच्ची सामग्री की कीमतें लगभग आधी हो गईं जिससे अंतिम उत्पाद कीमतों में गिरावट आ गई) के बीच बाजार स्थितियों में परिवर्तन।
  - उत्तरी भारत में स्थित आईएसआरपीएल की स्थान संबंधी हानि जबकि मुख्य उपभोक्ता पश्चिम तथा दक्षिण भारत में है।
  - याचिकाकर्ता – आईएसआरपीएल द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचीबद्ध कारक, यथा, आईएसआरपीएल की परियोजना के कार्यान्वयन में काफी लागत बढ़ जाना, वाणिज्यिक उत्पादन का देरी से आरंभ होना, प्राकृतिक रबर की कीमतों में काफी गिरावट, जिससे एसबीआर की कीमत और बिक्री प्रभावित हुई है।
  - याचिकाकर्ता – आरआईएल द्वारा अपनी निवेशक संबंधी दस्तावेजों में सूचीबद्ध कारक, यथा, नई क्षमता अभिवृद्धि और एसबीआर के लिए कमजोर मांग।
  - कोरिया और एशियन (थाइलैंड) के साथ एफटीए का प्रभाव। सीमा शुल्क में कमी करने से इन देशों से पहुँच मूल्य में परिणामी गिरावट आई है और उसे क्षति पर विचार करते हुए विधिवत रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

आरआईएल के संबंध में प्राधिकारी का वास्तविक मंदी विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है।

- प्राधिकारी ने वास्तविक मंदी विश्लेषण के लिए आधार के रूप में प्राधिकारी का डब्ल्यूटीओ प्रस्ताव पर विश्वास करना पूर्णतः अनुचित है, जैसा कि डब्ल्यूटीओ वार्ताएं सदस्यों में असहमति के कारण रुक गई हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि उल्लिखित प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ में भारत की स्थिति नहीं दर्शा सकता और उसमें बातचीत की प्रक्रिया दब जाएगी।

- केकेपीसी ने दावा किया है कि यदि आरआईएल को क्षति हुई है तो वह एसबीआर के उद्योग – ग्राहक की सख्ती तथा लंबी अनुमोदन प्रक्रिया में उच्च प्रवेशक बाधाओं के कारण है।
- आरआईएल की क्षति व्यापक नहीं है, जैसा कि आरआईएल का बिक्री लागत 82 प्रतिशत तक घटी है जबकि बिक्री कीमत केवल 32 प्रतिशत तक घटी है। समवर्ती रूप से, संबद्ध देश से आयात भी काफी घटा है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की कीमतों और लाभप्रदता संबद्ध देशों से आयातों की अलग-अलग है और आरआईएल को भी क्षति के संबंध में सहसंबंध स्थापित नहीं किया गया है।
- अन्य ज्ञात कारकों के कारण हुई क्षति, जैसे परस्पर घरेलू प्रतिस्पर्धा, कच्ची सामग्री की घटती हुई कीमतें, ऑटो क्षेत्र में दबी हुई मांग, प्रयोक्ता उद्योग द्वारा उत्पाद अनुमोदन का अभाव आदि को अलग-अलग किया जाना चाहिए और प्राधिकारी के विश्लेषण से हटा दिया जाना चाहिए।

प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से तथाकथित रूप से पाटित आयातों तथा याचिकाकर्ताओं को हुई तथाकथित क्षति के बीच साफ एवं बेदाग कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किए हैं।

- केकेपीसी ने अनुरोध किया है कि "पाटित आयातों के अलावा कोई ज्ञात कारक" का विश्लेषण नहीं किया गया है। यह बात दोहराई गई थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अन्य ज्ञात कारकों के कारण हुई क्षति तथाकथित रूप से पाटित आयातों से हुई क्षति के कारण नहीं हुई है, प्राधिकारी को चाहिए कि वे आवश्यक रूप से प्रत्येक कारक के कारण हुई क्षति को अलग एवं पृथक् करें तथा उसे याचिकाकर्ताओं को हुई समग्र क्षति से हटाएं।
- याचिकाकर्ताओं की निर्यात बिक्री के संबंध में प्राधिकारी की टिप्पणी पूर्ण नहीं है। यह अनुरोध किया गया था कि प्राधिकारी यह नोट करने में विफल रहे हैं कि निर्यात बाजार निष्पादन से संबंधित मानदंडों यथा लाभप्रदता और नकद लाभ/हानि को पूरी तरह अलग कर दिया गया है। इस संबंध में यह बात दोहराई गई थी कि याचिकाकर्ता आरआईएल ने निर्यात बाजार में ऑफ ग्रेड उत्पादों की बिक्री काफी हानियों पर की थी और उससे उसकी लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा है।
- "(छ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बिक्री किए गए अन्य उत्पादों का निष्पादन" के तहत विश्लेषण में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों की वित्तीय स्थिति का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए था। यह अनुरोध किया गया था कि चूंकि, आरआईएल एक पिछड़ा हुआ एकीकृत एकक है और वह कई पैट्रो केमिकल उत्पादों का उत्पादन करता है, अतः एसबीआर उत्पादन तक के प्रत्येक माध्यमिक स्तर पर उसकी अंतरण कीमत इस शीर्ष के तहत विश्लेषण में कारक बनाई जानी चाहिए।
- केकेपीसी ने अनुरोध किया कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण समुचित रूप से नहीं किया गया है। उसने अलग-अलग रूप से प्रत्येक आधार का विश्लेषण किया, यथा उत्पादन के दबाव को सिद्ध करने वाले जांच की अवधि के बाद के आंकड़े, क्षमता उपयोग में इष्टतम न होने के प्रमाण देने वाले जांच की अवधि के बाद के आंकड़े, कीमत कटौती को सिद्ध करने वाले जांच की अवधि के बाद के आंकड़े तथा समग्र कीमत दबाव/ह्रास।

गैर क्षतिकारक कीमत परिकलनों पर पुनः विचार किए जाने की जरूरत है।

- केकेपीसी ने प्राधिकारी के एनआईपी परिकलन के संबंध में कतिपय मुद्दे उठाए हैं। ये निम्नलिखित हैं:
  - आरआईएल की तरह एक नए प्रवेशक के लिए एक स्थापित उद्योग आईएसआरपीएल के लिए परिकलित गैर क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) का प्रयोग करने की अर्धक्षमता।
  - "कच्ची सामग्री लागत" और "यूटिलिटी लागत" के संबंध में प्राधिकारी "जांच की अवधि की विभिन्न तिमाहियों अथवा मानक उपभोग मानदंडों" ने घरेलू उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री/यूटिलिटियों की लागत के सर्वोत्तम प्राप्त मानदंडों के "अधिक" का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि "सर्वोत्तम प्राप्त मानदंड" न्यूनतम प्राप्त मूल्य को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, "मानक उपभोग मानदंड" का प्रयोग करने की अनुमति पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत नहीं है।
  - घरेलू उद्योग की गोपनीय परियोजना रिपोर्टों पर प्राधिकारी का विश्वास करना उचित नहीं है क्योंकि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद केकेपीसी को गैर गोपनीय सारांश नहीं दिया गया है।

प्रक्रिया तथा अत्यधिक गोपनीयता

- केकेपीसी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता और प्राधिकारी ने निम्नलिखित के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता बनाई।
  - याचिकाकर्ताओं की परियोजना रिपोर्टें
  - संस्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, मालसूची और निर्यात के संबंध में आईएसआरपीएल के आंकड़े
  - आरआईएल की मात्रा, मालसूची और कीमत मानदंड, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण पृष्ठ संख्या 55-56 में तालिका 12, 13, 14 और 15 प्रस्तुत की गई है।
- पाटनरोधी नियमावली में घरेलू उद्योग की परिभाषा समान वस्तुओं के सक्रिय उत्पादकों को ही दर्शाती है। आरआईएल जैसी कंपनी को शामिल करने के लिए कोई औचित्य नहीं है, जो कि कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं कर रही थी और जिसने जांच की अवधि के दौरान समान वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में कोई योगदान नहीं किया।

- प्राधिकारी उन उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के तहत शामिल नहीं कर सकते जिनका घरेलू उद्योग द्वारा इस समय विनिर्माण नहीं किया जा रहा है, जो स्थापित सेसटेट न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर है। इस प्रकार, 1739 और 1789 ग्रेडों को हटाने के दावे का पुनः विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी 1502 एनएफ (एनएफ का अर्थ है नाइट्रोसामिन फ्री जिसका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है), 1507, 1507 एच, 1745, 1763, 1769, 1789, 1793 और 1799 ग्रेडों को हटाने के लिए हमारे अनुरोधों पर विचार करने में भी विफल रहे हैं।
- विचाराधीन उत्पाद को सॉल्यूशन एसबीआर और स्टाइरिन - बुटाडीन - स्टाइरिन दोनों को हटाने के लिए परिभाषित किया जाना चाहिए।
- विचाराधीन आयात आंकड़ों के संबंध में उन्होंने स्टाइरिन बुटाडीन के रूपों के कतिपय लेन-देनों का उल्लेख किया था जो वर्तमान जांच में विचाराधीन नहीं हैं, परंतु याचिकाकर्ताओं द्वारा आयात आंकड़ों में शामिल किए गए थे।

प्राधिकारी ने आईएसआरपीएल और आरआईएल के लिए क्षति विश्लेषण को अनुचित रूप से "बांटा" है:

- प्रकटन विवरण के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आईएसआरपीएल एक स्थापित घरेलू उद्योग "वास्तविक क्षति" विश्लेषण में आता है तथा आरआईएल एक अविकसित घरेलू उद्योग "वास्तविक मंदी" विश्लेषण में आता है। तथापि, चूंकि, एकल घरेलू उद्योग पहचाना गया हो सकता है, अतः समग्र रूप से इस तरह के बंटवारे की अनुमति नहीं है।
- प्राधिकारी ने आईएसआरपीएल की तुलना में "वास्तविक क्षति" का विश्लेषण करने के लिए आरआईएल की क्षमता और मानदंडों को अनुचित रूप से शामिल किया है।
- "वास्तविक मंदी" विश्लेषण पूर्णतः डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव पर आधारित है और इस प्रकार दिग्भ्रमित है। प्राधिकारी ने निष्कर्ष स्वरूप आरआईएल और बाजार के जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के अपने विश्लेषण के आधार पर कोई "वास्तविक मंदी" सिद्ध नहीं की है। वस्तुतः जांच की अवधि के बाद के आंकड़े भारत में एसबीआर घरेलू उद्योग की सकारात्मक तस्वीर दर्शाते हैं।

याचिकाकर्ताओं को "वास्तविक क्षति" का कोई खतरा नहीं है।

- याचिकाकर्ताओं ने किसी उद्योग की स्थापना की (i) वास्तविक क्षति, (ii) वास्तविक खतरे और (iii) वास्तविक मंदी का साथ-साथ दावा किया है। तथापि, ये मानक परस्पर भिन्न हैं और साथ-साथ नहीं रह सकते।
- याचिकाकर्ताओं ने "वास्तविक क्षति के खतरे" का दावा किया है परंतु एडीए के अनुच्छेद 3.7 के संदर्भ में दावे को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोई तथ्यात्मक साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि खतरे पहले से देखे जा सकते हैं और आसन्न हैं। आयात की कीमतों से घरेलू कीमतों पर कोई कटौती अथवा दबाव नहीं आता है तथा आयात की मात्रा संबद्ध देशों से निरंतर कम हुई है (विशेष रूप से यूरोपीय संघ)।

याचिकाकर्ताओं को कोई "वास्तविक मंदी" नहीं हुई है।

- पाटनरोधी नियमावली में "वास्तविक मंदी" के मानक से संबंधित जांच करने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।
- याचिकाकर्ताओं ने "वास्तविक मंदी" के मानक को स्थापित करने के लिए डब्ल्यूटीओ के "प्रस्ताव" पर विश्वास किया है। ये प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ में वार्ता के परिणामों के अध्यधीन हैं और इनका कोई वैधानिक अथवा बाध्यकारी मूल्य नहीं है।
- अन्य क्षेत्राधिकार में स्थापित मानकों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को कोई "वास्तविक मंदी" नहीं हो रही है। "बाजार स्थिरीकरण" परीक्षण लागू करके (जापान से बेंजिल पेराबेन और जर्मनी से पीवीसी बैट्री कवर में उल्लिखितानुसार) याचिकाकर्ताओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उनके आंकड़ों से स्पष्ट "क्षति" सामान्य आरंभिक स्थितियों की केवल संकेतात्मक नहीं है अथवा यह कि उसका निष्पादन उससे बदतर है जो कि उच्च प्रवेशक बाधाओं वाले किसी उद्योग से उम्मीद की जा सकती है।
- जांच की अवधि के दौरान केवल आईएसआरपीएल संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन करता रहा है और वह 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर निष्पादन कर रहा था। प्रकटन विवरण के आधार पर हम नोट करते हैं कि आईएसआरपीएल ने जांच की अवधि में 30 प्रतिशत बाजार हिस्सा हासिल किया है। जांच की अवधि के बाद 6 माह के भीतर जब आरआईएल वाणिज्यिक उत्पादन में शामिल हुआ तो घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्से का 51 प्रतिशत प्राप्त किया।
- आईएसआरपीएल और आरआईएल दोनों ने क्रमशः 2013 और 2015 में क्षमताएं बढ़ाने के इरादे व्यक्त किए। यह स्थिति दर्शाती है कि एक बार जब याचिकाकर्ता स्थापित हो जाए तो क्षेत्र में लाभप्रदता की आशा है।

याचिकाकर्ताओं के आंकड़े कोई क्षति अथवा वास्तविक मंदी नहीं दर्शाते।

- याचिका में दिए गए आंकड़े और जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़े याचिकाकर्ताओं को कोई क्षति नहीं दर्शाते:
  - कोई कीमत क्षति नहीं है: कोई कीमत कटौती नहीं है (प्रकटन विवरण के अनुसार भी) तथा स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग की कीमतें आयात कीमतों से काफी कम हैं जो यह दर्शाता है कि कोई दबाव अथवा ह्रास नहीं है।
  - याचिकाकर्ताओं की हानियां और लागत एक घटती हुई प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं जो उनके उत्पादन और बिक्री का स्थिरीकरण दर्शाते हैं।
  - कोई मात्रात्मक क्षति नहीं है: आयात पूरे संदर्भों में तथा घरेलू उत्पादन और उपभोग की तुलना में कम हो रहे हैं।
  - याचिकाकर्ताओं की मालसूची एक घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है।
  - जांच की अवधि के बाद के आंकड़े घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा स्थिर बिक्री कीमतों को संयुक्त रूप में घटता हुआ दर्शाते हैं। क्षमता उपयोग, उत्पादन और बाजार हिस्सा भी सकारात्मक संकेतक हैं। याचिकाकर्ताओं को हुई हानियां भी जांच की अवधि की तुलना में नगण्य हो गई हैं।

संबद्ध देशों से आयात तथा याचिकाकर्ताओं की तथाकथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

- याचिकाकर्ताओं को यदि कोई क्षति हुई है तो वह संबद्ध देशों से आयातों के अलावा विभिन्न अन्य कारकों के कारण हुई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - अंतिम प्रयोक्ताओं से उत्पाद अनुमोदन का अभाव
  - आरआईएल द्वारा कम कीमतों पर संबद्ध सामानों के ऑफ ग्रेड की घाटे पर बिक्री करना
  - योजना चरण जब एसबीआर का बाजार आशावादी था और संयंत्र को शुरू करने का चरण जब एसबीआर का बाजार टूट गया था, दोनों के बीच बाजार स्थितियों में परिवर्तन।
  - आईएसआरपीएल की वार्षिक रिपोर्टों में सूचीबद्ध अन्य कारक:
    - आईएसआरपीएल द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में काफी कीमत बढ़ जाना
    - वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने में विलंब
    - प्राकृतिक रबर कीमतों में काफी गिरावट जिससे एसबीआर की कीमत और बिक्री प्रभावित हुई।
    - आईएसआरपीएल की स्थान संबंधी हानि, जिससे अंतर्देशीय भाड़े की लागत अधिक हो गई।
    - नई क्षमता अभिवृद्धि तथा एसबीआर के लिए कम मांग
    - याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाई गई आरंभिक लागत
  - यद्यपि विचाराधीन उत्पाद को स्पष्ट रूप से इमल्शन स्टाइरिन बुटाडीन रबर (ई-एसबीआर) के रूप में निर्धारित किया गया है। तथापि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आयात आंकड़ों में स्टाइरिन बुटाडीन के रूप शामिल किए गए हैं जो कि संबद्ध सामान नहीं हैं।
  - ई-एसबीआर 1739 और ई-एसबीआर 1789 को संबद्ध सामानों के क्षेत्र से हटा देना चाहिए क्योंकि इन ग्रेडों का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

88. मैसर्स बीएसटी एलस्टॉमर्स द्वारा दायर किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे एसबीआर 1712 कीमत का ही प्रयोग करते हुए थाइलैंड से भारत में एसबीआर 1700 सीरीज के पाटन मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करें जो कि सर्वोत्तम और सही तथ्य है क्योंकि बीएसटीई द्वारा जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यातित एसबीआर 1700 सीरीज के 95 प्रतिशत एसबीआर 1712 हैं।
- भारत में बीएसटीई का हिस्सा 5 प्रतिशत से कम था जिससे क्षति नहीं हो सकती।
- एसबीआर 1712 और 1500 दोनों के लिए हमारी घरेलू कीमत पर अतिरिक्त सूचना डब्ल्यूटीओ करार के अनुसार घरेलू बाजार का मूल्यांकन करने के लिए संलग्न की जा रही है।

- सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों का मूल्यांकन कैक्ट्री से बाहर के स्तर पर अर्थात् व्यापार के उसी स्तर पर किया जाए।

89. मैसर्स ट्रिसियो यूरोप जीएमबीएच का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स कंठ एंड एसोसिएट्स द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- मैसर्स ट्रिसियो ने यथा संभव आंकड़े प्रदान किए हैं और इसीलिए इसे गैर सहकारी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए बल्कि शेष श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

90. यूरोपिय आयोग द्वारा दायर किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

विश्लेषण की अवधि में मांग 40 प्रतिशत तक बढ़ी है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद 6 माह में मांग बढ़ती रही जो समग्र रूप से 47 प्रतिशत तक बढ़ी।

विश्लेषण की अवधि में संबद्ध देशों से आयात 26 प्रतिशत तक बढ़े हैं और इस प्रकार, घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में स्थापित होने तथा जांच की अवधि में उसका बाजार हिस्सा 29 प्रतिशत तक बढ़ाने दिया है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उसके बाद निरंतर बढ़ता रहा है तथा 51 प्रतिशत तक बढ़ने के लिए जांच की अवधि के बाद 6 माह में लगभग दोगुना हुआ है। ऐसी स्थितियों में आयोग यह नहीं समझ पा रहा है कि जांच प्राधिकारी इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्से में प्राप्ति महत्वपूर्ण नहीं है।

संबद्ध देशों से आयात पर नजदीकी से एक नजर डालने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य संबद्ध देशों के विपरीत यूरोपीय संघ के मूल आयात तुलनात्मक रूप से (8.753 मी. टन) और पूर्ण संदर्भ में (-11 प्रतिशत बिन्दु बाजार हिस्सा) दोनों में बढ़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपभोग काफी बढ़ा है, इससे यह प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के आयातों से विश्लेषण अवधि में घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ा है।

याचिकाकर्ता की स्थिति नए स्थापित उत्पादकों की स्थिति को दर्शाने वाले लगते हैं। वास्तव में याचिकाकर्ता अपने आरंभिक प्रचालनों से ही निरंतर अपनी उत्पादन मात्रा बढ़ाने में सक्षम रहा है। घरेलू बाजार पर बिक्री की मात्रा भी एक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है जिसने दो वर्ष के एक बहुत ही छोटी सी अवधि में घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को केवल खपत में वृद्धि से ही लाभ नहीं हुआ, उसे यूरोपीय संघ जैसे पुराने ऐतिहासिक व्यापारियों के हानिकारक हिस्से में बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार हिस्सा भी लिया है।

जहां तक कारणात्मक संपर्क का संबंध है, आयोग यह नहीं देख पाया है कि संबद्ध देशों तथा विशेषकर यूरोपीय संघ से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति कैसे हो सकती है। जांच से सिद्ध हुआ है कि संबद्ध देशों से आयातों से विश्लेषण की अवधि में 10 प्रतिशत बाजार हिस्से की क्षति हुई है और यदि इस अवधि को जांच की अवधि के बाद के 6 माह तक बढ़ाया जाए तो 45 प्रतिशत तक भी क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात भी पूर्ण संदर्भ में कम हुए हैं जबकि खपत 40 प्रतिशत तक बढ़ी है। संबद्ध देशों के लिए बाजार हिस्से में कमी घरेलू उद्योग के संपूर्ण लाभ के कारण हुई है।

ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति निरंतर सुधर रही है और उद्योग की स्थापना में किसी भी तरह से मंदी नहीं हुई है। वास्तव में उत्पादन एवं बिक्री निरंतर बढ़ी है तथा घरेलू उद्योग जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद 6 माह के बीच अपनी घरेलू बिक्री दोगुनी कर पाया है। बाद की अवधि घरेलू बाजार पर दूसरे उत्पादक की वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरुआत के समरूप है। यह तथ्य अपने आप में यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की स्थापना में मंदी नहीं हुई थी।

आयोग नोट करता है कि वास्तविक मंदी के संबंध में अपने मूल्यांकन को निर्देशित करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी ने एडीए के प्रस्तावित संशोधनों पर विश्वास किया है। जैसा कि जांचकर्ता प्राधिकारी सही-सही उल्लेख करते हैं और जैसा कि आयोग ने इस कार्रवाई को आरंभ करने के बाद अपने अनुरोध में इंगित किया था, ये प्रस्तावित संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। इसके विपरीत, डब्ल्यूटीओ एडीए का अनुच्छेद 3.4 इस कार्रवाई में लागू है तथा आर्थिक कारक और यह तथ्य कि सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए उनकी सूची का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए था।

91. ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- 1) मुद्दे के तहत जारी प्रकटीकरण विवरण के संबंध में, हम निवेदन करते हैं कि यह इस जांच के दौरान हमारी ओर से किए गए निवेदनों पर विचार नहीं करता। वर्तमान टिप्पणियों में इस जांच के दौरान किए गए सभी निवेदनों को हमने अपनाया है और अनुरोध करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तदनुसार परिणाम दिए जाएं।
- (2) वर्तमान टिप्पणियां 10 जुलाई, 2017 को प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण से संबंधित मुद्दों तक सीमित है। संक्षिप्तता के लिए इस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हमारे निवेदन हमारे लिखित निवेदनों में अंतर्निहित हैं और प्रत्युत्तर निवेदनों को दुबारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है; हालांकि इसे इन टिप्पणियों का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए।
- (3) प्राधिकारी द्वारा वर्तमान मामले में क्षति विश्लेषण को विभाजित कर दिया गया प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने विचार किया है कि एक सकल घरेलू उद्योग के स्थान पर भारतीय उद्योग में प्रत्येक उत्पादक पर घरेलू उद्योग का क्षति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पृथक-पृथक विचार किया जा सकता है।
- (4) हमने देखा है कि हमारे निवेदनों की प्राधिकारी के निर्धारणों में पूरी तरह से अनदेखी की गई है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट करने में पूरी तरह से अनदेखी की गई है। प्राधिकारी यह नोट करने में असफल रहे हैं कि आई एस आर पी एल और आर आई एल की स्थितियों को और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के लिए घरेलू उद्योग के पास उत्पादन अनुमोदनों की कमी को देखते हुए, सामग्री की कमी का दावा करने वाला वर्तमान मामला समय से बहुत पहले किया गया है। वास्तव में, जांच अवधि के बाद की अवधि के संबंध में प्राधिकारी के स्वयं के आंकड़े भी इस दावे का स्पष्ट साक्ष्य सहित समर्थन देते हैं। हम प्राधिकारी से वर्तमान जांच को आरंभ करने के औचित्य पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं।

- (5) किसी भी स्थिति में, हम एक "स्थापित" घरेलू उद्योग के रूप में आई एस आर पी एल के लिए विचार करने हेतु भारतीय बाजार में प्रथम प्रवेशक हैं और समान घरेलू उद्योग आर आई एल को "अस्थापित" के रूप में विचार करेंगे, जो आई एस आर पी एल के एक से भी अधिक वर्ष के पश्चात उत्पादन में प्रवेश करने वाला और वाणिज्यिक निष्पादन प्राप्त करने वाला एक अन्य उत्पादक है, के लिए "सामग्री क्षति" का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग के प्रतिभागियों पर व्यक्तिगत रूप से विचार करने को टालमटोल करने वाला तर्क समझते हैं। प्राधिकारी को ऐसे भेदभाव और निर्धारण का औचित्य बताना चाहिए। हम निवेदन करते हैं कि ऐसा निर्धारण गैर-कानूनी है और इसमें परिशोधन की आवश्यकता है।
- (6) प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण को दो भागों में विभाजित करने का दावा किया है-आई एस आर पी एल के लिए सामग्री क्षति का विश्लेषण और आर आई एल के लिए सामग्री की मंदी। हमारे प्राथमिक दावे के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कि ऐसा विभाजन कानूनी रूप से समर्थन योग्य नहीं है, हमने नोट किया है कि प्राधिकारी आर आई एल को उसके सामग्री क्षति विश्लेषण से बहिष्कृत करने में भी असफल रहे हैं। हमने नोट किया है कि संपूर्ण प्रकटीकरण टिप्पणियों में प्राधिकारी ने आई एस आर पी एल और आर आई एल दोनों की क्षमता को सामग्री क्षति के लिए अपने विश्लेषण में शामिल किया है। हम निवेदन करते हैं कि ऐसी विचारधारा का कोई आधार नहीं है। सामग्री क्षति पर विचार के लिए भारतीय उद्योग की कुल क्षमता में आर आई एल को शामिल किया जाना ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है जहां क्षमता उपयोग का अनुचित रूप से ह्रास किया गया है। यह इस कारण है कि जांच अवधि के दौरान, आर आई एल ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ नहीं किया था और इसकी क्षमता और उत्पादन दोनों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- (7) सामग्री क्षति विश्लेषण पर, चूंकि प्राधिकारी ने केवल आई एस आर पी एल के आंकड़ों पर विचार किया है, तब उन्हें अपने निर्णयों में अकेले आई एस आर पी एल का उल्लेख करना चाहिए, "घरेलू उद्योग" का संदर्भ देने के स्थान पर ऐसा श्रेणीकरण ही स्पष्ट करेगा कि क्या आई एस आर पी एल के आंकड़ों पर विचार किया जा रहा है या आर आई एल के अथवा दोनों के आंकड़ों पर विचार किया जा रहा है।
- (8) प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकारी द्वारा अत्यधिक गोपनीयता बरती गई है जो आंकड़ों को संपादित करने के जरिए प्रमाणित होता है, जिसे सामान्य रूप से हितवद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाता है। हम प्राधिकारी से ऐसे संपादन के लिए हमें मूलाधार उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं।
- (9) आई एस आर पी एल की सामग्री क्षति की विद्यमानता और जांच सामग्री की मंदी के पृथक विश्लेषण में बाधा डालती है। यह इस कारण है कि सामग्री क्षति की उपस्थिति/उपस्थिति की संभावना एक स्थापित उद्योग के अस्तित्व को मानती है। हम निवेदन करते हैं कि प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह स्थापित विधि सम्मत है कि क्या सामग्री मंदी के दावे का अस्तित्व हो सकता है जहां एक स्थापित उद्योग पहले ही विद्यमान हो। अन्यथा, विश्लेषण के पृथक्करण को, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। अमान्य किया जाना चाहिए।
- (10) प्राधिकारी का सामग्री मंदी के निर्धारण के प्रति "डब्ल्यूटीओ के प्रस्तावित संशोधन" पर प्राधिकारी का संदर्भ और विश्वास पूरी तरह से निराधार है और बिना किसी औचित्य के है। ऐसा विश्वास ऐसी जानकारी पर आधारित है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है और पूरी जांच के दौरान हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। हम अनुरोध करते हैं कि चाहे इसे आकर्षक मूल्य रखने वाला समझा जाए, ऐसी धारित रखे बिना डब्ल्यू टी ओ द्वारा किए गए प्रस्ताव को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि उल्लिखित प्रस्ताव डब्ल्यू टी ओ के समक्ष रखा गया भारत का प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में, डब्ल्यू टी ओ की बातचीत सदस्यों की राय में अतयधिक भिन्नता के कारण अब कुछ वर्षों के लिए रोक दी गई है। अतः प्राधिकारी को "डब्ल्यू टी ओ के समक्ष प्रस्ताव" पर आधारित भरोसे और तदनुसूची विश्लेषण का कोई आधार नहीं है।
- (11) इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति किए गए अभिसूचक आंकड़ों के आधार पर यह साक्षित है कि आर आई एल की बिक्री की लागत में 82 प्रतिशत कमी हुई है जबकि बिक्री की कीमत में केवल 32 प्रतिशत गिरावट आई है। यहां तक कि बिक्री की लागत के इसके आरंभिक मूल्य को पांचवा भाग हो जाने के साथ और बिक्री की कीमत में केवल 30 प्रतिशत गिरावट आने के बाद भी, याचिकाकर्ता (आर आई एल) अभी भी महत्वपूर्ण क्षति का सामना कर रहा है। परिणामस्वरूप, संबद्ध देश से आयातों में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है। अतः हम निवेदन करते हैं कि प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की कीमतों और लाभप्रदता और संबद्ध देशों से आयातों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। हम निवेदन करते हैं कि आर आई एल द्वारा सामना की जा रही क्षति से संबंधित परस्पर संबंध को प्राधिकारी द्वारा स्थापित नहीं किया गया।
- (12) कारणात्मक संबंध के विश्लेषण में, प्राधिकारी ने "पाटित आयातों के अतिरिक्त, कोई ज्ञात कारक" को विश्लेषित करने की अपेक्षा की है, जबकि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा इनमें से कई को सूचीबद्ध किया गया है। हम दोहराते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अन्य ज्ञात कारकों के कारण हुई क्षति कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के कारण नहीं हुई है, प्राधिकारी

को प्रत्येक कारक के कारण हुई क्षति को अनिवार्य रूप से पृथक और वियोजित करना चाहिए और इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई जा रही समग्र क्षति से अलग करना चाहिए।

- (13) इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं के वित्तीय रिकॉर्डों जैसे वार्षिक रिपोर्टों और निवेशक के प्रतिपादनों में सूचीबद्ध याचिकाकर्ताओं को क्षति का कारण बनने वाले अन्य कारकों का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। हम निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्ट उठाई जा रही क्षति के कारण के रूप में आयातों के अतिरिक्त अन्य कारण उपलब्ध कराती है, तो प्राधिकारी को इसके मूल्य पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए। याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्टें महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो याचिकाकर्ता की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है और इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस संबंध में हम आंध्र पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी {(2006) 201 ईएलटी 481} का आश्रय लेते हैं जिसमें यह धारित किया गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों को ध्यान में रखना चाहिए, जहां अपेक्षित क्षति आयातों के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से है। सेस्टेट का यह जांच परिणाम इसमें प्राधिकारी पर बाध्यकारी है।

- (14) हम निवेदन करते हैं कि प्राधिकारी का निष्कर्ष, जैसा कि प्रकटीकरण विवरण में अंतर्निहित है, निराधार है और पुनः विचार किए जाने योग्य है। पूर्वानुमान और जांच अवधि के बाद की अवधि में घटे हुए आयातों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ों से कोई कारणात्मक संबंध या उससे कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम प्राधिकारी से पूर्वानुमान निवेदनों के प्रकाश में उनके समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों का पुनः विश्लेषण करने का अनुरोध करते हैं।

- (15) प्रकटीकरण विवरण के प्राधिकारी के अनुबंध-4 के संबंध में, हम निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हैं :-

क. प्राधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि एक स्थापित उद्योग-आई एस आर पी एल के लिए परिकल्पित एक गैर-क्षतिकारक कीमत (एन आई पी) को आर आई एल जैसे एक अस्थापित, नए प्रवेशक के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

ख. “कच्ची सामग्री की लागत” और “उपयोगिता की लागत” के संबंध में प्राधिकारी के विचारों के संबंध में (प्रकटीकरण विवरण के पृष्ठ-61 पर), प्राधिकारी ने जांच अवधि की विभिन्न तिमाहियों में या मानक उपभोग मानदंडों, जो भी उच्च हों, को जांच अवधि दरों पर घरेलू उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम प्राप्त मानदंडों/उपयोगिताओं की लागत पर विचारित किया है। इस संबंध में हम निवेदन करते हैं कि “उच्चतर” मूल्य पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। हम निवेदन करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली में “सर्वोत्तम प्राप्त मानदंडों” के प्रयोग के लिए व्यवस्था की गई है और वह अनिवार्य रूप से निम्नतम उपभोग मानदंडों को समाविष्ट करते हैं। इस प्रकार, “उच्चतर” मानदंडों का विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-111 के भाव और अभिप्राय से विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, “मानक उपभोग मानदंड” पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्राधिकारी यहां विचार-विमर्श के तहत मानक उपभोग मानदंडों को साझा करने में भी असफल रहे हैं।

ग. “उत्पादन” के अंतर्गत, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्टों का सहारा लिया है। हम याचिकाकर्ताओं की परियोजना रिपोर्टों की अविश्वसनीयता के संबंध में हमारे निवेदन को दोहराते हैं, जैसा कि हमारे लिखित निवेदन में व्यक्त किया गया है। हम दोहराते हैं कि हम निवेदन करते हैं कि इसके अगोपनीय रूपांतरण को हमारे साथ साझा किया जाना चाहिए। हम यह भी निवेदन करते हैं कि ऐसे प्रावधान और टिप्पणी करने के अवसर के बिना, इस पर प्राधिकारी का भरोसा गैर-कानूनी है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

घ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए नियोजित पूंजी पर आय की दर से संबंधित हमारे निवेदनों का उल्लेख नहीं किया है। हम दोहराते हैं कि अपना संयंत्र आरंभ करते समय, आई एस पी आर एल ने एल आई बी ओ आर +72 प्रतिशत की व्याज दर पर, जो लगभग 2.5 प्रतिशत है, विदेशी मुद्रा में एक दीर्घावधिक ऋण सुरक्षित किया है। यहां यह निवेदन किया जाता है कि चाहे यदि वापसी की ऐतिहासिक दर की उपेक्षा की गई है, प्राधिकारी के मानक अभ्यास के अनुसार वापसी की दर को 22 प्रतिशत के रूप में नहीं लिया जा सकता। इस का “ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी” के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय द्वारा भी समर्थन दिया गया है जिसमें इसने संबंधित उद्योग में वापसी की ऐतिहासिक दर को उपलब्ध कराए बिना आवेदक की एनआईपी को निर्धारित करने के लिए वापसी की 22 प्रतिशत दर का प्रयोग करने के मूलाधार पर प्रश्न किया है।

हम प्राधिकारी से हमारे निवेदनों पर विचार करने का आग्रह करते हैं। हम यह भी प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं कि यदि कार्वाही को समाप्त नहीं किया जा सकता और यदि विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों में कोई परिवर्तन है, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी सूचना देते हुए एक अन्य प्रकटीकरण जारी किया जाना चाहिए, टिप्पणियां करने के लिए हमें एक और अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक और सार्वजनिक सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

92. प्राधिकारी ने प्रकटन के उत्तर में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है जो निम्नलिखित है:

- i. प्राधिकारी ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जिन्होंने इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी उपाय के प्रभाव को भी उठाया है, सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा जांच अनुरोध दोषपूर्ण एवं समयपूर्व किए जाने के संबंध में अनुरोध को नोट करते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि क्योंकि वास्तविक मंदी क्षति का एक रूप है और जांच शुरू करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका प्रथमदृष्टया संगत पाटनरोधी नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करती है, अतः प्राधिकारी ने उसे औचित्य और नियमानुसार शुरू किया है।
- ii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकों/निर्यातकों की उत्पादन लागत का मूल्यांकन करने के सिद्धांत पर घरेलू उद्योग का अनुरोध तथा साउथ कोरिया से संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों के अनुरोधों को भी नोट करते हैं तथा स्पष्ट करते हैं कि साउथ कोरिया से उत्पादकों/निर्यातकों, दोनों की घरेलू बिक्री के लिए उत्पाद की उत्पादन लागत परिशिष्ट-5, 6 और 7 में सूचित किए गए आंकड़ों से वैध की गई है। प्राधिकारी ने इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना में परिशिष्ट-5 और परिशिष्ट-8 के बीच कच्ची सामग्री खपत में अंतर नोट किया है जिसका उचित रूप से समाधान किया गया है तथा अंतिम उत्पादन लागत प्रकटन विवरण में उत्पादकों/निर्यातकों दोनों को बता दी गई थी। अपनाए गए सिद्धांत पर भी उस समय चर्चा की गई थी जब स्थल सत्यापन तथा उसके बाद जारी की गई सत्यापन रिपोर्ट के समय विभिन्न परिशिष्टों में अंतर को नोट किया गया था।
- iii. विशेष रूप से, मैसर्स एलजी केम. के लिए कंपनी ने अपने उत्पादन से तथा मैसर्स लोटे केमिकल्स से बुटाडीन (बीडी) और स्टाइरिन सामग्री (एसएम) ली। बीडी (मिक्स सी-4) तथा एसएम (बेंजीन) के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री लोटे केमिकल से ली जाती है। ये उनको किसी करार के तहत प्राप्त किए जाते हैं जो सही-सही लागतें नहीं दर्शाते हैं क्योंकि ये कीमतें संबंधित वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में निर्धारित नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच तुलना में, कोरिया में अन्य सहकारी उत्पादक तथा लोटे से एलजी की क्रय कीमतें यह दर्शाती हैं कि एलजी की क्रय कीमतें काफी कम थी। चूंकि, प्रमुख इनपुट की कीमतें सही लागत नहीं दर्शा रही थीं, अतः कोरिया में जांच की अवधि के दौरान अन्य सहकारी उत्पादकों के बीडी और एसएम की औसत क्रय कीमतों का संदर्भ लिया गया है।
- iv. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी मानते हैं कि यह सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश की बाजार स्थितियों के उत्पादन लागत के आंकड़े हैं जो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संगत हैं और किसी असंबद्ध देश में किसी दूसरे उत्पादक के लिए कोई अन्य विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं, जैसा कि घरेलू उद्योग ने इन आंकड़ों का संदर्भ देने के लिए विरोध किया है।
- v. जहां तक एलजी केम. इंडिया प्रा. लि. का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसका गठन विशिष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित क्रियाकलापों को करने के लिए नहीं किया गया है। कंपनी की समग्र बिक्री में विचाराधीन उत्पाद के योगदान में उसका 5 प्रतिशत से कम हिस्सा है। एसजीए के तहत बुक किए गए एलजी केम. इंडिया द्वारा किए गए खर्चे विचाराधीन उत्पाद पर उपयुक्त रूप से अनुपात में रखे गए हैं और पाटन मार्जिन का परिकलन करते समय उन पर विचार किया गया है।
- vi. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि एलजी समूह की कई होलडिंग्स सहायक कंपनियां मौजूद हैं जिनकी सूचना निर्यातक द्वारा दबा दी गई है। प्राधिकारी याचिकाकर्ता के इन अनुरोधों को नोट करते हैं और मानते हैं कि जहां तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को अपने सभी निर्यातों की सूचना प्रदान कर दी है। भारत को निर्यात से संबंधित कंपनियों की सूचना का प्राधिकारी ने मूल्यांकन किया है।
- vii. इसके अतिरिक्त, जहां तक संबद्ध सामानों की फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत के निर्धारण का संबंध है, उसका परिकलन यह सुनिश्चित करने के बाद कर दिया गया है कि उत्पादक द्वारा गैर प्रत्यक्ष निर्यात अर्थात् केकेपीसी द्वारा देवू इंटरनेशनल/देवू इंटरनेशनल, सिंगापुर के माध्यम से तथा एलजी केम. लि. द्वारा एलजी केम. अमेरिका इंक., हनसुक केमिकल्स कं. लि., एवरलाइट कोरिया कं. लि., हर्टी केम. कारपो. और वॉकेम लि. के माध्यम से हानि पर नहीं बेचे जाते हैं। इसे उचित ठहराने वाले समायोजन पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए सभी समायोजनों पर विचार किया है। तथापि, इन गैर प्रत्यक्ष कंपनियों की सीआईएफ कीमतों पर भारित औसत पहुँच मूल्य परिकलन करने के लिए विचार किया गया है।

- viii. प्राधिकारी मैसर्स बीएसटी एलस्टॉमर्स द्वारा किए गए अनुरोधों और देरी से उनके द्वारा दिए गए कुछ अतिरिक्त आंकड़ों को नोट करते हैं तथा यह मानते हैं कि चूंकि, उत्पादक/निर्यातक ने समय पर एक निर्मित प्रपत्र में संबंधित सूचना दायर नहीं की थी, अतः इस स्तर पर अन्य आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार थाइलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पहले से ही किए गए मूल्यांकन की पुष्टि करते हैं।
- ix. जहां तक मैसर्स ट्रिसियो द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि चूंकि, उत्पादक/निर्यातक ने पूरी सूचना दायर नहीं की थी, अतः अलग से कोई पाटन मार्जिन उपर्युक्त के आधार पर उनको नहीं दिया गया है। जैसा कि प्रकटन में भी कहा गया है और उत्पादक/निर्यातक को शेष श्रेणी के तहत माना जा रहा है।
- x. जहां तक विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि वास्तविक क्षति, क्षति के खतरे और वास्तविक मंदी का साथ-साथ मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से क्षति की जांच और मूल्यांकन किया जाता है जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार पात्र घरेलू उत्पादक आते हैं। घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से किए गए वास्तविक क्षति के सूक्ष्म मूल्यांकन में विभिन्न घरेलू उत्पादकों के लिए क्षति संबंधी मानदंडों की स्थिति में अंतर हो सकता है। घरेलू उद्योग के एक हिस्से को मात्रात्मक क्षति हो सकती है जबकि दूसरे हिस्से को कीमत की क्षति हो सकती है। घरेलू उद्योग का समग्र मूल्यांकन समग्र रूप से ऐसे प्रभावों में संचयी और औसतन होता है। यद्यपि यह मानदंड स्तर पर वास्तविक क्षति के मूल्यांकन के लिए होता है, तथापि, यही बात घरेलू उद्योग के विभिन्न भागों को अलग-अलग क्षति के रूपों में हो सकती है। अतः यह संभावना है कि जो उत्पादक घरेलू उद्योग का भाग है, उसे वास्तविक क्षति हो जबकि दूसरे को वास्तविक मंदी हो। पाटनरोधी नियमावली इन दोनों रूपों की साथ-साथ जांच को नहीं रोकती। यह माना जा सकता है कि क्षति के तीनों रूप पारस्परिक रूप से विशिष्ट हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आई एस आर पी एल और आर आई एल, दोनों ने एसबीआर की उत्पादन सुविधाएं स्थापित कर उपयुक्त प्रतिबद्धता की है। दोनों नए उद्योग हैं क्योंकि आईएसआरपीएल ने फरवरी, 2014 में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जबकि आरआईएल ने इसकी घोषणा जांच की अवधि के बाद की। दोनों के सामने उनकी स्थापना और प्रगति में चुनौतियां हैं। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दो उत्पादकों के लिए वास्तविक मंदी तथा वास्तविक क्षति दोनों का मूल्यांकन किया है और घरेलू उद्योग के लिए समग्र आधार पर निष्कर्ष निकाला है।
- xi. समग्र मांग, उत्पादन और क्षमता के प्रयोजन के लिए सभी उत्पादकों के आंकड़े संगत हैं और इसीलिए इन पर विचार किया गया है। क्षमता उपयोग, उत्पादन की प्रवृत्ति, बिक्री, मालसूची और आयात के विशिष्ट मूल्यांकन पर आईएसआरपीएल के आंकड़ों पर वास्तविक क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजन से विचार किया गया है।
- xii. आईएसआरपीएल को वास्तविक क्षति के विश्लेषण में यद्यपि आईएसआरपीएल के लिए विशिष्ट क्षति मानदंडों पर विशेष रूप से विचार किया गया है, तथापि, संबद्ध देशों से आयात का विश्लेषण देश में कुल मांग के संबंध में किया गया है। आईएसआरपीएल द्वारा बिक्री के बाजार हिस्से की प्रवृत्ति घरेलू उद्योग की तरह ही चलती है।
- xiii. जहां तक कीमत कटौती नकारात्मक होने का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि जांच के अधीन मामला एक विशिष्ट मामला है जिसमें आईएसआरपीएल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन फरवरी, 2014 में ही शुरू हुआ था जबकि जांच की अवधि अक्तूबर, 2014 से सितंबर, 2015 है। यह कंपनी एक नई प्रवेशक है और इसे बड़े आक्रामक रूप से आयात कीमतों के अनुरूप चलना है जिससे काफी अधिक नकारात्मक कीमत कटौती होती है, जब आईएसआरपीएल के एनएसआर की तुलना पाटित आयातों के पहुँच मूल्य से की जाए। अतः इसकी व्याख्या घरेलू उद्योग के लिए गणना किए गए क्षति मार्जिन के साथ किए जाने की आवश्यकता है।
- xiv. सहकारी कंपनी के विशिष्ट आंकड़े संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के दावे पर गोपनीय माने जाते हैं वही आईएसआरपीएल के लिए माना गया है। जहां तक संबद्ध देशों से आयात की प्रवृत्ति की व्याख्या में भ्रामकता का संबंध है, प्राधिकारी यह दोहराते हैं और स्पष्ट करते हैं कि प्रकटन में यह कहा गया है कि संबद्ध देश से आयात 2014-15 तक बढ़ा है और जांच की अवधि में घटा है परंतु काफी रहा है। क्षति का मूल्यांकन करने के मानदंड के रूप में आयातों की संगतता महत्वपूर्ण होने के नाते विशेष रूप से वास्तविक मंदी के क्षति रूप का मूल्यांकन करने के संदर्भ में संगत है।
- xv. उत्तरदायियों का यह कहना है कि क्षति का मूल्यांकन क्षति मार्जिन के निर्धारण से पूर्व किया जाए। अतः इसे इस तथ्य के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि क्षति की संकल्पना क्षति मार्जिन में मिल जाती है और उसे अलग नहीं किया जा सकता।
- xvi. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई क्षति न होने की आदर्श स्थिति में क्षति मार्जिन नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि यह विभिन्न क्षति मानदंडों को बताने की एक अलग योग्यता है। कम शुल्क नियम की संकल्पना, जिसके लिए एनआईपी के परिकलन की आवश्यकता होती है, यह केवल क्षति के कारणों को सुदृढ़ नहीं करता बल्कि क्षति की किस हद तक हुई है, यह भी बताता है। फिर भी प्राधिकारी ने प्रकटन में यह उल्लेख किया है कि आईएसआरपीएल को लाभप्रदता के कारण क्षति हुई है जो प्रकटन की तालिका 9 में दर्शाया गया था। जहां तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के विश्लेषण का संबंध है, प्राधिकारी ने विशेषकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के लिए उसे लिया है। जहां तक आईएसआरपीएल के विशिष्ट उच्च निर्धारित खर्चों का संबंध है, प्राधिकारी ने एनआईपी की गणना करते समय नई

- प्रवेशक कंपनी की खास परिस्थितियों के मद्देनजर सर्वोत्तम प्राप्त किए गए क्षमता उपयोग के बजाए परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्राप्य क्षमता उपयोग को लिया है।
- xvii. जहां तक नकद लाभ की प्रवृत्ति का संबंध है, जांच की अवधि की सभी तिमाहियों में अलग-अलग गहनता वाली क्षति दर्शाई गई है जिसे केवल मात्रा में उसके अंतर के बजाए हानियों की मौजूदगी के संदर्भ में लिए जाने की आवश्यकता है।
- xviii. नए प्रवेशक होने के नाते कंपनियों के पहलुओं का समाधान करने के लिए प्राधिकारी ने एक संभावित अवधि में क्षमता उपयोग के लिए आईएसआरपीएल के वास्ते एनआईपी का मूल्यांकन किया है जो अधिकतम प्राप्त किया जाएगा तथा परियोजना रिपोर्ट में दिए गए मानकों तथा सर्वोत्तम को अपनाकर उनकी तुलना में कच्ची सामग्री/उपयोगिताओं के लिए भी मूल्यांकन किया गया है। इसीलिए गैर क्षतिकारक कीमत कंपनी की सर्वाधिक आशावादी दक्षता के साथ निर्धारित की गई है। नए प्रवेशक के पहलू को भी ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने वास्तविक मंदी मानदंडों पर आरआईएल का मूल्यांकन किया है।
- xix. जहां तक आएसआरपीएल के लिए मजदूरी, रोजगार, उत्पादकता और मालसूची घटकों का संबंध है, प्राधिकारी ने समुचित सूची बनाने के बाद उसे शामिल कर लिया है।
- xx. जहां तक घरेलू उद्योग के दो नए प्रवेशकों में परस्पर प्रतिस्पर्धा का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि दोनों नए प्रवेशक संबद्ध देशों से आयातों के विरुद्ध प्रमुख रूप से अपना-अपना निर्धारण कर रहे हैं। यद्यपि, समग्र रूप में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के भीतर दोनों प्रवेशकों के बाजार हिस्से में भारी परिवर्तन हो सकता है। तथापि, दोनों नए प्रवेशक बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में एक नियंत्रक स्थिति में नहीं हैं।
- xxi. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति के संभावित कारणों के रूप में उल्लिखित किए जा रहे विभिन्न कारकों जैसे आरंभिक लागत, याचिकाकर्ता के उत्पादों का उत्पादन न होना, मांग में गिरावट आदि को नोट करते हैं। प्राधिकारी ने लाभप्रदता के उन मानदंडों पर आईएसआरपीएल के लिए वास्तविक क्षति का मूल्यांकन किया है जो किसी ऑफ ग्रेड बिक्री में नहीं है। अंतिम प्रयोक्ता, जो स्वयं पाटित सामग्री के लाभग्राही है, द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया के लिए लंबी अवधि को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता और घरेलू उद्योग को क्षति के कारक के रूप में एक सही तर्क भी नहीं माना जा सकता। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और उच्च असाधारण लागत में मौजूदा अदक्षताओं को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति को कम करने के लिए अच्छा संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एनआईपी की गणना करते समय उचित रूप से सामान्य किया गया है। प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री तथा उपयोगिताओं के सर्वोत्तम प्राप्त मानदंडों की तुलना मानक खपत मानदंडों के साथ भी की है तथा उपर्युक्त उप पैरा-XVI में उल्लिखित क्षमता उपयोग संबंधी सिद्धांतों के अतिरिक्त आरंभिक लागत के प्रभाव को हटाने के लिए दोनों कीमतों में से कम कीमत को अपनाया है।
- xxii. जहां तक भारत और कोरिया के बीच एफटीए के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी ने लागू सीमा शुल्कों के अनुसार पहुँच मूल्य का मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक ओर एफटीए प्रावधान पहुँच मूल्यों को कम कर सकते हैं परंतु साथ ही साथ निर्यातक अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में निर्यात कीमत में शून्य आयात शुल्क लाभ लेकर अपनी निर्यात वसूली को बढ़ा सकते हैं जिससे एक ओर किसी हद तक पहुँच मूल्य बढ़ेगा और निर्यात कीमत में वृद्धि के कारण पाटन मार्जिन भी कम होगा। इन पहलुओं के कारण भी समायोजन की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी ने लागू सीमा शुल्कों के साथ पहुँच मूल्य का मूल्यांकन करने की अपनी मौजूदा परिपाटी को अपनाया है।
- xxiii. जहां तक आरआईएल के सूचीबद्ध नंबरों की लागत और कीमत प्रवृत्ति लाइनों के विश्लेषण का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि के दौरान परीक्षण उत्पादन केवल अक्तूबर, 2014 में शुरू हुआ था जिसमें अत्यधिक कम बिक्री के साथ आरंभिक लागत बहुत अधिक थी। जांच की अवधि के दौरान लागत एवं कीमत का विश्लेषण जो कि आरआईएल के लिए परीक्षण उत्पादों का चरण था, वास्तविक सूचीबद्ध शब्दों पर यथार्थवादी नहीं है। प्राधिकारी ने वास्तविक पूर्ण संख्याओं का विश्लेषण किया है और यह नोटिस किया है कि जांच की अवधि के दौरान आरआईएल की कीमतें आईएसआरपीएल के लिए निर्धारित एनआईपी से कम हैं जो आरआईएल के लिए सस्ती कीमत का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसने वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया है।
- xxiv. जहां तक कारणात्मक संबंध के विश्लेषण का संबंध है, प्राधिकारी ने यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता नए प्रवेशक हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षति किसी असाधारण आरंभिक लागत के कारण नहीं है, प्राप्त सर्वोत्तम क्षमता उपयोग के बजाए सर्वोत्तम प्राप्य क्षमता उपयोग पर एनआईपी का परिकलन किया है। जहां तक निर्यात बिक्री का संबंध है, प्राधिकारी ने घरेलू बिक्री के लिए विशिष्ट रूप से नकद लाभप्रदता को लिया है।
- xxv. जहां तक आरआईएल को क्षति मूल्यांकन का संबंध है, उसे अकेले वास्तविक मंदी के संबंध में लिया गया है। चूंकि, आरआईएल का वाणिज्यिक उत्पादन जांच की अवधि के बाद घोषित किया गया था, अतः घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी आईएसआरपीएल के आंकड़ों के आधार पर माना गया है। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि एनआईपी के परिकलन के लिए आरआईएल को शामिल करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, तथापि, प्राधिकारी इसे इतना व्यवहार्य नहीं मानते जितना कि जांच की अवधि के दौरान आरआईएल की लेखा बहियों में एनएफए है। परंतु इसका परिकलन सीडब्ल्यूआईपी के रूप में किया गया है। प्राधिकारी उसे इतना व्यवहार्य पूंजीबद्ध कर दिए गए हैं।

- xxvi. प्राधिकारी ने आरआईएल को वास्तविक मंदी की जांच करते समय तथ्यों के आधार पर उसकी जांच की थी न कि अटकलों के आधार पर। डब्ल्यू टी ओ में विचार की जा रही वास्तविक मंदी की जांच करते हुए डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव पर एक संदर्भ के रूप में विचार किया गया है। जांच की अवधि में आरआईएल की बिक्री का कम बाजार हिस्सा आईएसआरपीएल के लंबी अवधि की तुलना में वाणिज्यिक उत्पाद घोषित करने के लिए तथा जांच की अवधि के बाद में 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग बढ़ाने में असमर्थ होने पर मांग की उपलब्धता के बावजूद यह दर्शाता है कि आरआईएल को पाटित आयातों के कारण वास्तविक मंदी की वजह से क्षति हुई है।
- xxvii. आरआईएल की बिक्री लागत का परिकलन करने के लिए प्राधिकारी ने अंतरण कीमत के स्थापित सिद्धांत को अपनाया है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, चूंकि आरआईएल जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं था, अतः निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना सही तुलना सुनिश्चित करने के लिए आईएसआरपीएल के लिए परिकलित एनआईपी से की गई है।
- xxviii. जहां तक गोपनीयता का संबंध है, प्राधिकारी ने मौजूदा परिपाटी को अपनाकर और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, किसी हितबद्ध पक्षकार की अलग कंपनी के वे आंकड़े प्रकट नहीं किए हैं, जिनमें गोपनीयता का दावा किया गया हो।
- xxix. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएस से गैर गोपनीय लेन-देन वार आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए डीजीएडी से प्राधिकार पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, एक बार डीजीसीआईएस द्वारा यदि वे आंकड़े किसी हितबद्ध पक्षकार को दिए जाते हैं तो उनका दायित्व है कि वे डीजीसीआईएस की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका प्रयोग करें। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस के इन लेन-देन वार आंकड़ों को सार्वजनिक फाइल में नहीं रखा है, जो विशेष वचनबद्धता पर अधिकृत प्रयोक्ता को डीजीसीआईएस द्वारा लेन-देन वार आंकड़े प्रदान किए जाने की नीति को रोकता है। अतः प्राधिकारी ने किसी भी तरह किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराए जाने में रुकावटी नहीं डाली है। अतः मैसर्स लूथरा एंड लूथरा द्वारा किए गए अनुरोध गलत रखे गए हैं तथा मामले और कानून के तथ्यों के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है।
- xxx. प्राधिकारी ने मैसर्स लूथरा एंड लूथरा विधि कार्यालय को दिनांक 15 मई, 2017 के पत्र के माध्यम से इस सूचना के अधिकृत उपयोग के संबंध में उनकी वचनबद्धता के बाद डीजीसीआईएस से लेन-देन वार आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए उन्हें प्राधिकार के लिए आश्वस्त किया था, जैसा कि जांच में शामिल सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपनाया जा रहा है।
- xxxi. जहां तक इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्रा.लि.(आईएसआरपीएल) द्वारा पहले एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उठायी गई दूरी होने के नाते कच्ची सामग्री की खरीद कीमतों का संबंध है, प्राधिकारी ने वास्तविक क्रय कीमत पर विचार कर तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के सिद्धांतों को समुचित रूप से लागू कर एनआईपी का मूल्यांकन किया है। जो भी हो, आईएसआरपीएल को कच्ची सामग्री की आपूर्ति में प्राथमिकता का व्यवहार किए जाने के कारण एनआईपी के कमतर परिकलन से आयातक अथवा प्रयोक्ता उद्योग के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके, अतिरिक्त प्राधिकारी ने मौजूदा नियमों और सिद्धांतों के अनुसार आय की दर की अनुमति दी है।
- xxxii. एन.आई.पी. मूल्यांकन के लिए लागत में सामान्यीकरण के संबंध में एक हितबद्ध पक्षकार के प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के उत्तर में प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि कच्ची सामग्री की सर्वोत्तम खपत के मानदंडों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, संभावित जांच अवधि में सर्वोत्तम प्राप्य क्षमता उपयोग पर इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है कि घरेलू उद्योग में 2014 में ही प्रचालन शुरू किए परंतु अपनी परियोजना रिपोर्ट में 3 वर्ष से आगे उच्चतर क्षमता उपयोग प्राप्त करने की बात कही है। एक तरह की क्षति जिसकी जांच की जा रही है, वास्तविक मंदी है जिसमें जांच की अवधि के बाद के निष्पादन का भी विश्लेषण किया गया है।
- xxxiii. प्राधिकारी ने उस प्रकटन विवरण पर ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (के आई आर आई ए) द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया और उनका समाधान किया जो इस निष्कर्ष में उपयुक्त पैराओं में गलती से उनके लिए छूट गए थे। आईएसआरपीएल और आर आई एल के लिए अलग-अलग उस जांच में वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी दोनों की वचनबद्धता संबंधी प्रमुख अनुरोधों का समाधान उप-पैरा x में कर दिया गया है। जबकि प्राधिकारी ने सामग्री की क्षति संबंधी मानदंडों जैसे शेयर में वृद्धि, उत्पादन और लाभप्रदता का इष्टतम स्तर के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में अंतर्निहित निर्धारित मानदंडों पर सामग्री क्षति का उल्लेख किया है क्योंकि नए प्रवेशक पर विचार किया गया है।
- xxxiv. जहां तक एनआईपी का संबंध है, प्राधिकारी ने अपनी विद्यमान परिपाटियों के अनुसार लगाई गई पूंजी पर आय की दर की अनुमति दे दी है। सामान्यीकरण परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अथवा उप-पैरा xxi में उल्लिखित सर्वोत्तम प्राप्त मानदंडों के अनुसार परियोजना मानक अपनाकर किया गया है। यह विशेष रूप से असामान्य उच्च आरंभिक लागत की स्थिति तथा इस तथ्य कि कंपनियां नए प्रवेशक हैं, का समाधान करने के लिए किया गया है। आरआईएल

के आंकड़े यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल नहीं किए गए हैं कि एनआईपी पर्याप्त एवं सस्ती है, जो अन्यथा अधिक होती।

xxxv. जहां तक संबद्ध देशों से जांच की अवधि के बाद में आयात में कमी को देखते हुए कारणात्मक संबंध की जांच का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि के बाद में आरआईएल की लाभप्रदता क्षति की सूची तथा क्षति विश्लेषण में सूचित की गई सूची के रूप में मानी गई है।

### **भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे**

93. जहां तक प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव के संबंध में किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उन्मूलन करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय थोपना, संबद्ध देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाना और उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित करना किसी भी तरह से नहीं है।
94. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है, परंतु भारतीय बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्द्धा ऐसे पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय से पाटन की परिपाटियों से होने वाले अनुचित लाभ कम हो जाएंगे जिससे घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति और उसकी मंदी, दोनों की दृष्टि से गिरावट को रोकेंगे तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध सामानों की व्यापक रूप से विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेंगे। उपभोक्ता आज ही दो या उससे अधिक आपूर्ति के स्रोतों को बनाए रख सकते हैं।

### **निष्कर्ष**

95. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने तथा उपर्युक्त किए गए विश्लेषण पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- संबद्ध देशों से संबंधित उत्पाद का पाटन हो रहा है।
- संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बना रहे हैं, लाभप्रदता को प्रभावित कर रहे हैं।
- उपर्युक्त क्षति का प्रभाव वास्तविक क्षति तथा वास्तविक मंदी, दोनों के रूप में है।

### **सिफारिशें**

96. उपर्युक्त निष्कर्ष निकालने के बाद प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं कि निम्नलिखित शुल्क तालिका में वर्णित किए गए रूप एवं तरीके में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर निम्नलिखित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाए।
97. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध देशों से निर्यातित अथवा उनके मूल के संबद्ध सामानों के आयात पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है:

**शुल्क तालिका**

सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण *	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	यूनिट	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	4002 19	1500 सीरीज और 1700 सीरीज का इमल्सन स्टाइरिन बुटाडीन रबर (ई-एसबीआर)	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	सिंथस करालुपी ए.एस. चेज गणराज्य	सिंथस करालुपी ए.एस. चेज गणराज्य	207.49	मी. टन	यूएस डालर

2.	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	सिंथस डाउरी 7 स्पे. जेड. ओओ. पौलेंड	सिंथस डाउरी 7 स्पे. जेड. ओओ. पौलेंड	207.49	मी. टन	यूएस डालर
3.	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	क्रम सं. 1 व 2 के अलावा कोई अन्य संयोजन		266.00	मी. टन	यूएस डालर
4.	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	266.00	मी. टन	यूएस डालर
5.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन कोई अन्य देश	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	कोई अन्य	266.00	मी. टन	यूएस डालर
6.	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कुम्हो पैट्रो केमिकल कं. लि.	कुम्हो पैट्रो केमिकल कं. लि.	33.95	मी. टन	यूएस डालर
7.	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कुम्हो पैट्रो केमिकल कं. लि.	i. देवी इंटरनेशनल कारपोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य ii. देवी इंटरनेशनल, सिंगापुर	33.95	मी. टन	यूएस डालर
8.	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य	28.68	मी. टन	यूएस डालर
9.	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि., कोरिया जनवादी गणराज्य	i. एलजी केम. अमेरिका इंक.; ii. हनसुक केमिकल्स कं. लि.; iii. एवरलाइट कोरिया कं. लि.; iv. हर्टी केम. कारपो.; v. वोंकेम लि.	28.68	मी. टन	यूएस डालर

10.	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	क्रम सं. 6, 7, 8 व 9 के अलावा कोई अन्य संयोजन		64.00	मी. टन	यूएस डालर
11.	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मी. टन	यूएस डालर
12.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन कोई अन्य देश	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मी. टन	यूएस डालर
13.	-वही-	-वही-	कोई अन्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मी. टन	यूएस डालर
14.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	243.60	मी. टन	यूएस डालर
15.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य			
16.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन कोई अन्य देश	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य			

\* टिप्पणी: स्टाइरिन बुटाडीन रबर 1900 सीरीज और सॉल्यूशन एसबीआर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

98. इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयात का पहुँच मूल्य मूल्यांकन करने योग्य मूल्य होगा, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किया गया है तथा इसमें उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत आने वाले शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

#### आगे की प्रक्रिया

99. इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जाएगी।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2017

**FINAL FINDINGS****Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series, originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand.**

**No. 14/10/2015-DGAD.**—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

**A. PROCEDURE**

1. The procedure described below has been followed:

a. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), under the above Rules, received a written application from The Indian Synthetic Rubber Private Limited (‘ISRPL’) and Reliance Industries Limited (‘RIL’) (hereinafter referred to as the “petitioner”) as domestic industry of the subject goods, alleging dumping of Styrene Butadiene Rubber (hereinafter also referred to as “subject goods” or “SBR”) originating in or exported from European Union (EU), Korea PR and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”) and resultant injury to domestic industry and requesting recommendations for imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject countries.

b. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petitioner filed an updated duly documented petition, which was considered by the Authority for initiation of investigation.

c. The Authority, on the basis of sufficient prima-facie evidence submitted by the petitioner to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries.

d. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.

e. The Authority issued a public notice dated 14<sup>th</sup> January 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, and initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods from the subject countries.

f. The Authority forwarded a copy of the public notice to all known exporters (whose details were made available by the Petitioner) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.

g. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.

h. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.

i. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Kumho Petrochemical Co., Ltd. East Wing 10-14th Floor, Signature Towers Seoul, 100 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Korea	LG Chem Ltd.: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Styron LLC:	Synthos SA:

1000 Chesterbrook Blvd., Berwyn, Pennsylvania 19312, USA	ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Poland
Versalis SPA: Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), Italy	SIBUR(PJSC SIBUR Holding): 16/1 Krzhizhanovskogo St., Moscow, GSP-7, 117997, Russia
Lanxess AG: Kennedyplatz 1, 50569 Cologne, Germany	Bangkok Synthetics Co. Ltd, 175 Sathorn City Tower, 22 <sup>nd</sup> Floor South Sathorn Road, Tungmahamek Sathorn, Bangkok- 10120

j. In response to the initiation notification, the following exporters/producers from the subject countries have responded:

- i. M/s Kumho Petrochemicals Co., Ltd, Korea RP
- ii. M/s Daewoo International., Korea RP
- iii. M/s Daewoo International., Singapore
- iv. M/s LG Chem Ltd., Korea RP
- v. M/s LG Chem America Inc, USA
- vi. M/s Wonchem, Ltd., Korea RP
- vii. M/s Heartychem Corp., Korea RP
- viii. M/s Everlite Korea Co Ltd., Korea RP
- ix. M/s Hansuk Chemicals Co Ltd., Korea RP
- x. M/s Synthos Krapuly A.S., Czech Republic
- xi. M/s Synthos Dwory 7 SP.Z. OO, Poland
- xii. M/s Trinseo Pvt. Ltd.

k. Questionnaire was sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

M/s JK Tyres, Link House, 3, Bahadurshah Zaafar Marg, New Delhi- 110 002	M/s Birla Tyre, Shivam Chambers 53, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata-700 019, West Bengal.
M/s Apollo Tyres, Apollo House 7, Institutional Area, Sector-32, Gurgaon -122001 (Haryana)	M/s CEAT Ltd., CEAT Mahal, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030
M/s MRF Ltd., 124 Greams Road, Chennai-06	M/s Ralson, Plot No: 3, New Industrial Area, Mandideep. Distt. Raisen, M.P. – 462046
M/s Poddar Tyre, GT Road Jugiana,	M/s Oriental Rubber Industries, 525 Koregoan Bima Pune Nagar Road, Pune

Ludhiana (PB) 141420	
M/s Hindustan Rubber, 1 Janki Center OFF Veera Desai Road Andheri(W) Mumbai-53	M/s Agarwal Rubber, 15-1-503/49/A, Ashok Market, Siddiamber Bazar, Hyderabad 500 01, Andhra Pradesh
M/s Exel Rubber, Flat no. 507, Sai Sadan Apts, Opp. SBI Balkampet, S.R. Nagar, Hyderabad – 500038	M/s Tega Industries, First floor, No 210, 5th Main Road Vijay Nagar 2nd Stage Bangalore 560040
Phoenix Conveyor Belt India Private Ltd. Ideal Plaza, North Block, 4th Floor, 11/1, Sarat Bose Road, Sreepally, Bhowanipore, Kolkata, West Bengal 700020	Hindustan Rubbers 1, Janki Center, Off. Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai – 400 053
Forech India Ltd. Hilton House, S-23, Green Park Extension, New Delhi, India - 110 016	Garware Bestrech Amar Avinash Corporate Plaza, 4th Floor, Bund Garden Road, Pune 411 001 (Maharashtra), India
Paragon Polymer Product Private Ltd. P.B.No.61, Paragon Building, Opp. Bishop Jacob memorial Hall, Sreenivasa Iyer Road, Chalukunnu, Kottayam, Kerala – 686001	Oriental Rubber Industries Ltd. Sharvani Gardens, 20, Viman Nagar, Pune, Maharashtra 411 014
Midas Rubber (P) Ltd. Midas Marketing Building, Varissery Jn., Mariathuruthu P.O, Kottayam, Kerala, India - 686 027	Ralson (India) Ltd. Ralson Nagar, G.T. Road, Ludhiana - 141 003, Punjab, India
Sempertrans Nirlon (P) Ltd. Nirlon Complex, Pahadi Village, Goregaon East, Mumbai - 400063	Metro Tyres Ltd. Metro Tower, C-49, Sector 62, Noida – 201 301, India
Balakrishna Tyres Ltd.	Alliance Tyre Group
M/s Balakrishna Industries Limited BKT House, C/15, Trade World Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013	M/s ATC Tires Pvt. Ltd Unit No. T 6 & 7, 5 <sup>th</sup> Floor, High Street Phoenix A Wing, Phoenix Mills Compound, 462, Senapati Bapat Marg Lower Parel, Mumbai- 400 013
Goodyear India Ltd, 1 <sup>st</sup> Floor, ABW Elegance Tower, Jasola, New Delhi- 110025	Bridgestone India Private Limited, Plot No. A 43, Phase- II, MIDC Chakan, Village Sawardari, Taluka Khed, Dist. Pune, Maharashtra- 410501

<b>Automotive Tyre Manufacturers' Association</b> PHD House, 4 <sup>th</sup> floor, Siri Fort Institutional Area Opp. Asian Village New Delhi-110016.	<b>All India Rubber Industries Association</b> 601, Pramukh Plaza, B Wing, 485, Cardinal Gracious Road, Opp. Proctor & Gamble, Chakala, Andheri (E) Mumbai- 400099.
---	---

m. Following importers/consumers filed questionnaire responses.

- i. M/s Apollo Tyres Ltd.,
- ii. M/s Bridgestone India Pvt. Ltd.,
- iii. M/s CEAT Ltd,
- iv. M/s JK Tyres Ltd.,
- v. M/s MRF Ltd.,
- vi. M/s TVS Srichakra Ltd.

Further a number of other interested parties have offered comments and submission with regard to the present investigation, which have been appropriately taken into account. The said interested parties are as follows:

- i. European Commission (Director General for Trade)
- ii. Government of Korea RP
- iii. All India Rubber Industries Association (AIRIA)
- iv. Automotive Tyres Manufacturers Association (ATMA)
- v. M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd.
- vi. M/s Rishiroop Ltd.

n. The Authority has obtained the transaction wise import data for product under consideration during POI from DGCIS and has broadly correlated the data filed by importers with the DGCIS/exporters response to the extent it was feasible for a broad validation.

o. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by all interested parties. The public file was inspected by a number of interested parties a number of times. Interested parties, who requested inspection and copies of the documents from the public file, were provided with the same.

p. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis, which was made available through public file.

q. Further information was sought from the petitioner and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.

r. A spot verification was also conducted at the premises of the following exporters:

- (i) Kumho Petrochemical Co., Ltd., Korea RP
- (ii) M/s Daewoo International., Korea RP
- (iii) M/s LG Chem Co. Ltd., Korea RP to verify direct exports data and the data of associated traders made available in Korea RP

- s. The above exporters were issued a report of the verification conducted. Comments offered by the exporters have further been taken into account in this Findings.
- t. Investigation was carried out for the period starting from 1<sup>st</sup> October 2014 to 30<sup>th</sup> September 2015 (12 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from February 2014 and up to POI, by dividing each financial year in to four quarters.
- u. The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') considering the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry. As M/s RIL declared commercial production in post POI, the information of M/s ISRPL only has been adopted for computing NIP.
- v. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 14<sup>th</sup> September 2016. Thereafter a second oral hearing was conducted on 4<sup>th</sup> November 2016. The parties, who presented their views in oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- w. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has referenced the DGCI&S imports data for computation of the volume & value of imports and injury analysis.
- x. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 15/6/2017 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 23<sup>rd</sup> June, 2017 which was further extended till 27<sup>th</sup> June, 2017. Since sending of the disclosure statement to All India Rubber Industries Association was inadvertently missed out, the same was emailed on 9<sup>th</sup> July, 2017 so as to enable them with an opportunity to respond to it quickly in view of pressing statutory timelines which cannot be extended further.
- y. Exchange rate for conversion of US\$ to Rs. is considered for the POI as Rs.63.62 as per customs data.
- z. In this Final Findings, \*\*\* represents information furnished by the interested parties on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

## **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

1. The product under consideration for the purpose of present investigation is Styrene Butadiene Rubber originating in or exported from EU, Korea (RP) and Thailand.

### **Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

2. SBR 1500, 1700 and 1900 were subject to antidumping duty and protection from 1999 till 2001. The remaining domestic producers continued to produce 1900 series, therefore just because the existing producers did not use existing production facilities to produce SBR 1500 and 1700 does not mean that they cannot use these facilities to produce PUC.
3. Specific grades such as 1502NF, 1507, 1507H, 1745, 1763, 1769, 1789, 1793, 1799 should be excluded from the PUC as they are not produced domestically.
4. M/s Luthra & Luthra law offices representing ATMA vide letter dated 24/4/2017 have submitted that ESBR 1739 and 1789 grades be excluded as M/s Reliance Industries has admitted that it cannot currently manufacture ESBR 1789 and M/s ISRPL on its website does not list this grade in their product list.
5. As admitted by the domestic industry, SBR 1500, 1700 and 1900 series can be manufactured interchangeably and it is the prevailing practice in other countries. It is domestic industry's inherent deficiency that it fails to manufacture all grades. Further there are known producers of 1900 series in India.
6. Solution SBR and certain product grades such as 1739 and 1789 which are different from the goods produced by the domestic industry in terms of composition and uses must be excluded.
7. M/s Luthra & Luthra representing ATMA through letter dated 24/5/2017 have responded to DGAD's letter

dated 15/5/17 written in response to their earlier dated 30/3/2017 stating that Designated Authority should share the transaction wise import data obtained from DGCI&S as done in the past and as per Rule 6 (7) and legal judgments quoted in support of this request.

8. Foreign manufacturers can manufacture SBR series 1500, 1700 and 1900 interchangeably and therefore the domestic industry can also manufacture.

#### **Views of the Domestic Industry**

9. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration: -

- a.) The product under consideration in the present investigation is Styrene Butadiene Rubber. Styrene Butadiene Rubber (SBR) describes family of synthetic rubbers derived from styrene and butadiene. These materials have good abrasion resistance and good aging stability when protected by additives. SBR is derived from two monomers, styrene and butadiene. The mixture of these two monomers is polymerized by two processes – from solution (S-SBR) or as an emulsion (E-SBR). The present case is only in respect of emulsion SBR.
- b.) Styrene butadiene rubber or SBR is the largest volume of synthetic rubber produced and consumed globally. Compared to natural rubber, SBR has better process ability, homogeneity, heat aging and abrasion resistance, but is inferior in terms of elongation, hot tear strength, hysteresis, resilience and tensile strength. The majority of SBR is consumed in the manufacture of tyres.
- c.) A number of grades of SBR are produced, which are characterized by the level of copolymer (% of styrene), emulsifier type, nominal mooney viscosity, coagulation, specific gravity and product stain. They are segregated into series 1000, 1500, 1600, 1700, 1800 and, 1900. The present petition pertains to SBR 1500 series and SBR 1700 series only. SBR 1900 series are specifically excluded from the scope of the product under consideration although they are also produced by the foreign producers. SBR 1000, 1600, 1700, 1800 series are also beyond the scope of the product under consideration.
- d.) The difference in grades are due to the difference in composition of Butadiene and Styrene, then the fact that the petitioner can also produce and supply different grades cannot be questioned. No additional manufacturing facilities are required to be added and within the existing facilities, the petitioners can also produce other grades also. The petitioners request the Designated Authority not to exclude any grade of the product.

#### **Examination by the Authority**

- a) The product under consideration in the present investigation is Styrene Butadiene Rubber; (SBR) of 1500 and 1700 series only of synthetic rubbers derived from two monomers styrene and butadiene. These materials have good abrasion resistance and aging stability when protected by additives. Solution SBR grades are outside the scope of investigation.
- b) Compared to natural rubber, SBR has better process ability, homogeneity, heat aging and abrasion resistance, but is inferior in terms of elongation, hot tear strength, hysteresis, resilience and tensile strength. The major demand of SBR is in the automotive sector in manufacture of tyres.
- c) The product is classified under Customs Tariff heading No. 400219. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- d) Rule 2(d) relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.
- e) The petitioner has claimed that the subject goods, which are exported from subject countries into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Styrene Butadiene Rubber produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. No specific instances of differences in technical characteristics which affect substitutability of domestic and imported subject goods have been substantiated which warrants a detailed examination. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are treated as 'Like Article' to the

subject goods being imported from the subject countries.

f) The Authority notes that the evidence elucidated by interested parties that M/s RIL is not currently in a position to manufacture the 1739 and 1789 grades need to be seen in context of the injury on account of market retardation examined later for M/s RIL in this disclosure. The current manufacturing status of a grade/grades does not erode the capability of a domestic industry to produce such grades in future when there are orders for the same and also fair play is established. Further M/s RIL has placed on record the license to manufacture these grades depicting its capability to produce these. Further the Authority has evaluated injury to RIL on account of material retardation. The Authority concludes that these two grades cannot be excluded from the scope of Product under consideration.

g) The Authority notes that in order to ensure availability of transaction wise import data of DGCI&S, it has been decided by the concerned authority to provide such data to all bonafide interested parties participating in an Anti-dumping investigation on the basis of an authorization letter issued by DGAD after the bona fide actual use of such data is undertaken and, ensuring non-disclosure and no other use of the same for other than ADD purpose. The Authority has issued authorization to various interested parties on request. The submission of Luthra & Luthra seeking the data used by Domestic Industry is not based on any justified reason as the same approach is being adopted by the Authority to make such data available to all interested parties through an authorisation letter as stated above.

h) The Authority notes that, according to the submission of the domestic industry and the other interested parties, the only difference between various grades belonging to a series of styrene butadiene rubber is the composition ratio of styrene and butadiene content in the rubber and the associated oil content. There exists no reason and evidence to believe that such grades of rubber cannot be produced by the domestic industry with their existing facilities if they should want to produce such grades. The Authority therefore holds that the product manufactured by the petitioner constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject countries. The product under consideration is Styrene Butadiene Rubber of 1500 and 1700 series excluding the solution SBR grades. Since the solution SBR grades are excluded from the scope of PUC and it is the text description of the product under consideration which assumes primacy over the customs tariff head, the Authority holds that with such an explicit exclusion of the solution grades of SBR would not create any ambiguity in levy of AD measures.

### **C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”*

#### **Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

a.) The applicants are not eligible for filing the application on the ground of material retardation. The claim of material retardation can be made only for the new product/new industry. The product is not new and the claim of being materially retarded by the applicant is not tenable since PUC already exists in India and had been subject to antidumping duty till 2010.

b.) Apcotex is another Indian manufacturer still manufacturing SBR 1502 under brand name APCOTEX SR 502. Invoices for such product sold in India have been procured from 2007-08, even before applicants began commercial production in 2014.

#### **Views of the Domestic Industry**

10. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration: -

a.) The petition has been filed by M/s Indian Synthetic Rubber Private Limited (ISRPL) and M/s Reliance Industries Limited as a domestic producer of the product under consideration.

b.) ISRPL is a joint venture company, jointly promoted by Indian Oil Corpn.; TSRC, Taiwan and Marubeni Corpn. Japan. Indian Oil, holding 50% of equity share capital in the company. TSRC, holding 30% of equity share capital in the Company, through its wholly owned subsidiary company, Trimurti Holding Corporation (THC). Marubeni

Corporation, holding 20% of equity share capital in the Company, through its wholly owned subsidiary company Marubeni Petrochemical Investments B.V. (M.P.I), Netherlands.

c.) Reliance Industries Limited is a well-known producer in the Country in Oil Exploration, Petroleum Refining & Marketing and Petrochemicals. RIL has not begun commercial production till the end of period of investigation.

d.) The petitioners are the only domestic producers of Styrene Butadiene Rubber. The petitioners are not related to any importer or exporter of the product under consideration from the subject country. In any case, there is no such relationship that would attract possibilities of exclusion under Rule 2(b).

#### **Response of the Domestic Industry to Other Parties' submission**

11. The domestic industry has made the following submissions in response to the submissions of the other parties:

a.) The authority had conducted the mid-term review in the previous SBR investigation and had discontinued duties on SBR 1500 and 1700 series and continued duties on SBR 1900 on the grounds that there was no producer of SBR 1700 and 1500 during the period of review. Therefore the Authority itself concluded that there was no domestic industry for the PUC.

#### **Examination by the Authority**

a.) The Authority notes that the application was filed by M/s Indian Synthetic Rubber Private Limited (ISRPL) and M/s Reliance Industries Limited as domestic industry. The Petitioners are the sole producers of the subject goods in India. Petitioner has not imported the subject goods during the POI. Further, petitioner is not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject countries. The production details are given in table 1 below.

**Table 1: Production of Petitioners**

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Production Volume					
ISRPL	MT	-	***	***	***
Reliance Industries Ltd	MT	-	-	***	***
Total Indian Production	MT	-	6,912	46,657	92,540
Share in Production					
ISRPL	%	-	***	***	***
Reliance Industries Ltd	%	-	***	***	***
Share of Petitioner- Total	%	-	100%	100%	100%

b.) As regards the contention that the domestic industry was already in existence prior to the commencement of operations by the Petitioners that, the Authority notes that during the previous investigation concerning SBR 1900 series there was no producer for SBR 1500 and SBR 1700 series in the country, which form the product under consideration in the present petition.

c.) The Authority however notes that M/s RIL has though declared commercial production only in post POI i.e. October 2016 and it is not feasible and appropriate to compute NIP including their data but it is a part of Domestic Industry and its injury assessment is done in the form of material retardation. The Authority has considered it appropriate to evaluate NIP on the basis of data of M/s ISRPL only for evaluating material injury to ISRPL. Both the producers of domestic industry have therefore been evaluated for injury assessment.

d.) In view of the aforesaid, the Authority holds that the petitioner satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules, i.e. the requirement of standing under the Rules. The petitioners are therefore held to constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of AD Rules.

#### **Evaluation of Normal Value, Export Price and Dumping Margin**

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

#### **Views of the Domestic Industry**

12. The following are the submissions made by the petitioner in respect of normal value:

(a) Efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of exporting countries as well as the price lists or quotations of producers of subject goods in subject countries; however these efforts were to no avail. There are very limited number of producers and consumers of the subject goods in the subject counties. Therefore business happens directly between the producers and exporters.

i. Petitioner submits that most of the producers of the subject goods do not have production of styrene and butadiene.

ii. In view of the same, and considering that the producers are in fact selling the product under consideration below cost of production, petitioners have constructed normal value for all exporters/producers from subject countries based on raw material prices and consumption norms, estimates of conversion costs, selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin. The methodology adopted for constructing normal value basis is as follows.

#### **Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

13. The exporters, importers, consumers and other interested parties made the following submissions:

(a) The submission by the Domestic Industry to calculate DM, price undercutting and injury margin on the basis of information contained in the contract is inconsistent with WTO Agreement and the practices of the DGAD. This practice has only been adopted in cases of high price volatility.

(b) The submission by the Domestic Industry to use the time lag approach to determine normal value having considered input cost at the time of order booking brings to the fore the question of how such information was obtained by the applicant when it is not available in the public domain.

(c) Construction by the Domestic Industry is not correct since the parameters calculated such as consumption factor are presumptive in nature.

(d) Constructed normal value can only be adopted when there are no sales of the like article in the domestic market of the exporting country or particular market situation or low volume of sales in the domestic market.

(e) The cost of production of only ISRL has been considered when there is another applicant.

(f) Normal value of developed industries cannot be based on the cost of production of a nascent industry.

(g) Raw material prices of Butadiene from Northeast Asia have been incorrectly considered for the EU.

(h) There is no consistency in the basis of prices adopted for raw materials for the countries involved in the investigation.

(i) Adjustment in raw material (M – 3) to determine constructed normal value has led to an inflated normal value.

(j) Constructed Normal Value did not take into account the fact that the petitioners starting production recently.

(k) Construction on the basis of the petitioner's cost is incorrect because of level of efficiencies and the various production rates.

(l) EU may have different cost structures due to their size and economies of scale.

**Submissions of Domestic Industry in response to submissions by Other Parties**

(a) Cost of production of SBR in the POI is comparable for both the applicants. Therefore, constructed normal value of the PUC calculated on the basis of the cost of either of the applicants would be comparable.

(b) While constructing normal value, actual cost of production has not been considered in view of the high fixed cost involved in start-up of the new producers, the fixed cost of production has been considered at 90% capacity utilization.

(c) Butadiene for Northeast Asia prices has been considered for EU because that was the best information available to the petitioners.

(d) The domestic industry has never claimed that the costs are equal for domestic industry and responding exporters. The applicants have considered the best available information to determine the normal value.

**Examination by the Authority**

14. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following parties have filed exporter questionnaire responses:

(a) (i) M/s Kumho Petrochemicals Co., Ltd, Korea RP

(ii) M/s Daewoo International., Korea RP

(iii) M/s Daewoo International., Singapore

(b) (i) M/s LG Chem Ltd., Korea RP

(ii) M/s LG Chem America Inc, USA

(iii) M/s Wonchem, Ltd., Korea RP

(iv) M/s Heartychem Corp., Korea RP

(v) M/s Everlite Korea Co Ltd., Korea RP

(vi) M/s Hansuk Chemicals Co Ltd., Korea RP

(c) (i) M/s Synthos Krapuly A.S., Czech Republic

(ii) M/s Synthos Dwory 7 SP.Z. OO, Poland

(d) M/s Trinseo Gmbh, Germany

(e) M/s BST Elastomers, Thailand

While producers/exporters (a) to (c) above filed structured and complete details whereas producers/exporters at (d) and (e) filed partial/limited data.

For evaluating the dumping margin the Authority has undertaken comparisons of weighted average normal value with weighted average exfactory export price during POI separately for 1500 and 1700 series. The Authority notes that there no positive evidence of lag in exports warranting comparison by referencing order/contract date and not the invoice date as normally done.

**I. EUROPEAN UNION**

**a. Cooperative producers/ exporters**

**A. M/s. Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Poland ("Synthos Dwory") and Synthos Kralupy A.S., Czech Republic ("Synthos Kralupy")**

15. M/s Synthos Dwory, the producer and exporter of the subject goods, has provided questionnaire response as a producer. Its related entity viz. producer cum exporter i.e. M/s Synthos Kralupy, have also filed questionnaire responses. The submissions are as under:

- a.) The Styrene Butadiene copolymer produced is in cold polymerization process using rosin and fatty acid soaps as an emulsifying system. Other parts are rosin and fatty acids, antioxidant and/or extender oil.
- b.) The main raw materials for production of the Product are monomers: \*\*\* and \*\*\*.
- c.) The product is sold in the form of bales, weighing \*\*\*kg, approximately \*\*\* mm.
- d.) The Product is used in production of car tires and inner tubes, conveyor belts, footwear, cables, hosepipes and various technical rubber articles.
- e) Normal value is claimed based on sales in home market.

**Examination by the Authority**

(i) Normal Value

During the POI, M/s Synthos Dwory has sold \*\*\* MT of 1500 series and \*\*\* MT of 1700 series and M/s Synthos Kralupy has sold \*\*\* MT of 1500 series and \*\*\* MT of 1700 series in the domestic market. All sales in the domestic market by both the companies were made to non-affiliated parties during the POI. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods for each series. Authority notes that profitable transactions of Synthos Dwory and Synthos Kralupy were more than \*\*\* % of the total domestic sales for both 1500 and 1700 series, therefore authority has considered all domestic sales for the determination of the normal value.

Synthos Dwory has claimed adjustment on account of inland and ocean freight, insurance, commission, packing, other sales variables & credit cost to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT for 1500 series and \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT for 1700 series respectively, the same has been allowed by the authority. Accordingly, the normal value for Synthos Dwory at ex-factory level works out to US\$ \*\*\* per MT for 1500 series and US\$ \*\*\* per MT for 1700 series.

Synthos Kralupy has exported \*\*\* MT of 1700 series only to India, therefore Authority has determined normal value for 1700 series only for Synthos Kralupy. Synthos Kralupy has claimed adjustment on account of inland freight, insurance, commission, packing, other sales variables & credit cost to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively and the same has been allowed by the authority. Accordingly, the Normal value for Synthos Kralupy at ex-factory level works out to US\$ \*\*\* per MT for 1700 series.

(ii) Export Price

From the response filed by Synthos Dwory and Synthos Kralupy, the Authority notes that Synthos Dwory has exported \*\*\* MT of 1500 series and \*\*\* MT of 1700 series to India and Synthos Kralupy has exported \*\*\* MT of 1700 series to India. All the exports were made to unrelated parties.

Synthos Dwory has claimed adjustment on account of inland and ocean freight, insurance, commission, packing, bank charges, other sales variables & credit cost to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT for 1500 series and \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT & \*\*\* US\$/MT for 1700 series respectively, the same has been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price for Synthos Dwory at ex-factory level works out to US\$ \*\*\* per MT for 1500 series and US\$ \*\*\* per MT for 1700 series.

Synthos Kralupy has claimed adjustment on account of inland freight, bank charges, insurance, commission, packing, other sales variables & credit cost to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT & \*\*\* US\$/MT for 1700 series respectively and the same has been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price for Synthos Kralupy at ex-factory level works out to US\$ \*\*\* per MT for 1700 series.

The weighted average dumping margin for 1500 and 1700 series for Synthos Dowry comes to \*\*\* US\$/MT. Dumping margin for Synthos Kralupy works out to \*\*\* US\$/MT. Overall dumping margin for Synthos Dwory and Synthos Kralupy comes to \*\*\* US\$/MT.

**b. Non-cooperative producers/exporters**

**A. M/s Trinseo Europe GmbH**

M/s Kanth & Associates representing M/s Trinseo Europe GmbH has filed response through letter dated 28/3/2016 providing details of 1723/1739 ESBR grades exported to India. Further it has been stating that M/s Trinseo Europe GmbH has a consignment manufacturing agreement with M/s Trinseo Deutschland GmbH.

**Examination by the Authority**

A questionnaire was filed by M/s Trinseo Europe GmbH (TEG) which has a consignment manufacturing agreement with M/s Trinseo Deutschland GmbH.

The response filed by M/s TEG was deficient and therefore producer/exporter was requested for completing the data are requesting their consent for onsite data verification, vide email dated 14/10/2016. The Authority in view of the above on account of lack of data sufficiency and consent for onsite verification, has not considered the producer/exporter for individual assessment and treated it under residual category as per rules.

For non-cooperative/residual producers/exporters, the highest dumping margin/injury margin evaluated for either of the two series of product under consideration in the analysis of cooperating exporters has been referenced.

EU							
Producer/ exporter	NV \$/MT		EX-EP \$/MT		DM \$/MT (wt. average)	DM% \$/MT(wt. average)	DM Range (%)
	1500 Series	1700 Series	1500 Series	1700 Series			
(i) Synthos Dwory 7 Sp. Z. Oo, Poland	***	***	***	***	***	***	10 – 20
(ii) Synthos Kralupy A.S., Czech Republic (1700 series only)	***	***	***	***	***	***	0 – 10
Weighted Average-of (i) & (ii) above	***	***	***	***	***	***	10 – 20
Residual Producers/exporters including M/s Trinseo	***	***	***	***	***	***	20 – 30

**II. KOREA RP**

**a. Cooperative producers/ exporters**

**A. M/s Kumho Petrochemical Co., Ltd. Korea RP (“KKPC”)**

16. M/s KKPC has submitted questionnaire response for its normal value computation and total exports to India. The submissions by KKPC are as follows:

a) The product is produced only at its Ulsan Synthetic Rubber Plant. –The exports to India in POI have been made directly and indirectly through Daewoo International Corporation.

17. Daewoo International Corporation, Korea RP, the exporter has submitted, that their company is only a trading company which, procures the subject goods from producers/ exporters based in Korea RP and resells them to India either directly or through Daewoo International, Singapore.\*\*\*MT of subject goods in POI has been exported by them to India. The weighted average CIF is determined as\*\*\*\$/MT.

18. Daewoo International, Singapore, the exporter has submitted, that their company is only an exporter of the

subject goods \*\*\*MT of subject goods in POI has been exported by them to India, at a weighted average CIF of \*\*\*/MT.

#### **Examination by the Authority**

##### **(i) Normal Value**

19. During the POI, KKPC has sold \*\*\* MT of 1500 series and \*\*\* MT of 1700 series in the domestic market. All sales in the domestic market by KKPC were made to non-affiliated parties during the POI. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods for each series. Authority notes that profitable transactions of KKPC were less than \*\*\* % of the total domestic sales for 1500 series and more than \*\*\*% of the total domestic sales for 1700 series. Therefore authority has considered only profitable domestic sales for 1500 series and all the domestic sales for 1700 series for the determination of the normal value.
20. KKPC has claimed adjustment on account of inland freight, credit cost, packing & level of trade to an extent of \*\*\* US\$, \*\*\* US\$ and \*\*\* US\$ for 1500 series and \*\*\* US\$, \*\*\* US\$ and \*\*\* US\$ for 1700 series. The authority has allowed all the adjustments except level of trade. Accordingly, the normal value for KKPC at ex-factory level works out to US\$ \*\*\* per MT for 1500 series and US\$ \*\*\* per MT for 1700 series.

##### **(ii) Export price of M/s. KKPC and its trader M/s. Daewoo International Corporation, Korea and M/s Daewoo International, Singapore**

21. From the response filed by KKPC, the Authority notes KKPC has made direct exports to India and also through unrelated trader M/s. Daewoo International Corporation, Korea and M/s Daewoo International, Singapore. KKPC has made direct exports of \*\*\* MT of 1500 series & \*\*\* MT of 1700 series to unrelated parties in India. KKPC has also exported \*\*\* MT of 1500 series & \*\*\* MT of 1700 series to India through Daewoo International Corporation, Korea and M/s Daewoo International, Singapore.

22. KKPC has claimed adjustment on account of inland freight, ocean freight, insurance, port expenses, bank charges, credit cost, packing & sales commission to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT & \*\*\* US\$/MT for 1500 series and \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT & \*\*\* US\$/MT for 1700 series respectively. The authority has allowed all the adjustments. Accordingly, the net export price for KKPC at ex-factory level works out to US\$ \*\*\* per MT for 1500 series and US\$ \*\*\* per MT for 1700 series respectively. While computing the exfactory export price, the Authority after examining the response filed by M/s Daewoo International Corporation, Korea and M/s Daewoo International, Singapore has ensured that exports through them were profitable and that all appropriate adjustments have been considered.

23. The Authority has verified data for post export discounts and has not found any evidence/justification for this or any other adjustments.

24. The Authority notes that the response by the producer/exporter is complete covering total domestic sales and exports to India. The Authority has therefore determined a single weighted average dumping margin for the producer for both its export channels i.e. direct and through Daewoo international and Daewoo International, Singapore.

25. The dumping margin for 1500 series, 1700 series and weighted average of 1500 and 1700 series comes to \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively.

#### **B. M/s LG Chem Ltd. (“LG Chem”)**

26. M/s LG Chem has submitted the questionnaire response for its normal value computation data, while the 5 traders have filed separate responses on export prices. The submission are as follows:

- It has exported through the channels of distribution - Direct exports to the end user in India, exported to Indian customer s through related exporter LG Chem America Inc., and, unrelated exporters Hansuk Chemicals Co. Ltd, Everlite Korea Co. Ltd., Hearty Chem Corp, and Wonchem Ltd.
- LG Chem America Inc. is a wholly owned subsidiary of LG Chem, Ltd. It is responsible only for sales activities of the goods manufactured by LG Chem, Ltd. The Company does not sell the subject goods in the domestic market.
- Hansuk Chemicals Co. Ltd. is 100% owned by Korea Petroleum Ind Co., Ltd. It does not manufacture subject good or any other in particular. As a trading company, specifications of the product is not maintained or differentiated from what was purchased.
- Everlite Korea Co. Ltd. does not manufacture subject good or any other in particular.
- Hearty Chem Corp does not manufacture the subject good or any other goods.

- Wonchem Ltd company does not manufacture the subject good or any other goods. As a trading company, specifications of the product is not maintained or differentiated from what was purchased. No catalogues or brochures in respect to the subject goods is maintained by the Company.

#### **Examination by the Authority**

##### **(i) Normal Value**

27. M/s LG Chem Ltd., Korea (LG Chem) has sold 1500 series and 1700 series in the domestic market to an extent of \*\*\* MT and \*\*\* MT respectively during the POI. The sales in the domestic market are in sufficient quantity and the Authority has determined the normal value of the 2 series separately based on domestic sales by LG Chem during the POI. The Authority has applied the ordinary course of trade test by comparing the exfactory domestic selling price with the exfactory cost of production and observes that in case of 1500 series \*\*\* % and in 1700 series \*\*\* % transactions in the domestic market are in profit. Therefore these profitable transaction have only been considered for determination of the normal value.

28. The producer/exporter has claimed adjustments on domestic selling price for 1500 series on account of freight expenses, credit expense and packing expense which have been considered at \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively and for 1700 series which have been considered at \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively for computing the normal value.

The normal value comes to \*\*\* \$/MT and \*\*\* \$/MT for 1500 series and 1700 series respectively.

##### **(ii) Export Price**

29. M/s LG Chem has exported \*\*\* MT and \*\*\* MT of 1500 series and 1700 series respectively during POI to India directly and through traders claiming adjustments on account of inland freight, ocean freight, other expense, credit expense, bank charges, overseas insurance, customs agent fee and packing expense to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT for 1500 series respectively and to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT respectively for 1700 series. M/s LG Chem has exported \*\*\*% directly and remaining \*\*\*% through 5 traders i.e. M/s Hansuk Chemicals, M/s Everlite Korea Co., Ltd, M/s Hearty Chem Corp, and M/s Wonchem Ltd (unrelated), M/s LG Chem America Inc(related). Since the entire response of domestic sales and exports of PUC during POI has been reported and verified, the Authority has considered a single weighted average dumping margin for the producer for export through both its channels i.e. direct exports and exports through traders. The Authority has considered these adjustments and determined the ex-factory export price as \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT for 1500 and 1700 series respectively. For all indirect exports through 5 traders which is even though miniscule the Authority has ensured that such exports are in ordinary course and no warranted adjustment for exfactory export price is missed out.

The dumping margin for 1500 series, 1700 series and weighted average of 1500 and 1700 series comes to \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively.

#### **b. NON COOPERATIVE PRODUCERS/ EXPORTERS FROM KOREA RP**

30. For non-cooperative/residual producers/exporters, the highest dumping margin/injury margin evidenced at either of the two series of product under consideration in the analysis of cooperating exporters has been referenced.

<b>Korea</b>							
Producer/ exporter	NV \$/MT		EX-EP \$/MT		DM \$/MT (wt. average)	DM% \$/MT(wt. average)	DM Range (%)
	1500 Series	1700 Series	1500 Series	1700 Series			
KKPC (Weighted Average) including – exports through Daewoo International/ Daewoo International, Singapore	***	***	***	***	***	***	0 – 10
LG	***	***	***	***	***	***	0 – 10

(Weighted Average)- including 5 traders							
Residual Producers/exporters	***	***	***	***	***	***	0 – 10

### III. Thailand

#### A. M/s BST Elastomers (“BSTE”)

31. M/s BSTE has stated in its submission/partial response dated 1/4/16 that their share in exports was less than 5 % of the demand which cannot cause injury to the Domestic Industry. Also the dumping margin for them would be in the range of 0 – 2 %.

#### Examination by the Authority

32. The Authority notes that M/s BSTE, Thailand filed partial data only on 1/4/2016 that too not as per the structured questionnaire. Subsequent to the oral hearings held on 14/09/2016 and 04/11/2016 they reiterated their submissions filed on 1/4/16 emphasising that BSTE’s share was less than 5% of the demand therefore it could not cause injury.

Further it has been stated that the Dumping margin on the basis of BSTE’s cost of production would be 0 – 2 % only but for this some unsubstantiated data has been provided.

The Authority has therefore evaluated the normal value for the subject goods considering optimum consumption norms for the major raw materials and utilities, purchase price claimed by BSTE and correlated with international prices of purchased raw materials, prices of captively produced raw material, including reasonable conversion cost, interest, SGA, and reasonable profit etc. in accordance with the best available information as per Rule 6 (8) to evaluate the Normal value. Data on conversion factor mentioned by BSTE has also been considered, to the extent feasible.

The normal value for BSTE and all producers/exporters of Thailand comes to \*\*\* US\$/MT for 1500 series and \*\*\* US\$/MT for 1700 series. For the purpose of exfactory export price, the Authority has considered the weighted average CIF import price of 1500 and 1700 series separately as per DGCIS data and allowed adjustments on CIF, ocean freight, marine insurance (0.5 % of CIF), commission (3% of FOB), Bank Charges (0.5% of FOB), Port expenses (0.5% of FOB) and Inland Freight (0.5% of FOB) to an extent of \*\*\* US\$/MT, \*\*\*US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, and \*\*\* US\$/MT for 1500 series and \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT for 1700 series respectively as per the evidence provided by the petitioner. The Exfactory export price comes to \*\*\* US\$/MT for 1500 series and \*\*\* US\$/MT for 1700 series.

The dumping margin for 1500 series, 1700 series and weighted average of 1500 and 1700 series comes to \*\*\* US\$/MT, \*\*\* US\$/MT and \*\*\* US\$/MT respectively.

The dumping margin as evaluated above has been applied for all producers/exporters of Thailand including BSTE.

Thailand							
Producer/ exporter	NV \$/MT		EX-EP \$/MT		DM \$/MT (wt. average)	DM% \$/MT(wt. average)	DM Range (%)
	1500 Series	1700 Series	1500 Series	1700 Series			
All producers/exporters including BST Elastomers Co. Ltd.	***	***	***	***	***	***	10 – 20

**E. INJURY****Submissions made by Domestic Industry**

33. The domestic industry has submitted that:

- a.) Since there was no production of subject goods in India up to Jan'14, entire demand of subject goods was being met by imports only. However, after commencement of production, the domestic industry could not get its projected share in demand despite the fact that domestic industry is having significant capacities.
- b.) The demand for the product in the country has increased gradually over the past periods and is also likely to show increase in future. The demand for the product under consideration fully justifies the capacity installed by the ISRPL and Reliance Industries Ltd. As against the above mentioned past, present and potential demand for the product under consideration, combined capacities with the domestic industry are now 2,70,000 MT. However, despite this level of demand, the capacity utilization of the domestic industry is abysmally low so far. Establishment of domestic industry is being retarded by dumping of the product under consideration in the Indian market.
- c.) Imports from the subject countries have increased in absolute terms till 2014-15 and declined thereafter in POI due to commencement of production by the petitioners.
- d.) Imports from the subject countries have remained significant in relation to total imports, consumption and production in India despite sufficient capacities lying with the petitioners.
- e.) Imports from the subject countries have remained so significant that the same has prevented the domestic industry from increasing its production. In fact, so significant were the imports that the domestic industry has been prevented from selling the goods to the extent of its production.
- f.) Domestic industry is not able to utilize capacities because of its inability to sell the product in the market. The low volumes of sales are a result of significant dumping of the product in the Country.
- g.) Domestic Industry is not able to sell its product in domestic market and resultantly inventories are piling up which are further forcing domestic industry to incur carrying cost.
- h.) Domestic industry has to incur significant interest cost on the working capital loan. This has resulted in further injury to domestic Industry. Though the domestic industry's sales volume is increasing, it is much lower than the sales volumes that the industry could have achieved in the absence of dumping.
- i.) Despite curtailment of production, the Inventories with the industry are increasing in view of the inability of the industry to sell the product due to dumping of the subject goods from the subject countries.
- j.) Market share in demand of subject goods is showing positive trend. Further, the domestic industry should have by now achieved a decent market share in the Country. However, significant dumping of the product is very adversely impacting the rise in the market share of the domestic industry.
- k.) The domestic industry had projected that the difference between the selling price of the product and costs on account of raw materials would be at least in the region of US\$ 800 pmt. Any price that is below this delta [delta in the industry is known as the difference between the selling price of the product and costs on account of major/principal raw materials. The term is widely known/understood in petrochemical industry] means a loss to the domestic industry. In fact, given that the domestic industry has introduced an import substitute product, the domestic industry should have got a very good price for the product produced by the domestic industry. The delta however achieved by the domestic industry on the sales made during this period is far lower than the expected delta, as would be seen from the information enclosed with the petition earlier filed. Petitioners submit that the fact that the imports are causing injury gets fully established by this single factor alone.
- l.) Profits, profit before interest, cash profits and return on investment, all have remained very adverse since commencement of production. The primary reason for this adverse profitability is aggressive dumping by the subject countries.
- m.) The domestic industry has short existence so far and these factors are in any case irrelevant for a new company, which commenced commercial production in Feb., 2014.
- n.) Productivity has moved in the same direction as that of production.
- o.) Growth of the domestic industry is adverse, both, in terms of volume and price parameters. Growth with regard to sales, production, profits, return on investments and cash flow was very adverse during the proposed period of investigation, as compared to the projections that were drawn by the petitioner at the time of setting up of the plant.
- p.) Details of investments made during the injury period can be seen in the information on gross & net fixed assets. Despite fresh investments, the performance of the domestic industry is adverse. Significant investment should have

resulted in significant revenue and profits. However, domestic industry is not able to produce and sell to the extent it could have because of dumping of the product under consideration in the Country. The domestic industry suffered significant financial losses.

q.) In the instant case, the ISRPL has commenced the commercial production w.e.f. Feb., 2014 (ISRPL) and Reliance Industries Limited has not yet begun commercial production till the end of POI. Therefore, petitioners submit that the Designated Authority may consider (a) actual performance so far to establish effect of dumping, (b) potential situation in order to establish threat of injury and (c) whether dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry in India.

r.) Petitioners submit that the past data for three years, in any case, is not relevant for the reason that the petitioners do not have any past history of commercial production and there was no other producer of the product under consideration in India.

s.) There is no requirement under the law that the domestic industry should have started commercial production to claim material retardation.

t.) With regard to the approval process, it is a process which is undertaken by the consumers and the producers are not to be blamed for the same. Further, the petitioners were approved by the consumers whose collective demand in POI was in excess of 70% whereas the supply by the domestic industry only accounted for 19%, which is due to dumped imports.

u.) It is illogical to connect high prices of crude and the profitability of the PUC.

v.) Rate of return on capital employed is standard and should not be changed on a case by case basis.

w.) Losses of the Petitioners are not due to a decrease in demand as can be seen if depreciation and interest over the period are removed.

x.) Utilizing time lag approach is permitted for calculating dumping margin, price undercutting and injury margin is endorsed under the principles of fair comparison if accuracy demands it.

y.) There are no other factors leading to injury to the domestic industry apart from the imported goods.

z.) The three forms of injury can coexist, in cases of injury, as the rules do not state that 3 forms of injury cannot be co-claimed, but only implies that if one form of injury is not found, other form may be examined.

aa.) The decline in capacity utilization is not owing to addition of capacity as capacity has not been increased by the domestic industry over the injury period.

bb.) Actual cost of production not considered owing to high fixed cost involved in the starting period for new entrants in the market.

cc.) The performance of the applicants is not impacted due to normal start up conditions of a company entering in market. Performance is impacted by dumping. Further, the performance of the domestic industry is worse than what could reasonably be expected. Comparison of projected performance with the actual performance will readily establish the same.

#### **Submissions made by importers, exporters, users and user associations**

34. The importers, exporters, users and user associations and other interested parties have submitted as follows:

a.) Adjustments made by domestic industry for export price are abnormally high.

b.) No guidelines have been evolved for determination of “material retardation” under Indian law and thus, the initiation of the subject investigation is bad in law.

c.) Data merely indicates normal startup conditions and the Petitioner cannot expect immediate achievement of sales and market share.

d.) A materially retarded Petitioner would not be able to expand capacities.

e.) The alleged injury is due to the lack of product approvals from end-users/buyers which lowered sales and prices of the DI, ‘off-grade’ sales by RIL at low prices, change in market conditions between the planning stage and stage of commencement of plant, new capacity additions and weakened demand for SBR, startup costs in lieu of delayed commercial production, increased trade with Korea and Thailand due to India-Korea CEPA and India-ASEAN FTA; other factors as listed in ISRPL’s annual report such as significant cost overruns, delayed start of commercial production, significant fall in natural rubber prices influencing price and sales of SBR, locational disadvantage of ISRPL.

f.) The costs and losses of the domestic industry show a declining trend which indicates stabilization, and lack of

alleged material retardation and alleged injury.

g.) The petitioner has calculated normal value on the basis of inflated cost and has wrongly claimed confidentiality over the constructed normal value. In this regard, *Birla Ericsson Optical vs Designated Authority* 2004(167) E.L.T. 163 (Tri. - Del.) was cited.

h.) Petitioner's inventories are declining which shows that its performance is improving

i.) The Respondent's capacities have increased, and so have imports coming from Korea RP.

j.) The Authority should consider planned costs of the Petitioners and not their actual costs.

k.) Related Party transactions must be readjusted for reflecting fair prices of Petitioner as it is critical to examine whether the transactions with Marubeni and IOCL have been done at arm's length.

l.) The adjustments made by the Petitioners with respect to export price are abnormally high.

m.) SBR 1700 series imports rose from 1495 MT to 70787 MT from '12-13 to the next year which raises doubts over the authenticity of the import data.

n.) Return on Capital Employed gives undue advantage to domestic industry and 41% profit margin on equity is not reasonable, actual profit must be adopted.

o.) The Petitioner has taken Q1 of 2014-2015 as the base period of indexation instead of February 2014. Indexation of indices such as demand and market share is illogical. The base taken must have been the POI and not the previous financial year. Non-confidential indexed data provided is contrary to established methodology.

p.) Petitioner has not provided the figure for the injury indicators separately for the sub product grades falling under 1500 and 1700 series manufactured by the domestic industry.

q.) Injury data of DI clearly establishes no adverse impact on the DI whereby installed capacity increased from 100 MT in Apr-Jun '14 to 225 in POI, Production increased from Apr-Jun '14 to Jul-Sept '15 by 365%, Domestic sales volume increased by 408% from Apr-Jun '14 to Jul-Sept '15. Volume of imports declined by 15% to 148,104 MT in POI from 173,323 MT in '14-15, Market share increased as imports fell by 15%, price suppression does not exist, Lack of profits on account of other factors such as interest compound and start up cost.

r.) The Petitioner cannot claim both the injury suffered due to material retardation and material injury as the law does not allow this.

s.) The alleged injury is due to lack of product approvals from end-users/buyers which lowered the sales and the prices of the domestic industry, off grade sales, stage of commencement of plant, new capacity additions and weakened demand for SBR, start up costs in lieu of delayed commercial production.

t.) ISRL's annual report contains factors which have affected their operations such as significant cost overruns, delayed start of commercial production, significant fall in natural rubber prices influencing price and sales of SBR and locational disadvantage of plant.

u.) WTO proposed amendments are not legally binding.

v.) The decline in capacity utilization is on account of capacity addition and not imports.

w.) The claim of suffering losses should be attributed to weak demand as accepted by one of the petitioners in their annual reports.

x.) 22% Return on Capital Employed gives undue advantage to DI and 41% profit margin on equity is not reasonable, actual profit must be adopted. ROC must not be hypothetical and should be revisited. [*Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. DA*] This reflects EU practice accurately. *EFMA V Council* [1999] ECR II-3291

y.) DI has not provided the figure for the injury indicators separately for the sub product grades falling under 1500 and 1700 series manufactured by the DI.

z.) DI argued that it is getting materially retarded on account of Korean imports and therefore there is no basis for including imports from EU and Thailand.

aa.) Post POI Situation clearly indicates that domestic industry is performing well and not suffering injury.

bb.) No price based injury or volume injury as per petition and information available.

- cc.) Planned costs of the Petitioner should be considered and not their actual costs.
- dd.) Related Party Transactions involving the Petitioners should be examined for determining whether they have been done at a fair price and at arm's length.
- ee.) Import data is incorrect as Non-PUC goods are included in the import statistics supplied by domestic industry.
- ff.) Provisional duties cannot be imposed in cases of material retardation.
- gg.) No guidelines exist for determining material retardation under Indian law.
- hh.) Data provided by domestic industry merely indicates normal start-up conditions.
- ii.) Capacity utilization has increased since April-Jun '14 from 100 MT to 225 MT in the POI. Due to this there is expected to be a decline in capacity utilization.
- jj.) DI's claims that its operating rate is 90% are contradicted by its own annual report that provides globally it is 70% and in Korea it was 40%-50%.
- kk.) The oral submission by the DI that the delta has improved by 53% is baseless and must be attributed to decline in global consumption, decline in operating rates, increase in interest payment and depreciation.
- ll.) DI admitted that there is negative price undercutting.
- mm.) Arbitrary adjustment on the basis that exporters receive interest free credit at the rate of 12% for 90 days is not permitted by the law. No evidence has been submitted.
- nn.) The domestic price of SBR 1502 and 1712 is INR 93,400 and 86,000 whereas landed price is much higher.
- oo.) The DI is not suffering any injury since the landed values of the imports are higher than the NIP of the domestic industry. The IM has to be determined by considering the average weighted price and not the lowest price reported in India. The positive injury margin is not in accordance with the law by inflating and submitting the incorrect data and therefore liable to be rejected.
- pp.) Steep decline in import price as well as domestic industry prices owing to the globally declining prices of Butadiene and Styrene which have a correlation with crude.
- qq.) Initiation based on normal values constructed upon the domestic industry's cost of production is not consistent with Article 5.2 of the WTO Anti-dumping Agreement.
- rr.) RIL cited weak demand in its annual report as being the cause of their shortcomings and therefore it is not due to imports.
- ss.) RIL has not started commercial production and the domestic industry is claiming material retardation when it is not eligible to supply PUC commercially.
- tt.) Projections in the domestic industry's project report cannot be accurate as in 2012-13, the market was optimistic owing to high crude which have more than halved since.
- uu.) DI cannot claim material injury, threat of material injury and material retardation simultaneously.
- vv.) The performance of domestic industry does not indicate any injury on account of imports from the subject countries. There are other factors which lead to the break in the causal link between the claim of material injury and the imports from the subject countries.
- ww.) Material injury, threat of material injury and material retardation cannot be claimed simultaneously.
- xx.) Exporting countries cannot be blamed if the Indian industry is lacking in infrastructure or cannot meet the demand of the market.
- yy.) M/s LKS representing M/s KKPC, M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. and M/s Rishiroop Pvt. Ltd. through letter dated 24/5/2017 submitted that in post POI i.e. Oct15- Sep 16 the share of imports from Korea have declined by 27% and petitioners market share have also increased substantially as users have increased procurement from Domestic Industry, due to the approval process by users. Therefore, post POI data is highly relevant for material retardation examination.
- zz.) M/s All India rubber industry association (AIRIA) has submitted that it has requisite legal basis as per 6(6) and 6(5) to make submissions. They have stated that the initiation is faulty and premature, historical rate of return be considered for NIP and users industry interest be also considered. Further the purchase of raw material by ISRPL is not a fair price.

aaa.) M/s Luthra & Luthra representing ATMA have submitted that claim of domestic industry in Normal value and adjustment is frivolous. There is no material retardation and initiation is erroneous. The quantum of procurement has increased for domestic industry. Material retardation and material injury cannot be considered together and there is no causal link. Investigation be only restricted to Korea.

bbb.) The Government of Korea has stated that the Authority should examine factors other than dumping (i.e. non-attribution) regarding injury to domestic industry viz. start-up costs of Domestic industry, delayed start, locational disadvantage, fall in natural rubber prices and the fact that approval process by user industry generally takes long. Further imports from Korea have reduced. The petition is premature and other factors are the reasons for injury. The sales of domestic industry have increased quarter to quarter. There is negative price undercutting reported and that Authority should disclose the methodology on material retardation.

ccc.) European Commission, Director General of trade has mentioned that the Authority should investigate dumping margin on the basis of established practice without deviating to order/contract date, examine injury as per WTO Article 3.4 and that reference not to be made to any amendment proposal in as WTO as mentioned by domestic industry. Further there is no case of material retardation to the domestic industry. The domestic industry is impacted by start-up costs. The other factors like duty reduction of imports from subject countries. Project report projected performance be considered and the case terminated.

ddd.) M/s WTC representing M/s LG Chem and its five traders stated that the MTR conducted on Anti-Dumping duties levied on the basis of final finding dated 2/6/98, were revoked on 1500 and 1700 series and those condition still continues. Domestic industry non-confidential petitions violate requirement of Rule 7 as it is grossly deficient. There is no evidence of injury and causal link and import data is manipulated. The claim of material retardation is misplaced as both companies have started production and have attained 40% capacity utilization. The injury to the domestic industry is due to high start-up cost, off grade material produced by them due to which heavy discount are to be given. The fall in import price is due to fall of crude prices and consequently the prices of styrene and Butadiene and is not a phenomenon of dumping.

eee.) Methodology of NIP should be revised especially with regard to Return of 22% keeping in view the CESTAT's ruling in Bridgestone tyre manufacturing case and also EU's practice pronounced in an order off European Fertilizer manufacturing association wherein court held that normal profit achieved in normal situations of no dumping be adopted should be considered in this case.

fff.) M/s LKS representing Synthos Dwory and Synthos Kralupy have submitted that initiation is faulty and claim of simultaneous injury of 3 forms material, threat of injury and material retardation is untenable. Grades ESBR 1739 and ESBR 1789 be excluded. The claim of domestic industry on lag period for dumping margin, material retardation are not faulty and not tenable. The post POI data needs to be examined to evaluate material retardation claim. The injury to domestic industry is due to non-tyre sector market where the two domestic industry producers are hitting each other. Further losses are due to off grade material produced by the domestic producers. Further domestic industry has not honoured the orders placed by user industry. Factors other than dumping like cost over runs, India-ASEAN FTA, delayed commercial production, locational disadvantage, lack of approvals, weakened demand of SBR, and fall in natural rubber prices have caused injury to domestic industry.

#### **Examination by the Authority**

35. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury both material and material retardation to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties. For the material injury, ISRPL's data has been referenced who had declared commercial production prior to POI while for material retardation, the data of M/s RIL has been examined who declared commercial production in post POI.
36. The AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry.

37. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

#### **Cumulative Assessment**

38. Annexure II (iii) of the Anti-Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;
  - b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
39. In the present case, the margin of dumping from each of the subject countries have been found to be more than the de minimis limit prescribed; the volume of dumped imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and the exports from the subject countries directly compete inter se and with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. Cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product. The Authority has therefore cumulatively assessed the effect of dumped imports.

#### **Economic parameters of the domestic industry**

40. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as under:

*“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*

41. It is not necessary that all parameters of injury need to show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Authority has considered all injury parameters and thereafter has concluded injury to the domestic industry due to dumping.
42. The Authority has therefore examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

#### **Assessment of Demand**

43. The demand for the subject is total of domestic sales and imports of subject goods from all countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S with appropriate correlation with responses filed by producers/exporters and importers. The Authority notes that demand for the subject goods increased significantly over the injury period as depicted in the table below.

**Table 2:** Demand of subject goods

Period	Unit	Subject countries	Other Countries	Total Imports	Indian Production	Indian Demand
2012-13	MT	1,18,468	37,357	1,55,825	-	1,55,825
2013-14	MT	1,58,567	18,838	1,77,405	-	1,78,031
2014-15	MT	1,57,514	9,196	1,66,710	46,657	1,93,234
Q1 14-15	MT	27,807	1,886	29,693	5,168	32,616

Q2 14-15	MT	49,452	3,683	53,135	5,977	57,053
Q3 14-15	MT	40,948	2,981	43,930	19,601	49,465
Q4 14-15	MT	39,307	645	39,952	15,911	54,100
Q1 15-16	MT	35,436	1,077	36,513	32,985	60,583
Q2 15-16	MT	33,040	2,626	35,666	24,043	54,397
POI	MT	1,48,732	7,329	1,56,061	92,540	2,18,546
POI (quarterly)	MT	37,183	1,832	39,015	23,135	54,636
Post POI- 6 months	MT	53,465	2,284	55,749	56,784	1,14,517
Post POI- 3 months	MT	26,732	1,142	27,875	18,928	57,258

44. It is seen from the above table that the demand for the product in the country has increased significantly over the period on an annual basis.

**Volume Effect of Dumped Imports on Domestic Industry's Import Volumes and Share of Subject Country**

45. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries are as under:

**Table 3: Absolute Imports from the subject countries**

Volume of Imports	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
EU	MT	41,276	39,626	27,695	32,523
Korea RP	MT	74,735	1,04,994	1,11,133	1,02,034
Thailand	MT	2,456	13,947	18,686	14,175
Subject Countries	MT	1,18,468	1,58,567	1,57,514	1,48,732
Other Countries	MT	37,357	18,838	9,196	7,329
Total Imports	MT	1,55,825	1,77,405	1,66,710	1,56,061
Indian Production	MT	0	6,912	46,657	92,540
Indian Demand	MT	1,55,825	1,78,031	1,93,234	2,18,546
<b>Imports from subject countries in relation to:</b>					
Indian Production	%	-	2294.01%	337.60%	160.72%
Indian Consumption	%	76.03%	89.07%	81.51%	68.06%
Imports in India	%	76.03%	89.38%	94.48%	95.30%

46. The analysis of the above indicates the following:

- Imports from the subject countries have increased in absolute terms till 2014-15 and declined in POI because of commencement of the production by the petitioners.
- Imports from the subject countries have remained significant in terms of total imports as well as in relation to consumption and production in India in spite of the sufficient capacity available with the petitioners.
- Imports from the subject countries have remained significant and has prevented the domestic industry from increasing its production and sales. The imports have been significant enough to prevent Domestic Industry from selling the goods to an optimal extent.

**Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales**

47. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization is as follows:

**Table 4 (a)**

Period	Import from Subject countries	Import from Other Countries	Capacities with Indian Industry	Indian Demand	Production of ISRPL	Sales of ISRPL	Production of RIL	Sales of RIL
	MT	MT	MT	MT	MT (Indexed)	MT (Indexed)	MT (Indexed)	MT (Indexed)
2012-13	1,18,468	37,357	-	-	-	-	-	-
2013-14	1,58,567	18,838	-	-	-	-	-	-
2014-15	1,57,514	9,196	50,000	-	100	100	-	-
Q1 14-15	27,807	1,886	30,000	32,616	75	467	-	-
Q2 14-15	49,452	3,683	30,000	57,053	86	625	-	-
Q3 14-15	40,948	2,981	65,250	49,465	88	756	100	100
Q4 14-15	39,307	645	65,250	54,100	106	1,322	63	736
Q1 15-16	35,436	1,077	65,250	60,583	299	2,694	91	902
Q2 15-16	33,040	2,626	65,250	54,397	168	1,736	92	985
POI	1,48,732	7,329	2,61,000	2,18,546	165	1,627	87	681
POI (quarterly)	37,183	1,832	65,250	54,636	165	1,627	87	681
Post POI- 6 months	53,465	2,284	1,30,500	1,14,517	192	2,064	112	2,063
Post POI- 3 months	26,732	1,142	65,250	57,258	192	2,064	42	2,063

**Table 4 (b): production and capacity of ISRPL**

Period	Installed capacity	Production	Capacity Utilization	Domestic Sales	Average Inventory	Exports
	MT	MT	%	MT	MT	MT
Q1 14-15	100	100	17%	100	100	100
Q2 14-15	100	116	20%	134	112	189
Q3 14-15	100	117	20%	162	108	220
Q4 14-15	100	142	24%	283	83	157
Q1 15-16	100	399	69%	577	74	270
Q2 15-16	100	224	39%	372	75	174
POI	100	221	38%	349	91	205
POI (quarterly)	100	221	38%	349	91	205
Post POI- 6 months	100	257	44%	442	85	26
Post POI- 3 months	100	257	44%	442	85	26

48. It is seen from the above table that:

- a) The domestic industry installed capacities to cater to the existing demand in the country.

- b) The demand for the product under consideration in the country has increased over the injury period.
- c) Production of the domestic industry has though increased but not to an optimal level.
- d) Capacity utilization has though increased considerably over 2014-15 and the POI. However, there are significant unutilised capacity with the domestic industry.
- e) Sales of domestic industry increased in 2014-15 and in the POI due to new units commencing their production and sales.
49. It is thus noted that production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry increased due to the fact that 2 new units commenced their production, on account of which an upward trend in domestic production and sales is expected. However the upward trend is not significant which can be construed as growth of the domestic industry.

### **Market Share**

50. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

**Table 5 (a)**

Period	Sales of DI	Subject Countries	Other Countries	Total Demand
	MT	MT	MT	MT
Q1 14-15	2,923	27,807	1,886	32,616
Q2 14-15	3,918	49,452	3,683	57,053
Q3 14-15	5,535	40,948	2,981	49,465
Q4 14-15	14,148	39,307	645	54,100
Q1 15-16	24,070	35,436	1,077	60,583
Q2 15-16	18,731	33,040	2,626	54,397
POI	62,485	1,48,732	7,329	2,18,546
POI (quarterly)	15,621	37,183	1,832	54,636
Post POI- 6 months	58,767	53,465	2,284	1,14,517
Post POI- 3 months	29,384	26,732	1,142	57,258

**Table 5 (b)**

Period	Share in Demand %			
	DI	Subject Countries	Other Countries	Total
Q1 14-15	9%	85%	6%	100%
Q2 14-15	7%	87%	6%	100%
Q3 14-15	11%	83%	6%	100%
Q4 14-15	26%	73%	1%	100%
Q1 15-16	40%	58%	2%	100%
Q2 15-16	34%	61%	5%	100%
POI	29%	68%	3%	100%
POI (quarterly)	29%	68%	3%	100%
Post POI- 6 months	51%	47%	2%	100%
Post POI- 3 months	51%	47%	2%	100%

**Table 5 (c) - Share of ISRPL in Demand on indexed basis**

Period	Share
Q1 14-15	100
Q2 14-15	78
Q3 14-15	111
Q4 14-15	167
Q1 15-16	311
Q2 15-16	222
POI	211
POI (quarterly)	211
Post POI- 6 months	256
Post POI- 3 months	256

**Table 5 (d)**

Period	Subject countries Imports in relation to		
	Indian Production	Indian Consumption	Imports in India
Q1 14-15	538%	85%	94%
Q2 14-15	827%	87%	93%
Q3 14-15	209%	83%	93%
Q4 14-15	247%	73%	98%
Q1 15-16	107%	58%	97%
Q2 15-16	137%	61%	93%
POI	161%	68%	95%
POI (quarterly)	161%	68%	95%
Post POI- 6 months	94%	47%	96%
Post POI- 3 months	94%	47%	96%

51. It is seen from the above table that the market share of the domestic industry has increased since its establishment in 2014-15. However, the gain in market share of the demand, despite their being the only producers of the subject goods in the Country is not significant. The share of imports from subject country which are evaluated to be dumped remained significant over the period.

**Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry**

52. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

*“With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule*

*18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”*

53. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the price of the dumped

imports of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression is as under.

### **Price Undercutting**

54. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared the landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. The Authority has separately worked out undercutting for SBR 1500 and SBR 1700 series. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from each of the subject countries and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level. The table below shows the level of price undercutting

**Table 6: Price Effect**

Priceundercutting	Unit	Q1 14-15	Q2 14-15	Q3 14-15	Q4 14-15	Q1 15-16	Q2 15-16	POI	Post POI
<b>SBR-1500 Series</b>									
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Subject Countries as a whole									
Landed Price	Rs/MT	1,08,428	1,21,842	1,23,795	96,541	82,305	96,101	1,01,164	83,431
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting %	%	(0-10)	(15-25)	(20-30)	(30-40)	(0-10)	(20-30)	(20-30)	(0-10)
EU									
Landed Price	Rs/MT	1,25,906	1,28,748	1,29,711	1,07,549	82,436	96,031	1,08,783	82,035
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting %	%	(20-30)	(30-40)	(25-35)	(40-50)	(0-10)	(20-30)	(30-40)	(0-10)
Korea									
Landed Price	Rs/MT	1,07,953	1,20,423	1,22,067	95,532	82,349	96,202	99,901	83,762
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting %	%	(0-10)	(15-25)	(20-30)	(30-40)	(0-10)	(20-30)	(20-30)	(0-10)
Thailand									
Landed Price	Rs/MT	1,10,493	1,17,700	1,19,755	82,165	81,256	94,084	91,228	82,183
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting %	%	(10-20)	(10-20)	(20-30)	(10-20)	(0-10)	(10-20)	(15-25)	(0-10)
<b>SBR-1700 Series</b>									
Subject Countries as a whole									
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Subject Countries as a whole									
Landed Price	Rs/MT	1,02,806	1,12,377	1,15,378	91,890	81,464	95,757	96,086	81,620

Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting %	%	(0-10)	(15-25)	(25-35)	(30-40)	(0-10)	(30-40)	(20-30)	(25-35)
EU									
Landed Price	Rs/MT	1,26,072	1,20,287	1,21,526	98,545	81,705	97,172	98,225	82,659
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting %	%	(30-40)	(25-35)	(30-40)	(40-50)	(0-10)	(30-40)	(20-30)	(25-35)
Korea									
Landed Price	Rs/MT	1,02,801	1,10,259	1,15,631	95,704	84,414	95,339	98,753	85,059
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting %	%	(5-15)	(15-25)	(25-35)	(35-45)	(5-15)	(25-35)	(25-35)	(30-40)
Thailand									
Landed Price	Rs/MT	98,778	1,09,361	1,07,149	77,154	75,513	89,698	84,646	70,128
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting %	%	(0-10)	(15-25)	(15-25)	(10-20)	0-10	(20-30)	(5-15)	(5-15)

55. In case of Korea while price undercutting was positive in Q1 of 15-16, it has otherwise been negative. The Authority notes that price pressure on domestic industry which has just entered into the market, a negative price undercutting indicates that industry has aggressively matched the import prices to ensure its presence in the market.

#### **Price Suppression/Depression**

56. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the Table below:

**Table 7: Price effect cost of sales and sales price**

Period	Cost of Sales	Trend	Selling Price	Trend	Landed Price	Trend
	Rs/MT		Rs/MT		Rs/MT	
Q1 14-15	***	100	***	100	92,730	100
Q2 14-15	***	94	***	102	1,04,576	113
Q3 14-15	***	95	***	101	1,11,899	121
Q4 14-15	***	68	***	73	85,034	92
Q1 15-16	***	47	***	83	72,162	78
Q2 15-16	***	60	***	82	93,063	100
POI	***	60	***	83	99,003	107
Post POI	***	54	***	79	82,612	89

57. The Authority notes that there is price suppression and depression with selling prices being lower than the cost of sales. The price underselling evaluation in the following para quantifies the extent attributable to the phenomena of dumping.

#### **Price Underselling**

58. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry by considering

data of ISRPL only has been compared with the landed price of imports. For determining the injury margin the Authority has evaluated the landed value of SBR 1500 and 1700 series separately. The landed value has been computed by adding applicable basic custom duty and cess on the assessable value of imports. In case of KKPC in respect of exports made through DWI /DWISG the CIF price of DWI/DWISG have been referenced, while for the direct exports by KKPC, the CIF prices of M/s KKPC have been adopted. Similarly in case of LG Chem the CIF price of direct export by LG Chem have been adopted. While for exports through traders the CIF price from traders data have been adopted. The export made by M/s Synthos Dwory and M/s Synthos kralupy are direct whose CIF prices have been adopted for landed value. In case of M/s Trinseo the response has been partial and producer did not consent for verification. The authority has not considered their response for individual determination of either dumping margin or injury margin. The highest injury margin amongst the cooperative producers of EU has been adopted for all other residual and cooperative producers. For M/s BSTE Thailand, the weighted average CIF price during POI has been referenced on the basis of DGCI&S data. The injury margin on the basis of the above methodology for various producers/exporters is as below:

### Table 8

[illegible]

Thailand									
All producers/exporters including BST Elastomers Co. Ltd.	***	***	***	***	***	***	***	***	20 – 30

**Profits, profitability, return on investment and cash profits**

59. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

**Table 9**

Particulars	UOM	Q1 14-15	Q2 14-15	Q3 14-15	Q4 14-15	Q1 15-16	Q2 15-16	POI	Post POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	95	68	47	60	60	54
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	101	73	83	82	83	79
Profit/loss	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(86)	(90)	(62)	(12)	(38)	(38)	(29)
Total Profit/(loss)	Rs.lacs	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(115)	(145)	(176)	(70)	(141)	(133)	(126)
Cash Profits	Rs.lacs	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(119)	(136)	(226)	(48)	(145)	(139)	(118)
PBIT- Domestic	Rs.lacs	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(119)	(150)	(171)	(46)	(124)	(123)	(95)
ROI	%	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Range	(0-20)	(0-20)	(20-30)	(20-30)	(0-10)	(15-25)	(15-25)	(15-25)

60. The Authority notes that:

- Both, the cost of sales and the selling price, declined over the period. The cost of production, despite sharply declining in the POI was still considerably higher than the selling price which resulted in a loss. The decline in cost is due to decline in raw material prices and overhead cost. The overhead cost per unit has come down due to some increase in production.
- The domestic industry had suffered increased loss, despite increase in the demand, production and sales in the POI as compared to the previous year.
- Return on investment over the injury period has shown the same trend as that of loss, while it slightly improved in the POI.
- Profit before interest and taxes (PBIT) was negative in this period
- Cash losses showed sharp increase in POI while the loss suffered was almost doubled in the POI and was significant.

61. Since the domestic industry has just started production, these factors are likely to be on the decline until the domestic industry manages to gain a foothold in the market. However it still shows that the domestic industry suffered losses since their establishment.

**Employment, Productivity and Wages**

62. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

**Table 10**

Period	Productivity per employee	Employment	Wages
	MT/No	Nos.	Rs Lacs
Q1 14-15	100	100	100
Q2 14-15	110	105	107
Q3 14-15	111	106	101
Q4 14-15	129	110	111
Q1 15-16	368	109	104
Q2 15-16	213	105	93
POI	203	109	102
Post POI	122	105	126

63. It is noted that employment with the domestic industry increased over the POI. However the per unit wages have declined.

**Inventories**

64. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

**Table 11**

Period	Average Stock
	MT
Q1 14-15	100
Q2 14-15	112
Q3 14-15	108
Q4 14-15	83
Q1 15-16	74
Q2 15-16	75
POI	91
Post POI	85

65. It is seen that inventories with the domestic industry declined modestly during in the period of investigation, but remained significant.

**Ability to raise capital investments**

66. The Authority notes that given rising demand of the product in the country, the domestic industry has made investments in setting up fresh capacity. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated adversely affecting its ability to raise funds.

**Level of dumping & dumping margin**

67. It is noted that imports from each of the subject countries are entering the country at dumped prices and that the

margins of dumping are above de-minimis limits.

### **Factors Affecting Domestic Prices**

68. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the non-injurious price of the domestic industry, causing price underselling in the Indian market. The Authority notes that the prices of the product under consideration in general should move in tandem with the prices of key raw materials and the domestic industry has been fixing its prices considering these input prices and landed price of imports. The landed value of subject goods from the subject countries is an important factor for determination of domestic prices.

### **Material Retardation of Establishment of an Industry in India**

69. The Authority notes that M/s ISRPL had commenced the commercial production w.e.f. Feb., 2014 (ISRPL) and Reliance Industries Limited has declared commercial production on 30<sup>th</sup> September, 2016. The Authority has analysed the trend of 6 months Post POI data. The Authority notes that submission on improvement of sales in post POI due to the approval accorded by the user industry to DI is an indication of only one aspect of market condition for domestic industry. The establishment of fair playing field also requires mitigating the extent of injury due to dumping evaluated during the POI. The Authority therefore notes of both the aspects in determining injury to domestic industry comprehensively. The Authority therefore notes actual performance so far to establish effect of dumping, potential situation in order to establish threat of injury and whether dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry in India.

70. Section 9B of the Customs Tariff Act provides as follows:

*9B - the Central Government shall not levy any countervailing duty or anti-dumping duty.*

*(ii) under sub-section (1) of each of these sections, on the import into India of any article from a member country of the World Trade Organization or from a country with whom Government of India has a most favored nation agreement (hereinafter referred to as a specified country), unless in accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, a determination has been made that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India; and*

Rule 11 of the Anti-Dumping Rules provides, inter-alia, as follows –

**11. Determination of injury.** - (1) *In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India.*

*(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to the establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.*

71. While the test of material injury or threat of material injury can be applied to an existing domestic industry or to the extent of operations that the domestic industry has had in the past, in the case of domestic industry yet to be fully established, the test to be applied is that of material retardation. The Authority notes that the following two conditions are relevant where the test of material retardation may be applicable:

- (i) *in case of “developing industry” which has not yet begun commercial production but substantial commitment to commence production has been made;*  
 (ii) *in case of “nascent industry” whose commercial production although has begun but the industry has yet to find its place in the market.*

72. The Authority notes the submission made by the domestic industry that the data of the past three years are not relevant in this case as the domestic industry is a nascent industry and did not have any past history of commercial production.

73. The Authority notes the guideline of WTO Committee on Anti-dumping Practices which states that the period of data collection for injury investigations normally should be at least three years, unless a party from whom data is being gathered has existed for a lesser period, and should include the entirety of the period of data collection for the dumping investigation.

74. The Authority notes the WTO's proposed amendment to the Anti-Dumping Agreement on this issue. The WTO member countries have proposed following amendment to the Agreement to address the injury in the form of material retardation to establishment of domestic industry.

3.9 *A determination of material retardation of the establishment of a domestic industry shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. An industry may be considered to be in establishment where a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the importing Member, but production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes. In making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may take into account evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made and financing obtained, and feasibility studies, investment plans or market studies.*

75. The above indicates that the member countries consider that material retardation to establishment of domestic industry is an important provision under the law. While this may not be legally binding, it still serves as a guiding factor for the purposes of determining material retardation of a domestic industry. This provision indicates that even if a company has not commenced commercial production, the company is entitled to seek protection under the rules. The proposal also guides the authority to consider the following parameters in such a situation.

- a. *a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in India;*
- b. *production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes.*

76. To analyse the above the Authority has analysed the following volume and price parameters of M/s RIL.

**Table 12**

Particulars	Unit	Q3 (2014-15)	Q4 (2014-15)	Q1 (2015-16)	Q2 (2015-16)	POI	Post POI (01/10/2015 to 31/03/2016)
Installed capacity	MT	100	100	100	100	100	100
Production	MT	100	63	91	92	87	112
Capacity Utilization	%	100	63	91	92	87	112
Domestic Sales	MT	100	736	902	985	681	2,063

**Table 13**

Particulars	Unit	Q3 (2014-15)	Q4 (2014-15)	Q1 (2015-16)	Q2 (2015-16)	POI	Post POI (1/10/2015 to 31/03/2016)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	30	20	20	26	18
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	74	78	76	77	68

Table 14

Particulars	UOM	Q3 (2014 – 15)	Q4 (2014- 15)	Q1 (2015 – 16)	Q2 (2015 –16)	POI	Post POI (1/10/2015 to 31/03/2016)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	30	20	20	26	18
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	74	78	76	77	68
Profit/loss	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	(100)	(18)	(5)	(4)	(12)	(5)
Total Profit/(loss)	Rs.lacs	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	(100)	(135)	(41)	(39)	(79)	(96)
Cash Profits	Rs.lacs	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	(100)	(135)	(41)	(39)	(79)	(95)
PBIT- Domestic	Rs.lacs	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	(100)	(135)	(41)	(39)	(79)	(93)
ROI	%	***	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	(100)	(134)	(41)	(39)	(78)	(92)

Table 15

Particulars	Unit	Q3 (2014-15)	Q4 (2014- 15)	Q1 (2015- 16)	Q2 (2015- 16)	POI	Post POI (01/10/2015 to 31/03/2016)
Average Stock	MT	100	213	214	185	84	113

77. M/s RIL declared commercial production only on 30.09.2016. In the post POI, though the capacity utilisation of M/s RIL increased the sales did not increase in proportion to the increase in production leading to increased inventory. The cost of sales has been declining over the POI and post POI but the selling price continues to be lower than the cost of production. Even though M/s RIL has declared commercial production only on 30.09.2016, the selling price in post POI is much below the fair threshold level of NIP determined for M/s ISRPL which is also an indicator for M/s RIL. Therefore, there is an evidence of price suppression and depression along with retardation on production, and attaining optimal capacity utilisation level. The adverse price impact has led to decline in profitability parameters like cash flow, PBIT and ROI.

#### Causal Link

78. Article 3.5 of the Anti-dumping Agreement and Annexure-II to the Indian Rules deals with injury to the domestic industry and is stated as under: -

“3.5 It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports, which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.”

"(v) It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the designated authority. The designated authority shall also examine any known factors other than the dumped imports, which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry."

79. The Authority has noted submissions on the likely causes of injury to domestic industry and evaluated the causal link between dumping and consequential injury on account of this only in accordance with relevant AD Rules and its consistent practice. The Authority has examined if there is a causal relationship between dumping and injury below.

**a) Volume and value of imports not sold at dumped prices:** - The domestic industry is facing injury from dumped imports entering into the country from the subject countries. Imports of product under consideration from other countries are insignificant in volume. Imports from other countries have not caused injury to the domestic industry in the POI.

**b) Contraction in demand:** - The demand of the product under consideration has shown a positive growth throughout the injury period. Hence, contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.

**c) Changes in the patterns of consumption:** - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

**d) Developments in technology:** - Technology for production of the product has not undergone any change nor there are any likely changes in coming future. In fact, petitioner has set up a new plant, which is the most recent technology available for the product under consideration. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

**e) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:** - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**f) Export performance** - The domestic industry has exported the product under consideration. The domestic industry has however segregated information with regard to sales and price parameters for the domestic operations.

**g) Performance of other products produced and sold by the domestic industry:** - This has been discussed earlier with regard to the product under consideration.

80. The Authority notes that if there is a volume and price effect from dumped imports under paragraph (ii) of Annexure II of the Rules, and the effects of injury caused by dumped imports are demonstrated in terms of the parameters set out in paragraph (iv) of Annexure II of the Rules, then, the next step to ensure that the injury is not caused by the dumped imports is through non-attribution analysis, i.e., those other factors have caused the injury. As demonstrated in the preceding paragraphs, listed known other factors do not establish that injury has been caused by these other factors. It is therefore concluded that the injury to the domestic industry has also been caused by the dumped imports from the subject countries. Following parameters show causal link: -

a) The dumped imports from the subject countries are available in large volume at prices lower than prices in India.

b) Since the domestic industry has started offering the product under consideration in the market from Feb., 2014, the prices fixed by the domestic industry are benchmarked to the import prices.

c) Presence of dumped imports is preventing the domestic industry to fully utilize their capacity and maximize its production and sales.

d) Profitability of the domestic industry is also suffering over the injury period.

e) Dumping of the product under consideration is not allowing the domestic industry to fully establish itself.

81. The Authority therefore notes that there does exist a causal relationship between the dumping and the injury.

**Factors establishing causal link**

82. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of both M/s ISRPL and M/s RIL of domestic industry has also deteriorated due to dumped imports from subject countries on account of material injury and material retardation respectively. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- a) The domestic industry is fixing its selling prices based on the import price from various subject countries. The imports of the product under consideration are causing price suppression and are preventing the domestic industry from raising the prices. The selling prices continue to be lower than the cost of production. Consequently, profits, cash flow and ROI has declined.
  - b) The subject imports are also resulting in price underselling in the market, when compared with the non-injurious price.
  - c) The growth of the domestic industry became negative in terms of various price and volume related economic parameters. While negative growth in volume parameters could somewhat be due to initial years of production, the negative growth in the price parameters is essentially due to dumping of the product.
  - d) While examining the material retardation of M/s RIL, the post POI parameters evidence suppression of production, non-optimality in capacity utilization, price underselling and overall price suppression/depression adversely affecting profitability indices.
83. The Authority has determined non-injurious price on the basis of M/s ISRPL's data by considering best consumption norms of the raw materials & utilization. The Authority has considered fixed expenses by considering optimum production volume of \*\*\* MT with best capacity utilization which the industry has projected in the project report. The Authority has also segregated and excluded various expenses considering the provisions of Annexure-III to the Rules. Capital employed of the domestic industry has been determined on the basis of provisions of Annexure III of the Rules and the return on capital employed has been computed at the optimum level of notional production. The non-injurious price of the domestic industry so determined has been compared with the landed values of the subject imports from each of the responding exporters from the subject countries and for residual producers/exporters to determine injury margin. The methodology of 'NIP' in this case to a large extent addresses the non-attribution analysis as submitted by various interested parties.

**Post disclosure comments**

84. **Submissions made by the domestic industry**

The petitioners requested disclosure of pertinent facts vide their emails dated 16<sup>th</sup> June 2017 and 17<sup>th</sup> June 2017. Petitioners received reply vide emails dated 19<sup>th</sup> June 2017.

Petitioners submit that the Authority has provided further disclosure with regard to NIP. No further information has been disclosed to the petitioners. Further, petitioners filed a detailed submissions vide email dated 20<sup>th</sup> June 2017 to highlight the need for such disclosure in the facts and circumstances of the present case. However, no further disclosure has been made to the petitioners.

In view of the above, the petitioners were unable to offer their comments effectively. Accordingly, petitioners requested additional time of one week to offer their comments. However, the petitioners received no reply to the request for extension of time made by the petitioners.

In view of the foregoing, the present submissions may kindly be considered as an interim submission on behalf of the petitioners.

It is evident from the disclosure statement that the facts that different grades of styrene butadiene rubber constitute one article and it would not be appropriate to exclude any grade. Since the petitioners are new entities in the market (one of the petitioner companies has not even commenced commercial production), it is natural that the petitioners have not started full scale production of all the grades these companies can produce. The petitioners have first focus on grades commanding majority consumption. The petitioners shall commence commercial production of remaining grades in due course. The grade wise capacity of producing different grades of petitioners are as under :

Grades	ISRPL	RIL
1502	Produced & supplied	Produced & supplied
1507	No capacity	Have capacity to produce
<b>Subtotal</b>		
1705	No capacity	Have capacity to produce
1712	Produced & supplied	Produced & supplied
1721	No capacity	Have capacity to produce
1723	Produced & supplied	Produced & supplied
1732	No capacity	Have capacity to produce
1737	No capacity	Have capacity to produce
1739	No capacity	Have capacity to produce
1778	Have capacity to produce	Have capacity to produce
1783	No capacity	Produced & supplied
1789	No capacity	Have capacity to produce

The subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the Product under consideration, in accordance with the AD Rules;

Petitioners disagree that the NIP can be determined only in respect of a company who has commenced commercial production in the facts of the present case, where injury is evidently in the form of material retardation to establishment of domestic industry in addition to the injury already inflicted on the domestic industry in respect of actual production and sale. The petitioner submits that the NIP is required to be determined in respect of all the constituents of petitioning companies. The interpretation drawn by the authority shall imply that a company who has not commenced commercial production is not entitled to protection under the law. It is, however, without any legal basis for the reason that the mere fact that a company who is establishing itself in the market is entitled to seek protection implies that the company need not have commenced commercial production. The petitioners stresses on the legal requirement that injury to the domestic industry may be in the form of “material retardation to the establishment of domestic industry”. Further, the authority has relied upon the project report in such situations and therefore the fact of actual production is of little consequences. In any case, RIL produced and supplied significant volumes of the product. Merely because production was declared as trial production does not mean that there is insufficient information for the determination of NIP.

Above all, the rules have not differentiated and distinguished between trial production and commercial production. Rule merely refers to “production”. The company has not only produced but also sold a significant volume of SBR in the market.

Domestic industry has suffered injury in the form of material injury (to the extent of its production and sale in the market) and material retardation to establishment of the industry;

Material injury and material retardation to the domestic industry is due to dumped imports from subject countries.

The dumping margin and injury margin are quite significant.

The Authority has rightly defined the product under consideration. The Petitioner is in agreement with the Authority over the decision to not exclude product grades such as 1739 and 1789 as the domestic industry has the capability to produce such grades when such orders come and the market is a fair playing field. The domestic industry has the technical capability to produce various grades as different grades are only determined by a difference in the amount of styrene and butadiene present in their composition. The current manufacturing status of grades does not erode such capability of the Petitioner.

Petitioner further submits that while capability of production may not be so relevant in a situation where a domestic producer has been in operation for quite some time now and had produced over the entirety of injury period, in a situation where domestic industry has commenced commercial production only recently and has a history of 20 months as against the injury period of four years, evidently, capability to produce becomes more relevant and appropriate parameter.

The Petitioner reaffirms that there was no domestic industry for the product under consideration in India during the injury period. Producers of SBR 1900 grade exist but are unable to produce SBR 1500 & 1700 grade, which is the product under consideration in the present investigation.

The project report given by the two petitioning companies make it evident that the petitioners have considered absence of production in the country while setting up plant. Further, as far as production of SBR by Apcotex is concerned, the company has produced only 1900 series SBR. The company does not produce SBR 1700 and 1500 series. The petitioner submits that production facilities for SBR 1900 series cannot be used for production of SBR 1700 and 1500.

Since the customs classification is indicative only, the Designated Authority may kindly specify in duty table that the product under consideration should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers. Further, the authority may kindly specify in duty table that the customs classification is indicative only. Petitioner submits that only the duty table contents are relevant in this regard. Anything mentioned in the para relating to "product under consideration" but not stated in duty table is likely to get ignored while issuing notification by the Ministry of Finance. Further, the Customs authorities at the port consider and rely upon the notifications issued by the MOF. The customs authorities do not take cognizance of the notification issued by the DGAD as final findings. It is, therefore, utmost important that the duty table itself includes all these clarifications.

The petitioners are unable to understand as to how an exporter be selling the product type at a price significantly higher than other exporters.

Petitioners have earlier raised their concerns about low quantum of dumping margin determined in the disclosure statement and have requested disclosure of pertinent documents/information/details. A copy of the communications sent to the Designated Authority is relied upon and are not being repeated for sake of brevity. Petitioners submit that unless adequate details are disclosed to the petitioners, the petitioners are unable to offer their comments on the dumping margin determined by the authority.

Without prejudice, the petitioners have done their own independent research with regard to various situations and have following submissions.

Suppression of facts by LG Chem – Petitioners find that LG Chem has resorted to suppression of vital facts from the authority. The petitioners have written a detailed letter to the Designated Authority, a copy of which is enclosed with these submissions also. Since LG Chem has resorted to suppression of vital facts, has not truthfully come before the authority and willfully withheld information, the authority should reject the entirety of questionnaire response. Petitioners further submit that it is not a case where the authority should make modifications to the dumping margin earlier determined. It is a case of vital concealment of facts and suppression of relevant information from the authority. Modification to the dumping margin shall actually imply condoning such kind of offenses by an exporter who has resorted to dumping the product in the Country. Petitioners submit that if the exporters have withheld such vital information with regard to the facts which somehow became known to the petitioners in India, there is no guarantee that the information provided by the producer with regard to their domestic sales or cost of production is credible enough. The credibility of the exporter should be a huge question mark and the questionnaire response should be rejected on this account.

The disclosure statement does not clarify whether the starting price adopted for determination of export price has been considered as CIF export price to India or the same is export price of producer. If the authority has considered CIF price to India, it follows that the export price is based on a combination of invoices raised by the producer and several traders, as the authority has found that some portion of the exports were made directly and some portions of sales were made through some related or unrelated traders. Thus, if the starting export price is the CIF export price to India, it follows that the authority has determined such export price on the basis of invoices raised onto the Indian consumers which were raised by the following parties:-

(a) (i) M/s Kumho Petrochemicals Co., Ltd, Korea RP

(ii) M/s Daewoo International., Korea RP

- (iii)M/s Daewoo International., Singapore
- (b) (i) M/s LG Chem Ltd., Korea RP
- (ii)M/s LG Chem America Inc, USA
- (iii)M/s Wonchem, Ltd., Korea RP
- (iv)M/s Heartychem Corp., Korea RP
- (v)M/s Everlite Korea Co Ltd., Korea RP
- (vi)M/s Hansuk Chemicals Co Ltd., Korea RP

In the alternative, the authority has considered the export volume and export value in the books of the producer concerned (i.e., LG Chem and Kumho Petrochemicals). If so, then, the export price has been determined on the basis of export value reported by the producer concerned. In that case, it follows that the entirety of the questionnaire response by the traders had become redundant. In that case, it is required to be examined whether the independent traders have kept a margin which was sufficient to meet their expenses and earn a reasonable profit. The traders might have kept huge margins or inadequate margins. Petitioners submit that under either situation, the margin kept by the traders become relevant to examine whether the same was sufficient and was neither lower nor higher than the expenses incurred by such traders and reasonable amount for the profit. Further, in case of invoicing through related party, the authority is required to consider the resale price of such trader's and construct backward price of the producer (the authority has in the past considered the resale price of the related trader and has deducted all expenses and reasonable profit of such related trader). It is however not clear whether the same has been done in the facts of the present case.

Valuation of captive raw materials and utilities – Petitioners had earlier submitted that the number of captive raw materials and inputs have been sourced by these producers. In a situation where a producer has a captive raw material or utility, the authority is required to consider whether valuation of such raw material or utility reported to the authority is reasonable and appropriate for the purpose of determination of cost of production. The authority has already found that significant sales in the domestic market by both the producers were below cost of production. Further, given positive dumping margin determined by the authority, it follows that significant exports by the two producers were below cost of production. Petitioners assume that the exporters have claimed their captive consumption on the basis of record and have claimed that the same is reasonable for the present purposes. However, the mere fact that the producer has claimed their captive input cost on the basis of records is insufficient for the present purposes. It does not appear from the questionnaire response or disclosure statement or any other documents disclosed to the petitioners that the exporter have provided complete details of such captive raw materials and the authority could have satisfied itself with regard to appropriateness of the valuation of such captive input by the producer.

Utilities – Both Kumho and LG Chem have significant portion of utilities getting captively generated out of production process of other product. There is nothing in the disclosure statement or questionnaire response which deals with the valuation of captive utilities.

Both Kumho Petrochemicals and LG Chem have significant captive utilities. Further, they are engaged in production of few products, some of which are listed below. Production of these products generates energy which is then converted into some form of utilities and then consumed in production of other products. It is unclear whether this fact has been disclosed to the authority; and, if so, how the value of such inputs has been charged to the cost of production of the PUC.

SGA Expenses – the authority has in the past rejected cost apportionment by Kumho Petrochemicals on account of SGA expenses and has adopted a different methodology than the one claimed by the company. The company had in fact agitated this issue before the CESTAT. Relevant decision is enclosed as Annexure 3. It is unclear whether the company has continued with its incorrect apportionment methodology and whether the authority has accepted the same. It is, however, pointed out that even the US authority have rejected the apportionment methodology adopted by LG Chem and has reapportioned their SGA expenses. Relevant extracts from the decision memorandum of the US authorities are enclosed with these submissions as Annexure 4.

Interest cost – Kumho Petrochemicals has been reporting interest expense after adjusting the same for interest income earned by the company (for different operations). Interest expenses incurred on funds taken for production of various

goods and interest income generated from investment activity cannot be compared. Such interest income generated from financing activities cannot be adjusted against the interest expenses incurred. The authority has in the past in fact rejected such reduction of interest income from interest expense and has apportioned the costs to the PUC. It is however unclear how the authority has determined COP at this time.

The turnover ratio – Kumho Petrochemicals has typically in the past determined turnover ratio by considering sales turnover (to apportion expenses on the basis of turnover ratio). However, considering that sales turnover are influenced by the relative profits of different products and therefore are unrepresentative of the expense incurred, more appropriate ratio is COGS ratio and not the turnover ratio. The COGS ratio directly show the impact of costs incurred on different accounts. It is, however, unclear whether the authority has adopted turnover ratio or COGS ratio.

Cost of production reported by TSRC completely ignored – TSRC has provided detailed information not only with regard to its own cost of production but also their estimates of cost of production of the Korean producers. TSRC is one of the world's leading producer of SBR and one of the world's most cost competitive producer of the PUC. It is, however, found that all the information provided by TSRC has been completely rejected. It does not even appear that the same has been considered as of any reference values for the present purposes.

Date of sale – Petitioners earlier contended heavily that a preliminary issue in the present case is establishing the relevant date of sale for the purpose of determining dumping margin. From the disclosure statement, the petitioners are unable to understand the basis adopted by the authority for determining relevant date of sale adopted for the determination and justification for the same given by the exporter. The date of sale could be date of contract, date of invoice, date of offer, date of arrival of goods in India, whichever forms material terms of sales. Petitioners had requested authority to determine when the material terms of sales were frozen by the exporters and the importers. Petitioners had specifically highlighted the fact that the product had been imported at materially different prices at around the same point in time. Relevant extracts from the written submissions are enclosed. The disclosure statement does not contain anything about the criteria used for establishing date of sale and the verification report has not been disclosed to the petitioners thus leading to a situation where petitioners are unable to offer their comments.

Comparison methodology – the petitioner had determined normal value, export price and dumping margin by undertaking month by month analysis. The disclosure statement however does not clarify whether the present dumping margins are based on month by month comparison or quarterly or annual comparison for the POI and appropriateness of the same.

The IHS trade journal has clearly reported that a Korean producer had negative margins in the relevant period. Further, the trade journal has quantified US\$ \*\*\* as the conversion costs of Korean producers. It is unclear how the fixed cost established by the authority compares with the estimates of IHS. It is clarified in this regard that the margins reported in IHS are not based on all fixed expenses such as SGA and interest. Thus, the actual cost of the exporter must at least be significantly higher than this cost.

The NIP has been determined by considering two alternative situations – capacity utilization of \*\*\*\*% and capacity utilization of \*\*\*\*%. Thereafter, the Authority has adopted \*\*\*\*% capacity utilization for the purpose of NIP determination.

Since the petitioner has set new production facilities, it is not a case where petitioner is already incurring full costs in the entire period. The concept of optimum utilization has been brought under the law only to adjust the costs for lower capacity utilization, when the company is already incurring all fixed expenses. However, in a situation where petitioner is not incurring full fixed cost (as the case is at present) that the petitioner would be incurring at such high capacity utilization, it would not be appropriate to consider a higher capacity utilization. For example, the table below gives production and fixed expenses in POI, 2015-16 and 2016-17.

Particulars	Unit	POI	2015-16	2016-17
Production at 90% capacity utilisation	MT	***	***	***
Salaries & Wages	Rs/MT	***	***	***
Other expenses	Rs/MT	***	***	***
Depreciation	Rs/MT	***	***	***

Finance Overheads	Rs/MT	***	***	***
TOTAL	Rs/MT	***	***	***

We had earlier submitted that the Designated Authority should reject questionnaire response in its entirety in case the exporter has not truthfully made all disclosures to the authority. Considering the way investigations are conducted, it is highly appreciated that the authority has to proceed on the basis of faith and thrust and all parties are expected to truthfully disclose all facts to the authority. We, however, now have got evidence that LG Chem, the exporter in the present case, has not truthfully disclosed all facts to the authority and has suppressed vital information from the authority.

LG Chem has not reported to the authority that it is having an office in India [namely, LG Chemicals India Pvt. Ltd.] which is involved with production or sale of the product under consideration. This office is responsible for procurement of orders and various business activities like Sales Forecasting, Strategic/Economic Planning, Personnel Training/Exchange, Engineering Services, Advertising, Sales Promotion, Distributor/Dealer Training, Procurement/Sourcing Services, Packing, Inventory Maintenance, Order Input/Processing, Direct Sales Personnel, Sales/Marketing Support, Market Research, Technical Assistance, Provide Rebates, Provide Cash Discounts, Pay Commissions, Provide Warranty Service, Provide Guarantees, Provide After-Sales Services, Perform Repacking, Provide Freight and Delivery and Provide Post-Sale Warehousing.

LG Chemicals India Pvt. Ltd. is a whole owned subsidiary of LG Chem., Korea.

In a situation where such vital business activities are being performed by a subsidiary company in India, the established legal position is to deduct overhead expenses and reasonable profit as price adjustment for the purpose of determination of ex-factory export price.

Since LG Chem has not reported that its Indian office is engaged in sales function, nor has reported price adjustments on this account, it should be considered that LG Chem has resorted to suppression of vital facts from the authority.

In a situation where an interested party provides misleading information or otherwise suppresses relevant fact, the questionnaire response is required to be rejected and dumping margin determined on the basis of Rule 6(8), i.e., facts available.

In support of the above, enclosed the relevant extracts from the questionnaire response filed by the producer where the producer has declared only its US subsidiary and has not declared Indian subsidiary; website information showing details about LG Chemicals India Pvt. Ltd.; email from petitioner company giving details about the business activities of LG Chemicals Pvt. Ltd.; relevant extracts from the questionnaire response showing price adjustments claimed by LG Chem.; relevant extracts from the disclosure statement showing the price adjustments made by the Designated Authority in the disclosure statement; relevant extracts from the final findings of the Designated Authority in the matter of Circular Weaving Machines, wherein the Designated Authority adjusted SGA and profit of the Indian arm; income statement of LG Chemicals India Ltd. showing therein details of income and expenses of LG Chemicals India Ltd. and Questionnaire response of LG – America INC showing marketing being done by them.

Some of these group companies are involved in providing services to various LG group companies, which clearly implies services being provided of the producer of SBR as well. Many group companies who are not engaged in any of manufacturing operations and are instead involved in providing some services –technical or commercial. This fact has also been suppressed by LG Chemicals and the questionnaire response is required to be rejected additionally on this account.

Subsidiaries are LG Chem HK Ltd., Hong Kong; LG Chem America, Inc., USA; LG Chem Europe GmbH Germany; LGC Petrochemical India Private Ltd., India; Haengboknuri, Korea; LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI, Turkey; LG Chem Japan Co., Ltd., Japan; Associates are LG Holdings (HK) Ltd., Hong Kong; TECWIN Co., Ltd., Korea; Lg Chem Brasil Intermediacao De Negocios Do Setor Quimico Ltda, Brazil; LG Chem Malaysia SDN.BHD.12, Malaysia; LG Fuel Cell Systems Inc., Usa; Joint Venture is SEETEC Co., Ltd., Korea; LG Corp Korea; Subsidiaries/ Joint Ventures of LG Corp. are Serveone Co. Ltd, LG CNS Co., Ltd., LG Siltron Inc., LG Management Development Institute, LG SPORTS Ltd., LG MMA Corporation

The onus for truthful disclosure is onto the responding exporter. The domestic industry cannot undertake a spying operation and provide relevant information to the authority. It has been time and again stated by the authority that the investigations are conducted on trust and faith. However, in a situation where this kind of suppression has been resorted by the exporter, the authority should hold then the trust and faith has been shattered by the exporter and exporter response is required to be rejected.

**Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties/ other Parties**

85. M/s Luthra & Luthra law offices representing M/s Automotive Tyres Manufacturing Association has filed various submissions:

- S-SBR grades are not covered within the scope of the investigation and the same has admitted by the DI in its submissions. Therefore, it is imperative that S-SBR grades be explicitly excluded from the scope of the PUC. In view of the same, the respondent submits that in the initiation notification, DA has given the product HSN code as 4002.19 (at 6 Digit level). However, it must be noted that at HSN 6 digit level, all SBR grades such as Emulsion SBR (E-SBR) and Solution SBR (S-SBR), are covered.
  - Therefore, in order to ensure that the description of the PUC in the final findings appropriately reflect that S-SBR is excluded from its scope, the respondent respectfully requests that the description of the PUC in the final findings be provided at HSN 8 digit level. This would ensure that there would be no case for any ambiguity considering the scope of the PUC in the present investigation. Lastly, it should be noted that this request on behalf of respondent is without prejudice to its argument that the factual and legal position in the present investigation does not warrant imposition of anti-dumping duty which has been elucidated in this written submission.
  - Further, it may be noted that this written submission is without prejudice, and in addition, to our submissions dated 21 March 2016, 23 September 2016, 11 November 2016, 16 November, 2016 and 03 April 2017 and letters dated 01 September 2016, 30 March 2017 and 24 May 2017. In the following paragraphs, the respondent provides its written response to the disclosure statement issued by the DA vide email dated 15 June, 2017.
- (1) It has been the consistent submission of the respondent that a simultaneous claim of material injury/ threat of material injury and material retardation cannot be examined and arrived at in an anti-dumping investigation. This is on account of the fact that both the concepts, i.e. material injury to the DI and material retardation to the DI are completely opposite to each other. For e.g. pursuant to a claim of material injury, the DA examines the existing injury or threat of injury to the DI in accordance with Annexure II of the *Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995* ('Indian AD Rules').
  - (2) On the other hand, pursuant to a claim for material retardation to the DI, the DA examines whether the imports of the dumped article have resulted in retarding the establishment of the domestic industry in India. It is to be noted that the fundamental requirement for a claim under material retardation is the non-existence of the DI for the product under investigation. This is because if the DI is already established, a claim for material retardation cannot be sustained. In fact this has also been the position of the DI in the present investigation and the following observation of the DI is noteworthy :-
 

*"In case petitioners had been in production for long period, it could be contended that material retardation provision should not be invoked and the case should be examined either in under material injury or under threat of material injury provisions.*
  - (3) Further, the above proposition is also supported by the WTO Agreement on Anti-Dumping ('ADA'). Footnote 9 of the ADA provides as follows:
 

*Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article*
  - (4) The footnote clearly implies that 'injury' will either mean material injury/ threat of material injury or material retardation and not both. Footnote 9 of the ADA has been incorporated in Section 9B(1)(b)(ii) of the Custom Tariff Act, 1975 ('Act') which provides as follows:
 

*No levy under section 9 or section 9A in certain cases. – (1) Notwithstanding anything contained in section 9 or section 9A*

(b) the Central Government shall not levy any countervailing duty or anti-dumping duty –

(ii) under sub-section (1) of each of these sections, on the import into India of any article from a member country of the World Trade Organisation or from a country with whom Government of India has a most favoured nation agreement (hereinafter referred as a specified country), unless in accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, a determination has been made that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India;

- (5) In view of the above legal position, a claim for injury can be either material injury/ threat of material injury or material retardation. This position also implies that if an investigating authority finds that there exists a case for material injury/threat of material injury, the claim related to material retardation becomes unsustainable as the DI for that product already exists.
- (6) In spite of the legal position being that 'injury' will mean material injury/ threat of material injury or material retardation and not both, the DA in the disclosure statement has concluded that there exists material injury as well as a case for material retardation. In this respect, attention is drawn to paragraph 35 of the disclosure statement wherein the DA has observed as follows:

“The Authority has examined the injury both material and material retardation to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties. For the material injury, ISRPL's data has been referenced who had declared commercial production prior to POI while for material retardation, the data of M/s RIL has been examined who declared commercial production in post POI.”

- (7) DA has come to a factual conclusion that for one of constituents of the DI, i.e. ISRPL there exists material injury and for the other constituent of the DI, i.e. RIL there exists material retardation. The respondent strongly disagrees with this observation of the DA because it results in an anomaly not contemplated in law. If ISRPL has suffered material injury, it implies that there exists an established industry for SBR series 1500 and 1700 and therefore, in such circumstances a case for material retardation cannot be made out.
- (8) In view of the above it can be concluded that there can either be a finding of material injury or material retardation and not both. In view of the same, the respondent respectfully submits that the conclusion of the DA in paragraph 35 with respect to existence of material injury for ISRPL and material retardation for RIL is legally untenable. The respondent respectfully requests the DA to take into account the above arguments and accordingly, reject the findings concerning material retardation while issuing the final findings.
- (9) DA in the disclosure statement has concluded that ISRPL and RIL constitute the DI within the meaning of Rule 2(b) of the Indian AD rules. Therefore, in order to determine material injury or material retardation, 'injury' data of the domestic industry as a whole needs to be taken into consideration. In other words, in order to establish 'injury' to the DI, whether material injury or material retardation, 'injury' data of both the applicants should be taken together to establish the same. This proposition is supported by Footnote 9 of the ADA as well as Section 9B(1)(b)(ii) of the Act. In this respect, the observation of the Hon'ble Supreme Court is noteworthy:

*In our opinion, the DA has clearly erred in law because the Authority was required to carry out the determination of injury and computation of NIP for the domestic industry as a whole, and not in respect of any particular company or enterprise ..... The provisions relating to injury analysis in Annexure II to the Anti-dumping Rules are also clear that the injury determination is always for the domestic industry as a whole and not for individual companies.*

- (10) It is clear that a determination of 'injury' would be for the domestic industry as a whole and not for one individual company. Instead, the DA for the purpose of determination of material injury has considered the data of ISRPL whereas for determination of material retardation, the data of RIL has been considered. Thus, DA has created two separate category of domestic industry in this investigation. However, if ISRPL is already an established industry then the question of material retardation to RIL does not arise.
- (11) Moreover, the above analysis has resulted in an anomaly which is not permitted in the ADA as well as in the Indian legal provisions. Article 4.1 and Footnote 9 of the ADA which is reflected in Rule 2(b) of the Indian AD rules and Section 9B(1)(b)(ii) of the Act respectively does not envisage that 'injury' data of the applicants be considered separately to establish material injury or material retardation as there cannot be two distinct categories of domestic industry in one anti-dumping investigation. This legal principle has also been upheld by

- the Hon'ble Supreme Court as highlighted above.
- (12) The conclusion of the DA in the disclosure statement to have a separate 'injury' analysis for ISRPL and RIL is legally untenable and also contradicts the conclusion with respect to the standing of the DI. In conclusion, the respondent requests the DA to reject the 'injury' determination concerning material retardation in the final findings.
- (13) DA in the disclosure statement has observed that with respect to transaction wise import data of DGCI&S, the Authority had issued authorization letter to various interested parties including Luthra & Luthra and therefore, the submission by respondent in this regard is misplaced and devoid of rationale.
- (14) At the outset, the respondent would highlight that the above explanation provided by the DA does not represent the correct factual situation. It should be noted that the respondent had sought the non-confidential version of the import data as provided by the DI and also the soft copy of the non-confidential version of the DGCIS&S import data as relied upon by the DA vide its letters dated 30 March 2017 and 24 May 2017. In response, the respondent was simply informed that it can get the transaction wise import data by directly approaching the DGCI&S.
- (15) The respondent has not been provided with the transaction wise import data provided by the DI and the transaction wise import data of the DGCIS&S that was relied upon by the DA. It should be noted that there is a distinction between the transaction wise import data available with the DGCI&S and the transaction wise import data from DGCI&S relied upon by the DA as there can be certain differences between the two.
- (16) It is an accepted legal position that the functions of the DA are quasi-judicial in nature and the DA is therefore bound to act judicially and follow the principles of natural justice. In view of the fact that the respondent has not been provided with the relevant import data as highlighted above, the respondent respectfully submits that the due process right of the respondent to adequately defend itself has been violated resulting in gross violation of principles of natural justice during the course of this investigation.
- (17) The respondent in spite of repeated requests was not provided with the transaction wise import data provided by the DI and the transaction wise import data of the DGCIS&S and relied upon by the DA.
- (18) The respondent submits that one of the cardinal principles of natural justice is that an adjudicating authority should provide access to the documents on which it has relied upon in its conclusion so that the opposing party can get an opportunity to provide a meaningful response to the case made out against it. In the current factual matrix, the DI has claimed that a transaction wise listing of imports was enclosed with the DI petition in a CD-ROM in view of large file size. Thus, if the DI had provided the transaction wise import data, it was incumbent upon the DA to ensure that the non-confidential version of such import data is made available to other interested parties.
- (19) The above proposition is supported by Rule 6(7) of the Indian AD Rules which provides as follows:  
*"the designated authority shall make available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation"*
- (20) The use of the word 'shall' in the above provision clearly establishes that the DA is obligated to make available the evidence presented to it by one interested party to the other interested party participating in this investigation. Accordingly, the non-confidential version of the import data provided by the DI as evidence for increased imports should be made available to the other opposing parties in excel format.
- (21) The above argument by the respondent is supported by the existing practice of the DA. For e.g. in the final findings dated 09 December 2016 in the anti-dumping investigation concerning import of *Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel originating or imported from China PR*, the following was observed:

*Some interested parties have contended that DGCI&S transaction wise data should not have been claimed confidential. It is, however, noted that DGCI&S transaction wise data has been made available by the petitioners for placing in the public file. The petitioners made available both the segregated data for PUC alone the data for product considered as well as product not under consideration. Further, the petitioners had provided soft copy in excel file and the same was also made available through public file.....However, the authority has placed DGCI&S transaction wise data in public*

*file and the same was made available to the interested party through the public file (Final Findings concerning imports of Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel originating or imported from China PR dated 09 December 2016, para 120(d)).*

(22) The non-confidential version of the DGCI&S data in excel format was placed in public file and was made available to other opposing parties. In view of the same, the respondent respectfully submits that the non-confidential version of the import data as provided by the DI in the present investigation be made available so that it can be analyzed and comments can be provided against the same.

(23) The Hon'ble Supreme Court has observed the following :

*“It is no doubt true that natural justice often requires the disclosure of the reports and evidence in the possession of the deciding Authority and such reports and evidence relevant to the subject matter of the inquiry may have to be furnished unless the scheme of the Act specifically prohibits such disclosure.” (Kanwar Natwar Singh v. Director of Enforcement & Anr. (2010) 13 SCC 255, paragraph 26)*

(24) Similarly, the Hon'ble Supreme Court in the matter of *North Bihar Agency & Ors. v. State of Bihar* quashed the order of cancellation of license of the appellant on the ground that proper opportunity was not provided to the appellant as the additional material which was relied upon while cancelling the license was not provided to the appellant which was in violation of the principles of natural justice. Also, the Hon'ble Supreme Court in the matter of *Sterlite Industries* has also explained the rationale for providing access to the relevant material to the other opposite parties as the same allows the affected party to file an effective appeal while non-disclosure of the relevant material makes the opposite party handicapped in filing an effective appeal.

(25) In addition to the above, the respondent also draws attention to the fact that the DA did not provide the non-confidential version of transaction wise import data received from the DGCIS&S data in spite of repeated requests as highlighted above. In this respect, the respondent submits that pursuant to Rule 7 of the Indian AD Rules, the DA cannot claim confidentiality on the data/information received from sources other than interested parties. This proposition has also been accepted by the Hon'ble Supreme Court wherein it has observed as follows:

*In our opinion, Rule 7 does not contemplate any right in the DA to claim confidentiality. Rule 7 specifically provides that the right of confidentiality is restricted to the party who has supplied the information, and that party has also to satisfy the DA that the matter is really confidential (Reliance Industries Ltd. vs Designated Authority and Ors., (2006) 10 SCC 368, paragraph 22)*

(26) The above observation in *Reliance Industries* has also been upheld by the Hon'ble Supreme Court in *Union of India v. Meghmani Organics Ltd.* Thus, it is clear that the DA cannot claim confidentiality on the data/information received from sources other than interested parties. Accordingly, the decision of the DA to not share the transaction wise DGCI&S import data as relied upon by the DA is legally untenable.

(27) The above practice of non-disclosure of data to other interested parties is also in violation of the principles espoused by the WTO agreement. Article 6.4 of the ADA provides that authorities should provide opportunities for all interested parties to see all information that is not confidential and that is used by the authorities in an anti-dumping investigation. The WTO Appellate Body while interpreting Article 6.4 of the ADA has observed as follows:

*We note the European Union's view that the term 'information' in Article 6.4 'concerns facts and raw data rather than factual determinations and conclusions by the investigating authorities'. In our view, there is no textual basis in Article 6.4 for limiting information 'relevant to the presentation of [parties'] cases' and 'used by the authorities' to facts or raw data unprocessed by the authorities. Indeed, the broad range of information subject to the obligation under Article 6.4 may take various forms, including data submitted by the interested parties, and information that has been processed, organized, or summarized by the authority. We do not see why only facts and raw data would be relevant to the parties' presentation of their cases. (Appellate Body Report, EC-Fasteners, WT/DS397/AB/R, paragraph 480)*

*The interested parties' right under Article 6.4, therefore, is to see all non confidential information relevant to the presentation of their cases and used by the investigating authority. Article 6.4 thus applies to a broad range of information that is used by an investigating authority for purposes of carrying out a required step in an anti-dumping investigation....”.*

- (28) The respondent submits that the conclusion of the DA in paragraph (g) on page 12 of the disclosure statement is inconsistent with the legal provisions and the judgments of the Hon'ble Supreme Court highlighted above. Accordingly, the respondent has not been able to adequately defend its interest as the respondent has not been able to analyze the relevant import data relied upon by the DA and provide its comments to the same. In view of the above, the respondent submits that the DGCI&S transaction wise import data and the import data provided by the DI must be shared with the opposing interested parties and adequate time must be provided to the respondents to comment on the same.
- (29) The DA vide paragraph 47 of the disclosure statement has analyzed the performance of the DI with respect to production; capacity, capacity utilization and sales. However, the entire injury data pertaining to ISRPL has been kept confidential and even the indexed version of the injury data has not been provided. In this respect, the respondent submits that injury data pertaining to production; capacity, capacity utilization and sales cannot be considered as confidential and the actual injury data should be made available to the opposing interested parties.
- (30) An analysis of numerous preliminary and final findings issued by the DGAD clearly establishes that the DGAD as a practice does not allow confidentiality with respect to indices such as capacity, production, domestic sales and capacity utilization even when such figures may not be in public domain. Thus, if the DA did not grant confidentiality to such indices in the previous investigations, the same indices cannot be considered to contain confidential information in the present investigation. In other words, the nature of information cannot change from non- confidential to confidential if the information pertains to the same criteria. In fact, even the basis on which the figures pertaining to the above indices have been kept confidential has not been divulged in the initiation notification or the petition.
- (31) It should be noted that even the indexed version of the data pertaining to the above indices has not been provided in the disclosure statement so that opposing interested parties can analyze the trend and comment upon the same. In this respect, attention is drawn to paragraph (iii) of Trade notice no. 01/2013 dated 9 December 2013 which provides that the non-confidential version of the data should be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, the injury data pertaining to the above indices have been kept confidential and even the indexed version of the injury data has not been provided.
- (32) The grant of confidentiality by the DA to the injury data pertaining to the above indices is inconsistent with the Trade notice 01/2013. Further, the non-disclosure of the injury data has also resulted in violation of the principles of natural justice as the respondent has not been able to provide any comments concerning the injury data and thus, has not been able to defend its interest adequately.
- (33) In paragraph 75 the DA has laid down the guidelines for evaluating a case on material retardation. While this clarifies the legal ambiguity pertaining to evaluation of the claim concerning material retardation as highlighted by the respondent in its previous submissions, it should be noted that these criteria have been laid out to the opposing interested parties for the first time in the disclosure report, after all the pertinent data and information of the interested parties has been evaluated by the investigating authority. This late disclosure has resulted in depriving ATMA of its right to provide a meaningful rebuttal to the claim of the material retardation based upon the criteria laid down by the DA.
- (34) One of the fundamental features of rule of law is the predictability in the application of law. This stand is supported by the observation of the Hon'ble Supreme Court in the matter of *S.G. Jaisinghani v. Union of India & Ors* wherein it was observed as follows:

*"In a system governed by rule of law, discretion, when conferred upon executive authorities, must be confined within clearly defined limits. The rule of law from this point of view means that decisions should be made by the application of known principles and rules and, in general, such decisions should be predictable and the citizen should know where he is."*

- (35) It is clear from the above judgment that generally a decision should be predictable meaning thereby that there should be consistency in the application of law and practice followed by an investigation authority, especially if it happens to be a quasi-judicial body. In view of the same, ATMA submits that since the criteria was not elucidated earlier and the principles that were considered by the DA were not known by the interested parties, the evaluation of the claim concerning material retardation is in violation of the principles of natural justice, and in view of the same, the claim concerning material retardation must be rejected.

- (36) The DA in the disclosure statement has stated that “M/s Luthra & Luthra law offices representing ATMA vide letter dated 24/4/2017 have submitted that E-SBR 1739 and 1789 grades be excluded as M/s Reliance Industries has admitted that it cannot currently manufacture E-SBR 1789 and M/s ISRPL on its website does not list this grade in their product list.” Further, the DA vide paragraph (f), page 12 of the disclosure statement has concluded that since RIL has the capability to manufacture the product grades E-SBR 1739 and E-SBR 1789, the same is included within the scope of the PUC.
- (37) The respondent would submit that the above statement in the disclosure report does not reflect the actual argument put forth by the respondent. The respondent in its letter had presented evidence that not only RIL has not manufactured the E-SBR grades 1739 and 1789, these product grades are also not *like article* to the other product grades manufactured by the DI on account of several factors such as chemical composition; usage; pricing; customer perception etc. Accordingly, the respondent argued that E-SBR grades 1739 and 1789 should be excluded from the scope of the PUC.
- (38) However, the DA has not excluded the E-SBR grades 1739 and 1789 from the scope of the PUC on the ground that RIL had the capability to manufacture these products, despite the self-admission by RIL. With respect to the issue of *like article*, the DA has simply observed that “*the only difference between various grades belonging to a series of styrene butadiene rubber is the composition ratio of styrene and butadiene content in the rubber*”. As mentioned above, the respondent had highlighted multiple reasons in support of its argument that E-SBR grades 1739 and 1789 are not *like article* to the products manufactured by the DI which is not even reflected in the disclosure report. Thus, the factual basis on which the DA has arrived that these E-SBR grades are *like article* is erroneous and misplaced and thus, should be discarded.
- (39) The above conclusion of the DA is also legally erroneous and is inconsistent with its own existing practice which is reflected in multiple final findings. Firstly, with respect to the issue of *like article* it has been the practice of the DA to ascertain whether the DI has actually manufactured and supplied the disputed product grades during the POI. Attention is drawn to the final findings issued in the *Anti-Dumping duty investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA* wherein it was observed as follows:
- The Authority has adopted certain broad principles for the purpose of exclusion of products of certain grades/specifications from the scope of the PUC. One such principle is whether the specification/grade/production process/production technology pleaded by the interested parties results in a different product in terms of physical characteristics and chemical composition whereby the distinctiveness of the product can be established with clarity and precision. The second principle is whether the domestic industry claimed through their product broacher as manufacturer of these grades and is manufacturing/supplying such distinctive items at all during the POI or prior to the POI. Thirdly, whether the product grades supplied by the domestic industry during the POI and are claimed to be equivalent to the grades proposed/considered for exclusion and in such a case whether any evidential scientific literature or any other technical evidence has been established by the domestic industry.*
- (40) Based upon the above criteria, the DA concluded in the final findings that the scope of the PUC in the investigation be restricted to 1250 mm as “*no evidence of actual supply of width beyond 1250mm has been provided by the domestic industry*”. Similarly, in the present investigation, it is an undisputed fact that RIL has not manufactured and supplied E-SBR grades 1739 and 1789 in the POI as well as during the post-POI. Therefore, based upon its past practice, the DA should have excluded these E-SBR grades from the scope of the PUC.
- (41) Secondly, it also cannot be argued that E-SBR grades 1739 and 1789 are *like articles* to the other E-SBR grades manufactured by the DI. The respondent in its previous submission has provided detailed arguments wherein it has been highlighted that these E-SBR product grades are used in high speed tyres wherein other E-SBR product grades cannot be used and therefore, there is a significant difference on account of factors such as chemical composition; usage, pricing; customer perception etc. For the sake of brevity, the respondent is not reproducing its previous submission and instead relies on the same.
- (42) The above principle has also been upheld and applied by the CESTAT in other cases such as *Indian Refractory Makers Association vs Designated Authority* and *Magnet Users Association vs Designated Authority*. In both these cases, it was held that the grades of the PUC with different product characteristics cannot be considered

as *like article* and therefore, cannot be the cause of injury to the domestic industry. In view of this observation, these grades were excluded from the scope of the PUC.

- (43) It should be noted that the disclosure statement contains no statement from the DI arguing that E-SBR product grades 1739 and 1789 are *like article* to the product grades manufactured by the DI. Thus, it is an undisputed fact that the DI itself has impliedly admitted that E-SBR product grades 1739 and 1789 are not *like article* to the product grades manufactured by them. In view of the same, the conclusion of the DA with respect to inclusion of these E-SBR grades within the scope of the PUC is factually and legally untenable.
- (44) The respondent submits that in view of the above paragraphs, E-SBR grades 1739 and 1789 must be excluded from the scope of the PUC.
- (45) The safety of the products used in this sector is of primary importance. Due to this reason, it is only after the major inputs used in their applications have undergone the approval process/trials, can the user industry procure such inputs for usage. The trails/approval process consists of various stages such as laboratory evaluation, factory trials, bulk trials, field trials, factory audit etc. which approximately takes up to 1-2 years depending on the material.
- (46) ISRPL commenced production in February 2014 and RIL in September 2016. This implies that the product trails/approvals with the user industry of the grades manufactured by the DI would have lasted at least two years pursuant to the commencement of production. In view of the same, it is apparent that the domestic off take of the DI could not have been high as is also reflected in the data during the POI. However, pursuant to ISRPL completing its trial process with the user industry, the domestic off take has increased remarkably and the same is also evident from the Post-POI data as highlighted in the respondent's letter and also elucidated below. In fact, there has been an increase in the domestic procurement in quantity as well as in the domestic procurement prices. This significant increase in domestic procurement in quantity and prices is pursuant to the PUC manufactured by the DI receiving the requisite approvals from the user industry after extensive trials during the POI.
- (47) The analysis concerning material injury and material retardation it is highlighted that confidentiality has been granted to figures for key economic indicators such as capacity, production, domestic sales and capacity utilization and not provided the actual figures for the same. In fact, even the indexed figures of the aforementioned important economic indicators have not been provided and this has deprived the respondent of the opportunity to properly analyze the data and adequately defend itself.
- (48) The respondent has provided detailed submissions previously rebutting all the claims of the DI on material injury, the recurrence of material injury and existence of the causal link and will place reliance on the same for the sake of brevity. However, the respondent in addition to the previous submissions, will highlight certain findings of the DA the subsequent paragraphs which are not consistent with the facts and data as reflected in the disclosure statement and require reconsideration by the investigating authority:-
- a) The DA in paragraphs 43-44 of the disclosure statement concerning the assessment of demand of subject goods has observed that "*the demand for the product in the country has increased significantly over the period on annual basis*". The respondent objects to this observation because it is clear from the table in paragraph 43 of the disclosure statement that the demand for the subject goods has increased during the injury period as well as the POI. However, the increase in demand is not significant by any stretch of imagination over the period on annual basis. Moreover, at the same time, the imports of the subject goods have declined from the subject countries over the period on an annual basis and the production of the DI has significantly increased over the period. Thus, the DA is requested to reconsider this finding at the time of issuance of the final findings.
  - b) With regard to the volume of the dumped imports, the DA has stated in paragraph 46 the following –
 

*Imports from the subject countries have increased in absolute terms till 2014-15 and declined in POI because of commencement of the production by the petitioners.*

*Imports from the subject countries have remained significant in terms of total imports as well as in relation to consumption and production in India in spite of the sufficient capacity lying with the petitioners.*

*Imports from the subject countries have remained significant and has prevented the domestic industry*

*from increasing its production and sales. In fact, so significant were the imports that the domestic industry has been prevented from selling the goods to the extent of its sub-optimal production.*

The respondent submits that the above observation provides a one-sided view which does reflect the current factual matrix accurately. The imports from the subject countries in relation to the Indian production has declined from 337.60% in 2014-15 to 160.72% whereas the imports from the subject countries in relation to Indian consumption has declined from 81.51% in 2014-15 to 68.06% in the POI. The production of the DI has increased from 6,912 MT in 2013-14 to 46,657 MT in the 2014-15 and 92,540 MT in the POI (i.e. an increase of 675% in the year 2014-15 and 1238% in the POI over the year 2013-14).

The respondent submits that that RIL had started the commercial production in September 2016 and other applicant of the DI i.e. ISRL had started commercial production in February 2014. Considering these facts, the significant decline in import of the PUC from the subject countries in the period October 2014-September 2015 (POI) clearly establishes that the DI has immediately been able to capture the domestic market. Thus, the DI has achieved the significant share of the domestic demand in such a short span of time.

The product approval process of the user industry for the DI was completed for other grades in the POST-POI, its production has increased significantly. Therefore, the respondent humbly submits that the DI was facing normal startup difficulties and as soon as, it completed its product approval process with the user industry, its production as well as sales have significantly improved in the POST-POI. Even in the POI, the share of DI in total production is quite significant. This is demonstrative of the fact that when the DI did not have the requisite approvals, imports were inevitable but pursuant to getting the requisite approvals from the user industry, the DI has been able to improve its performance on all important economic indicators. Thus, the respondents humbly submit that there is no volume effect of imports on the DI.

- c) The finding of the DA in clause (c) of the paragraph 48 of the disclosure statement that *“the production of the DI has increased but not to an optimal level”* is vague and incorrect. In this respect, it should be noted that it is a standard practice across industries that products produced by new manufacturers are first tested and once they satisfy the technical and the quality requirements, the user industry procures such products. The phase of testing and approval can often take from 1-2 years and even in the present investigation, the products manufactured by the DI are being tested and evaluated by the user industry from 2014-2016. Therefore, it is obvious that production would take time to reach the optimum level. In view of the same, an increase in production pursuant to getting product approvals is a favorable indicator. Therefore, the respondent submits that such an analysis requires reconsideration before issuance of the final finding.
- d) The DA in paragraphs 50-51 of the disclosure statement concerning the market share has stated that *“the gain in market share of the demand, despite being the only producers of the subject goods in the Country is not significant. The share of imports remained significant over the period”*. The respondent objects to this finding as it is factually incorrect. As per the data available in the disclosure statement, the share of the DI was 29% of demand in the POI whereas the share of imports was 68% of demand during the same period. Further, the share of DI in the POST-POI (6 months) has increased to 51% while the share of imports in the POST-POI (6 months) has declined to 47% as compared to POI. These figures clearly demonstrate that the jump in the market share of the DI from the POI to the POST-POI is significant and the same could be attributed to the completion of the product approvals of the DI from the user industry. During the same period, the imports too reflect a marked decline. Thus, the aforementioned observation of the DA is not consistent with the facts and data available on record and requires reconsideration.
- e) In paragraphs 54-55 of the disclosure statement the DA has stated concerning the claim of price undercutting that *“this comparison shows that during the period of investigation, there have been instances where the subject goods originating in the subject countries were imported into the Indian market at prices lower than the selling prices of the domestic industry.”* The respondent objects to the above assertion as the table given in the price undercutting analysis in the same paragraph shows that price undercutting is

negative for all the grades from the subject countries. Therefore, this self-contradictory finding which does not reconcile with the data provided in the disclosure statement is demonstrative of the inaccuracy of the price undercutting analysis.

The respondent objects to the finding of the DA in the paragraph 55 of the disclosure statement that “*price pressure on domestic industry which has just entered into the market, a negative price undercutting indicates that industry has aggressively matched the import prices to ensure its presence in market.*” This is because the data does not warrant this understanding of negative price undercutting as provided in the disclosure statement. Negative price undercutting simply implies that the prices of the DI are higher than that of the imports such that an imposition of the ADD is not required. Hence, the respondent humbly requests the authority to reconsider this issue before the issuance of the final findings.

- f) The profit figures provided in the disclosure statement in paragraph 59 pertain only to the ISRPL. Therefore, the observation of the DA that “the domestic industry suffered severe losses since their establishment” is not based on facts as the profit figures of RIL have not even been accounted for in the disclosure statement. Moreover, the respondent’s argument in its letter is reiterated that the financial position of ISRL has been divulged in the annual reports of the Indian Oil Corporation which has a 50% shareholding in ISRPL. As per the financial data disclosed in the annual reports of the Indian Oil Corporation, ISRL has earned total revenue of INR 242.64 crores in the year 2015-16 (a growth of about 95 % over the year 2014-15) and has a net cash flow of INR 43.63 crores in the year 2015-16 (a growth of about 194% over the year 2014-15). This data clearly establishes that ISRL has been in positive cash flow during the POI. Since Reliance was not in commercial production and ISRL only produces SBR, it therefore, implies that the DI had positive cash flow during the POI. This directly rebuts the claim of the DI that it has suffered loss during the POI and subsequently, any claim of material injury to the DI.

The observation of the DA pertaining to the losses, it must also be noted that losses suffered, if any, are on account of repeated shut down of the plants of the DI companies which clearly establishes that there exists inherent deficiencies within the DI and therefore, the claim of material injury by the DI cannot be sustained as it is self-inflicted. This issue was also flagged in the respondent’s letter wherein it was highlighted that the Hazira plant of the RIL which produces SBR and PBR was closed for the period 24 March 2017 to 20 April 2017. Due to the same, the user industry was facing severe issues concerning the supply of the PUC. In view of the same, the respondent respectfully requests the DA to take into account the inherent deficiencies of the DI which may have contributed to the injury. Therefore, the claim of material injury suffered by the DI is not sustainable.

- g) The DA in Annexure 4(j) of the disclosure statement, pertaining to the methodology for determination of Non-injurious price (‘NIP’), has stated that “*RIL’s financial data has been adopted for analysing material retardation injury to them*”. The respondent strongly objects to this and submits that any new factory/enterprise takes time to overcome the start up difficulties and procure market share and volume. As noted in the disclosure statement, RIL has started commercial production much later in comparison to ISRPL (ISRPL had commenced the commercial production from February, 2014 and RIL has declared commercial production on 30<sup>th</sup> September, 2016) and therefore, it is not possible for RIL to be perform sub par to ISRPL. It is expected that RIL will take time to stabilise operations since it has commenced commercial production from 2016. Moreover, as highlighted earlier in this submission, the simultaneous claims of material retardation and material injury cannot be examined separately in the same investigation.

(49) DA is requested to reconsider these issues and analyze the claims in light of the above mentioned grounds before issuance of the final findings.

(50) The DA has concluded in paragraph 81 that “*there exists a causal relationship between dumping and injury*”. The respondent has provided a detailed rebuttal to this claim in the previous submissions. The respondent reiterates that there exist other factors like injury due to high interest payment, increase in domestic sales, no price suppression/depression and the inherent deficiencies of the DI which have led to a break in the causal link between the claim of injury and import of the PUC from the subject countries.

(51) DI has been able to perform significantly well on almost all of the economic parameters and, therefore, the import of the PUC from the subject countries has not caused any injury to the DI. Any injury/material retardation to the DI, if at all, is on account of factors listed above and cannot be attributed to the import of the PUC from the subject countries.

86. M/s WTC representing M/s LG Chem Ltd., Korea and its traders filed its submissions as under:

As per the said Disclosure Statement, DGAD has worked out a Dumping Margin of 2.07% in respect of exports by LG Chem. We strongly raise our concerns against such computation. As per confidential version of the Disclosure Statement provided to us, we understand that main reason for such high dumping margin assessment is adoption of very high cost of production of SBR at LG Chem by DGAD. We are tabulating the same as under:

<b>Cost of Production (US\$/MT)</b>	<b>1500 Series</b>	<b>1700 Series</b>
As claimed by LG Chem	***	***
As Considered by DGAD in Disclosure Statement	***	***

We understand that DGAD has used the price of BD and SM based on some arbitrary/ hypothetical premise and not based on the actual cost data submitted by LG Chem and duly verified by the team of officers at the premises of LG Chem in Korea.

There are two main raw materials namely Butadiene and SM used for manufacturing SBR. It is submitted that LG Chem is mainly sourcing both the raw materials from Lotte Chemical with its plant located next door to the plant of LG Chem for manufacture of SBR. Both LG Chem and Lotte Chemical are unrelated companies. Screenshots from websites of LG Chem and Lotte Chemical indicating their past histories are enclosed. This is a sufficient clarification that there is no compensatory arrangement between Lotte Chemical and LG Chem to lower the price of of the two raw materials, BD and SM.

Both LG Chem (earlier named as LG Daesan Yuhwa) and Lotte Chemical (earlier named as Honam Daesan Yuwha) are unrelated companies and have entered into a long-term agreement way back in 2005 for purchase of number of items/products manufactured by Lotte Chemical (earlier names as Honam Daesan Yuwha). Copy of such agreement is enclosed herewith (Copy of the same was provided to the investigation team during the on-site verification). BD is sold by Lotte Chemical to LG Chem based on a formula.

It is submitted that how can DGAD conclude that the purchase price of raw material is unreliable due to the reason that the same is lower than others due to locational advantage. Difference in price of BD and SM between Lotte Chemical and KKPC is due to high transportation. It may please be seen that cost of transportation of BD is very high. BD is a highly inflammable product and hence needs special tankers and facilities to transport the same from one place to another.

Alteration in the cost of a participating exporter which was duly verified is in violation of Article 2.2.1.1 and para 1 of Annexure -1 to the Anti-Dumping Rules.

Para 1 of Annexure -1 to the Anti-Dumping Rules states that *“The elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sales of the article under consideration.”*

For the purposes of paragraph 2, costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided that such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration.

This issue has been duly addressed by the Appellate Body in its Report No. WT/DS473/AB/R dated 6<sup>th</sup> October 2016 (European Union-Anti-Dumping Measure on Biodiesel from Argentina.)

Paragraph 6.41 of the Appellate Body report states “We do not subscribe to the European Union's reading of the Panel Report. We note that, to the Panel, the second condition in the first sentence of Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement requires a comparison between the costs in the producer's or exporter's records and the costs incurred by such producer or exporter. The Panel emphasized that “the object of the comparison is to establish whether the records reasonably reflect the costs actually incurred, and not whether they reasonably reflect some hypothetical costs that might have been incurred under a different set of conditions or circumstances and which the investigating authority considers more ‘reasonable’ than the costs actually incurred.” In this connection, the Panel explained that its understanding of this condition does not imply that “whatever is recorded in the records of the producer or exporter must be automatically

accepted.” To the Panel, an investigating authority is “certainly free to examine the reliability and accuracy of the costs recorded in the records of the producers/exporters” to determine, in particular, whether all costs incurred are captured; whether the costs incurred have been over- or understated; and whether non-arms-length transactions or other practices affect the reliability of the reported costs. The Panel further stated that “Article 2.2.1.1 does not involve an examination of the ‘reasonableness’ of the reported costs themselves, when the actual costs recorded in the records of the producer or exporter are otherwise found, within acceptable limits, to be accurate and faithful.” In light of these statements, we consider the Panel’s interpretation of Article 2.2.1.1 to be more nuanced than the European Union’s argument suggests.” The above findings of Appellate Body clearly show that in case cost claimed is reasonably reflected in the cost records of the company concerned, investigating authority cannot reject the cost and arbitrarily adopt some other costs. It is submitted that all cost data of LG Chem was duly verified by the officers during the course of verification at the premises of LG Chem in Seoul, Korea RP.

Cost claimed by LG Chem was duly supported by the records maintained as per records of the company. The verification team even examined the SAP system of the company thoroughly and collected copies of all necessary records as verification exhibits.

LG Chem has reported actual and true cost of production of SBR in its questionnaire response and the same has been duly verified by the verification team.

- Cost claimed by LG Chem reasonably reflects the cost of production and is not distorted due to sourcing of raw materials from supplier due to relation or otherwise.
- All books of accounts are maintained by LG Chem as per Korean GAAP.
- Any modification of cost of production as claimed by LG Chem and verified by the Designated Authority is in violation of Article 2.2.1.1 of WTO Agreement.
- For applying ordinary course of trade test, DGAD shall adopt the cost of production of SBR based on records maintained, reported and as verified by the Investigating Team.
- Cost of BD and SM sourced from Lotte Chemical is very low due to locational advantage.
- Lotte Chemical is located next to plant of LG Chem where SBR is manufactured. No transportation cost is involved for transporting BD and SM sourced from Lotte Chemical.
- In case adjustment on account of transportation cost is made, prices of BD and SM from Lotte Chemical will be almost similar to other companies in Korea RP.
- While adopting prices of BD and SM as reflected and claimed by other producers of SBR in Korea RP, it shall be duly adjusted for transportation cost which is not applicable for material sourced from Lotte Chemical.

87. M/s Lakshmikumaran & Sridharan representing M/s KKPC, Synthos Group, M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd and M/s Rishiroop Ltd. had filed various submissions as under:

Illegality of the Investigation pertaining to Material Retardation:

- KKPC has submitted that the subject proceedings are illegal as Section 9 B of the Customs Tariff Act, 1975 does not lay down any guidelines for the determination or conduct of an investigation pertaining to material retardation of the domestic industry. KKPC’s participation in the present proceedings is without prejudice to their stance on the illegality of the same.
- KKPC submitted that since “injury” and “domestic industry” are not defined under the Customs Tariff Act, 1975, their meaning must be strictly interpreted, as is the norm for tax legislations.
- KKPC further alleged that the DGAD’s authority to conduct the investigation is the result of illegal exercise of sub-delegation and cannot be held to be validly exercised.

Calculation of Normal Value, Export Price and Dumping Margin with respect to KKPC

- KKPC received the confidential Annexure pertaining to Calculation of Normal Value, Export Price and Dumping Margin with respect to KKPC along with the Disclosure Statement dated 15 June, 2017.
- KKPC has claimed that the Authority should not have disregarded the actual costs reported by KKPC in Appendix 8B and requested the DA to adopt the same. KKPC submitted that its data in the EQR was based on the actual costing and was duly verified by the DGAD investigative team.

The Injury Analysis conducted by the Authority is flawed

- KKPC claimed that it is not possible, legally, for the Petitioners to claim (i) material injury; (ii) threat of material injury; and (iii) material retardation to the establishment of an industry, simultaneously as the standards are mutually exclusive.
- It is submitted that consideration of these standards as the same or interchangeable renders the legal provisions *non-est*. Moreover, citing Section 9B(1)(b) of the Customs Tariff Act, 1975, KKPC claimed that usage of the word “or” between the three injury bases indicates disjunctive, separate legal bases. In such a case, the Authority cannot read “or” to mean “and”.
- KKPC argues that it is not possible to bifurcate the injury analysis, on the bases of material injury for ISRPL and material retardation to the establishment of RIL. This is because the existence of material injury precludes the existence of material retardation, as it presumes the existence of an ‘established’ industry. KKPC submitted that the Authority must determine a singular Domestic Industry (DI) and whether the DI, as a whole, is established or not. KKPC seeks the Authority’s analysis regarding whether it is possible that a new-entrant in an established market can claim material retardation.
- KKPC claimed that conduct of the present investigation is illegal as no legal guideline exists for the same. Paras. (i) and (vii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules provide the principles for determination of injury and threat of material injury, respectively. However, no such principles exist for the determination of material retardation.
- KKPC submitted that the Authority’s bifurcated analysis has created an anomalous situation by carrying out an examination for both, material injury and material retardation such that there is a presumption that the industry is both, established and *not* established, at the same time.

The Authority’s Material Injury analysis pertaining to ISRPL is flawed

- The Authority in its material injury analysis for ISRPL, has failed to disregard the production and supply figures pertaining to RIL. It has cited various examples of such inclusion of RIL figures. E.g., the capacity under consideration of the Authority is very high, at 2,61,000 MTPA which is the combined capacity of the Petitioners.
- There is no volume injury as import volumes from the subject countries declined in absolute terms between 2014-15 and the POI, and also in relation to Indian production and consumption. KKPC also submitted that “imports from the subject countries have remained significant in terms of total imports” is not a criteria for analysis under the AD Rules
- ISRPL has gained substantial market share and singularly held 29% of the market share at the end of one year of production, i.e., POI. Thus, the Authority’s conclusion that ‘the performance of the DI is not significant’ is baseless. KKPC also noted that within 6 months after the POI, the market share of the DI has escalated to 51%.
- The “*price undercutting*” is misguided and requested the Authority to record reasons as to why one instance of price undercutting, from one of the subject countries, in one quarter of the POI at 0-10% is sufficient basis to conclude that there have been instances where the subject goods originating in the subject countries were imported into the Indian market at prices lower than the selling prices of the domestic industry.
- KKPC also claimed that the Authority’s conclusion that “*a negative price undercutting indicates that industry has aggressively matched the import prices to ensure its presence in market*” is arbitrary as the negative margin of undercutting is substantial, establishing that DI prices were 20-30% below import prices from the subject countries. KKPC also cites *Indian Spinners Association v. Designated Authority*, [2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. - Del.), paragraph 15] wherein, CESTAT noted that the DI prices being about 11% higher than the prices of the allegedly dumped imports established the independence of the two. KKPC also submitted that negative undercutting establishes only that import prices are higher than DI prices and no other conclusion may be drawn from an analysis of price undercutting alone.
- With respect to the Price Underselling analysis of the Authority KKPC submitted that the calculation of injury margin should follow conclusions on injury. The same is not a ‘factor’ to assess injury. In this regard, it cited the findings of the Gujarat High Court in *Nirma Ltd. v. Union of India* [Special Civil Applications No.16426/2016 & 16427/2016]. KKPC also raised this issue with respect to the examination of “Factors affecting Domestic Prices”.

- KKPC cites inter-se competition between the Petitioners as an injury factor to the Petitioners as it is evident that the cost of sales of RIL are far lower than that of ISRPL. ISRPL's injury is caused due to the low selling price of RIL. KKPC also reiterated its submissions pertaining to 'other factors' which have caused injury. We note KKPC's submission that injury to the Petitioners is caused by the following reasons:
  - Lack of Product Approvals from end-users / buyers and resultant inability to supply in the domestic market.
  - Off-Grade Sales made by RIL at low prices.
  - Change in market conditions between the planning phase (when the market had been experiencing unprecedented boom and was very optimistic) and the stage of commencement (when the market crashed and prices of the raw material almost halved, leading decline in end-product prices)
  - Locational Disadvantage of ISRPL, located in Northern India when the main consumers are in West and South India.
  - Factors listed by the Petitioner-ISRPL in its Annual Reports, such as significant cost over-runs in the execution of ISRPL's project, delayed start of commercial production, significant fall in natural rubber prices influencing price and sales of SBR.
  - Factors listed by the Petitioner-RIL in its Investor Related Documents, such as, new capacity additions and weakened demand for SBR.
  - Impact of the FTAs with Korea and ASEAN (Thailand). The reduction in customs duty has led to resultant reduction in the landed values from these countries and the same must be duly adjusted in consideration of injury.

The Authority's Material Retardation analysis pertaining to RIL is flawed

- The Authority's reliance on a WTO proposal as the basis for its material retardation analysis is completely unfounded as the WTO negotiations have stalled due to disagreement amongst Members. It is also submitted that the cited proposal may not be reflective of India's stance at the WTO and would undermine the negotiation process therein.
- KKPC has claimed that injury, if any, to RIL is attributable to the high entry barriers in the SBR industry-customer stickiness and lengthy approval processes.
- RIL injury is incomprehensible as the cost of sales of RIL have reduced 82% while selling price has only declined by 32%. Concurrently, imports from the subject country have also declined substantially. Thus, the prices and profitability of the Petitioner move independent of the imports from the subject countries and the correlation regarding the injury suffered by RIL has not been established.
- Injury caused by other known factors, such as inter-se domestic competition, declining raw material prices, suppressed demand in the auto sector, lack of product-approvals by user industry, etc. must be segregated and excluded from the Authority's analysis.

The Authority has not established a clear and untarnished causal link between the alleged injury suffered by the Petitioners and the allegedly dumped imports from the subject countries

- KKPC has submitted that "*any known factors other than dumped imports*" have not been analyzed. It was reiterated that for ensuring that injury caused by these other known factors is not attributed to the injury caused by the allegedly dumped imports, the Authority must necessarily isolate and segregate injury caused by each factor and exclude the same from the overall injury suffered by the Petitioners.
- Authority's observation regarding export sales of the Petitioners is incomplete. It was submitted that the Authority has failed to note that parameters pertaining to export market performance have been completely excluded, such as profitability and cash profit / loss. In this regard, it was reiterated that the Petitioner-RIL sold off-Grade products in the export market at substantial losses and the same has impacted its profitability.
- The analysis under "(g) *Performance of other products produced and sold by the domestic industries*", should have analyzed the financial status of other products produced by the DI. It was submitted that since RIL is a backward-integrated unit, and it produces many petrochemical products, its transfer pricing at each intermediate level up to SBR production must be factored in the analysis under this head.
- KKPC submitted that post-POI data has been inappropriately analyzed. It individually analyzed each ground such as Post-POI data evidencing suppression of production, Post-POI data evidencing non-optimality in capacity utilization, Post-POI data evidencing price underselling and overall price suppression / depression.

### Non-Injurious Price Calculations merit reconsideration

- KKPC has raised certain issues with respect to the NIP calculation of the Authority, these are:
  - The viability of using a non-injurious price (NIP) calculated for an established industry- ISRPL for a new entrant like RIL.
  - With respect to “raw material cost” and “cost of utilities”, the Authority cannot use the “higher” of *the best achieved norms of raw material / cost of utilities by the domestic producer, over various quarters of POI or standard consumption norms* as “best achieved norms” refers to the lowest achieved value. Moreover, the usage of “standard consumption norms” is not permitted under Annexure III of the AD Rules.
  - The Authority’s reliance on confidential project reports of the DI is unwarranted as no non-confidential summary has been provided to KKPC despite repeated requests.

### Procedure and Excessive Confidentiality

- KKPC alleged excessive confidentiality exercised by the Petitioners and the Authority with respect to the following:
  - Project Reports of the Petitioners
  - The data of ISRPL concerning installed capacity, production, capacity utilization, domestic sales, inventory and exports.
  - Volume, inventories and price parameters of RIL, as reproduced by the Authority at Tables 12, 13, 14 and 15 at pages 55-56 of the Disclosure Statement.
- AD Rules definition of “domestic industry refers only to active producers of the like article there is no justification for the inclusion of an entity like RIL, which was not undertaking any commercial production and did not contribute to the domestic output of the like article during the period of investigation.
- Authority cannot include under PUC those products which are not being currently manufactured by the DI, based on established CESTAT jurisprudence. Thus, the claims for exclusion of Grades 1739 and 1789 needs to be reanalyzed. Moreover, the Authority has failed to consider our submissions for exclusion of Grades 1502NF (NF denotes nitrosamine free which is not produced in India), 1507, 1507H, 1745, 1763, 1769, 1789, 1793 and 1799.
- PUC should be defined to exclude both Solution SBR and Styrene-Butadiene-Styrene.
- With respect to the import statistics under consideration, it had pointed out certain transactions of forms of styrene-butadiene which are not under consideration in the present investigation but were included in the import statistics by the Petitioners.

The Authority has inappropriately “bifurcated” the injury analysis for ISRPL and RIL

- Based on the Disclosure Statement, it appears the Authority has determined that ISRPL, an established domestic industry merits a “material injury” analysis and RIL, an embryonic domestic industry merits a “material retardation” analysis. However, since there can only be a singular domestic industry, identified as a whole- such bifurcation is impermissible.
- Authority has inappropriately included capacity and related parameters of RIL for analyzing “material injury” vis-à-vis ISRPL.
- “Material retardation” analysis is based solely on a WTO proposal and is thus, misguided. The Authority has not conclusively established any “material retardation” based on its analysis of the post-POI data of RIL and the market. In fact, the post-POI data shows an overwhelmingly positive picture of the SBR domestic industry in India.

The Petitioners are not under any “threat of material injury”

- The Petitioners claimed (i) material injury; (ii) threat of material injury; and (iii) material retardation of the establishment of an industry, simultaneously. However, these standards are mutually exclusive and cannot co-exist.
- The Petitioners have claimed “threat of material injury” but failed to substantiate the claim in terms of Article 3.7 of the ADA. The Petitioners have provided no factual evidence that the threat is clearly foreseen and imminent. The prices of import do not undercut or suppress the domestic prices and volume of imports have consistently declined from subject countries (particularly, EU).

The Petitioners have not suffered any “material retardation”

- The AD Rules do not provide any guidelines for the conduct of an investigation pertaining to the standard of “material retardation”.
- The Petitioners relied on a “proposal” at the WTO to establish the standard of “material retardation”. Such proposals are subject to the outcome of negotiations at the WTO, and have no legal or binding value.
- Based on established standards in other jurisdictions, the Petitioners are not suffering any material retardation. Applying the “market stabilization” test (as laid down in *Benzyl Paraben from Japan* and *PVC battery covers from Germany*), the Petitioners have not established that the “injury” apparent from its data is not merely indicative of normal start up conditions or that its performance is worse than what can be expected in an industry with high entry barriers.
- During the POI, only ISRPL has been commercially producing the subject goods and it was performing at 80% capacity utilization. Based on the Disclosure Statement, we note that ISRPL achieved 30% market share in the POI. Within 6 months post-POI, with RIL joining commercial production, the DI gained 51% of the market share.
- Both ISRPL and RIL expressed intentions to expand capacities in 2013 and 2015, respectively. The same shows the expected profitability of the sector once the Petitioners are established.

The data of the Petitioners do not indicate any injury or material retardation

- The data provided in the Petition and the data available for the post-POI period do not indicate any injury to the Petitioners as:
  - There is no price injury: there is no price undercutting (even as per the disclosure statement) and evidently, the DI prices are substantially lower than the import prices- showing there is no suppression or depression.
  - The Petitioners’ losses and costs are showing a declining trend, indicating stabilization of their production and sales.
  - There is no volume injury: Imports are declining in absolute terms and relative to domestic production and consumption.
  - The Petitioners’ inventories show a declining trend.
  - Post-POI data shows overwhelming decline in combined cost of sales of the DI, as well as stabilized selling prices. Capacity utilization, production and market share are also positive indicators. Even the losses of the Petitioners have become negligible compared to POI.

There is no causal link between the imports from the subject countries and the alleged injury of the Petitioners

- The Petitioners’ injury, if any, is attributable to various other factors, apart from the imports from subject countries. These include:
  - Lack of product approvals from end-users
  - Loss making sales of ‘Off-Grade’ subject goods by RIL at low prices
  - Change in market conditions between the planning stage, when SBR market was optimistic, and stage of commencement of plant, when the SBR market crashed
  - Other factors as listed in ISRPL’s Annual Reports
    - Significant cost overruns in the execution of project by ISRPL
    - Delay in start of commercial production
    - Significant fall in natural rubber prices influencing price and sales of SBR
    - Locational disadvantage of ISRPL leading to higher costs for inland freight
    - New capacity additions and weakened demand for SBR
    - Start-up costs incurred by the Petitioners
- While the PUC is clearly demarcated as Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR), the import statistics provided by the Petitioners include forms of styrene-butadiene which are not subject goods.
- ESB 1739 and ESB 1789 should be excluded from the scope of the subject goods since these grades are not manufactured by the DI.

88. Submissions filed by M/s BST Elastomers are as under:

- The Authority is requested to re-evaluate the dumping margin of SBR 1700 series from Thailand to India by using only SBR 1712 price to be best and correct facts as 95 % of SBR 1700 Series exported by BSTE to India during the POI period are SBR1712.
- BSTE share in India was less than 5% which cannot cause injury.
- Additional information on our domestic price both SBR 1712 and 1500 is being attached to evaluate domestic market as per WTO agreement.
- Both normal value and export price be evaluated at ex-factory level i.e. at same level of trade.

89. Submissions by M/s Kanth & Associates representing M/s Trinseo Europe GmbH is as under:

- M/s Trinseo has provided data to the extent possible and therefore it should not be treated as non-cooperative but rather in residual category.

90. Submissions filed by European Commission are as under:

Demand has increased by 40% over the period of analysis. It is also noted that demand continued to rise in the 6 months following the POI to reach an overall increase of 47%.

Over the period of analysis, imports from the subject countries have increased by 26% thus allowing the domestic industry to settle in the domestic market and to reach a market share of 29% in the POI. The market share of the domestic industry continued increasing afterwards and almost doubled in the 6 months following the POI to reach 51%. In such circumstances, the Commission fails to understand how the investigating authority can claim that the gain in market share of the domestic industry is not significant.

When taking a closer look at the imports from the subject countries, it appears that, contrary to the other subject countries, imports originating in the EU have decreased both in relative (-8.753 MT) and absolute terms (-11 percentage points market share). Bearing in mind that consumption increased significantly, this questions the impact that EU imports could have had on the domestic industry over the period of analysis.

The situation of the petitioner appears to reflect a situation of a newly-established producer. Indeed, the petitioner has been able to increase its production volume steadily since the start of operations. The sales volume on the domestic market also shows a very positive trend, whereby in a very short period of time of 2 years, the domestic industry achieved a sizable share of around 50% of the Indian market. Furthermore, the domestic industry did not only benefit from the increase in consumption, it also gained very significant market share to the detriment of historical players such as the EU.

As far as causal link is concerned, the Commission fails to see how imports from the subject countries and from the EU in particular could have caused injury to the domestic industry. The investigation has evidenced that imports from the subject countries have lost over 10% market share over the period of analysis and even 45% when extending this period by 6 months after the POI. Furthermore, imports from the subject countries also decreased in absolute terms whereas consumption has increased by over 40%. The decrease in market share for the subject countries has taken place to the entire benefit of the domestic industry.

It appears that the situation of the domestic industry has been improving continuously and the establishment of the industry is not retarded in any manner. As a matter of fact, production and sales have increased steadily and the domestic industry could even double its domestic sales between the POI and the 6 months following the POI. The latter period coincides with the beginning of the commercial activities of the second producer on the domestic market. This fact demonstrates on its own that the establishment of the domestic industry was not retarded.

The Commission notes that the investigating authority has relied on proposed amendments to the ADA in order to guide its assessment with regard to material retardation. As the investigating authority rightly points out and as the Commission had indicated in its submission following the initiation of this proceeding, such proposed amendments are however not legally binding. On the contrary, Article 3.4 of the WTO ADA is applicable in this proceeding and the economic factors and indices that it lists should have been analyzed in order to reach meaningful conclusions.

91. Submissions filed by All India Rubber Industries Association are as under:

- 1) With respect to the Disclosure Statement under issue, we submit that the same does not consider the submissions made by us during this investigation. We adopt all the submissions made during this investigation in the present comments and request that findings may be given by the Designated Authority accordingly.
- 2) The present comments are limited to issues pertaining to the Disclosure Statement issued by the Authority on 10 July, 2017. For the sake of brevity, our submissions before this Authority contained in our Written Submissions and Rejoinder Submissions are not being reproduced; though the same may be treated as part and parcel of these comments.
- 3) The Authority appears to have split the injury analysis in the present case. It appears that the Authority has considered that instead of a singular domestic industry, each producer in the Indian industry can be separately considered for the purposes of determining injury to the DI. This is completely baseless and the Authority has not provided any rationale for such an analysis.
- 4) We note that our submissions have been altogether overlooked in the Authority's determinations. The Authority has failed to note that given the situations of ISRPL and RIL, and the lack of product approvals with the DI for sale of the subject goods, the present case claiming material retardation was highly premature. In fact, even the Authority's own data regarding the post-POI period lends evidentiary support to this claim. We request the Authority to reconsider the propriety of the initiation of the present investigation.
- 5) In any case, we find it eludes logic to consider the domestic industry players individually to determine "material injury" for ISRPL as an "established" domestic industry even though it is the first entrant into the Indian market and to consider the same domestic industry as "unestablished" for RIL, another producer entering production more than a year after ISRPL has been established and attained commercial performance. The Authority must justify such distinction and determination. We submit that such a determination is illegal and merits rectification.
- 6) The Authority has claimed to split the injury analysis into two parts- analysis of material injury for ISRPL and material retardation for RIL. Without prejudice to our primary claim that such a division is not legally tenable, we note that the Authority has even failed to completely exclude RIL from its material injury analysis. We note that time and again, throughout the Disclosure Comments, the Authority has included the capacity of both ISRPL and RIL in its analysis for material injury. We submit that such an approach is without any basis. Inclusion of the RIL capacity in the total capacity of the Indian industry, for a consideration of material injury, leads to a situation where capacity utilization is unduly suppressed. This is because, during the POI, RIL had not begun commercial production and its capacity and production should both be excluded.
- 7) On the material injury analysis, since the Authority claims to have only considered data for ISRPL, then it should refer to ISRPL alone in its conclusions, instead of referring to "domestic industry". Such categorization would clarify whether data of ISRPL or RIL or both is being considered.
- 8) There is excessive confidentiality exercised by the Authority in the Disclosure Statement evidenced through redaction of data that is generally provided to the interested parties. We request the Authority to provide us with the rationale for such redaction.
- 9) The existence and examination of Material Injury of ISRPL precludes a separate material retardation analysis. This is because the existence / possibility of existence of material injury presumes the existence of an established industry. We submit that the Authority must clarify whether it is establishing jurisprudence that a claim of material retardation may exist where an established industry already exists. Otherwise, the segregation of analysis as done in the present case appears to be null.
- 10) The Authority's reference and reliance on "WTO's proposed amendment" to determine material retardation is completely unfounded and without any justification. Such a reliance is based on information that is not available with us, and has not been made available to us throughout the investigations. We submit that the proposal to the WTO must be rejected, without even holding it as having any persuasive value, as the cited proposal is not India's proposal before the WTO. In fact, WTO negotiations have been stalled for some years now due to high level of variances in members' opinions. Thus, the Authority's reliance and subsequent analysis based on the "proposal before the WTO" is without merit.

- 11) Moreover, based on the indexed data supplied by the Authority, it is evident that the cost of sales of RIL have reduced 82% while selling price has only declined by 32%. Even with cost of sales becoming a fifth of its initial value, and selling price declining by a mere 30%, the Petitioner (RIL) is still experiencing substantial losses. Concurrently, imports from the subject country have also declined substantially. Thus, we submit that Authority must establish the correlation between the prices & profitability of the Petitioner and the imports from the subject countries. We submit that the correlation regarding the injury suffered by RIL has not been established by the Authority.
- 12) In the causal link analysis, the Authority has neglected to analyze “any known factors other than dumped imports” despite many of them having been listed by the interested parties. We reiterate that for ensuring that injury caused by these other known factors is not attributed to the injury caused by the allegedly dumped imports, the Authority must necessarily isolate and segregate injury caused by each factor and exclude the same from the overall injury suffered by the Petitioners.
- 13) Moreover, other factors’ causing injury to the Petitioners listed in the Petitioners’ Financial records, such as Annual Reports and Investor presentations must necessarily be addressed. We submit that when the Annual Reports of the Petitioners provide reasons other than imports as the cause for injury suffered, then the Authority must fully consider the value of the same. The Annual Reports of the Petitioner are important documents that ensure transparency in the Petitioner’s process and the same cannot be ignored. In this regard, we place reliance on *Andhra Petrochemicals Ltd. vs. Designated Authority* [(2006) 201 ELT 481] wherein it was held that Designated Authority must take into consideration Annual Reports of the company, where the injury projected are not due to imports but other reasons. This finding of the CESTAT is binding on the Authority herein.
- 14) We submit that the Authority’s conclusions, as contained in the Disclosure Statement are without any basis and merit reconsideration. Considering the foregoing, and the fact of decreased imports in the period post-POI, no causal link or conclusion thereof may be derived from the data supplied by the Authority. We request the Authority to reanalyse the data before them in light of the foregoing submissions.
- 15) With respect to the Authority’s Annexure 4 of the Disclosure Statement, we raise the following issues:
  - a. The Authority must clarify how a non-injurious price (NIP) calculated for an established industry-ISRPL can be used for a non-established, new entrant like RIL.
  - b. With respect to the Authority’s consideration (at page 61 of the Disclosure Statement) regarding “raw material cost” and “cost of utilities”, the Authority has considered “the best achieved norms of raw material/cost of utilities by the domestic producer, over various quarters of POI or standard consumption norms, whichever is higher at POI rates”. In this regard, we submit that there is no basis for considering the “higher” value. We submit that the AD Rules provide for usage of the “best achieved norms” and that implies, necessarily, the lowest consumption norms. Thus, the consideration of “higher” norms is against the letter and spirit of the Annexure III of the AD Rules. Further, there is no provision for considering “standard consumption norms”. The Authority has also failed to share the standard consumption norms under discussion here.
  - c. Under “Production”, the Authority has relied on the project reports of the DI. We reiterate our submissions pertaining to the non-reliability of the Petitioners’ project reports, as pressed in our Written Submission. We reiterate that the We submit that a non-confidential version of the same should be shared with the us. We also submit that without such provision, and opportunity of comment, the Authority’s reliance on the same is illegal and violative of principles of natural justice.
  - d. The Authority has not addressed our submissions pertaining to the rate of return on capital employed for the DI. We reiterate that while commissioning its plant, ISRPL has secured a long-term loan in foreign exchange at interest rate of LIBOR + 0.72% which is approximately 2.5%. It is submitted that even if the historical rate of return is neglected, the rate of return cannot be taken as 22% as per the standard practice of the authority. This is also supported by the decision of the Hon’ble CESTAT in the matter of *Bridge Stone Tyre Manufacturing v. Designated Authority* wherein it questioned the

rationale of using 22% rate of return for determining the NIP of the applicant without providing the historical rate of return in the industry concerned.

We urge the Authority to consider our submissions. We also pray that, if the proceeding is not terminated and if there is any change in the essential facts under consideration then, the DA must issue another Disclosure Statement intimating of the same, another opportunity may be provided to us to make comments and another public hearing should be granted by the Designated Authority.

#### **Examination by the Authority**

92. The Authority has examined submissions made by various interested parties in response to the disclosure as under:
- i. The Authority notes submissions on faulty and premature initiation of investigation submissions by various interested parties including All India Rubber Industries Association who besides this have also raised impact of AD measure on user industry. The Authority holds that as Material Retardation is one of the forms of injury, and the petition filed by Domestic Industry for initiation fulfilled prima facie the requirements of relevant AD Rules based on which, the Authority initiated the same on merits and as per rules.
  - ii. The Authority notes submission of Domestic Industry on methodology to evaluate the cost of production of producers/exporters and also those of the concerned producers/exporters from South Korea and clarifies that the cost of production of product under consideration for domestic sales of both the producers cum exporters from South Korea has been validated from the data reported in Appendices 5, 6 and 7. The Authority has noted variance in raw material consumption between appendix 5 and appendix 8 in the information provided by these producers/exporters which has been appropriately addressed and the final cost of production was disclosed to both the producers/exporters in the disclosure statement. The methodology adopted was also discussed with the concerned producers/exporters when the variance in various appendices was noted at the time of onsite verification and the verification report issued thereafter.
  - iii. Specifically for M/s LG Chem, the company has sourced Butadiene (BD) and Styrene material (SM) from own production as well from M/s Lotte Chemicals. The raw materials required for the production of BD (mix C4) and SM (Benzene) are sourced from Lotte Chemicals. These inputs are procured under some agreement which do not truly reflect the costs as such prices are not benchmarked to international prices of respective commodities. The comparison between international prices, another cooperative producer in Korea and LG's purchase prices from Lotte shows that LG's purchase prices were significantly lower. Since the prices of key inputs were not demonstrating the true cost, the average purchase prices of BD and SM of the other cooperative producer during POI in Korea has been referenced.
  - iv. Further the Authority holds that it is the cost of production data of the cooperating producers/exporters and the market conditions of the subject country which are relevant for determination of normal value and not any other data specific for another producer in a non-subject country as contested by the Domestic Industry for referencing such data.
  - v. As regards, LG Chem India Pvt. Ltd., the Authority notes that it has not exclusively been set up for handling activities related to product under consideration. The contribution of product under consideration in overall sales of the company comprises less than 5% of its share. The expenses incurred by LG Chem India booked under SGA have been appropriately proportioned on PUC and considered while computing dumping margin.
  - vi. The Authority notes that domestic petitioners have stated that many holding, subsidiary companies of LG group exist whose information has been suppressed by the exporter. The Authority notes these submissions of the petitioner and holds that as far as the PUC is considered, the producer has provided information of all its exports to India during POI. The information of the entities related to exports to India has been evaluated by the Authority.
  - vii. Further as regards determination of ex-factory export price of subject goods, the same has been computed after ensuring that the non-direct exports by the producer i.e. through Daewoo International / Daewoo International Singapore by KKPC and through LG Chem America Inc., Hansuk Chemicals Co. Ltd, Everlite Korea Co. Ltd., Hearty Chem Corp, and Wonchem Ltd. by LG Chem Ltd. are in ordinary course and not sold at a loss. Adjustment warranting this has been considered. The Authority has therefore considered all adjustments to

- evaluate the dumping margin. The CIF prices of these non-direct entities have however been considered for computing weighted average landed value.
- viii. The Authority notes the submissions made by M/s BST Elastomers, Thailand and some additional data provided by them at a belated stage and holds that as the producer/exporter had not filed the relevant information in the structured format in timely manner, no further data at this stage can be considered. The Authority thereby confirms the evaluation already done for all producers/exporters of Thailand as per the best available information.
  - ix. As regards submissions by M/s Trinseo, the Authority holds that as the producer/exporter did not file complete information therefore no individual dumping Margin has been granted to them on account of the aforesaid as also stated in the disclosure and the producer/exporter is being considered under the residual category.
  - x. As regards submissions by various interested parties that the material injury, threat of injury and material retardation cannot be simultaneously evaluated, the Authority holds that the injury is examined and evaluated for Domestic Industry as a whole which comprises of eligible domestic producers in accordance with the Rule 2 (b) of the AD Rules. The macro assessment of material injury done for Domestic Industry as a whole may contain variation in incidence of injury parameters for different domestic producers. A part of Domestic Industry may suffer volume injury while another part may suffer price injury. An overall assessment of Domestic Industry as a whole cumulates and averages such impacts. While this happens for material injury assessment at parameter level, a similar phenomena can happen in terms of different injury forms to different parts of Domestic Industry. Therefore it is likely that a producer which is part of Domestic Industry may face material injury while another may face material retardation. The Anti-Dumping Rules do not prevent simultaneous examination of both these forms. It cannot be held that the 3 forms of injury are mutually exclusive. The Authority holds that both ISRPL and RIL have made genuine commitment by setting up production facilities of SBR. Both are nascent and new industry as ISRPL started commercial production only in February 2014 while RIL announced this after POI. Both are facing challenges in their establishment and progress. The Authority has therefore evaluated both material injury and material retardation separately for the two producers of Domestic Industry and drawn conclusion on an overall basis for Domestic Industry as a whole.
  - xi. For the purpose of considering overall demand, production and capacity, the data of all producers is relevant and therefore have been considered. For specific analysis of capacity utilisation, trend of production, sales, inventory and exports, data of ISRPL has been considered for the purpose of analysing material injury.
  - xii. In the analysis of material injury to ISRPL, while specific injury parameters have been considered exclusively for ISRPL, the import from subject countries have been analysed with reference to total demand in the country. The trend of market share of sales by ISRPL follows the same trend as that of Domestic Industry.
  - xiii. As regards price undercutting being negative, the Authority holds that the case under investigation is peculiar in which even the commercial production by ISRPL has only commenced in February 2014 whereas the POI is October 2014 to September 2015. The company is a new entrant and has to aggressively match the import prices which leads to a reasonably high negative price undercutting when the net sales realization (NSR) of ISRPL is compared with the Landed Value of dumped imports. It would therefore need to be interpreted along with the injury margin computed for the domestic industry.
  - xiv. Specific data of a cooperating entity is treated confidential on a claim by the concerned interested parties. The same has been considered for ISRPL as well. As regards the fallacy in interpretation of trend of imports from subject countries, the Authority reiterates and clarifies that in the disclosure it has stated that imports from subject country increased till 2014-15 and have declined in POI but remained significant. The relevance of imports being significant as a parameter of assessing injury is relevant in context of evaluating the injury form of material retardation in particular.
  - xv. The premise of the respondents that the evaluation of injury be prior to determination of Injury Margin therefore needs to be seen in context of the fact that the concept of injury subsumes Injury Margin intrinsically and is inseparable.

- xvi. The Authority holds that in an ideal situation of no injury, the Injury Margin should be negative as it is a surrogate qualification of manifestation of various injury parameters. The concept of Lesser Duty Rule which requires computation of NIP not only strengthens non-attribution but also quantifies the extent of injury. In any case, the Authority has in the disclosure stated that ISRPL has suffered injury on account of profitability, which was reflected in table 9 of the disclosure. As regards post POI data analysis the Authority has undertaken the same for Reliance Industry Limited in particular. As regards the high fixed expenses of ISRPL, the Authority has while computing the NIP adopted the highest achievable capacity utilization as per the project report rather than best achieved capacity utilization keeping in view the peculiar circumstances of a new entrant company.
- xvii. As regards the trend of cash profit, all quarters of POI show losses with varying intensity which needs to be appreciated as prevalence of losses rather than its mere variation in quantum.
- xviii. In order to address the aspect of companies being new entrants, the Authority has evaluated NIP for ISRPL for a capacity utilization in a prospective period which would be maximally attained and raw material/utilities compared with standards given in project report and adopting the best. Therefore the non-injurious price has been determined with most optimistic efficiency of the company. Also keeping the new entrant aspect in view, the Authority has evaluated RIL on material retardation parameters.
- xix. As regards wages, employment, productivity and inventory indices for ISRPL, the Authority has included the same after appropriate indexation.
- xx. As regards inter se competition amongst two new entrants of DI, the Authority holds that both the new entrants are benchmarking themselves primarily against the imports from subject countries though within the market share of Domestic Industry as a whole there could be a dynamic change of market shares of the two entrants. However, the two new entrants are not in a commanding position to dictate market prices.
- xxi. The Authority notes various factors like start-up costs, non-approval of petitioners products, fall in demand etc. being cited as possible causes of injury to Domestic Industry. The Authority has evaluated the material injury for ISRPL on parameters of profitability which do not contain any off grade sales. The long gestation period of approval process done by end users who themselves are beneficiary of dumped material cannot be considered as a rational and fair argument as a factor of injury to Domestic Industry. The inefficiencies prevalent in domestic industry's production cost and high abnormal costs have been appropriately normated while computing NIP to ensure a fair protection to mitigate injury caused due to dumped imports. The Authority has compared the best achieved norms of raw material and utilities further with standard consumption norms and adopted the lower amongst the two to eliminate the impact of startup costs, besides the methodology on capacity utilization stated in sub para xvi above.
- xxii. As regards impact of FTA between India and Korea, the Authority has evaluated the Landed Value as per the applicable custom duties. The Authority notes that on the one hand the FTA provisions might lower the landed value, but at the same time the exporters could leverage this to increase their export realization by factoring the zero import duty advantage in export price as compared to other competitors which would though increase the landed value to some extent on the one hand and also decrease the dumping margin due to increase in export price. Therefore these aspects may also warrant an adjustment. Therefore the Authority has adopted its consistent practice of evaluating the landed value with applicable custom duties.
- xxiii. As regards the analysis of cost and price trend lines of indexed numbers of RIL, the Authority holds that during POI the trial production had only began in October 2014 which included high start-up costs with low sales. The analysis of cost and price trend during POI which was the phase of trial production for RIL is therefore not realistic, on indexed terms. The Authority has analysed the actual absolute numbers and has noticed that during POI the prices of RIL are lower than the NIP determined for ISRPL which also surrogates as fair price for RIL who has declared commercial production.
- xxiv. As regards the causal link analysis, the Authority keeping in view that the petitioners are new entrants has computed NIP on best achievable capacity utilization rather than best achieved capacity utilization to ensure that injury is not attributed to any abnormal startup costs. As regards export sales, the Authority has undertaken the cash profitability exclusively for domestic sales.
- xxv. As regards injury assessment to RIL, the same has been undertaken with regard to material retardation alone. Since the commercial production of RIL was declared post POI, therefore the NIP for domestic industry has

been considered on the basis of ISRPL's data. While the petitioners have stated that there is no bar to include RIL for NIP computation, the Authority does not consider this as feasible as the NFA during POI in the book of accounts of RIL but is captured as CWIP.

- xxvi. The Authority while examining material retardation to RIL has evaluated the same on facts and not conjectures. The proposal on WTO examining material retardation being considered in WTO has been considered as a reference. The lower market share of RIL's sales in POI with relatively longer gestation period than ISRPL to declare commercial production and unable to enhance capacity utilization in post POI even beyond 50% despite availability of demand indicates that RIL has suffered injury on account of material retardation, due to dumped imports. Though their sales have increased in post POI, the profitability is negative.
- xxvii. To compute the cost of sales of RIL the Authority has adopted the established principle of transfer pricing and as stated above, since RIL was not in commercial production during POI, the comparison of net sales realization (NSR) has been done with NIP computed for ISRPL to ensure a fair comparison.
- xxviii. As regards confidentiality, the Authority following its consistent practice and as per AD Rules has not disclosed individual companies' data of any interested party, where even confidentiality has been claimed.
- xxix. Further the Authority holds that any Interested Party can request for an authorization letter from DGAD to obtain non-confidential transaction wise import data from DGCIS. However once such a data is provided by DGCIS to any of the Interested Party, they are obliged to use the same as per terms and conditions of DGCIS. The Authority has not placed such a transaction wise data of DGCIS in public file which would only circumvent the policy of providing transaction wise data by DGCIS to bonafide users on specific undertaking. Therefore the Authority in no way has constrained availability of such data to any Interested Party. The submissions by M/s. Luthra and Luthra are therefore misplaced and not appropriate both in context of facts of the case and law.
- xxx. The Authority through letter dated 15<sup>th</sup> May, 2017 to M/s Luthra & Luthra Law Offices had assured for authorisation to them to obtain transaction wise import data from DGCIS after their undertakings on bonafide use of such information as being followed with all interested parties involved in the investigation.
- xxxi. As regards raw material purchase prices by Indian Synthetic Rubber Private Limited (ISRPL) being at arm's length raised by one of the interested party earlier, the Authority has evaluated NIP by considering the actual purchase price and appropriately applying principles of annexure 3 of AD Rules. In any case downward computation of NIP due to preferential treatment in supply of raw material to ISRPL does not adversely impact the interest of importers or the user industry. Further the Authority has allowed rate of return as per existing rules/principles.
- xxxii. In response to the post disclosure comments of one of the interested party regarding normation in costs for NIP evaluation, the Authority confirms that best consumption norms of raw material have been considered. Further best achievable capacity utilization in prospective POI period has been considered keeping in view that DI has started operations in 2014 only but stated to achieve higher capacity utilization in their project report from 3<sup>rd</sup> year onwards. Also one of the injury forms being examined is material retardation wherein post POI performance has also been analysed.
- xxxiii. The Authority has considered and addressed the submissions made by All India Rubber Industries Association (AIRIA) to the disclosure which was inadvertently missed to them in appropriate paras in this finding. The key submissions on undertaking both material injury and material retardation in the same investigation separately for ISRPL and RIL respectively has been addressed in sub para x. While the Authority has addressed material injury on the stipulated parameters contained in Annexure II of AD Rules, for material retardation parameters like growth in share, optimal level of production and profitability of new entrant has been considered.
- xxxiv. As regards NIP, the Authority has though allowed rate of return on capital employed as per its consistent practices. The normation has been done by adopting project standards as per the project report or the best achieved as stated in sub para xxi. This has been done to specifically address the situation of abnormal high costs of startup keeping in view the fact that companies are new entrants. RIL's data has not been included to ensure that NIP is reasonable and fair, which otherwise would have been higher.

- xxxv. As regards examination of causal link keeping in view decrease in imports in post POI from subject countries, the Authority holds that in post POI the profitability of RIL has been considered as an index of injury and reported in injury analysis.

#### **Indian industry's interest & other issues**

93. As regards the submissions regarding impact on user industry the Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of antidumping measures is not to restrict imports from the subject countries in any way, and, to affect the availability of the products to the consumers.
94. The Authority also holds that though in the event of imposition of anti-dumping duties the price level of product in India may be affected but fair competition in the Indian market will not be reduced by such anti-dumping measures. On the contrary, the anti-dumping measures may mitigate the unfair advantage gained by dumping practices, which would arrest the decline of the domestic industry both material injury and its retardation and would help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

#### **Conclusions**

95. Having examined the contentions of various interested parties and analysis undertaken above, the Authority concludes that:
- There is dumping of product concerned from the subject countries.
  - The dumped imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry, impacting profitability.
  - Manifestation of the aforesaid injury is both in form of material injury as well as material retardation

#### **Recommendations**

96. Having concluded as above the Authority considers it necessary to recommend following definitive Anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner as described in the duty table given below.
97. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty equal to the amount mentioned in Col. 8 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government, on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**DUTY TABLE**

No.	Heading/ Subheading	Description of goods *	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E- SBR) of 1500 Series and 1700 Series	European Union	European Union	Synthos Kralupy A.S., Czech Republic	Synthos Kralupy A.S., Czech Republic	207.49	MT	US\$
2.	-do-	-do-	European Union	European Union	Synthos Dwory 7 Sp. Z. Oo, Poland	Synthos Dwory 7 Sp. Z. Oo, Poland	207.49	MT	US\$
3.	-do-	-do-	European Union	European Union	Any combination other than S. No. 1 & 2		266.00	MT	US\$

4.	-do-	-do-	European Union	Any	Any	Any	266.00	MT	US\$
5.	-do-	-do-	Any country other than those subject to anti-dumping duty	European Union	Any	Any	266.00	MT	US\$
6.	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Kumho Petrochemical Co., Ltd	Kumho Petrochemical Co., Ltd	33.95	MT	US\$
7.	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Kumho Petrochemical Co., Ltd	i. Daewoo International Corporation, Korea RP ii. Daewoo International, Singapore	33.95	MT	US\$
8.	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	LG Chem Ltd, Korea RP	LG Chem Ltd, Korea RP	28.68	MT	US\$
9.	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	LG Chem Ltd, Korea RP	i. LG Chem America Inc.; ii. Hansuk Chemicals Co. Ltd; iii. Everlite Korea Co. Ltd.; iv. Hearty Chem Corp.; v. Wonchem Ltd	28.68	MT	US\$
10.	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Any combination other than S. No. 6, 7, 8 & 9		64.00	MT	US\$
11.	-do-	-do-	Korea RP	Any	Any	Any	64.00	MT	US\$
12.	-do-	-do-	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Korea RP	Any	Any	64.00	MT	US\$
13.	-do-	-do-	Any	Korea RP	Any	Any	64.00	MT	US\$
14.	-do-	-do-	Thailand	Thailand	Any	Any	243.60	MT	US\$
15.	-do-	-do-	Thailand	Any	Any	Any			

16.	-do-	-do-	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Thailand	Any	Any			
-----	------	------	---	----------	-----	-----	--	--	--

\*Note: Styrene Butadiene Rubber of 1900 Series and Solution SBR are excluded from the scope of the Product Under Consideration

98. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

**Further Procedure**

99. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority